राष्ट्रीय संस्करण

CopyRight - Jagran.com

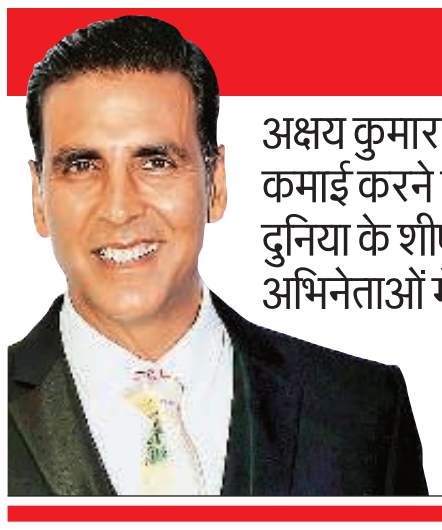

अक्षय कुमार सर्वाधिक कमाई करने वाले दुनिया के शीर्ष अभिनेताओं में शामिल

>> 16

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 74

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 23 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

BYJU'S The Learning App

IAS 2020 के लिए

निःशुल्क कार्यशाला

DATE : 25TH AUGUST 2019 (SUNDAY) | TIME : 4:30 PM

आधुनिक भारत के साथ बैच प्रारम्भ

26th AUGUST 2019

5.00 PM TO 7.30 PM

DEMO CLASS AVAILABLE FROM 26TH AUGUST 2019

5.00 PM TO 7.30 PM

कार्यालय का पता : Shop No. 15, Ground Floor, Vardhman Central Mall, Nehru Vihar, Mukherjee Nagar, Delhi-54

निःशुल्क पंजीकरण के लिए अपना नाम SMS/WHATSAPP करें- 9205881869

सरोकार

फ्लोराइड लेवल की जांच अब चुटकियों में

दुर्गापुर : सीएमईआरआइ के वैज्ञानिकों ने सस्ती-कारगर फ्लोराइड डिटेक्शन किट विकसित की है। इससे शरीर में फ्लोराइड की मात्रा जांचना आसान होगा और खर्च होंगे सिर्फ 10 रुपये। फ्लोराइडयुक्त पानी वाले क्षेत्रों के लिए इसे उपयोगी माना जा रहा है। (पेज-10)

जागरण विशेष

पूर्वांचल के कालीन उद्योग को पैट यार्न ने दिए नए पंख

भदोही : पश्चिमी देशों में प्लास्टिक के धागों (पैट यान) से तैयार कालीन की मांग बढ़ी है। पानीपत और बीकानेर के बाद अब उत्तर प्रदेश के भदोही, मीरजापुर, बनारस के कारोबारी भी पैट यार्न से बने कालीन निर्यात करने लगे हैं। (पेज-10)

चिदंबरम चार दिन की सीबीआइ रिमांड पर

बढ़ी मुश्किलें ▶ आइएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री को नहीं मिली राहत, धरी रह गईं सारी दलीलें

सीबीआइ ने मांगी थी पांच दिन की रिमांड, रोज आधे घंटे के लिए मिल सकेंगे परिजन व वकील

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आइएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को गुरुवार को विशेष अदालत में पेश करने के लिए ले जाते सीबीआइ के अधिकारी। प्रेट्र

आइएनएक्स मीडिया केस में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को गुरुवार को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने 26 अगस्त तक के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की रिमांड पर भेज दिया। बुधवार देर रात गिरफ्तार करने के बाद सीबीआइ ने भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच उन्हें विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार के समक्ष पेश किया। सीबीआइ ने अदालत से पांच दिन का रिमांड मांगा। खचाखच भरी अदालत ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि तथ्यों को देखने के बाद कि चिदंबरम को चार दिन की सीबीआइ रिमांड पर भेजना उचित है। इस दौरान परिजन और वकील उनसे रोज 30 मिनट के लिए मुलाकात कर सकेंगे। हर 48 घंटे बाद उनके स्वास्थ्य की जांच की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि उनकी व्यक्तिगत गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचे।

सीबीआइ की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तो चिदंबरम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच लंबी बहस हुई। तुषार मेहता ने कहा कि मनी लांड्रिंग का यह एक गंभीर और ऐतिहासिक मामला है। अन्य लोगों के साथ चिदंबरम भी आपराधिक साजिश में शामिल थे, लेकिन वह जांच एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहे हैं। वह सभी दस्तावेज मुहैया नहीं कर रहे। गंभीर अपराध में फंसने के बावजूद वह कपटपूर्ण तरीके से जवाब दे रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 अगस्त को सुनाए फैसले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए गंभीर टिप्पणी की थी। ऐसे में उनकी पांच दिन की रिमांड जरूरी है। दस्तावेजों से मिलान और अन्य आरोपितों से आमना-सामना कराया जाना है। कुछ सवाल तभी पूछे जा सकते हैं जब आरोपित सुरक्षित छाते तले न हो। चिदंबरम ने भी कुछ बोलना चाहा तो तुषार ने विरोध किया, लेकिन अदालत ने इसकी अनुमति दी तो वह सिर्फ दो ही बात बोले।

पत्नी और बेटा भी रहे मौजूद : पूरी सुनवाई के दौरान चिदंबरम की पत्नी नलिनी, बेटे कार्ति चिदंबरम के अलावा दक्षिण भारत के कई नेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक भी मौजूद रहे। अदालत के बाहर मुकुल वासनिक ने कहा कि यह राजनीतिक बदले का मामला है और हमे अदालत पर पूरा भरोसा है।

एजेंसी को यही नहीं पता है कि उन्हें सवाल क्या पूछना है : सिब्बल

कपिल सिब्बल ने कहा, इस मामले में चिदंबरम के पुत्र कार्ति व अन्य आरोपितों को जमानत मिल चुकी है। पहली गिरफ्तारी कार्ति के चार्टर्ड अकाउंटेंट भास्कर रमन की हुई थी, उसके बाद कार्ति को पकड़ा गया। आरोपित पीटर और इंद्राणी मुखर्जी को भी जमानत मिली हैं। जांच एजेंसी ने चिदंबरम से कुल 12 सवाल पूछे, जिनमें छह के जवाब वह पूर्व में दे चुके हैं। पूछताछ करने वालों को यही नहीं पता कि उन्हें प्रश्न क्या पूछना है। बुधवार रात गिरफ्तारी के बावजूद चिदंबरम से गुरुवार 11 बजे तक पूछताछ नहीं की गई। विदेशी निवेश की मंजूरी सरकार के जिन छह सचिवों ने दी थी, उनमें से किसी को भी नहीं पकड़ा गया। मामले की जांच खत्म हो चुकी है। जज ने सात माह तक आदेश नहीं दिया तो चिदंबरम कैसे सुरक्षित छाते तले हो गए? एफआइआर में उनका नाम नही है। चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। अगर चिदंबरम के पास कुछ दस्तावेज हैं, तो क्या एजेंसी ने कोई पत्र लिखा?

पूर्वमंत्री बोले, सीबीआइ ने मुझे एक ही बार बुलाया

पी. चिदंबरम ने कहा कि मुझे सीबीआइ ने एक ही बार बुलाया, 6 जून 2018 को। मुझसे पूछा गया कि क्या मेरा विदेशी खाता है? मैंने जवाब दिया कि मेरा कोई विदेशी खाता नहीं है। सीबीआइ ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे बेटे का विदेशी खाता है? मैंने जवाब दिया कि बेटे कार्ति का खाता है।

चिदंबरम वह जवाब नहीं दे सकते जो सीबीआइ चाहती है

अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा, सीबीआइ का पूरा मामला इंद्राणी के बयान पर आधारित है, जो मामले में सरकारी गवाह बन चुकी हैं। गवाह सिर्फ एक पद है, कोई सुबूत नहीं है। चिदंबरम वह जवाब नहीं दे सकते जो सीबीआइ चाहती है। असहयोग, सुबूत से छेड़छाड़ और देश से भागने जैसा कोई खतरा नहीं है।

यह है पूरा मामला

आइएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआइ ने 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि पी. चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को दी गई एफआइपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुईं। इसके बाद ईडी ने गत वर्ष इस संबंध में मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था। सीबीआइ और ईडी केस में जांच कर रही हैं कि कैसे चिदंबरम के बेटे कार्ति को 2007 में एफआइपीबी से आइएनएक्स मीडिया के लिए मंजूरी मिली। जांच में पता चला कि एफआइपीबी से मंजूरी दिलाने के लिए आइएनएक्स मीडिया के निदेशक पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी ने पी. चिदंबरम से भेंट की थी ताकि मंजूरी में कोई देरी न हो। इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी अब सरकारी गवाह बन चुकी हैं।

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

अगर वहां कब्जा हिंदुओं को दिया जाता है तो ऐतराज नहीं

नई दिल्ली : अयोध्या राम जन्मभूमि में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। 1934 में दंगा हुआ तब से वहां नमाज पढ़ना बंद है। हिंदू वहां पूजा करते थे। अगर कब्जा हिंदुओं को दे दिया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं। ये बातें कुछ मुसलमानों ने 1950 में फैजाबाद की अदालत में हलफनामा दाखिल कर कहीं थीं।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

छत्तीसगढ़ में पांच इनामी नक्सलियों ने किया समर्पण

जगदलपुर : पुलिस के बढ़ते दबाव और नक्सली लीडर की तानाशाही के चलते बस्तर संभाग में पांच इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें सुकमा में पांच लाख का इनामी नक्सली मेहतर कोर्राम उर्फ रोंडा ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के बीच पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

जन्मजात नागरिकता के अधिकार को खत्म करने की तैयारी में ट्रंप

वाशिंगटन : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता के अधिकार को खत्म करने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा है कि वह अमेरिका में जन्में उन बच्चों के नागरिकता अधिकार खत्म करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं, जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं हैं। अगर यह अधिकार समाप्त होता है तो इससे बड़ी संख्या में भारतीय भी प्रभावित होंगे।

कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में शरद पवार के खिलाफ एफआइआर के आदेश

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- 1000 करोड़ रुपये के इस घोटाले में बांबे हाई कोर्ट ने दिया आदेश
- भतीजे अजित पवार और 70 अन्य के खिलाफ भी दर्ज होगा केस

शरद पवार फाइल फोटो

महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (एमएससीबी) घोटाले में बांबे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को राकांपा प्रमुख शरद पवार, उनके भतीजे व पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और 70 अन्य के खिलाफ पांच दिन के भीतर एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में पहली नजर में उनके खिलाफ विश्वसनीय सुबूत हैं।

जस्टिस एससी धर्माधिकारी और एसके शिंदे की पीठ ने गुरुवार यह आदेश दिए। शरद पवार और अजित पवार के अलावा इस मामले के आरोपितों में राकांपा नेता जयंत पाटिल, कई अन्य राजनेता, सरकारी अधिकारी और राज्य के 34 जिलों के कोऑपरेटिव बैंक के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। सभी आरोपित 2007 से 2011 के बीच एमएससीबी को कथित रूप से 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने में शामिल थे। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा कराए गए निरीक्षण और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसायटीज एक्ट के तहत अर्धन्यायिक जांच आयोग द्वारा दाखिल आरोपपत्र में शरद पवार, अजित और बैंक के कई निदेशकों को दोषी ठहराया गया था। इसमें कहा गया था कि उनके फैसलों, कार्यों और लापरवाही की वजह से बैंक को यह नुकसान उठाना पड़ा। नाबार्ड की ऑडिट रिपोर्ट में यह तथ्य भी उजागर हुआ था कि आरोपितों ने चीनी और कताई मिलों को कर्ज बांटने, कर्जे नहीं चुकाए जाने और कर्जों की वसूली में कई बैंकिंग कानूनों व रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया। खास बात यह है कि उस दौरान अजित पवार बैंक के निदेशक थे।

निरीक्षण रिपोर्ट के बावजूद इस मामले में कोई एफआइआर दर्ज नहीं की गई थी। स्थानीय आरटीआइ कार्यकर्ता सुरेंद्र अरोड़ा ने 2015 में आर्थिक अपराध शाखा में एक शिकायत दर्ज कराई थी और हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआइआर दर्ज किए जाने की मांग की थी।

निजी क्षेत्र के कर्मी पेंशन के बदले ले सकेंगे एकमुश्त रकम

नई दिल्ली : निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की एक-तिहाई रकम एकमुश्त निकालने की सुविधा फिर से मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सेंट्रल ट्रस्टी बोर्ड ने पेंशन स्कीम के सदस्यों को सेवानिवृत्ति के वक्त तिहाई पेंशन के एवज में एकमुश्त रकम लेने का विकल्प फिर से देने का निर्णय लिया है। इससे सवा छह लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में गत दिवस हुई ईपीएफओ के बोर्ड की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें से एक निर्णय ईपीएस में कम्यूटेशन अर्थात पेंशन की आंशिक रकम एकमुश्त लेने का विकल्प बहाली के लिए ईपीएस-95 में संशोधन करने का है। (पेज-12)

मप्र से पकड़े गए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के पांच एजेंट

भोपाल : मध्य प्रदेश पुलिस ने सतना जिले से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के पांच एजेंटों को पकड़ा है। ऑनलाइन ठगी के जरिये 'टेरर फंडिंग' और जासूसी के मामले में जहां सुनील सिंह, बलराम सिंह और शुभम मिश्रा को गिरफ्तार कर भोपाल लाया गया है, वहीं भारवेंद्र सिंह और प्रदीप कुशवाहा सतना पुलिस की हिरासत में हैं। सूत्रों ने बताया कि पकड़े गए लोगों ने कई राज्यों में जाल फैला रखा है। आरोपितों के फोन में 17 पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। इन लोगों ने पाकिस्तानी एजेंटों को बैंक खाते, एटीएम कार्ड की जानकारियों के साथ धनराशि भेजी थी। साथ ही युद्ध की स्थिति में सामरिक महत्व की जानकारियां एकत्रित कर रहे थे। पाकिस्तानी हैंडलरों से मिलकर ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। (पेज-6)

कश्मीर पर भारत को मिला फ्रांस का साथ

जागरण ब्यूरो नई दिल्ली

- मैक्रों ने कहा, कश्मीर द्विपक्षीय मसला, बातचीत से सुलझाएं
- मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस का साथ सराहनीय

पेरिस पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गले मिलकर स्वागत करते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। रायटर

कश्मीर मुद्दे को लेकर फ्रांस खुलकर भारत के साथ आ गया है। कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत और पाकिस्तान से इसे बातचीत के जरिये सुलझाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती सदियों पुरानी है।

तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी और मैक्रों की पेरिस से करीब 50 किलोमीटर दूर फ्रांस की सांस्कृतिक विरासत में शुमार चेटेउ डी चंतिलि में मुलाकात हुई। लगभग डेढ़ घंटे की बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती देने वाले द्विपक्षीय और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। उसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर की बातचीत भी हुई।

इसके बाद दोनों ने साझा प्रेस कांफ्रेंस की। मोदी ने कहा कि समूह-7 को भारत का पूरा सहयोग है। भारत और फ्रांस की दोस्ती किसी स्वार्थ पर नहीं टिकी है। उन्होंने कहा कि जैवविविधता के लिए भारत सदियों से प्रतिबद्ध है। भारत और फ्रांस के बीच सौर गठबंधन अहम है। पीएम ने बताया कि फ्रांस 36 राफेल लड़ाकू विमानों में से पहला विमान अगले महीने सौंपेगा। उन्होंने कहा कि पांच ट्रिलियन इकोनामी हमारा मुख्य लक्ष्य है। भारत में फ्रांसीसी उद्यमियों के लिए निवेश का बहुत सुनहरा मौका है। दोनों देशों ने तकनीकी और सह उत्पादन के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है दोनों देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में भी इजाफा हो रहा है। मोदी बोले, आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस का सहयोग मिला। वहीं, राष्ट्रपति मैक्रों ने अपने संबोधन में पुलवामा हमले की निंदा करते हुए दोहराया कि कश्मीर भारत-पाक के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है। दोनों देशों को बातचीत के जरिये मतभेदों को दूर करना चाहिए। मैक्रों ने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को भारत का आंतरिक मामला बताया। साथ ही चंद्रयान मिशन के लिए उन्होंने मोदी को बधाई दी।

इससे पहले पेरिस पहुंचने पर हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। विदेश मंत्री जीन वेस ली ड्रायन ने उनकी आगवानी की। मोदी यहां प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे और फ्रांस में 1950 व 1960 के दशक में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले दो भारतीय विमानों की याद में स्मारक का उद्घाटन करेंगे। शुक्रवार को वह फ्रांस के प्रधानमंत्री एडुवर्ड फिलिप से मिलेंगे। मोदी शुक्रवार को फ्रांस से यूएई और बहरीन की यात्रा पर जाएंगे। रविवार को वह फिर फ्रांस के शहर बियारित्ज लौटेंगे और समूह-7 की बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत वैसे तो समूह-7 देशों का सदस्य नहीं है लेकिन फ्रांस ने विशेष तौर पर भारत समेत कुछ और देशों को आमंत्रित किया है। सोमवार को उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। दोनों के बीच कश्मीर मुद्दे पर बातचीत लगभग तय है। इस मुलाकात की पहले से कोई तैयारी नहीं थी लेकिन कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के बाद इस मुलाकात की तिथि तय की गई। ट्रंप ने मंगलवार को कश्मीर को लेकर काफी चिंता जताने के साथ यह भी कहा था कि वह मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। मोदी ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से भी मिल सकते हैं।

फ्रांस से पीएम मोदी शुक्रवार की शाम यूएई रवाना होंगे। भारत से रवाना होने से पहले उन्होंने ट्वीट किया था, 'यूएई में क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान के साथ बहुत ही अहम बैठक होने वाली है। दोनों मिल कर महात्मा गांधी की 150 वें जन्म दिवस पर एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। वहां रू पे कार्ड भी लांच किया जाएगा।' यूएई में मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'जायद मेडल' से भी नवाजा जाएगा। बहरीन यात्रा के बारे में पीएम ने लिखा था कि यह किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा होगी। बहरीन में मोदी प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। वह भगवान श्रीनाथ जी के प्राचीन मंदिर के नए सिरे से विकास से जुड़ी योजना का भी शुभारंभ करेंगे।

सोनिया गांधी बोलीं, बहुमत की ताकत के सहारे देश में डर का माहौल

पेज>>4

इंद्राणी के मुताबिक, चिदंबरम ने कार्ति के कारोबार में मदद करने को कहा था

पेज>>4

कश्मीरी बोले

घाटी को मिली अलगाववादियों की हड़तालों और बंद के फरमानों से आजादी, अलगाववादियों के उकसावे और फतवों पर कान नहीं दे रहे आम लोग, कई बार प्रदर्शन और मार्च के लिए बुलाया, लेकिन कोई नहीं पहुंचा

अलगाववादियों की दुकान पर ताला लगा चाबी झेलम में फेंक दो

नवीन नवाज, श्रीनगर

कश्मीर में जिंदगी धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही है। श्रीनगर में दौड़ते वाहन इसे साबित कर रहे हैं। जागरण

लोगों ने लगाई पोस्टर गैंग से बचाने की गुहार

राजबाग में तैनात एक अधिकारी ने कहा कि कुछ दिन पहले कुछ स्थानीय लोग ही पोस्टर लेकर हमारे पास पहुंचे और ऐसे लोगों से बचाने की गुहार भी लगाई। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी, क्योंकि इससे पहले इस तरह के पोस्टर तक हटाने में हमें खासी मशक्कत करनी पड़ती थी।

कश्मीर में बदलाव की बयार के बीच अब अलगाववादियों की धमकियों और फतवों के खिलाफ भी लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। कल तक उनके इशारे पर सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ती थी, लेकिन अब उनके फरमानों पर आम कश्मीरी कान ही नहीं दे रहे हैं। न ही कोई उनके हड़ताली कैलेंडर का जिक्र करना ही पसंद नहीं करता है। लोगों का कहना है कि दिल्ली को इनकी दुकान पर ताला लगाकर चाबी झेलम में फेंक देनी चाहिए। इसके बाद ही वादी में हमेशा के लिए अमन बहाल हो पाएगा।

अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद पिछले एक पखवाड़े में पूरी वादी में माहौल तेजी से बदला है। पाबंदियों में ढिलाई देने के बाद सामान्य जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। ऐसे में हताश अलगाववादी विभिन्न माध्यमों से लोगों को उकसाने का कोई मौका नहीं चूक रहे। पोस्टर के माध्यम से धमकियां दी जा रही हैं और अराजक तत्वों के सहारे खुली दुकानों और वाहनों पर पथराव कराने की साजिश रची जा रही है, लेकिन आम कश्मीरी अब उनके फरमान मानने से इन्कार कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग तो खुद सुरक्षाबलों से इन लोगों की शिकायत भी कर रहे हैं।

विफल हो चुकी हैं माहौल बिगाड़ने की कई साजिश : श्रीनगर के सौरा इलाके में बुधवार को हुर्रियत समेत कई अलगाववादी संगठनों के साझा संगठन जेआरएल (ज्वॉइंट रजिस्टेंस लीडरशिप) ने कुछ पोस्टर चस्पा कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। इन पोस्टरों में मार्च निकालने का आह्वान किया था। इससे पूर्व आठ अगस्त को राजबाग इलाके में जेआरएल और एक अन्य संगठन ने हड़ताली कैलेंडर के पोस्टर चिपकाकर प्रदर्शनों के लिए उकसाने का प्रयास किया था। वहीं, ईद से दो दिन पहले भी डाउन-टाउन और बटमालू में कुछ आपत्तिजनक पोस्टर मिले, लेकिन लोगों ने उनकी तमाम साजिशों की हवा निकाल दी और कोई भी प्रदर्शन करने ही नहीं पहुंचा।

इन्हीं पोस्टर वालों ने तबाह किया : सौरा में इशियाक अहमद नामक एक बुजुर्ग ने कहा, इन पोस्टर वालों ने ही तो हमें तबाह किया है। सिर्फ मीडिया वाले ही इन्हें उछालते थे और इन पोस्टरों पर अमल के लिए डर पैदा करते थे। इनका जिक्र न करो तो ही बेहतर। अगर लोग इनके साथ होते तो आपको पूरे शहर में इस समय जुलूस नजर आते।

उनकी दुकान बंद होगी तभी हमारी खुलेगी : बटमालू स्थित सब्जी मंडी में अपनी दुकान का शटर उठा रहे युसुफ से जब हुर्रियत और जेआरएल पर बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी दुकान अब बंद हो रही है, उसे खुलने का मौका मत दो मेरे भाई। नहीं तो मेरी दुकान का शटर कब उठेगा, यह कोई नहीं बता पाएगा। यहां सभी लोग रोज रोज के बंद और हड़ताल से तंग आ चुके हैं।

जल्द जमीन पर दिखेंगे बदलाव : कश्मीर मामलों के जानकार एजाज अहमद ने कहा कि अभी आपको असर शायद कम नजर आए, लेकिन चार से छह महीने बाद आप खुद यहां जमीन पर बदलाव को प्रत्यक्ष रूप से महसूस करेंगे। यह कोई छोटी बात नहीं कि शरारती तत्वों के हंगामें के बावजूद कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें खुली रखी हैं। सड़कों पर वाहन भी चल रहे हैं।

कश्मीर में अधिकांश क्षेत्रों में प्रतिबंध में ढील

पेज>>5

गाजियाबाद में सीवर लाइन में उतरे पांच मजदूरों की दम घुटने से मौत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

- प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मजदूरों के पास नहीं थे सुरक्षा उपकरण

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक मकान के सामने बने सीवर चैंबर को मेन लाइन से जोड़ने के दौरान दम घुटने से पांच मजदूरों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मजदूरों के पास सुरक्षा उपकरण नहीं थे।

गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के कृष्णकुंज इलाके में जल निगम व कार्यदायी एजेंसी ईएमएस इंफ्राकॉन की ओर से सीवर लाइन डालने का काम कराया जा रहा है। गुरुवार को एक घर के सामने बने चैंबर को मुख्य सीवर लाइन से जोड़ने के लिए एक मजदूर ने जैसे ही चैंबर का ढक्कन खोला, वह उसमें गिर गया और बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए एक-एक कर चैंबर में अन्य मजदूर उतरने लगे। पांच मजदूर अंदर पहुंचे तो वे भी बेहोश हो गए। घर के मालिक राजवीर के शोर मचाने पर भीड़ एकत्र हो गई। इसके बाद मॉस्क लगाकर मजदूर जितेंद्र व साजिद मेनहोल में उतरे और सभी को बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस बेहोश मजदूरों को सेंट जोसफ अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सभी मजदूर बिहार के समस्तीपुर जिले के निवासी थे और पास में ही झुग्गी में रहते थे। उन्होंने बताया कि मामले में दोषी एजेंसियों या दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना में जान गंवाने वाले मजदूरों के पास सुरक्षा उपकरण नहीं थे। जिस चैंबर में वे उतरे थे, करीब 13 फीट गहरा था। ज्ञात हो, इंसान को सीवर में उतार सफाई कराने पर सुप्रीम कोर्ट प्रतिबंध लगा चुका है। बीते मई माह में ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख जस्टिस एचएल दत्तू ने टिप्पणी की थी कि सीवेज की सफाई के दौरान लोगों की मौत समाज के लिए अभिशाप है। 'सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव न होना दर्शाता है कि कानून ठीक तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है।'

35.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा गुरुवार को राजधानी में। यह सामान्य से एक डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से दो डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक बूंदाबांदी हो सकती है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 23 अगस्त 2019

विधानसभा में गूंजा रविदास मंदिर हटाए जाने का मुद्दा

मानसून सत्र ▸ सत्ता पक्ष के विधायक भाजपा के खिलाफ नारे लगाते हुए वेल में आए, सदन की कार्यवाही दो बार करनी पड़ी स्थगित

पारित हुआ मंदिर निर्माण का संकल्प, भाजपा नेताओं ने भी दिया समर्थन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

तुगलकाबाद में रविदास मंदिर हटाए जाने का मुद्दा गुरुवार को विधानसभा में भी गूंजा। मानसून सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष के विधायक हाथों में पोस्टर लिए और भाजपा के खिलाफ नारे लगाते हुए वेल में आ गए। एक विधायक ने तो विरोध स्वरूप अपने कपड़े भी फाड़ डाले। विधानसभा अध्यक्ष के बार-बार समझाने पर भी जब विधायक शांत नहीं हुए तो दो बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आखिरकार सदन में इसी जगह भव्य मंदिर बनाए जाने के लिए एक संकल्प प्रस्ताव लाया गया, जिसका समर्थन भाजपा नेताओं ने भी किया। विधायक विशेष रवि ने इस प्रस्ताव को सदन में रखा और सभी की सहमति से यह प्रस्ताव पास हुआ। संकल्प किया कि केंद्र सरकार से भूमि आवंटन हो और वहां पर दिल्ली सरकार एक भव्य मंदिर बनवाए।

मानसून सत्र की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज, भाजपा के पूर्व विधायक मांगेराम गर्ग व अन्य को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। हालांकि अध्यक्ष रामनिवास गोयल के सदन में पहुंचते ही आंबेडकर नगर के विधायक अजय दत्त इस मुद्दे को लेकर वेल में आ गए। विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़लान ने भी इसका समर्थन किया। देखते-देखते सत्ता पक्ष के ज्यादातर विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस पर विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता भी उठ गए और उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ने उन्हें शोक संवेदनाएं प्रेषित करने के लिए जैसे-तैसे शांत कराया। लेकिन जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, आप के कई विधायक फिर से हाथ में पोस्टर लिए नारेबाजी करने लगे। पोस्टर में भाजपा को दलित विरोधी बताया गया था। दो बजकर 15 मिनट पर सदन अगले 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। ढाई बजे सत्र फिर से शुरू हुआ। सत्र शुरू होते ही फिर से आप विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। इस पर अध्यक्ष ने एक बार फिर 15 मिनट के लिए सत्र स्थगित कर दिया।

पौने तीन बजे शुरू हुई रविदास मंदिर पर चर्चा : पौने तीन बजे विधानसभा अध्यक्ष ने नियम 54 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके तहत विधायक विशेष रवि ने संत रविदास मंदिर को हटाए जाने का मुद्दा उठाया। समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि 1948 से रविदास समिति पंजीकृत है, जबकि डीडीए का गठन इसके बाद हुआ है। मंदिर को हटाना का कदम भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। एक तरफ वह सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, दूसरी ओर रविदास मंदिर को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मंदिर हमारी आस्था है। देश मंदिर को हटाने से नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने से बनता है। कहा कि मोदी जी आपका मंदिर, मंदिर है और हमारा मंदिर, मंदिर नहीं।

भाजपा ने दिया आश्वासन : चर्चा के दौरान भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने मंदिर को हटाए जाने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि संत रविदास सर्व समाज के संत हैं। सदन में सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा विद्वेष पूर्ण वक्तव्य देकर इस कृत्य के लिए भाजपा को दोषी ठहराना राजनीतिक रोटी सेंकने जैसा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को मंदिर हटाने का आदेश दिया। जहां तक भाजपा की बात है तो हम भी चाहते हैं कि मंदिर वहीं बने।

भाजपा विधायकों को सदन से बाहर किया : चर्चा के क्रम में शाम को जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना वक्तव्य दे रहे थे तो बीच-बीच में टोकाटाकी करने पर भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता और ओमप्रकाश शर्मा को सदन से बाहर कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें कई बार शांत रहने को कहा, लेकिन जब वे नहीं माने तो उन्हें मार्शल आउट करा दिया गया।

विधानसभा मानसून सत्र में जाते अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। ध्रुव कुमार

केजरीवाल बोले, रविदास मंदिर की जमीन के लिए अध्यादेश लाए केंद्र सरकार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दक्षिणी दिल्ली स्थित रविदास मंदिर को हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मंदिर हटाए जाने से सभी वर्गों के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मुद्दा यह है कि वापस उसी जगह पर मंदिर को कैसे बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार चार-पांच एकड़ जमीन रविदास समाज को दे दे तो दिल्ली सरकार की ओर से उसी जगह पर संत रविदास का एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा।

केजरीवाल ने मंदिर के पुनर्निर्माण के समाधान के दो तरीके सदन में सुझाए। उन्होंने कहा कि एक तरीका है कि केंद्र द्वारा समीक्षा याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष दाखिल की जाए और इसमें कानून एवं व्यवस्था का हवाला भी दिया जाए। दूसरा तरीका अध्यादेश पारित कर चार-पांच एकड़ जमीन दे दी जाए।

उन्होंने कहा कि जमीन को लेकर कहा जा रहा है कि वन विभाग की जमीन है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पूरे देश का वन क्षेत्र इसी कुछ एकड़ जमीन पर निर्भर करता है? अगर डीडीए चार-पांच एकड़ जमीन रविदास समाज को दे तो वह एक सौ एकड़ में घना वन लगवाकर देंगे। वह दिल्ली सरकार की ओर से 100 एकड़ जमीन केंद्र को देने के लिए भी तैयार हैं।

केजरीवाल ने कहा कि संत रविदास ने ऐसे समाज की परिकल्पना की थी, जहां सब लोग बराबर हों, सबको एक जैसी सुविधाएं मिलें। दिल्ली सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वाली जमीन छोड़ दो कहीं और दूसरी जमीन पर मंदिर बना दें। संत रविदास का जहां पर मंदिर था, उसी जगह पर मंदिर बनाया जाएगा।

मंदिर वाली भूमि को वन क्षेत्र की श्रेणी से मुक्त करे आप सरकार : गुप्ता

विजेंद्र गुप्ता

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल मामले को न्यायालय में उलझाए रखना चाहते हैं, जबकि इस मसले का समाधान न्यायालय के बाहर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मार्शलों द्वारा उनको बलपूर्वक सदन से बाहर निकाला गया। उनकी और ओमप्रकाश शर्मा की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। आम आदमी पार्टी की रुचि सभी को साथ लेकर हल निकालने में नहीं है।

इस मसले पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, लेकिन सरकार जानबूझकर इस पर राजनीति कर रही है। गुप्ता ने सदन में अपने संबोधन में कहा कि इस मसले का सबसे सटीक और सरल समाधान है कि दिल्ली सरकार का पर्यावरण मंत्रालय तुगलकाबाद के जहांपनाह वन क्षेत्र में स्थित संत रविदास मंदिर वाली भूमि को वन क्षेत्र की श्रेणी से मुक्त करे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने यह आश्वासन दिया है कि दिल्ली सरकार यदि संबंधित मंदिर की भूमि को वन क्षेत्र से मुक्त कर देती है तो केंद्र सरकार रविदास समाज की भावनाओं के अनुकूल अविलंब कार्रवाई करेगी। उन्होंने सदन में कहा कि दिल्ली सरकार इस पर तुरंत फैसला ले, चाहे उसे आज ही रात अपने कार्यालय खुलवाकर काम करना पड़े।

डीएसएसएसबी परीक्षा में कृपाणधारी सिखों को रोकने का विरोध

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : सिख नेताओं ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) की परीक्षा में सिख छात्रों को कृपाण एवं कड़ा पहनकर जाने की अनुमति देने की मांग की है। इसे लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिखा है। कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने चेयरमैन को इसे लेकर ज्ञापन सौंपा है। इन दिनों विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए डीएसएसएसबी की परीक्षा चल रही है।

सिरसा ने कहा कि कृपाणधारी एवं कड़ाधारी सिखों को डीएसएसएसबी की परीक्षा में अनुमति नहीं देने की शिकायत मिल रही है। उन्हें परीक्षा केंद्र में जाने से पहले कड़ा व कृपाण उतारने को कहा जा रहा है। यह सिख छात्रों के साथ भेदभाव है। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा है कि कृपाणधारी सिखों को उच्च सुरक्षा वाले स्थानों में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने चेयरमैन से इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है।

जीके ने कहा कि बोर्ड ने धातु वाले वस्तुओं के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं देने का निर्देश जारी किया गया है। इस वजह से सिख छात्रों को परेशानी हो रही है। उन्होंने बोर्ड के चेयरमैन से मिलकर यह पाबंदी वापस लेने की मांग की।

कालकाजी थाने में लगी अदालत 96 आरोपितों को भेजा जेल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तुगलकाबाद स्थित गुरु रविदास मंदिर को हटाए जाने के विरोध में हुए उग्र प्रदर्शन के 96 आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बुधवार को प्रदर्शनकारियों की अगुआई करने वाले भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर सहित 96 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। गुरुवार को कालकाजी थाने में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हारुन प्रताप सिंह ने सुनवाई की। इसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया। चंद्रशेखर और अन्य पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 186 और 332, 120 बी/34 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल, आरोपितों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें कोर्ट में पेश करने की बजाय थाने में ही आकर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सुनवाई की। कुछ आरोपितों को रोहिणी व कुछ को तिहाड़ जेल भेजा गया। प्रदर्शन में शामिल सीआइएसएफ कमांडो सोनिंदर को भी गिरफ्तार किया गया है। उसकी तैनाती सुकमा में थी। वह चंद्रशेखर की साथ था और प्रदर्शन में उसकी सहायता कर रहा था।

हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश व राजस्थान से आए प्रदर्शनकारी रामलीला मैदान से होते हुए संत रविदास मंदिर के पास पहुंच गए थे। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने बाइक फूंक दी और कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए थे। इस पर पुलिस ने 96 लोगों को गिरफ्तार किया था। सभी पर दंगा करने, अवैध रूप से एकत्र होने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। बुधवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद एहतियात के तौर पर आसपास के स्कूल भी बंद रखे गए।

तुगलकाबाद प्रकरण पर गरमाई दलित राजनीति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास मंदिर प्रकरण को लेकर बुधवार को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव के मुद्दे पर दलित राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा। प्रियंका के ट्वीट के छह घंटे बाद बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट किया। उन्होंने हिंसक वारदातों से किनारा करते हुए जनता को हुई परेशानी पर दुख व्यक्त किया।

बसपा प्रमुख ने भीम आर्मी जैसे अनुसूचित वर्ग के संगठनों को बिना नाम लिए संविधान का सम्मान करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि बसपा पूरी तरह अनुशासित पार्टी है और कानून के दायरे में रहकर लोगों की मदद के लिये आगे आती है। तोड़फोड की घटनाओं से जनता को संकट झेलना पड़ता है, जो गलत है। दूसरी पार्टियों व संगठनों के लिए कानून तोड़ना आम बात है। हमें अपने संतों व गुरुओं के सम्मान में बेकसूर लोगों को तकलीफ व क्षति नहीं पहुंचानी है।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट में लिखा, 'भाजपा सरकार पहले करोड़ों दलित बहनों-भाइयों की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक रविदास मंदिर स्थल से खिलवाड़ करती है और जब राजधानी में हजारों दलित भाई-बहन अपनी आवाज़ उठाते हैं तो भाजपा लाठी बरसाती है, आँसू गैस चलवाती है, गिरफ्तार करती है। दलितों की आवाज़ का ये अपमान बर्दाश्त से बाहर है।'

सावरकर की मूर्ति पर लगाई स्याही, छात्रों ने दूध से नहलाया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह और वीर सावरकर की मूर्तियों की स्थापना के बाद गुरुवार को फिर से विवाद हो गया है। कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआइ) की तरफ से वीर सावरकर की मूर्ति पर स्याही पोती गई। इन मूर्तियों को 20 अगस्त को डूसू के पूर्व अध्यक्ष शक्ति सिंह ने स्थापित किया था। सावरकर की मूर्ति पर एनएसयूआइ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने गुरुवार को तड़के तीन बजे स्याही डाली। इस मामले में गुरुवार को मॉरिस नगर थाने में अक्षय के खिलाफ शक्ति सिंह ने कार्रवाई के लिए शिकायत की है। वहीं, अक्षय ने आरोप लगाया है कि कि इस घटना के बाद से ही मुझे एबीवीपी से जुड़े कई लोगों की तरफ से धमकी भरे फोन कॉल आए। अक्षय का सावरकर की मूर्ति पर स्याही लगाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

डीयू के छात्रों ने बताया कि गुरुवार को दोपहर 11 बजे के बाद वीर सावरकर की मूर्ति में लगी स्याही को दूध से नहलाकर हटाया गया। ये छात्र किसी छात्र संगठन से जुड़े नहीं थे। वहीं 20 अगस्त को मूर्ति स्थापना के बाद से ही आर्ट्स फैकल्टी के बाहर पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। इस पूरे प्रकरण में पर डीयू प्रशासन शांत है।

अदालत की अवमानना में फसेंगे जमीन विक्रेता

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

शाहबेरी मामले में बिल्डरों के साथ अब उन लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने जा रही हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट का स्थगन होने के बाद भी जमीन को बिल्डरों को बेचा था। प्राधिकरण इसे लेकर हाई कोर्ट में जल्द ही अवमानना याचिका दायर करेगा। प्राधिकरण बोर्ड ने इस पर सहमति जताई है। शाहबेरी प्रकरण में अब तक हुई कार्रवाई से भी प्राधिकरण ने बोर्ड को अवगत कराया है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शाहबेरी में 155 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया था। किसानों की याचिका पर 2011 में हाई कोर्ट ने अधिग्रहण को रद कर दिया था। इसके बाद प्राधिकरण ने 2013 व 14 में एक बार फिर से जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की तो इसके खिलाफ किसानों ने दोबारा हाई कोर्ट में 31 याचिकाएं दायर की थीं। इन पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 2014 यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसके तहत भूमि के हस्तांतरण व निर्माण पर रोक है। अधिकारियों के मुताबिक हाई कोर्ट का यह आदेश अभी भी लागू है। इसके बावजूद भूमि के मालिकों ने जमीन को बिल्डरों को बेच दिया और बिल्डरों ने उस पर प्राधिकरण की बिना अनुमति के इमारतें बनाईं। स्थगन आदेश के बावजूद

शाहबेरी प्रकरण

भूमि बेचने व उस पर निर्माण करने वालों को प्राधिकरण अब हाई कोर्ट में घेरने की तैयारी कर रहा है। प्राधिकरण हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही स्थगन समाप्त कर जमीन के अधिग्रहण की अनुमति की मांग करेगा। प्राधिकरण के इस कदम से जमीन बेचने वालों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक जाएगी।

इमारतें धराशायी होने से पहले पुलिस ने दबाए रखी प्राधिकरण की तहरीर : प्राधिकरण अधिकारियों ने बोर्ड के सामने दावा किया कि 17 जुलाई 2018 में शाहबेरी में दो इमारतों के जमींदोज होने से पहले उसने अवैध इमारतों का निर्माण करने वाले 143 बिल्डरों के खिलाफ बिसरख थाने में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इमारतें गिरने से हुई नौ लोगों की मौत के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। जुलाई 2019 तक पुलिस ने 44 बिल्डरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दादरी के सब रजिस्ट्रार कार्यालय से जानकारी मिलने के बाद 20 और बिल्डरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।

आज रात से आरएफआइडी टैग अनिवार्य

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ **बिना आरएफआइडी टैग के प्रवेश पर व्यावसायिक वाहनों को भरना होगा जुर्माना**

आज रात यानी 23 अगस्त की रात 12 बजे से दिल्ली में 13 टोल नाकों से प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहन बिना रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआइडी) टैग के प्रवेश नहीं कर पाएंगे। टैग न होने पर जुर्माना लगाकर प्रवेश दिया जाएगा। निगम ने इस बार हिदायत की दी है कि अब आरएफआइडी टैग लगवाने की तारीख नहीं बदली जाएगी। इसलिए जिन व्यावसायिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करना है वे आज रात 12 बजे से पहले टैग लगवा लें अन्यथा 24 अगस्त से भारी जुर्माने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। निगम सूत्रों के मुताबिक गुरुवार तक तकरीबन डेढ़ लाख आरएफआइडी टैग की बिक्री हो चुकी है। निगम के 13 टोल नाकों के अलावा छह अन्य स्थान चिन्हित किए हैं, जहां टैग लगवाने की व्यवस्था है।

बता दें कि ट्रांसपोर्टर व टैक्सी संगठनों की अपील पर निगम ने 16 अगस्त की समय सीमा को 23 तक बढ़ा दिया था। अब बिना टैग के व्यवसायिक वाहन के प्रवेश पर पहले सप्ताह के दौरान जुर्माने के तौर पर निर्धारित पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क और टोल राशि का दोगुना भुगतान लिया जाएगा। दूसरे सप्ताह के दौरान जुर्माने के तौर पर निर्धारित पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क और टोल राशि का चार गुना भुगतान लिया जाएगा। तीसरे सप्ताह के दौरान जुर्माने के तौर पर निर्धारित पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क और टोल राशि का छह गुना भुगतान लिया जाएगा। वहीं, टैग को लेकर ट्रांसपोर्टरों की परेशानी जारी रही। केंद्रों पर भीड़ देखने को मिली।

व्यावसायिक वाहन चालक विभिन्न केंद्रों के बाहर टैग लेने के लिए घंटो लाइनों में खड़े रहे। यहां लाइनों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स व अन्य कैब चालकों के लिए टेंट, पानी आदि की अस्थाई व्यवस्था नहीं की गई है। धूप और बारिश से बचने के भी इंतजाम नहीं हैं। कई लोगों की यह शिकायत भी थी कि टैग लेने के लिए प्लाजा केंद्र प्रशासन भी ठीक से कोई जवाब नहीं देता है।

इस मामले को लेकर दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष परमीत सिंह गोल्डी ने बताया कि टैग जारी करने पर आ रही समस्याओं को हमने पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) और दक्षिणी दिल्ली निगम को अवगत कराया है। इसमें टैग बनाने पर गाड़ी की फोटो अपलोड करने का प्रावधान है,जबकि कई गाड़ियां अभी भारत के अलग-अलग शहरों में गई हैं, जिनको टैग जारी करने के लिए टोल बनाने वाले स्थान पर तत्काल लाना मुश्किल है। ऐसे में इस अनिवार्यता को हटाया जाए।

आरएफआइडी टैग से दिल्ली में आने वाले हर एक व्यावसायिक वाहन की निगरानी हो सकेगी क्योंकि टोल नाके पर सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो जाएगी। इससे यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि दिल्ली में किस व्यावसायिक वाहन ने किस इलाके से प्रवेश किया और कब किया।

इन हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं संपर्क : आरएफआइडी टैग लगवाने के लिए निगम ने टोल वसूलने वाली कंपनी के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इसमें डीएनडीए के 7903176120, रजोकरी 9354320562 और केजीटी (कुंडली) 9205262947 पर संपर्क कर सकते हैं और आरएफआइडी टैग लगवाने का अनुरोध भी कर सकते हैं। साथ ही एमसीडी टोल एप मोबाइल में डाउनलोड करके पंजीकरण के बाद ऑनलाइन रिचार्ज भी करा सकते हैं।

डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी को हिंदी शलाका सम्मान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : हिंदी अकादमी की संचालन समिति की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए गुरुवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अकादमी के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की। इसके तहत हिंदी अकादमी के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हिंदी अकादमी शलाका सम्मान डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी को दिया जाएगा। उन्हें पुरस्कार के साथ पांच लाख रुपये की राशि भेंट की जाएगी। इसके अलावा विशिष्ट सृजनात्मक योगदान के लिए शीला झुनझुनवाला को दिल्ली शिखर सम्मान दिया जाएगा। उन्हें पुरस्कार के साथ दो लाख की राशि भेंट की जाएगी। संतोष कोली सम्मान डॉ. निर्मला जैन को दिया जाएगा। इस पुरस्कार के साथ उन्हें भी दो लाख की राशि दी जाएगी।

यह पुरस्कार दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी की पूर्व कार्यकर्ता संतोष कोली के नाम पर शुरू किया है। इसके ही 12 अन्य पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसके तहत पुरस्कार के साथ एक-एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इसके अंतर्गत जाने-माने लेखक श्यौराज सिंह बेचैन को हिंदी अकादमी गद्य विद्या सम्मान दिया जाएगा।

साइबर अपराध से मुकाबले को प्रशिक्षण जरूरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

साइबर अपराध से सुरक्षा को लेकर मंडी हाउस स्थित फिक्की ऑडिटोरियम में दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने किया। इसमें साइबर अपराध के जाने-माने विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। वक्ताओं ने साइबर अपराध की चुनौतियां पेश करने के साथ ही इससे लड़ने का पुख्ता इतंजाम किए जाने पर बल दिया।

विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन व फिक्की के संयुक्त तत्वावधान में होमलैंड सिक्योरिटी 2019-इनोवेशन लेड साइबर क्राइम मैनेजमेंट विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि साइबर अपराध से मुकाबले के लिए काम करने वाली एजेंसियों के अधिकारियों में कौशल की काफी कमी है। खुफिया सूचना संग्रह, डेटा विश्लेषण, जांच तकनीक और डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्र में और काम किए जाने की जरूरत है। वर्तमान में देश सहित दुनिया भर में साइबर अपराधों के ग्राफ में खतरनाक वृद्धि देखी जा रही है। इसके लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों को प्रशिक्षण के साथ ही एक वैश्विक रणनीति के निर्माण पर कार्य करने की जरूरत है। साइबर

फिक्की सभागार में आयोजित होमलैंड सिक्योरिटी सेमीनार में उपस्थित मुख्य अतिथि उपराज्यपाल अनिल बैजल (बाएं से चौथे) और अन्य अतिथि। जागरण

अपराध किसी देश की सीमा से नहीं बंधा होता, इसलिए इससे पुख्ता तरीके से निपटने के लिए समंवित दृष्टिकोण अपनाना होगा।

उन्होंने साइबर अपराध से मुकाबले के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा कानूनी ढांचे के संशोधन की भी बात कही। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक व लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. राजेश पंत ने कहा कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध के कारण औसत वैश्विक जीडीपी का 2.5 फीसद का नुकसान होता है। भारतीय रुपये में इसकी कीमत दो लाख करोड़ है। वर्तमान में साइबर सुरक्षा नीति 2013 के तहत काम होता है। वहीं, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 बनाने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है। इसका मसौदा अगले दो महीनों में तैयार होने की उम्मीद हैं। मंत्रिमंडल के सामने रखने के बाद अगले वर्ष की शुरूआत में यह एक नई रणनीति के साथ सामने आएगा। इस मौके पर विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के निदेशक डॉ. अरविंद गुप्ता सहित राहुल चौधरी, विदुर गुप्ता, पार्टनर व राजन लूथरा ने भी लोगों को संबोधित किया।

कवायद

दिल्ली-एनसीआर ठंड के दौरान फिर से स्मॉग में न जकड़े इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अभी से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं

सीपीसीबी का फरमान, शहर में न रहे कचरे का नामोनिशान

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

जाड़े के दौरान दिल्ली-एनसीआर फिर से स्मॉग में न जकड़े इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने अभी से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में पहला फरमान दिल्ली-एनसीआर के सभी स्थानीय निकायों के नाम जारी किया गया है। उन्हें लिखित में हिदायत दी गई है कि शहर में जहां कहीं भी खुले में या खाली जगहों पर कचरा डंप हो रहा है, उसे अविलंब वहां से साफ कराएं। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक प्रदूषण वाले हॉट स्पॉट की पहचान भी की जा रही है ताकि वहां अलग से उपाय किए जा सकें।

जानकारी के मुताबिक दिल्ली के तीनों नगर निगमों, दिल्ली विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, दिल्ली मेट्रो एवं गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के स्थानीय निकायों को एक पत्र जारी किया गया है। सीपीसीबी की ओर से जारी इस पत्र में उन्हें निर्देश दिया गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में जहां कहीं भी खुले में कचरा डाला जा रहा है या खाली पड़ी जमीन पर कूड़ा डंप हो रहा है तो इसे सितंबर तक साफ करा दें।

सीपीसीबी अधिकारियों का कहना है कि यही कचरा जब बढ़ने लगता है तो उसमें चोरी- छपे आग लगा दी जाती है। कचरे का यह धुआं सारे वातावरण को प्रदूषित करता है। अधिकारियों के मुताबिक सर्दी में प्रदूषण बढ़ने की प्रमुख वजह वाहनों के धुएं के अलावा कचरे और पराली का धुंआ भी है।

सीपीसीबी अधिकारियों ने यह भी बताया कि जाड़े में प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए एक अन्य कदम यह उठाया गया है कि दिल्ली-एनसीआर के कुछ हॉट स्पॉट चिह्नित किए जा रहे हैं। यहां हर साल सर्वाधिक प्रदूषण होता है। इन जगहों पर प्रदूषण थामने के लिए अलग से एक्शन प्लान भी तैयार किया जा रहा है।

रेलवे अफसरों को पढ़ाया जाएगा पर्यावरण संरक्षण का पाठ

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली

रेलवे स्टेशनों व ट्रेनों में तमाम कोशिशों के बाद भी गंदगी की शिकायतें मिलती रहती हैं। सबसे बड़ी समस्या कचरा निस्तारण की है। इसे ध्यान में रखकर रेल अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसके लिए भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान (आइआरआइटीएम) में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही दो अक्टूबर से रेलवे स्टेशनों, रेल परिसरों और ट्रेनों में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर पाबंदी लग जाएगी।

राजधानी के चार सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और आनंद विहार से रोजाना करीब दस टन कूड़ा जमा होता है। सिर्फ नई दिल्ली से चार टन कूड़ा निकलता है जिसमें बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा होता है। इन स्टेशनों पर सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए एकीकृत सफाई व्यवस्था शुरू की गई है। अधिकारियों का कहना है कि लखनऊ स्थित आइआरआइटीएम में प्रशिक्षण कार्यक्रम से सफाई व्यवस्था सुधारने में मदद मिलेगी। इस संस्थान में 26 से 30 अगस्त तक चलने वाले पर्यावरण संरक्षण एवं हाउस कीपिंग प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक क्षेत्र के रेल अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा 50 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगेगी। सभी रेलवे स्टेशनों पर पानी की बोतलों के सुरक्षित निस्तारण के लिए क्रशिंग मशीनें भी लगेंगी। अधिकारियों का कहना है कि प्लास्टिक पर रोक लगने से रेलवे ट्रैक के किनारे फैलने वाली गंदगी और सीवर जाम की समस्या दूर करने में मदद मिलेगी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण और सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। अपशिष्ट जल प्रबंधन और वर्षा जल संचयन, सुरक्षित ठोस अपशिष्ट संग्रहण व निस्तारण पर ध्यान दिया जा रहा है।

ऑनलाइन देह व्यापार गिरोह का पर्दाफाश, दो को कराया मुक्त

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नंद नगरी इलाके में चल रहे एक ऑनलाइन देह व्यापार गिरोह का दिल्ली महिला आयोग और पुलिस की टीम ने भंडाफोड़ किया है। यहां से एक 15 साल की मासूम और 30 साल की महिला को मुक्त कराया है। इसके साथ दंपती समेत तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपितों की पहचान नजमा (27), उसका पति असगर (30) व कमर राजा (30) के तौर पर हुई। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल और सिम भी बरामद किए हैं। जांच में पता चला है कि नजमा इस गिरोह की सरगना है। उसने करीब पांच-छह महीने पहले पति और एक अन्य के साथ मिलकर देह व्यापार का यह गिरोह शुरू किया था। विभिन्न एप के जरिये नजमा ग्राहक तलाशती थी। इसके साथ इन एप पर गिरोह के शिकंजे में फंसी लड़कियों की अश्लील वीडियो भी डाले जाते थे। साथ ही ग्राहकों से फोन पर इनकी अश्लील बातचीत भी कराई जाती थी।

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली महिला आयोग को 14 अगस्त को एक महिला ने अपनी 20 साल की बेटी के लापता होने की सूचना दी थी। आयोग की टीम ने युवती की एक सहेली से बात की। उससे पता चला कि नंद नगरी में एक ऑनलाइन देह व्यापार गिरोह चल रहा है। वहां करीब 20 लड़कियों से यह काम कराया जा रहा है। वह खुद उनके चंगुल में फंस गई थी, जिस वजह से 15-20 दिनों तक वहां पर रही। यहां उससे सोशल मीडिया प्लेटफार्म आइएमओ पर रात दस से सुबह छह बजे के बीच अश्लील वीडियो कॉल करवाए जाते थे। उसे उसकी एक सहेली ने इस गिरोह के जाल में फंसाया था, लेकिन वह किसी तरह वहां से निकल गई। उसने आशंका जताई कि उसकी सहेली भी उन्हीं के जाल में है। इस पर आयोग की टीम ने बुधवार रात नंदनगरी के ए-3 ब्लॉक में एक मकान पर छापा मारा। उससे 15 साल की बच्ची और एक महिला को मुक्त कराया गया।

100 से अधिक भाजयुमो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है बंगाम में बाइक रैली निकालने पर। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35ए हटाए जाने की खुशी में भाजयुमो ने 26 अगस्त तक यह अभियान जारी रखने की घोषणा की है।

सांसदों को जागरूक और जानकार बनाना मेरी प्राथमिकता : ओम बिरला

साक्षात्कार

दो ढाई महीने पहले की बात है जब राजस्थान से चुनकर आए भाजपा सांसद **ओम बिरला** को लोकसभा अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया तो सभी चौंक गए थे। इस फैसले के कारण ढूंढे जाने लगे थे, लेकिन बतौर अध्यक्ष अपने पहले सत्र में ही जिस तरह बिरला ने सत्तापक्ष के साथ-साथ विपक्षी दलों का भी विश्वास जीता और अक्सर बाधित रहने वाली लोकसभा को सुचारू कर दिया, उसने उनकी प्रतिभा और संकल्प को स्थापित कर दिया। लगभग दो दशक बाद सदन में इतना काम हुआ। अब वह एक कदम और आगे बढ़कर सांसदों को जागरूक और जानकार बनाने के मिशन पर काम करना चाहते हैं, ताकि संसद के प्रति लोगों का भरोसा बढ़े और यह आम व्यक्ति के लिए आदर्श बने। **दैनिक जागरण** के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख **आशुतोष झा** से हुई बातचीत का अंश :

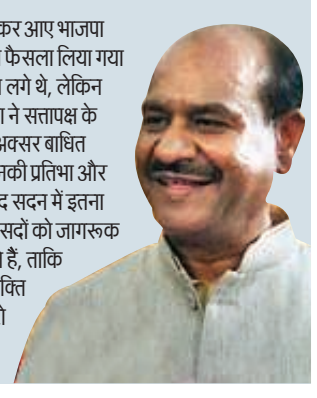

● सत्र में जिस तरह सदन को चलाया, इसके लिए कार्यप्रणाली में किस तरह का बदलाव लाया गया?

-मेरे मन में शुरू से था कि सदन चलना चाहिए। सदन में सहमति और असहमति दोनों के लिए स्थान होता है। मजबूत विपक्ष की भी जरूरत होती है। सदन में हर विषय पर चर्चा होनी चाहिए। एक तरफ विधायी कार्य होता है लेकिन अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को व्यक्त करने का भी मंच है। मैंने कोशिश की और सभी दलों के नेताओं ने सहयोग किया। सदन कभी बहुमत के आधार पर नहीं चलता है। यह संख्याबल पर नहीं चलता है। यह सर्वसम्मति से चलता है। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता था, लेकिन जब यह जिम्मेदारी मिली तो शिक्षित और बेहतर लोकतंत्र बनाने की जवाबदेही तो उठानी ही होगी।

● क्या आपका कोई ऐसा खट्टा अनुभव रहा जिसके कारण आपने आते ही सर्वसम्मति बनाने और सबको मौका देने का प्रयास शुरू किया?

-सांसद के रूप में भी मेरा कुछ अनुभव रहा था लेकिन बड़ा कारण यह है कि सार्वजनिक जीवन में भी मैं संवाद को बहुत महत्व देता रहा हूं।

● आपके काल में लोकसभा की कार्यवाही कभी बाधित नहीं हुई, लेकिन क्या शोर में, जब विपक्षी सांसद उग्र हों तो सदन चलाना उचित होता है?

-सदन सबका है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। विपक्ष कई मुद्दों पर आक्रोशित हो सकता है। इस बार भी था। मेरा मानना है कि आप अपनी बात रखो। विरोध करना है तो भी अपनी बात रखो। मेरे पास इसके लिए पर्याप्त समय है, लेकिन अगर बोलना भी नहीं है और केवल सदन स्थगित कराना है तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। यह देश के हित में नहीं है।

● जब भाजपा विपक्ष में थी और किसी मुद्दे पर वेल में थी तो भी तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने शोर शराबे के बीच सदन चलाने की कोशिश की थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी के तेवर उग्र हो गए थे और सोमनाथ को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी?

-राजनीतिक दलों का रुख कुछ भी हो सकता है। परिस्थितिजन्य कारणों से दबाव बनाने की कोशिश होती है, लेकिन अध्यक्ष के रूप में मेरा स्पष्ट मानना है कि कार्यवाही कभी स्थगित नहीं होनी चाहिए। किसी दबाव में देश का कामकाज नहीं रुकना चाहिए। किसी दल के प्रभाव में सांसदों के अधिकारों को बाधित नहीं करना चाहिए।

● आपने हाल में संसद के आधुनिकीकरण की बात कही थी। किस तरह का आधुनिकीकरण चाहते हैं?

अगर हम चाहते हैं कि सांसद अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त यहां दें तो हमें इसे उपयुक्त बनाना पड़ेगा। फिलहाल संसद में हमारे पास पर्याप्त स्थान नहीं है। देश-विदेश की कई संसद को देखकर हम यहां भी व्यवस्था कर सकते हैं। मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि जब स्वतंत्रता के 75 साल हो रहे हों तो हमें संसद के बारे में भी सोचना चाहिए।

● नए संसद भवन के लिए कोई खास स्थान?

-सभी के सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। सांसद, यहां काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी। कई और लोगों से बात हो रही है।

● आपने हिंदी का प्रयोग बढ़ाया। और किस-किस सुधार पर नजर है?

-सामान्य रूप से हिंदी देश की भाषा है। सदन में 22 भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था है। इसीलिए मैंने हिंदी को चुना। रही बात बदलाव और सुधार की तो मेरी कोशिश है कि सांसद जागरूक बनें, जानकार बनें और सकारात्मक भूमिका अदा करें। इसीलिए मैंने व्यवस्था को ऑनलाइन करना शुरू किया है। उन्हें सवालों के जवाब, शून्यकाल में बोलने के अवसर, पेश होने वाले विधेयक के बारे में ऑनलाइन पूरी जानकारी मिले ताकि उन्हें तैयारी करने का पूरा वक्त मिले। ऑनलाइन रिसर्च का पेपर होगा, एक्सपर्ट के नाम और फोन नंबर भी दे देंगे ताकि कोई सांसद विधेयक पर चर्चा करने आ रहा है तो पहले अपनी जानकारी पुख्ता कर ले। मेरा मकसद है कि सांसदों का ज्ञान बढ़े, उनकी दक्षता बढ़े और उनके जरिये देश का काम सही दिशा में हो। संसद को हर व्यक्ति के लिए मापदंड बनना चाहिए।

● क्या अलग-अलग विषय के लिए अलग-अलग एक्सपर्ट होंगे?

जी हां, और हर किसी के नाम और नंबर सांसदों को उपलब्ध होंगे। कोई विधेयक चर्चा के लिए आ रहा है तो पहले ही कांफ्रेंस हॉल में एक्सपर्ट के साथ चर्चा कर सकेंगे।

● आपने अनुशासन लाने की बहुत कोशिश की। वेल में आने पर तत्काल निलंबन को लेकर कोई विचार है?

-सभी परिवार के सदस्य हैं। इस तरह का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

● रास में प्रश्नकाल को शोर शराबे से बचाने के लिए शून्यकाल पहले कर दिया गया था। क्या लोकसभा में ऐसा करने का विचार है?

-अभी तक तो किसी सदस्य की ओर से ऐसा विचार नहीं आया है। मेरे मन में भी फिलहाल ऐसी सोच नहीं है।

हलफनामा दाखिल ▶ अयोध्या के कुछ मुसलमानों ने फैजाबाद की जिला अदालत से कहा

'अगर वहां कब्जा हिंदुओं को दिया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं'

पूजा का अधिकार मांगने वाले पक्षकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कुछ हलफनामों का दिया गया हवाला

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि में मंदिर तोड़ कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। 1934 में दंगा हुआ तब से मुसलमानों ने वहां नमाज पढ़नी बंद कर दी। हिंदू वहां पूजा करते थे। अगर वहां का कब्जा हिंदुओं को दे दिया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं। ये बातें अयोध्या में रहने वाले कुछ मुसलमानों ने 1950 में फैजाबाद की जिला अदालत में हलफनामा दाखिल कर कहीं थीं। गुरुवार को मामले के पक्षकार और रामलला के उपासक होने के आधार पर अबाधित पूजा-अर्चना का अधिकार मांगते हुए गोपाल सिंह विशारद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इन हलफनामों का हवाला दिया गया और कोर्ट से उन पर गौर करने की अपील की गई।

गुरुवार को दसवें दिन की सुनवाई में पक्षकार गोपाल सिंह विशारद की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजेंद्र सिंह की ओर से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें

दीं। कुमार ने 1949 में मूर्ति रखे जाने के विवाद के बाद जन्मभूमि को सरकार के कब्जे में ले लेने और वहां रिसीवर नियुक्त करने की धारा 145 के तहत हुई कार्रवाई का हवाला देते हुए बताया कि उस समय पब्लिक नोटिस निकला था। इसके जवाब में अयोध्या में रहने वाले 20 लोगों ने फैजाबाद की अदालत में हलफनामे दाखिल किये थे। हलफनामा देने वालों में कुछ मुसलमान भी थे। कुमार ने अब्दुल गनी के हलफनामे का अंश पढ़ा। इसमें कहा गया है कि अयोध्या राम जन्मभूमि में मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। 1934 में दंगा हुआ था। इसके बाद वहां नमाज बंद हो गई। कुमार ने हसन अली मुहम्मद के हलफनामे का भी अंश पढ़ा जिसमें कहा गया है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि है। गदर हुई थी जिसके बाद मुस्लिम यहां शुक्रवार को नमाज करते थे। हिंदू अंदर पूजा करते थे। 1934 के बाद मुस्लिम ने नमाज बंद कर दी। मुझे ऐतराज नहीं अगर सरकार इसे हिंदुओं को दे दे। रंजीत कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले और रिकार्ड में इनका जिक्र है लेकिन हाईकोर्ट ने हलफनामों को यह कह कर स्वीकार नहीं किया था कि जिनके हलफनामे हैं उनसे जिरह नहीं हो सकती। कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इन पर गौर करना चाहिए। इस पर पीठ के न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि यह ठीक है कि हलफनामे दाखिल किए गए लेकिन हलफनामे में जो बात कही गई है उसकी सत्यता जिरह पर नही परखी गई है इसीलिए हाईकोर्ट ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तब कुमार ने कहा कि पब्लिक नोटिस के जवाब में लोगों ने अदालत में ये हलफनामे दिए थे। भले ही हलफनामा देने वालों से जिरह न हुई हो लेकिन किसी ने उनका खंडन नहीं किया। ऐसे में कोर्ट सहयोगी साक्ष्य के तौर पर तो उन पर विचार कर ही सकती है।

पूजा-अर्चना का अधिकार जारी रहना चाहिए : कुमार ने कहा कि उनका मुवक्किल रामलला का उपासक है और वह मानता है कि जन्मस्थान के मालिक भगवान रामलला ही हैं। वह उपासक है और उसका पूजा का कानूनी अधिकार है जो जारी रहना चाहिए। कुमार ने 1856 से लेकर बाद तक के सरकारी दस्तावेजी रिकार्ड का हवाला देकर यह साबित करने की कोशिश की कि अयोध्या में वह स्थान राम जन्मभूमि है और वहां प्राचीन काल से हिंदू पूजा करते चले आ रहे हैं। वहां मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाई गई थी।

कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा से कहा-स्पष्ट करो नजरिया

निर्मोही अखाड़ा की ओर से गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में फिर से अपना पक्ष रखा गया लेकिन उसकी ओर से दी गई लिखित और मौखिक दलीलों में विपरीत नजरिया होने पर कोर्ट ने अखाड़ा की पैरवी कर रहे वकील सुशील जैन से कहा कि आप अपना नजरिया स्पष्ट करें। साफ बताएं कि आप जन्मस्थान को देवता और कानूनी व्यक्ति मानते हैं कि नहीं। इस पर निर्मोही अखाड़ा के वकील जैन ने कहा कि वह उन्हें कानूनी व्यक्ति मानने से इन्कार नहीं कर रहे। वह मालिकाना हक का दावा नहीं कर रहे सिर्फ पूजा प्रबंधन का अधिकार और कब्जा मांग रहे हैं। इस पर संविधान पीठ के सदस्य जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ ने कहा-लेकिन आपकी लिखित दलीलों में इससे उलट बात कही गई है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि आप स्थिति स्पष्ट कर कोर्ट को संतुष्ट करें तभी आगे अपील सुनी जाएगी।

मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से की पूछताछ

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- नौ घंटे तक चली मैराथन पूछताछ के बाद घर लौटे ठाकरे
- पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) नेता राज ठाकरे से मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ की। दक्षिण मुंबई में स्थित जांच एजेंसी के कार्यालय पर मनसे नेता 11:25 बजे पहुंचे और रात 8:15 पर वह वहां से रवाना हुए। करीब नौ घंटे तक पूछताछ के बाद बाहर निकले मनसे नेता ने किसी सवाल कर जवाब नहीं दिया। वह हाथ जोड़े अपनी कार तक पहुंचे और दादर इलाके में स्थित अपने घर रवाना हो गए।

कोहिनूर सीटीएनएल कंपनी को वित्तीय संस्था आइएलएंडएफएस द्वारा दिए गए कर्ज की जांच ईडी कर रहा है। इसी क्रम में कंपनी के भागीदार रहे राज ठाकरे को गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी अधिकारियों ने उनके लिए प्रश्नावली तैयार की थी। मामले में बयान दर्ज करने के बाद अधिकारियों ने राज को जाने दिया। ईडी अधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि उन्हें पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जा सकता है या नहीं।

परिवार के साथ पहुंचे थे मनसे नेता : ईडी कार्यालय पहुंचे राज के साथ उनकी पत्नी शर्मिला, पुत्र अमित और बहू मिताली भी थी। राज के कार्यालय में अकेले प्रवेश करने के बाद उनके परिवार के लोग बाहर समीप के होटल में रुक गए।

शांत रही मुंबई, कई जगह धारा 144 लागू : पूरे दिन के घटनाक्रम में मुंबई में शांति रही और कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। पुलिस ने ईडी कार्यालय और दादर और सेंट्रल मुंबई के

मनसे प्रमुख राज ठाकरे मनी लांड्रिंग के एक मामले में गुरुवार को मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। प्रेट्र

कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू कर रखा है। दादर, सेंट्रल मुंबई और अन्य स्थानों पर पुलिस तैनात है। समन मिलने के बाद मनसे कार्यकर्ता आंदोलित हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस ने करीब 200 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है।

राकांपा भी राज के समर्थन में उतरी : राज ठाकरे से पूछताछ को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) खुलकर राज के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता रह चुकीं अंजली दमानिया ने सपरिवार ईडी कार्यालय पहुंचने पर व्यंग्य किया। उन्होंने ट्वीट किया है, 'राज ठाकरे परिवार के साथ ईडी कार्यालय जा रहे हैं, या सत्यनारायण की कथा सुनने।'

रतुल पुरी ने मनी लांड्रिंग मामले में आत्मसमर्पण की अर्जी दी

नई दिल्ली : बैंक धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आत्मसर्मण करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में आवेदन दाखिल किया है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। बुधवार को अदालत ने पुरी के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में जारी गैर जमानती वारंट को रद करने से इन्कार कर दिया था।

राकांपा अध्यक्ष शरद पवार की पुत्री एवं सांसद सुप्रिया सुले ने अंजली का नाम लिए बिना जवाब में कहा है कि ईडी की जांच एक प्रकार का राजनीतिक दबाव है। जो भी कोई सरकार के विरुद्ध आवाज उठाता है, उसकी आवाज दबाने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। ऐसे में अपना परिवार ही साथ में खड़ा रहता है। किसी को प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं है। राकांपा के मुंबई अध्यक्ष नवाब मलिक एवं विधान परिषद में नेता विरोधी दल धनंजय मुंडे ने भी राज ठाकरे का पक्ष लेते हुए सरकार पर निशाना साधा है। राज ठाकरे के चचेरे भाई शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे एक दिन पहले ही क्लीन चिट देते हुए कह चुके हैं, कि ईडी की जांच में कुछ खास निकलकर नहीं आएगा।

नीरव की न्यायिक हिरासत 19 सितंबर तक बढ़ी

- भारत प्रत्यर्पण के लिए सुनवाई अगले साल मई में होने की संभावना
- ब्रिटिश अदालत ने कोर्ट क्लर्क को दी तारीखों की पुष्टि की हिदायत

लंदन, प्रेट्र : दो अरब डॉलर के पीएनबी घोटाले और मनी लांड्रिंग में आरोपित भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की ब्रिटेन की अदालत में गुरुवार को वीडियो लिंक के जरिए पेशी हुई। लंदन स्थित जेल में कैद मोदी की न्यायिक हिरासत 19 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए पांच दिन की सुनवाई अगले साल मई से शुरू होने के आसार हैं।

इस संक्षिप्त सुनवाई के दौरान 48 वर्षीय नीरव मोदी को वेस्टमिंस्टर कोर्ट के जज टैन इकराम ने बताया कि भारत प्रत्यर्पण मामले में उनकी सुनवाई की तारीखें अगली सुनवाई पर यानी आगामी 19 सितंबर को निर्धारित होंगी। इस दिन नीरव मोदी को फिर से अदालत में वीडियो लिंक के जरिए ही पेश किया जाएगा।

हालांकि पाकिस्तानी मूल के जज टैन (तनवीर) इकराम ने कहा कि मामले में आज कोई प्रगति नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने कोर्ट क्लर्क को नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए पांच दिन की सुनवाई की तारीखें 11 मई, 2020 से शुरू करने के लिए पुष्टि करने की हिदायतें दीं। ध्यान रहे के मामले के प्रबंधन को लेकर भी अगले साल फरवरी से सुनवाई होने की उम्मीद है। नीरव मोदी को लंदन के दक्षिण-पश्चिम स्थित वांड्सवर्थ जेल में विगत मार्च से रखा

नीरव मोदी की फाइल फोटो। एएनआइ

गया है। उन्हें यहां प्रत्यर्पण की सुनवाई पूरी होने तक रखा जाना है। विगत जुलाई में वेस्टमिंस्टर मेजिस्ट्रेट अदालत में सुनवाई के दौरान जज ने संकेत दिया था कि दोनों पक्षों की सहमति से पांच दिन की प्रत्यर्पण सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की जाएगी। ब्रिटिश कानून के तहत नीरव मोदी को अदालत के समक्ष 28 दिन के अंतराल पर पेश किया जाना है। गिरफ्तारी के बाद नीरव मोदी ने कई बार जमानत लेने की कोशिश की लेकिन उसकी याचिका हर बार भगोड़ा बताकर खारिज कर दी गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से यूएई के साथ संबंध होंगे और मजबूत

जेएनएन, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस से शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से यूएई के साथ भारत के संबंधों में और प्रगाढ़ता आने की उम्मीद है। 2017 में जब आबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को गति मिली थी और साइबरस्पेस, रक्षा, समुद्री और सड़क परिवहन व ऊर्जा के क्षेत्र में कई अहम समझौते हुए थे। आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी सऊदी की अरामको और भारत की सरकारी तेल कंपनियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र में 44 अरब डॉलर की रिफाइनरी भी लगाने जा रही है।

प्रधानमंत्री की तीन देशों की यह यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने के पाकिस्तान की कोशिशों को भी विफल करने में मदद मिलेगी। फ्रांस ने पहले ही कश्मीर को भारत-पाक के बीच द्विपक्षीय मुद्दा बताया है। वहीं यूएई ने अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को भारत का आंतरिक मामला बताया था।

चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत-फ्रांस संबंध अहम

जेएनएन, नई दिल्ली : हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत और फ्रांस के आपसी संबंध बहुत अहम हो गए हैं। पिछले साल मैक्रों की नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत-फ्रांस के बीच हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। हिंद महासागर में फ्रांस का सैनिक अड्डा भी है। इसके अलावा फ्रांस भारत का चौथा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीद का भी सौदा किया है। फ्रांस भारत को स्कॉर्पिन पनडुब्बी, मिराज विमान, मिसाइल इत्यादि भी दे चुका है।

पेरिस में हवाई अड्डे पर भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एएनआइ

मोदी के खिलाफ हमेशा दुष्प्रचार से नहीं बनेगी बात : जयराम रमेश

- कहा, मोदी ऐसी भाषा में बात करते हैं जो उन्हें लोगों से जोड़ती है
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने करोड़ों महिलाओं को मोदी से जोड़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन का मॉडल 'पूरी तरह नकारात्मक गाथा' नहीं है और उनके काम के महत्व को स्वीकार नहीं करना तथा हर समय उन्हें खलनायक की तरह पेश करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है।

रमेश ने कहा कि यह वक्त है कि हम नरेंद्र मोदी के काम और 2014 से 2019 के बीच उन्होंने जो किया उसके महत्व को समझें, जिसके कारण वह सत्ता में लौटें। उन्होंने राजनीतिक विश्लेषक कपिल सतीश कोमीरेड्डी की किताब 'मालेवॉलेंट रिपब्लिक : ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द न्यू इंडिया' का विमोचन करते हुए ये टिप्पणियां की।

कांग्रेस नेता ने कहा, 'वह (मोदी) ऐसी भाषा में बात करते हैं जो उन्हें लोगों से जोड़ती है। जब तक हम यह न मान लें कि वह ऐसे काम कर रहे हैं जिन्हें जनता सराह रही है और जो पहले नहीं किए गए, तब तक हम इस व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएंगे।' उन्होंने आगाह किया, 'साथ ही अगर आप हर समय उन्हें खलनायक की तरह पेश करने जा रहे हैं तो आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे।' रमेश ने स्पष्ट किया कि वह किसी से प्रधानमंत्री की सराहना या तारीफ करने के लिए नहीं कह रहे है बल्कि चाहते हैं कि राजनीतिक वर्ग कम से कम उन बातों को माने जो वह शासन में लेकर आए खासतौर से 'शासन के अर्थशास्त्र' के संदर्भ में। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा, 'मैं आपको बता दूं कि जब शासन के अर्थशास्त्र की बात आती है तो यह पूरी तरह नकारात्मक गाथा नहीं है, शासन की राजनीति पूरी तरह अलग है।' उन्होंने यह भी कहा कि उनके शासन मॉडल से जिस प्रकार के सामाजिक संबंध सृजित हुए हैं वे भी पूर्णतः भिन्न हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए रमेश ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूजे) का उदाहरण दिया कि वह कैसे प्रधानमंत्री के लिए सफल साबित हुई। कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य ने कहा, 'साल 2019 में राजनीतिक विमर्श में हम सभी ने उनकी एक या दो योजनाओं का मजाक उड़ाया लेकिन सभी चुनावी अध्ययनों में यह सामने आया कि पीएमयूजे अकेली ऐसी योजना रही जो उन्हें करोड़ों महिलाओं से जोड़ पाई। इसने उन्हें ऐसा राजनीतिक खिंचाव दिया जो उनके पास 2014 में नहीं था।' उन्होंने कहा कि पिछले दशक में ऐसा कुछ हुआ जिसने मोदी को 2009 के आम चुनाव में 'राष्ट्रीय राजनीति में एक मामूली नेता' से ऐसा व्यक्ति बना दिया जिसने लगातार चुनाव जीते।

दावा

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने विशेष अदालत में रखा पक्ष, 18 सितंबर को इस मामले में फिर होगी सुनवाई

एजेएल प्लॉट आवंटन में पूरी पारदर्शिता बरती : हुड्डा

- हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, फंसाने की कोशिश, राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया
- हुड्डा ने याचिका दायर कर डिस्चार्ज करने की मांग की

जागरण संवाददाता, पंचकूला

एजेएल (एसोसिएट जर्नल लिमिटेड) प्लाट आवंटन घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की विशेष अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने याचिका दायर कर डिस्चार्ज करने की मांग की। याचिका में उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। प्लॉट आवंटन नियमों के अनुसार हुआ। इसमें पूरी पारदर्शिता बरती गई। उन्होंने किसी को भी कोई लाभ नहीं पहुंचाया। कोर्ट ने नोटिस जारी कर सीबीआइ से इस पर जबाव मांगा है। सुनवाई के दौरान हुड्डा पेश हुए। अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।

उल्लेखीय है कि 24 अगस्त 1982 को पंचकूला सेक्टर छह में 3360 वर्गमीटर का प्लॉट नंबर सी -17 तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल ने एजेएल प्रकाशन समूह के हिंदी अखबार नवजीवन को अलॉट किया था। कंपनी को इस पर छह माह में निर्माण शुरू कर दो साल में काम पूरा करना था, लेकिन वह 10 साल में भी ऐसा नहीं कर पाई। इसके बाद 30 अक्टूबर 1992 को हुडा (अब एचएसवीपी) ने आवंटन रद कर प्लॉट वापस ले लिया। 14 मार्च 1998 को एजेएल की ओर

भूपेंद्र सिंह हुड्डा फाइल फोटो

से हुडा के चेयरमैन आबिद हुसैन ने प्लॉट आवंटन की बहाली के लिए अपील की। 14 मई 2005 को हुडा के चेयरमैन ने अफसरों को एजेएल कंपनी के प्लॉट आवंटन की बहाली की संभावनाएं तलाशने को कहा, लेकिन कानून विभाग ने इससे साफ इन्कार कर दिया। 18 अगस्त 1995 को नए आवंटन के लिए आवेदन मांगे गए। इसमें एजेएल कंपनी को भी आवेदन करने की छूट दी गई। 28 अगस्त 2005 को हुडा चेयरमैन ने एजेएल को ही 1982 की मूल दर पर प्लॉट अलॉट कर दिया। साथ ही कंपनी को छह माह में निर्माण शुरू करके एक साल में काम पूरा करने को भी कहा। एजेएल अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज अखबारों का प्रकाशक रहा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) की शिकायत पर राज्य सतर्कता विभाग ने मई 2016 को इस मामले में केस दर्ज किया। चूंकि मुख्यमंत्री हुडा के पदेन अध्यक्ष होते हैं और यह गड़बड़ी तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में हुई, इसलिए सतर्कता ब्यूरो ने 5 मई 2016 को उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। 5 अप्रैल 2017 को राज्य सरकार ने मामला सीबीआइ को सौंप दिया था। सीबीआइ ने हुड्डा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोती लाल वोरा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

मानेसर जमीन घोटाले में भी हुई सुनवाई : उधर, मानेसर जमीन घोटाले में गुरुवार को वकीलों की ओर से आरोप तय करने के लिए दलीलें रखी गईं। लगभग पांच घंटे तक इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान हुड्डा सहित अन्य आरोपित भी कोर्ट में पेश हुए। अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक कानून को चुनौती

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तीन तलाक कानून को चुनौती दी गई है। इसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। मुस्लिमों में एक बार में तीन तलाक को कानून बनाकर अवैध करार दिया गया है और ऐसा करने पर तीन साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। जमायत उलेमा-ए-हिंद ने इसके खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में तीन तलाक पर नए कानून मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है और कहा गया है कि यह कानून संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। इससे पहले केरल के एक सुन्नी मुस्लिम संगठन ने भी शीर्ष अदालत में इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की थी।

जमायत उलेमा ने कहा है कि चूंकि तीन तलाक को पहले ही 'शून्य व अवैध' घोषित कर दिया गया है, इसलिए इस पर कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन नया कानून बनाकर तीन तलाक को आपराधिक मामला बना दिया गया है, जो कानून की नजर में असंवैधानिक है। याचिका में तीन साल तक कैद की सजा को भी अनावश्यक बताया गया है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

न्यायमूर्ति सुनील ने ही दिया था नेशनल हेराल्ड पर आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को रद करने के साथ ही गंभीर टिप्पणी करने वाले न्यायमूर्ति सुनील गौर ने ही वर्ष 2018 में गांधी परिवार से जुड़े नेशनल हेराल्ड मामले में भी सख्त फैसला सुनाया था। गुरुवार को सेवानिवृत्त हुए 62 वर्षीय न्यायमूर्ति सुनील गौर ने ही वर्ष 2018 में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को आइटीओ स्थित नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया था। इस आदेश को हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने बरकरार रखा था। हालांकि, बाद में एजेएल की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। मामला अब भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

न्यायमूर्ति सुनील गौर ने हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति सुनील गौर को अस्थायी तौर पर वर्ष 2008 में निचली अदालत से दिल्ली हाई कोर्ट भेजा गया था। इसके बाद वह 11 अप्रैल 2012 को दिल्ली हाई कोर्ट में स्थायी न्यायमूर्ति के तौर पर नियुक्त हुए थे।

इंद्राणी के मुताबिक, चिदंबरम ने कार्ति के कारोबार में मदद करने को कहा था

नई दिल्ली, प्रेट्र : आइएनएक्स मीडिया में अनुमति से अधिक विदेशी निवेश को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी दिलाने के बदले तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने अपने बेटे कार्ति के कारोबार में मदद करने और विदेश में पैसा भेजने के लिए कहा था। मनी लांड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले की जांच के दौरान इंद्राणी मुखर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जांचकर्ताओं को यह जानकारी दी थी। वहीं, पीटर का कहना था कि उन्होंने दो या तीन बार सीनियर चिदंबरम से मुलाकात की थी। पीटर और इंद्राणी मुखर्जी ही आइएनएक्स मीडिया ग्रुप के प्रमोटर थे।

इंद्राणी मुखर्जी ने 2017 में ईडी को दिए अपने लिखित बयान में कहा था कि जब उन्हें पता चला कि एफआइपीबी मंजूरी आवेदन में कथित रूप से अनियमितताएं थीं तो पीटर ने इस मसले का समाधान करने के लिए चिदंबरम से मिलने का फैसला किया। इंद्राणी के मुताबिक, 'पीटर का कहना था कि कथित उल्लंघनों को कार्ति और पी. चिदंबरम की मदद से कानूनी बनाया जा सकता है और एफआइपीबी से जुड़े इन मामलों के समाधान में उनकी सलाह ली जा सकती है। 2008 में उसने अपने पति पीटर मुखर्जी के साथ पी. चिदंबरम से उनके नॉर्थ ब्लॉक स्थित कार्यालय में मुलाकात की थी। पीटर ने आइएनएक्स मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) लाने के लिए आवेदन का जिक्र करते हुए पी. चिदंबरम से बातचीत शुरू की थी और आवेदन की एक प्रति उन्हें सौंपी थी। मामला समझने के बाद चिदंबरम ने पीटर से अपने बेटे कार्ति की उसके कारोबार में मदद करने को कहा था। इसके बाद दोनों ने दिल्ली के एक होटल में कार्ति से मुलाकात की थी। कार्ति इस मसले के बारे में जानता था और उसने मामले के समाधान के लिए उसके या उसके सहयोगियों के विदेशी खातों में 10 लाख अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर करने के लिए कहा।

ईडी को बताया था, एफआइपीबी मंजूरी दिलाने के बदले की थी मांग

जब पीटर ने कहा कि विदेशी खातों में रकम ट्रांसफर करना संभव नहीं हो पाएगा तो कार्ति ने विकल्प के तौर पर दो कंपनियों चेस मैनेजमेंट और एडवांटेज स्ट्रैटेजिक के नाम सुझाए और उनके खातों में रकम जमा करने को कहा। साथ ही उसने कहा था कि दोनों कंपनियां आइएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को कंसल्टेंट के रूप में दर्शाई जाएंगी।' इंद्राणी का आगे कहना था, 'भुगतान के मामले पीटर देखते थे और उसे नहीं पता कि सीनियर चिदंबरम के बेटे के हित के लिए कितनी रकम का भुगतान किया गया। आइएनएक्स ग्रुप के निदेशक (लीगल एंड रेगुलेटरी अफेयर्स) ने एफआइपीबी से जुड़े मामले में कार्ति की कंपनी चेस मैनेजमेंट से बात की थी और उसकी जानकारी के मुताबिक कार्ति से जुड़ी दूसरी कंपनी एडवांटेज स्ट्रैटेजिक ने आइएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को कभी सेवाएं नहीं दीं।' ईडी को जांच के दौरान पता चला कि आइएनएक्स मीडिया ने 2008 में एडवांटेज स्ट्रैटेजिक को चेक के जरिये 9.96 लाख रुपये का भुगतान किया था। पीटर मुखर्जी ने अपने बयान में ईडी जांचकर्ताओं को बताया था कि एडवांटेज स्ट्रैटेजिक को किया गया यह भुगतान कार्ति द्वारा 10 लाख अमेरिकी डॉलर की मांग का हिस्सा था। पीटर का कहना था कि उनके आवेदन में रुकावट या देरी न हो इसलिए वह पी. चिदंबरम से मिलते रहते थे और चिदंबरम अपने बेटे के कारोबारी हित का ध्यान में रखने की बात कहते थे और मौका मिलने पर विदेश में भुगतान करने को कहते थे।

पीटर या इंद्राणी से कभी नहीं मिला : कार्ति

नई दिल्ली, प्रेट्र : आइएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने साफ कहा है कि पीटर या इंद्राणी मुखर्जी से उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई है। पीटर और इंद्राणी मुखर्जी आइएनएक्स मीडिया के प्रमोटर हैं। कार्ति चिदंबरम भी इस मामले में आरोपित हैं।

चेन्नई से गुरुवार सुबह दिल्ली पहुंचे कार्ति ने कहा कि उनके पिता को ही नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी निशाना बनाया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन करने वह जंतर मंतर जाएंगे।

कार्ति ने कहा कि उनके पिता को सीबीआइ के सामने पेश होने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। उन्होंने इन आरोपों को भी गलत बताया कि उनके पिता जांच एजेंसियों से छिप रहे थे। कार्ति ने कहा कि लाख कोशिशों के बावजूद सीबीआइ उनके पिता के खिलाफ कोई केस नहीं बना पाई। उनके पिता इस सरकार के प्रबल आलोचक थे, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

कार्ति ने कहा कि वह न तो पीटर और इंद्राणी मुखर्जी को जानते हैं और न ही उनसे कभी मिले हैं। उन्होंने कहा कि इंद्राणी मुखर्जी से उनकी सिर्फ एक बार मुलाकात हुई है और वह भी भायखला जेल में सीबीआइ पूछताछ के दौरान। उन्होंने कहा कि वह विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) में भी किसी को नहीं जानते और न ही उन्हें एफआइपीबी की प्रक्रिया ही पता है।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में भाग लेते कार्ति चिदंबरम। जागरण

समाचार एजेंसी आइएएनएस के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी ने 17 फरवरी, 2018 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में दर्ज कराए बयान में दावा किया था कि जब वो (इंद्राणी एवं पीटर मुखर्जी) दिल्ली के हयात होटल में कार्ति चिदंबरम से मिले थे, तब उन्होंने उनसे 10 लाख डॉलर (सात करोड़ रुपये) घूस मांगी थी।

370 से ध्यान भटकाने की चाल : समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक दिल्ली रवाना होने से पहले चेन्नई में कार्ति चिदंबरम ने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सरकार यह सब कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें 20 बार बुलाया गया। सीबीआइ ने उनसे घंटों तक पूछताछ की। वह सीबीआइ की हिरासत में 11 दिनों तक रहे थे, लेकिन कोई केस नहीं बना। मामले की जांच कर रहे अधिकारी भी जानते हैं कि हमारे खिलाफ कोई केस नहीं बन रहा है। किसी अधिकारी में यह कहने की हिम्मत नहीं है।

बहुमत की ताकत के सहारे देश में डर का माहौल

बोलीं सोनिया ▶ राजीव गांधी ने कभी भी डराने-धमकाने के लिए नहीं किया बहुमत का इस्तेमाल

चिदंबरम की गिरफ्तारी के मामले में भी परोक्ष रूप से सरकार को घेरा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बहुमत की ताकत के सहारे देश में डर का माहौल बनाने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राजीव गांधी को मिले रिकॉर्ड बहुमत का हवाला देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राजीव ने कभी बहुमत की ताकत का इस्तेमाल डराने-धमकाने के लिए नहीं किया।

कांग्रेस नेता व पूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर जारी राजनीतिक घमासान के बीच सोनिया गांधी ने सीधे इसका जिक्र तो नहीं किया मगर सत्ता की ताकत के सहारे असहमति के सुर दबाने की बात कह इस ओर इशारा जरूर किया। राजीव गांधी के 75वें जयंती वर्ष पर आयोजित पार्टी के विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने यह बात की। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर दोबारा पार्टी की कमान संभालने के बाद यह उनका पहला संबोधन था। इसमें उन्होंने मौजूदा सरकार को बहुमत का अनुचित इस्तेमाल करने को लेकर घेरा। सोनिया ने कहा, 'राजीव गांधी 1984 में बेमिसाल बहुमत से जीतकर आए थे। उन्होंने उस ताकत का इस्तेमाल डराने-धमकाने के लिए नहीं किया। संस्थानों की स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए नहीं किया। असहमति और विरोध के स्वर को कुचलने के लिए नहीं किया। लोकतांत्रिक परंपरा और जीवन शैली के लिए खतरा पैदा करने के लिए नहीं किया।'

कांग्रेस और राजीव की लोकतंत्र के मूल्यों में गहरी आस्था का उदाहरण देने के लिए सोनिया ने सत्ता छोड़ने के राजीव के फैसले का भी उदाहरण दिया। सोनिया ने कहा, '1989 में कांग्रेस दोबारा अकेले पूरे बहुमत से जीतकर नहीं आ पाई। तब राजीव ने गरिमा और विनम्रता के साथ जनादेश को स्वीकार किया। कांग्रेस के सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के बावजूद सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके नैतिक बल, उदारता और उनकी ईमानदारी ने ऐसा करने नहीं दिया। ऐसा आज कोई नहीं कर सकता।' फिर कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल इसमें संशोधन करते हुए कहा कि राहुल ने भी ऐसा किया। उनका इशारा यूपीए सरकार के समय राहुल गांधी के मंत्री से लेकर पीएम बनने तक के प्रस्ताव को ठुकराने की ओर था।

नई दिल्ली में गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती समारोह के दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद रहे। प्रेट्र

कार्यकर्ताओं को दिया संदेश : सोनिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार होने का संदेश देते हुए कहा कि चुनावी हार-जीत होती रहती है। कांग्रेस के सामने आज बहुत बड़ी चुनौती है कि वह विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ अपनी वैचारिक लड़ाई मजबूती से जारी रखे। ये ताकतें आज समाज का स्वरूप ही नहीं भारत की बुनियादी आत्मा, जिसकी आधारशिला हमारे संविधान ने रखी है, उसे बदलने पर उतारू हैं।

भविष्य पर रहती थी राजीव की निगाह : सोनिया गांधी ने अतीत पर सत्तापक्ष के हमले पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां कुछ लोग अतीत को खोदने में जुटे हैं, वहीं राजीव देश का भविष्य बनाने की दृष्टि तय करने में लगे थे। राजीव को अपने इतिहास पर गर्व था, मगर उनकी दृष्टि साफ थी कि भारत को एक आधुनिक देश बनना है। यहां वैज्ञानिक दृष्टि की जरूरत है न कि विभाजनकारी सोच की। यहां पूर्वाग्रह, सामाजिक विभेद और ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस को एकजुट होकर ऐसी ताकतों का मुकाबला करना होगा जो उन मूल्यों को नष्ट कर रही हैं जिनमें राजीव की आस्था थी। यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

गिनाईं राजीव की उपलब्धियां : सोनिया गांधी ने इस दौरान प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी के पांच साल के अहम कामों का भी जिक्र किया जिसने नए और आधुनिक भारत की नींव रखी।

पंजाब के विधायक राजा ने कहा– देश व पार्टी की जरूरत हैं राहुल

कार्यक्रम के दौरान पंजाब विधायक और युवा कांग्रेस के पूर्व प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा ने भावुक अपील की। उन्होंने कहा, 'राहुल को यह संभवत: अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी को राहुल की जरूरत है और देश को राहुल की जरूरत है।' विधायक की इस बात पर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह समेत कार्यक्रम में उपस्थित हर किसी ने ताली बजाकर समर्थन किया।

शिअद ने साधा सोनिया गांधी पर निशाना

सोनिया गांधी द्वारा राजीव गांधी की तारीफ पर शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने निशाना साधा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में सिखों की हत्या करने और आतंक फैलाने वालों को पुरस्कृत किया गया था। सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और अन्य आरोपित कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

कांग्रेस ने गिरफ्तारी को बताया दिनदहाड़े लोकतंत्र की हत्या

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- बिना एफआइआर हत्या अभियुक्त के बयान के आधार पर गिरफ्तारी पर उठाए सवाल
- कहा, सरकार ने ईडी और सीबीआइ को बनाया व्यक्तिगत बदला लेने वाली एजेंसी

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने आक्रोश जताते हुए कहा है कि यह दिनदहाड़े लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिस आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। पूरी कार्रवाई बदले की भावना और मौजूदा हालात से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए की गई है।

सुरजेवाला ने गुरुवार को कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा में सरकार पर चिदंबरम की गिरफ्तारी को लेकर और भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने ईडी और सीबीआइ को व्यक्तिगत बदला लेने वाली एजेंसी में तब्दील कर दिया है। देश के पूर्व वित्त और गृह मंत्री को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उससे यह साफ हो गया है कि बदला लेने के लिए मोदी सरकार किसी भी हद तक गिर सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार मंदी, बेरोजगारी जैसे कई मोर्चों पर स्थिति से निपटने में नाकामयाब साबित हो रही है। ऐसे में मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पिछले दो दिनों से यह ड्रामा कर रही है। चिदंबरम की गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी तब की गई है, जब उनके ऊपर और न ही उनके बेटे के ऊपर आइएनएक्स मीडिया केस में कोई एफआइआर दर्ज है। साथ ही उनके खिलाफ इससे जुड़े कोई सुबूत भी नहीं मिले हैं, जबकि संबंधित एजेंसियां कई बार कार्ति चिदंबरम और पी. चिदंबरम के आवास पर छापा मार चुकी हैं और पूछताछ भी कर चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने 12 साल पुराने मामले की जांच के औचित्य पर भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि इनमें पांच साल पिछली मोदी सरकार के भी हैं। इस दौरान उन्होंने न ही विदेशी निवेश की अनुमति देने वाले अधिकारियों को कभी पकड़ा और न ही जिस कंपनी में यह निवेश हुआ उन्हें भी कभी पकड़ा गया। चिदंबरम को गिरफ्तार करने के न तो आधार हैं और न ही सुबूत। सिर्फ एक ऐसी महिला के बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई है जो पहले से ही एक अपराधी है और जेल में बंद है।

रणदीप सुरजेवाला फाइल फोटो

ईडी भी चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ की तैयारी में

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सीबीआइ की रिमांड पर भेजे गए पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के लिए कानून के शिकंजे से बचना अब आसान नहीं होगा। सीबीआइ की हिरासत खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी उन्हें मनी लांड्रिंग मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ करने की तैयारी में जुट गया है। वैसे ईडी को अभी चिदंबरम को हिरासत में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार करना होगा। चिदंबरम ने अग्रिम जमानत खारिज किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर शुक्रवार को जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ सुनवाई करेगी।

दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी और सीबीआइ दोनों के मामलों में पी. चिदंबरम को मिली अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। दोनों ही मामलों में चिदंबरम ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब चूंकि सीबीआइ ने चिदंबरम को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया और उसे चार दिन की रिमांड भी मिल गई है, इसीलिए सीबीआइ की गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका औचित्यहीन हो गई है। इस मामले में अब चिदंबरम को नए सिरे से नियमित जमानत की अर्जी लगानी होगी।

वहीं, ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। ईडी अधिकारियों को उम्मीद है कि अग्रिम जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी और चिदंबरम से घोटाले में पूछताछ की जरूरत बताने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को राहत नहीं मिलेगी। लेकिन ईडी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है, इसके लिए आइएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले और उसकी जांच पर वकीलों को ब्रीफ किया जा रहा है। वकीलों को चिदंबरम के खिलाफ पुख्ता दस्तावेजी सुबूत भी दिए गए हैं ताकि वे सुप्रीम कोर्ट के सामने हिरासत में पूछताछ की जरूरत को प्रभावी तरीके से रख सकें। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज हो जाने और सीबीआइ की पूछताछ हो जाने के बाद अदालत से चिदंबरम को ईडी की हिरासत में देने की मांग की जाएगी।

इन सुबूतों को कैसे झुठला पाएंगे पूर्व वित्त मंत्री

नीलू रंजन, नई दिल्ली

चिदंबरम भले ही अपने खिलाफ कोई सुबूत नहीं होने का दावा कर रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि आइएनएक्स मीडिया मामले में ठोस सुबूत मिलने के बाद ही सीबीआइ ने एफआइआर दर्ज की थी। ईडी ने सारे सुबूतों के साथ ही सीबीआइ को एफआइआर करने की सिफारिश की थी। इनमें चेक से कार्ति चिदंबरम से जुड़ी कंपनी एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसलटेंसी को किया गया भुगतान भी शामिल है। इस भुगतान में साफ-साफ एफआइपीबी के लिए बताया गया है। यही नहीं, आइएनएक्स मीडिया के वित्त विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों ने अपने बयान में इसकी पुष्टि भी की है।

'दैनिक जागरण' के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार, ईडी ने 16 दिसंबर, 2016 को सीबीआइ को भेजे पत्र में बताया था कि आइएनएक्स मीडिया को एफआइपीबी क्लीयरेंस देने के मामले में कार्ति चिदंबरम द्वारा बनाई गई और उन्हीं की स्वामित्व वाली कंपनी चेस मैनेजमेंट सर्विसेज के माध्यम से रिश्वत ली गई थी। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले और एयरसेल मैक्सिस केस के जांच अधिकारी राजेश्वर सिंह की ओर से भेजे गए पत्र में बताया गया है कि चेस मैनेजमेंट सर्विसेज के निर्देश पर एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसलटेंसी को नौ लाख 96 हजार 296 रुपये का चेक दिया था। 002914 नंबर का यह चेक 15 जुलाई, 2008 को जारी किया गया था। यह वही वक्त है जब आइएनएक्स मीडिया के एफआइपीबी क्लीयरेंस का मामला लटका हुआ था और पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी ने पी. चिदंबरम से वित्त मंत्रालय के उनके दफ्तर में मिलकर मदद की गुहार लगाई थी। बाद में इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी दोनों ने अपने बयान में बताया कि पी. चिदंबरम ने इसके एवज में कार्ति चिदंबरम को बिजनेस में मदद करने को कहा था। आइएनएक्स मीडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ ने ईडी को दिए लिखित बयान में बताया कि यह चेक एफआइपीबी की कंसलटेंसी के लिए दिया गया था।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह कहना गलत है कि सिर्फ हत्या की अभियुक्त इंद्राणी मुखर्जी की गवाही के आधार पर चिदंबरम के खिलाफ शिकंजा कसा गया है। हकीकत यह है कि पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के खिलाफ पहले से ही काफी ठोस सुबूत मौजूद हैं। आइएनएक्स मीडिया को चेस मैनेजमेंट सर्विसेज के निर्देश पर विभिन्न कंपनियों की ओर से भेजे चार इनवॉयस भी मिले हैं। इसमें जो इनवॉयस विदेश स्थित कंपनियों के हैं उनमें डॉलर में पेमेंट की मांग की गई है। इनमें ग्रीस के एथेंस में पंजीकृत गेबेन ट्रेडिंग की ओर 26 सितंबर, 2008 को पांच लाख डॉलर का इनवॉयस भेजा गया था। जबकि सिंगापुर में पंजीकृत एडवांटेज स्ट्रैटिजिक कंसलटेंसी की ओर से 24 सितंबर, 2008 को 20 हजार डॉलर का इनवॉयस भेजा गया था। ध्यान देने की बात है कि भारत में पंजीकृत एडवांटेज स्ट्रैटिजिक कंसलटेंसी की ओर से भी आइएनएक्स मीडिया को 22 सितंबर, 2008 को 35 लाख रुपये का इनवॉयस भेज दिया गया था। जबकि नॉर्थस्टार सॉफ्टवेयर की ओर से 26 सितंबर, 2008 को 60 लाख रुपये का इनवॉयस भेजा गया था।

वैसे इन चारों इनवॉयस का पेमेंट आइएनएक्स मीडिया के खाते से नहीं किया गया। उसके सीएफओ ने ईडी को बताया कि यदि कहीं और से इनका भुगतान किया गया हो तो उन्हें इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन इन इनवॉयस के एवज में पेमेंट करने के लिए चेस मैनेजमेंट सर्विसेज की ओर से आइएनएक्स मीडिया को ईमेल भेजे गए थे। ईडी के पास ये ईमेल मौजूद हैं।

राउज एवेन्यू कोर्ट से चार दिन की रिमांड पर पी चिदंबरम को ले जाती सीबीआइ की टीम। संजय

भ्रष्टाचार के लिए एकजुट हो गई है कांग्रेस : भाजपा

नई दिल्ली, प्रेट्र : आइएनएक्स मनी लांड्रिंग मामले को 'विशाल भ्रष्टाचार घोटाला' करार देते हुए भाजपा ने पी चिदंबरम का समर्थन करने के लिए कांग्रेस पर हमला किया। पार्टी ने कहा कि भ्रष्टाचार के संरक्षण में कांग्रेस एकजुट हो गई है और सीबीआइ की हिरासत में पूर्व केंद्रीय मंत्री को सौंपा जाना 'प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार का मामला' दर्शाता है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कांग्रेस ने पूर्व मंत्री के खिलाफ कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध कहा है। असल में न्याय हो रहा है। सीबीआइ कोर्ट का उन्हें हिरासत में भेजने के फैसले से स्पष्ट है कि यह भ्रष्टाचार का मामला है। यह प्रथम दृष्टया मामला है। कांग्रेस का राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप गलत है।

जावडेकर ने राहुल और प्रियंका सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की चिदंबरम का बचाव करने के लिए आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एकजुट है। वह भ्रष्टाचार का पर्यायवाची है। जब वह सत्ता में रही तो देश को लूटा।

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्षी पार्टी और उसके नेता भ्रष्टाचार को क्रांति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस नकारात्मक विचार से काम कर रही है। यह पहला मौका है जब भ्रष्टाचार को क्रांति बनाया जा रहा है।

बदले हालात

जिस इमारत के उद्घाटन में रहे थे शामिल, वहीं हुए कैद

चिदंबरम आठ साल पहले बतौर गृह मंत्री सीबीआइ मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में हुए थे शामिल, अब उसी के गेस्ट हाउस में उन्हें रखा गया है

नई दिल्ली, एएनआइ : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पलानीअप्पन चिदंबरम आठ साल पहले जिस सीबीआइ मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में बतौर केंद्रीय गृह मंत्री प्रमुख मेहमान थे, बुधवार की रात से वह उसी मुख्यालय के गेस्ट हाउस में कैद हैं।

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आइएनएक्स मीडिया से संबंधित मामले में एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद बुधवार रात को गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआइ के अफसर पूर्व वित्त मंत्री को दिल्ली के जोरबाग स्थित उनके आवास से सीबीआइ मुख्यालय ले गये। 30 जून, 2011 को दिल्ली के लोधी रोड स्थित सीबीआइ के इसी मुख्यालय के उद्घाटन में पी. चिदंबरम शामिल हुए थे। उस वक्त वह केंद्रीय गृह मंत्री थे। तब सीबीआइ मुख्यालय की नई इमारत का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। इस समारोह में चिदंबरम के साथ तत्कालीन कानून मंत्री वीरप्पा मोइली, मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। तब के सीबीआइ निदेशक एपी सिंह ने चिदंबरम समेत इन नेताओं को इमारत का भ्रमण कराया था और इस दौरान उन्हें वह गेस्ट हाउस भी दिखाया गया था, जिसमें अब चिदंबरम कैद हैं। कांक्रीट और कांच से बनी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस इमारत के उद्घाटन से पहले दशकों तक देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीजीओ कांप्लेक्स के संकरे चैंबरों में काम करती थी।

सीबीआइ मुख्यालय पर मंडराता वास्तु दोष : सीबीआइ के कुछ अफसरों का कहना है कि सीबीआइ मुख्यालय का वास्तु ठीक नहीं है। उनका मानना है कि इस इमारत को एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है। लिहाजा, इस सीबीआइ मुख्यालय के उद्घाटन के समय से ही सभी सीबीआइ निदेशकों को किसी न किसी विवाद का सामना करना पड़ा है। एपी सिंह के बाद सीबीआइ प्रमुख बने रंजीत सिन्हा के खिलाफ तो मामला ही दर्ज हो गया था। जबकि अनिल सिन्हा को उद्योगपति विजय माल्याके भारत से फरार होने को लेकर कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। जबकि आलोक वर्मा की अपने जूनियर से खटपट इतनी बढ़ गई थी उन्हें जांच एजेंसी से ही हटा दिया गया था।

कई दिग्गज नेता जा चुके हैं जेल : पी. चिदंबरम से पहले कई हाईप्रोफाइल नेताओं को सीबीआइ गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। करोड़ों के चारा घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रांची की बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे हैं।

दिवंगत अन्नाद्रमुक नेता जे.जयललिता को भी सुब्रह्मण्यम स्वामी की शिकायत पर सीबीआइ ने वर्ष 1996 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जयललिता पर वर्ष 1991-1996 के बीच तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहते हुए बेहिसाब संपत्ति बनाने का आरोप था। इसके बाद सितंबर, 2014 में बेहिसाब संपत्ति मामले में दोषी पाए जाने पर उन्हें और उनकी सहयोगी शशिकला समेत तीन लोगों को दोषी ठहराया गया था। उन्हें चार साल की जेल और सौ करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

नई दिल्ली में 30 अप्रैल, 2011 को सीबीआइ के नए मुख्यालय भवन के उद्घाटन समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम। प्रेट्र

विशेष अदालत में बहस के बाद मुश्किल था फैसले का इंतजार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में पेश करने से लेकर रिमांड पर भेजे जाने की प्रक्रिया काफी लंबी चली। चिदंबरम को तीन बजकर 15 मिनट पर अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद पांच बजे तक बहस चली। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कटघरे में खड़े चिदंबरम को कुर्सी पर बैठने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया और पूरी बहस के दौरान खड़े ही रहे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आधे घंटे के लिए फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन यह इंतजार लंबा हो गया। शाम साढ़े छह बजे अदालत ने रिमांड का आदेश सुनाया तो चिदंबरम तनाव में आ गए। उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी।

बहस पूरी होने के बाद चिदंबरम की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी अदालत से बाहर चले गए। करीब 25 मिनट बाद सिब्बल लौट आए, लेकिन सिंघवी जा चुके थे। इस दौरान चिदंबरम आराम से कुर्सी पर बैठे थे और बीच-बीच में अपने अधिवक्ताओं से बात कर रहे थे। छह बजकर 25 मिनट पर जब कोर्ट स्टाफ ने न्यायाधीश के आने की सूचना दी तो चिदंबरम फिर से कटघरे में आ गए। स्टाफ ने कुछ दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर लिए। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने रिमांड का आदेश सुनाया। इसके बाद चिदंबरम ने किसी से कोई बात नहीं की। सीबीआइ ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया और काफी मशक्कत के बाद कोर्ट से बाहर ले गई। बीच रास्ते चिदंबरम के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान दिखी और उन्होंने हाथ भी हवा में उठाया, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोला।

बहस के दौरान कार्ति चिदंबरम कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे। बीच-बीच में हंस रहे थे। उन्होंने ट्वीट कर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों की तारीफ की। कार्ति ने कहा कि दोनों अधिवक्ताओं ने काफी सटीक दलीलें दीं।

24 अगस्त को श्रीनगर सेंटर में होने वाले एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट को स्थगित कर दिया गया है। इसकी नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी। हालांकि जम्मू और लेह में बने परीक्षा केंद्र में पहले से जारी अधिसूचना के तहत ही परीक्षा होगी।

कश्मीर में स्कूल से लेकर सड़क तक सब शांत

सुधरे हालात ▶ प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में हाजिरी बढ़ी, सरकारी कार्यालयों और बैंकों में भी कामकाज सुचारू

सड़कों पर नजर आने वाली कंटीली तारें व अवरोधकों की तादाद घट गई है

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर घाटी में गुरुवार को प्रशासनिक पाबंदियों में राहत का असर सामान्य जनजीवन पर साफ नजर आया। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में हाजिरी भी बीते दिनों से बेहतर रही। सरकारी कार्यालयों और बैंकों में कामकाज गति पकड़ता दिखा। विभिन्न जगहों पर ठेलों पर रोजमर्रा का सामान खरीदते लोगों की चहल-पहल और वाहनों की आवाजाही बढ़ने के साथ कई जगहों पर दुकानें भी खुलीं। दिन में सुरक्षाबलों की मौजूदगी भी अब सिर्फ संवेदनशील इलाकों और प्रमुख चौराहों तक सिमटती जा रही है। अधिकांश सड़कों पर नजर आने वाली कंटीली तारें व अवरोधकों की तादाद में कमी आई है।

श्रीनगर में गुरुवार को पाबंदियों में ढील के दौरान गंतव्य को जाती महिलाएं। प्रेट्र

स्कूलों में बढ़ी उपस्थिति : स्कूल शिक्षा निदेशक मोहम्मद यूनिस मलिक ने बताया कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति अब बढ़ने लगी है। दक्षिण कश्मीर के मिडिल स्कूलों में गुरुवार को बीते रोज की तुलना में पांच से छह गुणा ज्यादा हाजिरी रही। उत्तरी कश्मीर में विशेषकर बारामुला, कुपवाड़ा और बांडीपोरा में एलओसी के साथ सटे इलाकों के स्कूलों में 50 फीसद से ज्यादा हाजिरी रही। श्रीनगर और बड़गाम में भी छात्रों की संख्या बेहतर रही है। अधिकांश निजी स्कूल बंद हैं, लेकिन कुछेक गुरुवार को खुले और उनमें सामान्य अकादमिक गतिविधियों के बहाल होने की सूचना है।

सरकारी दफ्तरों में कामकाज हुआ सामान्य : मंडलायुक्त बसीर अहमद खान के अनुसार, वादी में लगभग हर जिले में प्रशासनिक कामकाज सामान्य हो चला है। जिला उपायुक्त कार्यालयों में गुरुवार को कर्मचारियों की उपस्थिति 90 फीसद के करीब रही। नागरिक सचिवालय में 98 फीसद कर्मचारियों व अधिकारियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। सभी आवश्यक सेवाएं बहाल हैं। बिजली-पानी की आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से काम कर रही हैं। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान भी हर जिले और कस्बे में खुले हैं।

श्रीनगर के सिविल लाइंस इलाकों में ही नहीं वादी के अन्य कस्बों और शहरों में भी धीरे-धीरे दुकानें खुलने लगी हैं। पहले सिर्फ सुबह नौ बजे तक तीन घंटे के लिए ही दुकानें खुल रही थीं या फिर शाम को पांच बजे से करीब सात बजे तक, लेकिन अब कई इलाकों में दोपहर को भी दुकानें खुल रही हैं। पेट्रोल पंप भी शाम को खुले नजर आने लगे हैं।

कुछ जगह पथराव की सूचना : राष्ट्रविरोधी तत्वों ने वीरवार को श्रीनगर के बटमालू व डाउन-टाउन के कुछ हिस्सों के अलावा उत्तरी कश्मीर के कुछ हिस्सों में पथराव किया। पुलिस ने तुरंत इन तत्वों को खदेड़ दिया। कई जगह शरारती तत्वों ने खुली दुकानों को बंद कराने के लिए दुकानदारों को भी धमकाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक शरारती तत्व वहां से भाग निकले थे।

50 पुलिस थाना क्षेत्रों में दिन की पाबंदियां हटाईं : स्थिति में सुधार को देखते हुए प्रशासन ने वादी में 50 पुलिस थाना क्षेत्रों में घोषित तौर पर दिन की पाबंदियों को हटा लिया है। अन्य थानों के कार्याधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि वह पाबंदियों को सख्ती से अमल में नहीं लाएं। डीआइजी सेंट्रल कश्मीर रेंज बीके विरदी ने कहा कि कुछ इलाकों में छिटपुट पथराव की घटनाएं हुई हैं, लेकिन स्थिति पर जल्द ही काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि हालात की समीक्षा करते हुए प्रशासनिक पाबंदियों में राहत का दायरा बढ़ाया जा रहा है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

टेलीफोन सेवा नहीं हो रही बहाल: प्रशासन के दावों के बावजूद वादी में अधिकांश लैंडलाइन फोन ठप पड़े हैं। जवाहर नगर, राजबाग, एयरपोर्ट के आस-पास ही कुछ लोगों के लैंडलाइन फोन बहाल हो पाए हैं। इसके अलावा सभी प्रमुख सरकारी कार्यालयों के लैंडलाइन फोन बहाल हैं। अन्य सभी ठप हैं। इंदिरानगर और उसके साथ सटे इलाकों में पहले दिन ही लैंडलाइन फोन बहाल हुए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद यह अचानक बंद हो गए। लालचौक और उसके साथ सटे इलाकों में भी लैंडलाइन सेवा बेहाल है। राज्यपाल के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने बताया कि कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण ऐसा हुआ है। बीएसएनएल इन दिक्कतों को दूर कर रहा है। जल्द ही सभी लैंडलाइन फोन बहाल हो जाएंगे।

फारूक खान ने श्रीनगर में स्कूलों का निरीक्षण किया

राज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने गुरुवार को श्रीनगर जिले के कई सरकारी कार्यालयों और शैक्षिक संस्थानों का दौरा किया। उन्होंने स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी पर संतोष जताया और कहा कि जो भी गैरहाजिर हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मिडिल स्कूल कोठीबाग, मिडिल स्कूल राजबाग में उन्होंने शिक्षकों और प्रिंसिपलों को स्कूलों में शत-प्रतिशत हाजिरी सुनिश्चित बनाने के लिए भी कहा। उनके साथ डायरेक्टर स्कूल एजूकेशन कश्मीर मोहम्मद यूनिस मलिक और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले सलाहकार ने हार्टिकल्चर, प्लानिंग और मार्केटिंग निदेशालय का निरीक्षण भी किया।

जम्मू-कश्मीर से सुरक्षा बलों को हटाने की तत्काल कोई योजना नहीं : केंद्र

हैदराबाद, प्रेट्र : केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर से सुरक्षा बलों को हटाने की केंद्र सरकार की तत्काल कोई योजना नहीं है। हम वहां से फिलहाल सुरक्षा बलों को वापस क्यों बुलाएंगे, जब पाकिस्तान हमें उकसाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान कश्मीरियों को उकसा कर वहां की शांति बाधित चाहता है, ताकि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे को उठा सके। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को वापस बुलाया जाए अथवा नहीं, यह फैसला वहां का स्थानीय प्रशासन लेगा।

रेड्डी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में फिलहाल शांति है और गृह मंत्री अमित शाह नियमित रूप से वहां के हालात की निगरानी कर रहे हैं। स्कूल खुल गए हैं। धारा 144 हटा ली गई है। सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू हो गया है। कुछ पाबंदियों को हटा दिया गया है। चार-पांच जिलों को छोड़कर बाकी जगहों पर इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं।

एक कार्यक्रम से इतर रेड्डी ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'हमने जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था बाधित करने की साजिश रचने और लोगों को भड़काने की पाकिस्तान की मंशाओं को ध्यान में रखते हुए एहतियातन कुछ पाबंदियां लगाई हैं। हमारा मकसद लोगों को परेशान करना नहीं है।'

राज्य में हिंसा की खबरों पर रेड्डी ने कहा कि वहां छोटी-मोटी घटनाएं पहली बार नहीं हो रही हैं। वहां तनावपूर्ण हालात नहीं हैं, जहां महीनों तक कर्फ्यू रहता था। पहले भी नेता वर्षों तक जेल में रहते थे। उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान दुनिया के सामने यह साबित करने की साजिश रच रहा है कि भारत सरकार ने जो किया वह गलत है। पूरी दुनिया आज अनुच्छेद 370 को खत्म करने के मुद्दे पर भारत सरकार के फैसलों के साथ खड़ी है।'

साफ किया रुख

- केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा, अतिरिक्त सुरक्षा बल की वापसी पर स्थानीय प्रशासन लेगा फैसला
- गृह मंत्री हालात पर रख रहे हैं नजर

राहुल गांधी जितनी चाहें सभाएं कर सकेंगे : रेड्डी

जम्मू-कश्मीर में विपक्षी नेताओं को सभा क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, यह पूछे जाने पर रेड्डी ने कहा, 'विपक्ष को धैर्य रखना चाहिए। कुछ दिन शांति रखिए। अभी पाकिस्तान की समस्या को देखते हैं। उसके बाद राहुल गांधी जितनी चाहें, सभाएं कर सकते हैं। कौन मना कर रहा है? धैर्य रखिए।'

पदभार संभालने से पहले जम्मू पहुंचे बीएसएफ के नए डीजी

राज्य ब्यूरो, जम्मू

सीमा सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल (डीजी) का पदभार संभालने से पहले वीके जौहरी जम्मू संभाग के सीमांत क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने जवानों को सीमा पर कड़ी सतर्कता बरतते हुए दुश्मन के हर मंसूबे को नाकाम करने के निर्देश दिए।

वर्ष 1984 बैच के आइपीएस अधिकारी वीके जोहरी वर्तमान में खुफिया एजेंसी रॉ के विशेष सचिव हैं। इससे पहले भी वह कई अहम पदों पर रह चुके हैं। राज्य के पहले दौरे के दौरान नए डीजी ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) फ्रंटियर मुख्यालय में अधिकारियों से बैठक कर सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया। सूत्रों के अनुसार वह शुक्रवार को जम्मू का दौरा करने के उपरांत नई दिल्ली लौट जाएंगे। आपको बता दें कि बीएसएफ के मौजूदा डीजी रजनी कांत मिश्रा 31 अगस्त को सेवानिवृत हो रहे हैं। ऐसे में नए डीजी एक सितंबर को पदभार संभाल लेंगे।

जम्मू संभाग के सीमांत क्षेत्रों का किया दौरा: सूत्रों के अनुसार अहम जिम्मेवारी संभालने से पहले वीके जोहरी ने जम्मू के अखनूर में मकवाल, आरएसपुरा, रामगढ़ और कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टरों की अग्रिम चौकियों का दौरा किया। यहां उन्होंने मौजूदा चुनौतियों व उनसे निपटने के कदमों की जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के आइजी एनएस जम्वाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

जायजा

- जवानों को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कड़ी सतर्कता बरतने के दिए निर्देश
- आरएसपुरा, रामगढ़ और हीरानगर में अग्रिम चौकियों का किया दौरा

पांच अगस्त के बाद से गोलाबारी कर रहा पाक

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से पाक कड़े तेवर दिखा रहा है। पांच अगस्त के बाद से पाक सेना कश्मीर के मछल, टंगडार व उड़ी सेक्टर के साथ पुंछ, राजौरी व जम्मू में भी नियंत्रण रेखा पर भारी गोलाबारी कर रहा है। इस कारण अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर हाई अलर्ट पर है। ऐसे हालात में अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है।

अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ विपक्षी दलों का प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 एवं 35 ए हटाए जाने और नेताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में विपक्षी दलों ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, वाम दल व राजद समेत अन्य दलों के नेता शामिल हुए। नेताओं ने हिरासत में लिए गए जम्मू-कश्मीर के नेताओं को छोड़ने के साथ वहां जल्द से जल्द सामान्य जनजीवन की मांग की। प्रदर्शन में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिंदबरम भी शामिल हुए।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआइ के महासचिव डी राजा, सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव, लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव, राजद के मनोज झा व तृणमूल कांग्रेस से दिनेश त्रिवेदी समेत अन्य नेता विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मौके पर एक प्रस्ताव भी पारित किया। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर पाबंदी लगाई गई है। लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। बिना जम्मू-कश्मीर के लोगों व जनप्रतिनिधियों से मशविरे के अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। भारी सुरक्षा बलों के बीच जम्मू-कश्मीर में आपातकाल जैसे हालात हैं। हम वहां के लोगों के साथ खड़े हैं।

गुलाम नबी ने कहा कि वहां के हालात ठीक नहीं हैं, इस बारे में विदेशी मीडिया से पता चल रहा है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी होते तो जम्मू-कश्मीर में ऐसे हालात न होते। वहां के नेताओं को हिरासत में लिया गया है जो जम्मू-कश्मीर के लोगों और शेष भारत में संपर्क का काम कर रहे थे। रामगोपाल ने केंद्र के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कश्मीर में सब कुछ सामान्य है तो नेताओं को क्यों हिरासत में रखा गया है? कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि यह मात्र जम्मू-कश्मीर की लड़ाई नहीं है, बल्कि समूचे लोकतंत्र के अधिकारों की लड़ाई है।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते विपक्षी दलो के नेता गुलाम नबी आजाद, सीताराम येचुरी, विंदा करात, मनोज झा, शरद यादव व अन्य। जागरण

कश्मीर में अफगान आतंकियों को उतारने की साजिश रच रहा पाक

नई दिल्ली, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने से बौखलाया पाकिस्तान बड़ी साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीर में अस्थिरता फैलाने के लिए अफगानिस्तान से 100 से ज्यादा आतंकियों को ला रहा है। इनके अलावा जैश-ए-मुहम्मद के करीब 15 आतंकी नियंत्रण रेखा के नजदीक पाकिस्तान की लिपा घाटी में रुककर घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं।

खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। इनके जरिये वह दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि अनुच्छेद 370 हटने से घाटी में अशांति है। सूत्रों ने बताया, 'हमारे पास पुष्ट खुफिया जानकारी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से 100 से ज्यादा आतंकियों को ला रहा है। इन्हें अगले कुछ हफ्तों में कश्मीर में दाखिल कराने की कोशिश होगी। जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर के भाई मुफ्ती रऊफ असगर ने भी कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ के एजेंडे पर बहावलपुर स्थित ठिकाने पर अपने टॉप कमांडरों से चर्चा की है।' खुफिया रिपोर्टों में कहा गया है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन अगले कुछ हफ्तों में भारत के कई शहरों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं।

जम्मू में पाक ने फिर की गोलाबारी

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ करवाने की मंशा से पाकिस्तानी सेना ने लगातार दूसरे दिन भी अखनूर के केरी बट्टल में गोले दागे। भारतीय सेना की ओर से इसका कड़ा जवाब दिया जा रहा है।

पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार देर शाम पौने नौ बजे के करीब जम्मू जिले के अखनूर स्थित केरी बट्टल और इसके साथ लगते चकला इलाके में गोले दागना शुरू कर दिया। पाक सेना ने सैन्य चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। सीमा पार से गोलाबारी शुरू होते ही भारतीय सेना भी मोर्चा संभालते हुए पाक को कड़ा जवाब दे रही है। चिनाब दरिया के पार जिस इलाके को पाकिस्तान लगातार निशाना बना रहा है वह सेना की सुंदरबनी सेक्टर का हिस्सा है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पाक सेना सीमा पार से लगातार गोलाबारी कर रही है।

पीआरओ डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने पाकिस्तान की ओर से केरी बट्टल में लगातार दूसरे दिन भी गोलाबारी करने की पुष्टि करते हुए कहा कि अभी तक गोलाबारी में किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है।

कश्मीर पर प्रियंका के विचार एक भारतीय का नजरिया

जागरण संवाददाता, कोलकाता

कश्मीर पर केंद्र सरकार के हालिया फैसले के समर्थन में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भारतीय नागरिक होने के नाते जो विचार रखे, वह स्पष्ट रूप से एक भारतीय के नजरिए से उनके विचार हैं। यह कहना है विख्यात गीतकार व शायर जावेद अख्तर का। अख्तर बुधवार रात कोलकाता में एक साहित्यिक कार्यक्रम के इतर मीडिया से बात कर रहे थे। बता दें कि पाकिस्तान की एक मंत्री ने प्रियंका को शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना दूत (गुडविल एंबेस्डर) के तौर पर हटाए जाने की मांग की थी। इसी मांग पर अख्तर ने टिप्पणी की।

अख्तर ने कहा कि यदि उनकी टिप्पणियों ने पाकिस्तानी प्रतिष्ठान को नाराज किया है तो वे जो चाहें, वह कर सकते हैं। पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरीटा एच फोरे को पत्र लिखकर कहा था कि प्रियंका कश्मीर पर भारत सरकार की नीतियों का समर्थन करती हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि प्रियंका चोपड़ा भारत और पाकिस्तान के बीच 'परमाणु युद्ध' के समर्थन में हैं।

जावेद अख्तर फाइल फोटो

जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को टाडा कोर्ट में पेश करने के आदेश

जेएनएफ, जम्मू : जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के चीफ यासीन मलिक को टाडा कोर्ट ने पेश करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल के प्रभारी को यासीन मलिक को 11 सितंबर को टाडा कोर्ट में पेश करना होगा। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान मलिक को पेश करने के आदेश दिए थे, लेकिन सीबीआइ ने समय की कमी बताने हुए गुरुवार को उसे पेश करने में असमर्थता जताई थी।

जम्मू कश्मीर की टाडा कोर्ट में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रूबिया सैयद के अपहरण और वायुसेना के पांच अधिकारियों की हत्या के मामले की सुनवाई चल रही है। रूबिया सैयद अपहरण मामले में सीबीआइ के चालान के मुताबिक, श्रीनगर के सदर पुलिस स्टेशन में आठ दिसंबर 1989 को रिपोर्ट दर्ज हुई। रिपोर्ट के अनुसार, रूबिया सैयद मिनी बस में लललद अस्पताल श्रीनगर से नौगाम स्थित अपने घर जा रही थी। इसी दौरान कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने उसका अपहरण कर किया।

भाजपा की संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया शुरू

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू-कश्मीर प्रदेश भाजपा के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया गुरुवार को जिला चुनाव प्रभारियों की कार्यशाला के साथ शुरू हो गई। राज्य स्तरीय कार्यशाला के बाद जिलों में 31 अगस्त व एक सितंबर की बैठक में ब्लॉक, मंडल व बूथ पर होने वाले चुनाव के प्रभारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी।

जम्मू आए संगठनात्मक चुनाव के राष्ट्रीय सह प्रभारी, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद विनोद सोनकर ने लोकतांत्रिक तरीके से संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया दिसंबर के पहले सप्ताह में नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना की अध्यक्षता में गुरुवार को भाजपा मुख्यालय में हुई कार्यशाला में संगठन महामंत्री अशोक कौल, पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह, कवींद्र गुप्ता, पूर्व मंत्री सत शर्मा, एमएलसी अशोक खजूरिया, संगठनात्मक चुनाव के प्रभारी विरेंद्रजीत सिंह, सह प्रभारी मुनीश शर्मा के साथ सदस्यता अभियान के प्रभारी जुगल किशोर गुप्ता भी मौजूद थे।

सोनकर बोले-लोकतांत्रिक तरीके से हों भाजपा के संगठनात्मक चुनाव हों: सांसद विनोद सोनकर ने चुनाव प्रभारियों से कहा कि भाजपा लोकतंत्र की प्रतीक है। ऐसे में बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनाव होता है। उन्होंने जोर दिया कि चुनाव प्रभारी बूथ स्तर तक प्रशिक्षण का आयोजन कर सुनिश्चित करें कि लोकतांत्रिक तरीके से राज्य में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव हों। सदस्यता अभियान के दौरान कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर उनसे संपर्क स्थापित करें। बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ एमएलसी, पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक भी मौजूद थे।

अनुच्छेद 370 हटाए जाने से लोगों में उत्साह : रविंद्र रैना

जम्मू-कश्मीर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि ट्रेनिंग कार्यशालाओं के माध्यम से संगठन को मजबूत बनाना संभव होगा। चुनाव प्रभारी निष्पक्षता से चुनाव कर सुनिश्चित करें कि संगठन में जिम्मेदार नेता व कार्यकर्ता आगे आएं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने से राज्य के लोगों में बहुत उत्साह है। 10 जिलों में वरिष्ठ नेताओं के दौरों के दौरान लोगों से विचार विमर्श से इसकी पुष्टि हुई है। अशोक कौल व विरेंद्रजीत सिंह ने संगठनात्मक चुनाव को कामयाब बनाने के लिए आने वाले समय में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी दी। सदस्यता अभियान के प्रभारी जुगल किशोर गुप्ता ने

रविंद्र रैना फाइल फोटो

जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में नए सदस्य बनाने के अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला का संचालन संगठनात्मक चुनाव के सह प्रभारी मुनीश शर्मा ने किया।

सियासत

शिवराज सरकार ने दो बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्जा देकर मुंह कर दिया था बंद, देवमुरारी बापू ने कमलनाथ सरकार में पद न मिलने पर आत्मदाह की धमकी दी

मध्य प्रदेश में बाबा अब ब्लैकमेलिंग की राजनीति पर उतरे

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ सालों से बाबाओं की चर्चा जोरों पर है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में कंप्यूटर बाबा और अन्य कुछ महंत करोड़ों पौधे लगाए जाने के फर्जीवाड़े के खिलाफ यात्रा निकाल रहे थे तब चुनाव के पहले शिवराज सरकार ने दो बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्जा देकर मुंह बंद कर दिया। प्रदेश में सरकार बदलने से पहले ही कंप्यूटर बाबा ने पाला बदला और अब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में भी सरकारी पद व रुतबे का लुत्फ उठा रहे हैं। अब नए बाबा आए हैं देवमुरारी बापू। उन्होंने सीधे मांग कर दी कि गो-संवर्धन बोर्ड का अध्यक्ष बनाओ, वरना मुख्यमंत्री निवास पर आत्मदाह कर लूंगा। डर के मारे सरकार के मंत्री गए बाबा को मनाने और कहा कि सितंबर के पहले आपको भी नवाज दिया जाएगा, तब माने बाबा। सियासत करने वाले बाबा अब ब्लैकमेलिंग की राजनीति पर उतर आए हैं।

कंप्यूटर बाबा यानी नामदेव त्यागी ने नर्मदा में अवैध खनन का आरोप लगाते हुए शिवराज सरकार के खिलाफ विधानसभा चुनाव से महीना भर पहले मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने संत समागम के नाम से अभियान शुरू किया था। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कंप्यूटर बाबा समेत पांच धार्मिक नेताओं को अप्रैल 2018 में राज्यमंत्री का दर्जा दिया था, लेकिन कंप्यूटर बाबा ने इसके कुछ समय बाद ये आरोप लगाते हुए इस दर्जे से इस्तीफा दे दिया था कि शिवराज सरकार ने नर्मदा को स्वच्छ रखने और इस नदी से अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के मामले में संत समुदाय से वादाखिलाफी की है।

अब वृंदावन के आचार्य देवमुरारी बापू ने इसी सप्ताह सोमवार को मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह करने का एलान कर दिया। वह सरकार से अपने लिए मध्य प्रदेश गो-संवर्धन बोर्ड में एक पद की मांग कर रहे हैं। एक दिन पहले ही रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने दावा किया था कि 'मैंने पिछले साल नवंबर माह में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को समर्थन देकर उसके पक्ष में प्रचार किया था। संतों के समर्थन के बिना मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती थी, लेकिन कांग्रेस सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। मैंने कमलनाथ से मांग की थी कि 15 अगस्त तक मप्र गो-संवर्धन बोर्ड में मेरी नियुक्ति की जाए, ताकि मैं गो सेवा कर सकूं, लेकिन यह मांग भी अनसुनी कर दी गई। उन्होंने कहा कि इससे मैं आहत हूं और मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह करूंगा।' हालांकि, बाद में उन्हें एक मंत्री ने मना लिया, इस वादे के साथ कि सितंबर के पहले आपको नियुक्ति दी जाएगी।

जहां तक देवमुरारी की बात है तो वह प्रवचन करने वाले हैं। साधु-संत नहीं हैं। यही वजह है कि उन्होंने ब्लैकमेलिंग का रास्ता अपनाया। यह वाकया निंदनीय है। इससे सारे समाज के सम्मान को ठेस पहुंची है। चुनाव में तो हजारों संतों ने काम किया तो क्या सभी को सरकार में शामिल कर लेंगे।

- कंप्यूटर बाबा, अध्यक्ष, नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी नदी न्यास

देवमुरारी बापू। फाइल फोटो

संतों का राजनीति में आना गलत नहीं है। समाज का उत्थान किया जा सकता है, पर पद पाने के लिए किसी तरह का पाखंड का मार्ग अपनाना संत परंपरा को कलंकित करने जैसा है।

- परमहंस अवधेशपुरी महाराज, पूर्व महामंत्री अखाड़ा परिषद, उज्जैन

जमीन घोटाला : नहीं हो पाई अंतिम बहस, वाड्रा के वकील ने मांगा समय

संवाद सूत्र, जोधपुर

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी द्वारा जमीन की खरीद-फरोख्त में गड़बड़ी के मामले में गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान वाड्रा के वकील ने अंतिम बहस के लिए समय देने की मांग की। प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने वाड्रा के वकील को समय देते हुए इसकी अगली सुनवाई 12 सितंबर को तय कर दी। इस मामले में वाड्रा व उनके भागीदारों की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक जारी रहेगी।

जस्टिस जीआर मूलचंदानी की कोर्ट में गुरुवार को इस मामले में अंतिम बहस होनी थी, लेकिन सुनवाई शुरू होते ही वाड्रा के वकील कुलदीप माथुर ने कहा कि उन्हें अंतिम बहस के लिए कुछ समय और चाहिए। वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सोलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि बार-बार समय देना उचित नहीं रहेगा। ऐसे में आज ही अंतिम बहस कर ली जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अंतिम बहस की अगली तारीख 12 सितंबर तय कर दी।

यह है मामला: वर्ष 2007 में रॉबर्ट वाड्रा ने स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्रा.लि. नाम से एक कंपनी शुरू की। रॉबर्ट व उनकी मां मौरिन इसके डायरेक्टर थे। बाद में कंपनी का नाम बदलकर स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड लायबिलिटी कर दिया गया। पंजीयन के वक्त बताया गया था कि यह कंपनी रेस्टोरेंट, बार और कैंटीन चलाने जैसे काम करेगी। इस कंपनी ने वर्ष 2012 में बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में कुछ दलालों के माध्यम से 270 बीघा जमीन 79 लाख रुपये में खरीदी। जबकि यह जमीन भारतीय सेना की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लिए आवंटित की गई थी। कुछ लोगों ने इस जमीन के फर्जी कागजात तैयार करवा वाड्रा की कंपनी को बेच दिया। फर्जी तरीके से जमीन खरीदने-बेचने का मामला उजागर होने से पहले ही वाड्रा की कंपनी ने पांच करोड़ रुपये में यह जमीन बेच दी।

39 लाख से ज्यादा लोग अब तक आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का लाभ उठा चुके हैं। योजना के तहत मरीजों को 6,100 करोड़ रुपये से ज्यादा के कैशलेस इलाज की सुविधा मिली है।

आयुध निर्माणियों की हड़ताल से करोड़ों का उत्पादन प्रभावित

नईदुनिया, जबलपुर: आयुध निर्माणियों के निगमीकरण को रोकने देश की सभी 41 निर्माणियों में तीसरे दिन गुरुवार को भी हड़ताल जारी रही। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित चार आयुध निर्माणियों के कर्मचारी भी इस आंदोलन में शामिल रहे। कर्मचारियों की हड़ताल से जबलपुर की चार आयुध निर्माणियों में 18 करोड़ का उत्पादन कार्य प्रभावित हो चुका है।

केंद्र ने निर्माणियों में हड़ताल के दौरान एस्मा लागू किया है। इसलिए निर्माणियों में ग्रुप 'ए' व ग्रुप 'बी' अधिकारी सुबह से ड्यूटी पर पहुंच रहे हैं। निर्माणियों में आते-जाते इन अधिकारियों के सामने हड़ताल में शामिल कर्मचारी नारेबाजी करके प्रदर्शन करते हैं। इस पर निर्माणियों के सुरक्षा अधिकारी व कर्मचारी नेताओं के बीच छुटपुट विवाद भी हो रहे हैं।

आज होगी बैठक : रक्षा मंत्रालय सचिव और फेडरेशनों तथा एसोसएिशनों के पदाधिकारियों की शुक्रवार को दोपहर 12 बजे दिल्ली में बैठक होगी। इसमें निर्माणियों की हड़ताल को लेकर फैसला होने के आसार हैं।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए वरदान बनेगी मानसून की दूसरी पारी

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

देश के ज्यादातर हिस्सों में आई बाढ़ का पानी अभी नीचे उतरा भी नहीं कि मानसून अपनी दूसरी पारी में सक्रिय हो गया है। राहत की बात यह है कि दूसरी पारी की तेज बारिश उन्हीं इलाकों में होगी, जहां सूखे जैसी स्थिति है। खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, तटीय कर्नाटक व पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में आने वाले पांच दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना है। इससे यहां सूख रही फसलों को नया जीवन मिल सकता है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश और सीमा से लगे बिहार राज्य के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। ऐसी ही स्थिति तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के ऊपर भी बनी हुई है। दूसरी ओर, पश्चिमी विक्षोभ समूचे उत्तरी क्षेत्रों में सक्रिय है। 27 से 29 अगस्त तक भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से, उत्तरी क्षेत्र के मैदानों और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना है। इन क्षेत्रों में जमकर बारिश का अनुमान है।

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में कई दिनों तक तेज गर्जना के साथ बारिश होगी। इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। दक्षिण पश्चिमी अरब सागर से तेज हवाओं के चलने की संभावना है। इससे पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और झारखंड प्रभावित होगा।

भारत में जून से सितंबर के बीच सक्रिय रहने वाला मानसून इस बार जून-जुलाई के पहले सप्ताह तक बहुत सक्रिय नहीं रहा, लेकिन जुलाई मध्य से अगस्त मध्य तक जमकर बारिश हुई। देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश के चलते नदियों में बाढ़ आ गई है। हिमालयी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जबर्दस्त बारिश से नदियां उफना गईं, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों पर पड़ रहा है।

प्रयागराज के दारागंज घाट में शाष्त्री पुल के नीचे नाव पर मछली पकड़ता नाविक। एएफपी

- पूर्वी उत्तर प्रदेश, तटीय कर्नाटक व पूर्वोत्तर में होगी झमाझम बारिश
- सूखने की स्थिति में पहुंची खरीफ फसलों को मिलेगा नया जीवन

सूखा प्रभावित सात संभागों को मिलेगी भारी बारिश की संजीवनी

मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर में शनिवार से अगले चार-पांच दिनों तक भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने देश को कुल 36 संभागों में विभाजित किया है। इनमें सात सूखा प्रभावित हैं, जहां अब अच्छी बारिश का अनुमान है। आंकड़ों के मुताबिक, कुल 36 संभागों में से 20 में सामान्य, जबकि आठ में औसत से ज्यादा बारिश हुई है। एक संभाग में अत्यधिक बारिश हुई है।

मानसून के पहले चरण की भारी बारिश के बावजूद देश के कुछ क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए। इनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के दो दर्जन से अधिक जिले शामिल थे। इनसे लगे बिहार का क्षेत्र भी सूखे की मार झेल रहा है।

मलेशिया में गिरफ्तार युवक की वतन वापसी की गुहार

जागरण संवाददाता, नैनीताल : मलेशिया में फंसे बागेश्वर के युवक की वतन वापसी को लेकर उसके पिता ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से यह पता लगाने को कहा है कि युवक को मलेशिया पुलिस द्वारा किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

उत्तराखंड के जिला बागेश्वर निवासी विरेंद्र कुमार सेना में भर्ती होने के लिए घर से देहरादून जाने के लिए निकला था। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कबूतरबाजों ने मर्चेंट नेवी में भर्ती कराने के लिए पांच लाख रुपये लेकर उसे मलेशिया नौकरी के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि विरेंद्र को मर्चेंट नेवी में नौकरी के बजाय किसी के घर में काम पर रख दिया। घर से संपर्क टूटने पर पिता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उसकी वतन वापसी की गुहार लगाई है।

गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि मलेशिया पुलिस द्वारा विरेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। एकलपीठ ने केंद्र सरकार से यह बताने को कहा है कि उसे किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

न्यूज गैलरी

और तीन हफ्ते बढ़ी नलिनी की पैरोल अवधि

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने नलिनी श्रीहरन की पैरोल और तीन हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में वह उम्रकैद की सजा भुगत रही है। उसके पैरोल की अवधि 25 अगस्त को समाप्त होने वाली थी। जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस एम निर्मल कुमार ने कहा कि बढ़ाई गई अवधि के दौरान पहले दिए गए आदेश की शर्तें लागू रहेंगी। कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार से नलिनी की याचिका पर जवाब मांगा था। नलिनी ने 25 अगस्त के बाद और 30 दिनों के लिए पैरोल बढ़ाने की मांग की थी। नलिनी ने कहा था कि वह कोर्ट में आने के लिए बाध्य हुई क्योंकि राज्य के जेल डीआइजी ने 13 अगस्त के उसके पत्र को ठुकरा दिया है। उसने इस पत्र में और 30 दिनों के लिए पैरोल बढ़ाने का आग्रह किया था। 25 जुलाई को वेल्लोर सेंट्रल जेल से रिहा होने के बाद नलिनी सातुवाचारी में रह रही है। 27 साल से जेल में बंद नलिनी ने बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए छह माह का पैरोल मांगा था। (प्रेट्र)

गोरखपुर हादसे में डॉ. कफील का निलंबन रद करने की मांग

नई दिल्ली : इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) ने डॉक्टर कफील अहमद के निलंबन को रद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से नवजात बच्चों की मौत के मामले में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कफील को निलंबित कर दिया गया था। आइएमए ने कहा है कि निलंबन के बाद से डॉ. कफील और उनके परिवार को जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने डॉ. कफील के खिलाफ दर्ज मामलों को भी वापस लेने और बीआरडी मेडिकल कॉलेज मामले की केंद्रीय एंजेसियों से जांच की मांग भी की है। आइएमए ने कहा है कि वेंडर ने भुगतान नहीं होने पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी थी, जिससे बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई थी। (प्रेट्र)

कोटकपूरा गोलीकांड की सुनवाई आज

फरीदकोट : जिला व सेशन जज की अदालत में कोटकपूरा गोलीकांड की शुक्रवार को सुनवाई होगी। मामले में निलंबित आइजी परमराज सिंह उमरानंगल, पूर्व एसएसपी चरनजीत शर्मा, कोटकपूरा के पूर्व विधायक मनतार सिंह बराड़ सहित अन्य आरोपित पेश हो सकते हैं। केस का ट्रायल शुरू हो चुका है और केस में नामजद छह आरोपितों पर आरोप तय कर दिया है। जिला अदालत में सात अगस्त से केस ट्रायल शुरू हुआ है। इससे पहले इस केस में एसआइटी ने करीब दो माह पहले जेएमआइसी एकता उप्पल की अदालत चालान पेश किया था। इसे तीन अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान उसे ट्रायल के लिए जिला व सेशन जज की अदालत में भेज दिया था। (जासं)

मध्य प्रदेश से पकड़े गए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के पांच एजेंट

नापाक इरादे ▶ टेरर फंडिंग में गिरफ्तारी, आइएसआइ के लिए करते थे काम

आरोपितों के फोन में 17 पाकिस्तानी नंबर मिले, जासूसी का आरोप

नईदुनिया, भोपाल

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ (इंटर सर्विस इंटेलीजेंस) के पांच एजेंट मध्य प्रदेश से पकड़े गए हैं। ऑनलाइन ठगी के जरिये 'टेरर फंडिंग' और जासूसी के मामले में जहां तीन की गिरफ्तारी हुई है, वहीं दो को हिरासत में लिया गया है। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में इन्होंने जाल फैला रखा है। आरोपितों के फोन में 17 पाकिस्तानी नंबर मिले हैं।

पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता आशुतोष प्रताप सिंह ने मीडिया को बताया कि सतना से सुनील सिंह, बलराम सिंह और शुभम मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। इनको एटीएस की टीम भोपाल ले आई है। इनके खिलाफ धारा 123 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। दो आरोपित भारवेंद्र सिंह और प्रदीप कुशवाहा सतना पुलिस की हिरासत में हैं। इन लोगों ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी एजेंटों को बैंक खाते, एटीएम कार्ड की जानकारियों के साथ धनराशि भेजी थी। ये पहले भी योजनाबद्ध तरीके से जासूसी कर रहे थे। साथ ही युद्ध की स्थिति में सामरिक महत्व की जानकारियां एकत्रित कर रहे थे। पाकिस्तानी हैंडलरों से मिलकर ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। फोन कॉल के जरिये इनाम जीतने का लोगों को झांसा देकर राशि वसूलने वाले गिरोह से भी इनकी सांठगांठ थी। एटीएस मामले की अन्य कड़ियां खोलने में जुटी है। पुलिस के रडार पर अन्य आरोपी भी हैं। इलाहाबाद, चित्रकूट, सतना और रीवा के कुछ लोगों की निगरानी की जा रही है।

जासूसी पर खर्च करते थे रुपये : सतना से गिरफ्तार आरोपितों से पाकिस्तान के कई नंबरों से संपर्क, डाटा ट्रांसफर और बड़ी धनराशि के लेनदेन का ब्योरा मिला है। एटीएस का कहना है कि टेरर फंडिंग का यह पैसा पाक हैंडलर्स व जासूसी पर खर्च हो रहा था। यह राशि कश्मीर, झारखंड, बिहार, और पश्चिम बंगाल के कई खातों में पहुंचाई गई।

आठ फीसद देते थे कमीशन : पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपित जिन लोगों के बैंक खातों का उपयोग कर रहे थे, उन्हें इसके एवज में बतौर कमीशन आठ फीसद राशि भी दे रहे थे। इनके पास से पुलिस को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए काम कर रहे हैंडलरों के मोबाइल और फोन नंबर, लेपटॉप और अन्य दस्तावेज मिले हैं। 17 पाकिस्तानी नंबरों पर इनका संपर्क बार-बार हुआ। मप्र एटीएस इनकी भूमिका टेरर फंडिंग के लिए फाइनेंशियल स्लीपर सेल के बतौर देख रही है।

वीडियो कॉलिंग के जरिये करते थे संपर्क : आरोपित आतंकियों के फंड मैनेजरों से वीडियो कॉलिंग, वॉट्सएप कॉलिंग और आइएमओ के जरिये संपर्क में थे। आयकर विभाग को धोखा देने के लिए मप्र के खातों में 50 हजार रुपये से कम की राशि मंगवाते थे, जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के खातों में इन्होंने लाखों रुपये का लेनदेन भी किया है। मप्र एटीएस ने 2017 में बलराम सहित 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये सभी पाकिस्तानी हैंडलरों के इशारे पर फर्जी बैंक खाते खुलवाकर उनमें धनराशि जमा करवा रहे थे।

आरोपित शुभम।

बलराम सिंह।

सुनील सिंह। नईदुनिया

उप्र के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी रैगिंग मामले में सात मेडिकल छात्र दोषी

सैफाई मेडिकल कॉलेज में बाल मुंडवाकर और सिर झुकाकर जाते छात्र। जागरण आर्काइव

जागरण संवाददाता, इटावा

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के कैंपस में रैगिंग को दो दिन तक नकारने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गुरुवार शाम सच्चाई कुबूल ली। एंटी रैगिंग कमेटी की गुरुवार देर शाम कुलपति प्रो. राजकुमार को मिली रिपोर्ट में 2018 बैच के सात छात्रों को दोषी माना गया है। कमेटी ने दोषी छात्रों पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाने व एक माह तक छात्रावास व कक्षाओं से प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है। इन छात्रों पर जल्द एफआइआर की तैयारी है।

यूनिवर्सिटी कैंपस में जूनियर छात्रों से रैगिंग की बात कुलपति ने तब कुबूली, जब डीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट में विश्वविद्यालय को दोषी मानते हुए रैगिंग होने संबंधी रिपोर्ट चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव को भेज दी। वहीं, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में रैगिंग को लेकर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने भी यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे में जवाब मांगा है। पूछा है कि क्यों न यूनिवर्सिटी पर 1.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते हुए दोषी छात्रों को एक माह के लिए निलंबित कर दिया जाए।

यह था मामला: सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में इस बार प्रथम वर्ष में 200 छात्र-छात्राओं ने प्रवेश लिया है। इनकी रैगिंग रोकने के लिए हॉस्टल से लेकर कक्षाओं तक कड़ी सुरक्षा के इंतजाम करने का दावा यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा किया गया। बावजूद इसके सीनियर्स का आदेश हॉस्टलों तक पहुंच गया। जिसमें उन्हें हॉस्टल से कॉलेज आने जाने के दौरान सिर झुकाकर लाइन में लगकर चलने का फरमान सुनाया गया।

कैंपस से निकलते समय इन छात्रों को एप्रेन के थर्ड बटन पर सिर करने को कहा गया है। छात्रों के अनुसार रैगिंग पिछले छह दिनों से चल रही है। इसमें छात्राओं को भी नहीं बख्शा गया। उनको भी चोटी बांधने के निर्देश दिए गए। बताया गया है कि सलाम न करने पर बीते दिनों अवकाश के दौरान ही सभी छात्रों का सिर मुड़वा दिया गया था। इसके बाद कुलपति ने जांच कमेटी गठित की थी।

बिहार में बच्चा चोरी के आरोप में महिला को पीटकर मार डाला

जागरण संवाददाता, हाजीपुर : बिहार के हाजीपुर में चोरी के आरोप में एक विक्षिप्त महिला की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। गुरुवार सुबह उसका शव सड़क किनारे मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की शिनाख्त नहीं की जा सकी है। वहीं पुलिस की मानें तो महिला की मौत का कारण स्पष्ट नहीं है।

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि उस महिला को कुछ लोग एक पेड़ से बांधे हुए हैं और उससे पूछताछ कर रहे हैं। फुटेज में महिला जो वस्त्र पहने है, वही शव पर थे। कुछ लोगों ने बताया कि महिला विक्षिप्त थी। वह लगातार कह रही थी कि मेरा बच्चा खो गया है। यह कहते हुए वह एक घर में घुस गई। उसकी आवाज सुनकर घरवाले उठे और बच्चा चोर कह कर उसे पीटने लगे। शोर होने पर पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। कुछ लोगों ने उस विक्षिप्त महिला को बचाने की कोशिश भी की। वह कहां की रहने वाली थी इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है। चर्चा है कि शव को बाइक पर लाद कर सड़क के किनारे फेंक दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट में यूएपीए में संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि इनसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। यूएपीए में संशोधन संबंधी विधेयक को संसद ने दो अगस्त को पारित किया था और राष्ट्रपति ने नौ अगस्त को इसे मंजूरी दी थी।

संशोधन अधिनियम केंद्र को किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने और उसकी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है। गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 में किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर दिए जाने पर ऐसे व्यक्ति के यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान है। यह याचिका गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) ने दायर की है। याचिका में कहा गया है, 'किसी व्यक्ति का पक्ष सुने बिना उसे आतंकवादी घोषित करना व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और निजी स्वतंत्रता के अधिकार का एक पहलू है।'

याचिका में कहा गया है कि महज सरकार की मान्यता के आधार पर किसी व्यक्ति का पक्ष सुने बिना उसकी निंदा करना अतर्कसंगत, अनुचित, असंगत और उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि संशोधन अधिनियम की धारा 35 में इस बात का उल्लेख नहीं है कि कब किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है, 'क्या महज प्राथमिकी दर्ज हो जाने पर या आतंकवाद से संबंधित मामले में दोषी ठहराए जाने पर व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जाएगा। महज सरकार की मान्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना मनमाना और ज्यादती है।'

याचिका में न्यायालय से गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 35 और 36 को असंवैधानिक और अमान्य घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई है क्योंकि उनसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।

सिपाही की चुनौती याचिका पर सीबीआइ से मांगा जवाब

उन्नाव कांड

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : उन्नाव कांड में उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही आमिर खान की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने इसके साथ ही निचली अदालत में चल रही सुनवाई का डिजिटल रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है। वहीं, तीस हजारी कोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस दौरान पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने बयान दर्ज कराए। आरोपित सिपाही आमिर खान ने हाई कोर्ट से मांग की है कि उन पर लगाए गए हत्या, आपराधिक साजिश रचने के आरोप को रद किया जाए। उनके अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता का काम सिर्फ एफआइआर दर्ज करना और हथियार की बरामदगी के मेमो पर हस्ताक्षर करना भर था। तीस हजारी अदालत ने गत 13 अगस्त को उन्नाव कांड से जुड़े दो मामलों को जोड़कर आरोप तय किए थे।

सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पर छह छात्र निष्कासित

जासं, सहारनपुर : उप्र के सहारनपुर स्थित शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन राजकीय मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्रों ने जूनियर के छात्रावास में घुसकर रैगिंग की। कुछ से गाना गाने को कहा तो कुछ से नाचने को भी कहा। इसी बीच एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्य पहुंच गए। कमेटी ने छह छात्रों को पांच-पांच माह के लिए निष्कासित कर दिया है। पांच-पांच हजार जुर्माना भी लगाया है। सभी छात्रों से हॉस्टल भी खाली करवा लिया गया है। मेडिकल कॉलेज में मंगलवार रात 2018 के एमबीबीएस के छह छात्रों ने 2019 बैच के छात्र-छात्राओं के साथ रैगिंग की। हॉस्टल गार्ड ने जूनियर छात्रों का मानसिक उत्पीड़न करने की जानकारी दी तो एंटी रैगिंग टीम के साथ प्राचार्य डॉ. अरविंद कुमार त्रिवेदी भी पहुंच गए। सीनियर छात्र दीवार कूदकर भागने लगे, जिनमें से दो को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपने चार और साथियों के नाम बताए, जो रैगिंग में शामिल थे। प्राचार्य ने कहा कि आरोपितों से पांच माह के लिए हॉस्टल खाली करवा लिए गए हैं।

तकनीक

सौर ऊर्जा से चलने वाला देसी आरओ दूर करेगा फ्लोराइड, एचबीटीयू छात्र ने विकसित की पानी को शुद्ध करने वाली तकनीक, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ केमिकल में भेजा शोध पत्र

सूर्य की रोशनी से खत्म किए जाएंगे पानी के सभी दोष

विक्सन सिकरोड़िया, कानपुर

आपके घर के आसपास भूगर्भ जल यदि फ्लोराइड युक्त अथवा खारा है तो अब टेंशन न लें। सूर्यदेव इन दोषों को हर कर पानी पीने योग्य बनाएंगे। यह संभव होगा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय (एचबीटीयू) के छात्र कृष्ण प्रताप के सौर ऊर्जा से पानी शुद्ध करने वाले देसी आरओ (रिवर्स ऑसमोसिस) के माध्यम से। प्रयोग सफल होने पर उन्होंने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ केमिकल में अपना शोध पत्र भेजा है।

पर्यावरण इंजीनियरिंग से एमटेक अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे कृष्ण प्रताप ने स्लोबदार लकड़ी के फ्रेम, गैलवेनाइज्ड आयरन (जीआइ शीट), थर्माकॉल व कांच के शीशे से एक उपकरण तैयार किया है, जो धूप की गर्माहट से फ्लोराइड, खारापन व क्लोराइड खत्म करके वाष्पीकरण के जरिये एक दिन में आठ लीटर तक पानी को शुद्ध कर सकता है।

सिविल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ.दीपेश सिंह के दिशा-निर्देशन में कृष्णप्रताप ने छोटा प्लांट बनाया है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले जीआइ शीट में पानी भरा जाता है। इस शीट में एक्टिवेटेड चारकोल रहता है, जो पानी से हानिकारक तत्वों को खींच लेता है। जीआइ शीट के ऊपर कांच की स्क्रीन लगाई गई है। शीट से छनकर धूप की गर्माहट पानी को वाष्प में परिवर्तित करती है। यह पानी शीशे के पास लगे पाइप के जरिए एक जगह इकट्ठा होने लगता है।

फेस चेंजिंग मेटीरियल शाम सात बजे तक शुद्ध करता है पानी

कृष्ण प्रताप ने बताया कि पूर्वाह्न 11 से शाम चार बजे तक धूप की गर्माहट अधिक रहती है। इस दौरान अधिक मात्रा में पानी शुद्ध किया जा सकता है पर उन्होंने जीआइ शीट के नीचे फेस चेंजिंग मेटीरियल लगाकर उसकी क्षमता बढ़ा दी है। इससे सूर्य ढलने के तीन घंटे बाद तक उपकरण की गर्माहट बरकरार रहेगी, जिससे शाम सात बजे तक पानी शुद्ध होता रहेगा।

उपकरण बनाने में 4500 रुपये आया खर्च

उन्होंने बताया कि साल भर के शोध के बाद यह उपकरण तैयार किया है जिसका खर्च 4500 रुपये आया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह काफी उपयोगी साबित हो सकता है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में पानी शुद्ध करने की देशी तकनीक के बारे में जानकारी देते एचबीटीयू के एमटेक छात्र कृष्ण प्रताप। जागरण

जमानत को लेकर आश्वस्त होने पर ही आत्मसमर्पण करेंगे अनंत

जागरण संवाददाता, पटना

मोकामा (पटना, बिहार) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह भले ही फरार हैं, मगर अपने करीबी और खासकर वकीलों के संपर्क में हैं। पुलिस से बचने के लिए वह लगातार गाड़ी और लोकेशन बदल रहे हैं।

सूत्रों की मानें तो अनंत सिंह अपने कानून विशेषज्ञों से इस बात को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं कि उन्हें जमानत मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। वकील लगातार उनके मामले का अध्ययन कर रहे हैं। वकीलों की ओर से जमानत की हरी झंडी मिलते ही वह अदालत में समर्पण कर सकते हैं। गुरुवार दोपहर बाद यह अफवाह उड़ी कि अनंत सिंह कोर्ट में आत्मसमर्पण करने वाले हैं। यह खबर सामने आते ही पुलिस प्रशासन के साथ मीडिया का जमावड़ा पटना से लेकर बाढ़ में कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन यह बात बाद में अबी अफवाह साबित हुई। अनंत सिंह ने समर्पण नहीं किया।

- पुलिस से बचने को बदल रहे गाड़ी और लोकेशन
- वकीलों के साथ लगातार संपर्क में हैं विधायक

दो लोग चल रहे साये की तरह साथ

अनंत सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस के हाथ लगी हैं। उनके साथ उनके दो करीबी लोग साये की तरह साथ चल रहे हैं। अनंत सिंह फरारी अवस्था में भी अपनी दिनचर्या में समझौता नहीं कर रहे हैं। सुबह व्यायाम कर पसीना बहाना उनका अब भी जारी है। उनके मनपसंद भोजन और देसी गाय के दूध की भी व्यवस्था की गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अनंत सिंह कभी झारखंड तो कभी पश्चिम बंगाल का रुख कर रहे हैं। पुलिस की टीम भी उनकी तलाश में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

न्यूज गैलरी

नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे गृहमंत्री

लखनऊ : उप्र के सोनभद्र में जमीन विवाद को लेकर हुए नरसंहार के बाद देशभर में रहने वाले आदिवासियों और वनवासियों को लेकर चिंता बढ़ गई है। इनकी स्थितियों और सुविधाओं की समीक्षा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं। वह 26 अगस्त को नई दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विभिन्न मंत्रालयों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के अनुसार, उप्र के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय बैठक में भाग लेंगे। इसके लिए शासन ने जनजाति विकास विभाग से जमीन संबंधी पूरी रिपोर्ट तैयार कराई है। गौरतलब है कि विगत में सोनभद्र के उभ्भा गांव में हुए जमीन विवाद में 10 आदिवासियों की हत्या हो चुकी है। (जासं)

झारखंड में उत्पाती हाथियों ने दो को कुचलकर मार डाला

चतरा : झारखंड के चतरा और पूर्व सिंहभूम में उत्पात मचा रहे हाथियों ने दो लोगों को कुचल कर मारा डाला। पहली घटना पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा के बड़शोल थाना क्षेत्र के चिंगडा पंचायत के कटुशोल गांव की है। यहां चूनाराम सबर (45) नाम के व्यक्ति को गुरुवार को हाथियों के झुंड ने जंगल में कुचल दिया। दूसरी घटना चतरा जिले की है। यहां टंडवा थाना क्षेत्र के सुइयाटांड़ निवासी जोहन उरांव को हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला। बताया जाता है कि जोहन तीन दोस्तों के साथ साप्ताहिक बाजार बड़गांव गया हुआ था। (जेएनएन)

धोखाधड़ी में ई-बिज कंपनी का मालिक व बेटा गिरफ्तार

कार्रवाई ▶ 17 लाख लोगों से धोखाधड़ी के आरोप में हुई गिरफ्तारी

18 साल पुरानी कंपनी पर छात्रों व बेरोजगारों को सदस्य बना कर ठगी करने का है आरोप

जागरण संवाददाता, नोएडा

उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर-63 स्थित मल्टी लेवल कंपनी ई-बिज के प्रबंध निदेशक पवन मल्हन और उसके बेटे रितिक मल्हन को हैदराबाद पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कंपनी को सीज करते हुए आरोपितों के खाते को फ्रीज कर दिया है। कंपनी पर देश भर के करीब 17 लाख छात्रों व बेरोजगार युवाओं से पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। हैदराबाद पुलिस कोतवाली फेस तीन पुलिस को सूचना देकर आरोपितों को अपने साथ ले गई है।

सेक्टर-63 में स्थित ई-बिज कंपनी को पवन मल्हन ने वर्ष 2001 में शुरू किया था। कंपनी से उसके बेटे रितिक मल्हन समेत परिवार के कई सदस्य जुड़े हैं। हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने मंगलवार को सेक्टर-63 स्थित ई-बिज कंपनी में छापेमारी कर पवन मल्हन और रितिक को गिरफ्तार किया। पुलिस को देखकर दोनों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। इस मामले में कुछ और आरोपितों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर कंपनी को सीज कर दिया है। कंपनी व पदाधिकारियों के बैंक खाते को भी फ्रीज कर दिया गया है। खाते में करीब 389 करोड़ रुपये मिले हैं।

बाएं से पवन मल्हन व हितिक मल्हन। यह तस्वीर हितिक मल्हन के फेसबुक अकाउंट से ली गई है

- पुलिस ने कंपनी को सीज करते हुए आरोपितों के खाते को फ्रीज कर दिया है।

पवन मल्हन कंपनी का एमडी है और उसकी पत्नी निदेशक है, जबकि बेटा रितिक कंपनी का बाहरी काम देखता है। कंपनी के खिलाफ हैदराबाद के वारंगल व अदिलाबाद में दो मामले दर्ज हैं। इसके अलावा कई अन्य शहरों में भी रिपोर्ट दर्ज है।

आरोप है कि कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के जरिए युवाओं को दोगुना पैसा देने का लालच देकर फंसाती थी। कंपनी सदस्य बनाने के एवज में 16 हजार रुपये लेती थी और उन्हें अन्य लोगों को सदस्य बनवाने पर चार फीसद कमीशन दिया जाता था। कंपनी का कारोबार हैदराबाद, बेंगलूरू, चेन्नई, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में फैला हुआ है। कोतवाली फेस तीन के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने बताया कि हैदराबाद पुलिस कंपनी पर छापेमारी करने आई थी। किसी को गिरफ्तार कर अपने साथ लेकर गई है, इसकी जानकारी नहीं है।

मेरी हत्या कराना चाहते थे बुद्धदेव और विमान बोस : तस्लीमा नसरीन

जागरण संवाददाता, कोलकाता : बांग्लादेश की निष्कासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और वाममोर्चा अध्यक्ष विमान बोस पर हमला करते हुए कहा कि ये दोनों वामपंथी नेता उन्हें मारने की साजिश कर रहे थे। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि वह खुद भी वामपंथी विचारक थीं, सो उन्हें उम्मीद थी कि बांग्लादेश से निकाले जाने के बाद उन्हें बंगाल में शरण मिलेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि वामपंथियों द्वारा उन्हें ज्यादा परेशान किया गया और कोलकाता से उन्हें बाहर फेंक दिया गया। इसके अलावा उन्होंने अपने पोस्ट में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य और विमान बोस के साथ उनके बेहतर संबंधों का भी जिक्र किया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पुस्तक 'लज्जा' पर प्रतिबंध लगने के बाद बुद्धदेव को उनके चेहरे से भी नफरत हो गई थी। हालांकि दो साल बाद पुस्तक पर लगे प्रतिबंध को कोलकाता हाई कोर्ट ने हटाने का निर्देश दिया, लेकिन इसके बाद उन्हें कई बार पुलिस ने फोन किया और उन्हें तत्काल राज्य छोड़ने के आदेश के साथ ही चार माह तक नजरबंद रखा गया। इधर, सड़कों पर 'तस्लीमा गो बैक' के नारे लगने लगे। एक नवंबर, 2001 को पुलिस ने उन्हें उठा लिया और उन्हें एक अज्ञात घर में नजरबंद कर दिया गया। हालांकि जब उन्होंने सवाल किया तो उन्हें बताया गया कि सिद्दीकुल्ला के समर्थक उनकी हत्या कर सकते हैं। खैर, उनकी लोकप्रियता के कारण उनकी जान बच गई।

मेडिकल कॉलेज में दाखिले की धोखाधड़ी में संपत्ति अटैच

जागरण संवाददाता, देहरादून

- एचआइएचटी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर की गई थी 1.29 करोड़ की धोखाधड़ी
- 2015 में पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा एक साल बाद ईडी ने शुरू की थी जांच

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जौलीग्रांट स्थित हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट (एचआइएचटी) मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर की गई 1.29 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपित की 19.52 लाख रुपये की संपत्ति अटैच की है। जांच अभी जारी है, इस मामले में कुछ और संपत्ति जल्द अटैच की जा सकती है।

ईडी के उत्तराखंड के उप निदेशक रवींद्र जोशी के मुताबिक 2015 में पुलिस ने हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट (एचआइएचटी) मेडिकल कॉलेज में पीजी में दाखिले के नाम पर 1.29 करोड़ रुपये की वसूली का मुकदमा दर्ज किया था। इसमें विट एडुलिंक प्रा. लि. के निदेशक रोहित चौहान, अंकुश सागर खत्री समेत संदीप गुप्ता, अनुभव गर्ग, राजीव राणा, सतीश नेगी, सुधाकर नेगी, सुरजीत सिंह, विजय पाल को आरोपित बनाया गया है।

प्रकरण में पुलिस चार्जशीट भी फाइल कर चुकी है। 2016 में ईडी ने भी इस दिशा में कार्रवाई करते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) में मामला दर्ज किया था। इस दिशा में अब कार्रवाई करते हुए ईडी ने रोहित सिंह चौहान की 19.52 लाख रुपये की संपत्ति को अटैच कर दिया है। यह संपत्ति उत्तर प्रदेश के एटा जिले के चमकड़ी गांव में है। इसमें चमकड़ी में संयुक्त नाम की 0.138 हेक्टेयर भूमि शामिल है। इसके अलावा नई दिल्ली के रंजीत नगर स्थित फ्लैट को भी अटैच किया गया। बताया जा रहा है कि ईडी के हाथ जल्द अन्य आरोपियों तक भी जाएंगे। इसके अनुरूप संपत्तियों को अटैच करने का सिलसिला जारी रहेगा।

कंपनी के खाते में जमा की गई थी रकम

रोहित चौहान और उनके सहयोगियों पर यह मामला लक्कम बिकासपति, डॉ. अमरदीप कुमार, डॉ. सिद्धांत कुलकर्णी, डॉ. तरुण राव की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि मैनेजमेंट कोटे के तहत पीजी कोर्स में दाखिले के नाम पर उनसे 1.29 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। ईडी की जांच में पता चला कि बड़ी राशि रोहित चौहान की कंपनी के खाते में भी ट्रांसफर की गई थी। इसके बाद इस राशि को कई खातों में ट्रांसफर किया गया। इनमें कुछ खाते रोहित चौहान के परिजनों के भी शामिल थे। कुछ राशि कंपनी के खाते से कैश में भी निकाली गई, जिसे अन्य खातों में जमा कराया गया।

इसरो चेयरमैन के. सिवन को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार

चेन्नई, प्रेट्र : तमिलनाडु सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष के. सिवन को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसरो प्रमुख ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी से पुरस्कार हासिल किया। पुरस्कार के तहत आठ ग्राम का स्वर्ण पदक, पांच लाख रुपये नकद और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

वर्ष 2015 में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम के निधन के बाद तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने उनके नाम पर इस पुरस्कार की घोषणा की थी। यह पुरस्कार तमिलनाडु के रहने वाले उन लोगों को दिया जाता है, जो विज्ञान व प्रौद्योगिकी, मानवता व छात्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। प्रशस्ति पत्र में इसरो प्रमुख को 'रॉकेट मैन' की उपाधि दी गई है। 62 वर्षीय सिवन वर्ष 1980 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की डिग्री पाने वाले परिवार के पहले सदस्य हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करने के बाद वह इसरो से जुड़े। उन्हें डॉ. विक्रम साराभाई रिसर्च अवार्ड (1999) समेत कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले केरल के नेता यूएई में गिरफ्तार

दुबई, प्रेट्र : केरल के वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राजग के घटक दल भारत धर्म जन सेना (बीडीजेएस) के प्रत्याशी तुषार वेल्लापल्ली को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वेल्लापल्ली की गिरफ्तारी 19 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में हुई है।

वेल्लापल्ली बीडीजेएस के अध्यक्ष हैं। वह केरल के पिछड़ा एझावा समुदाय के प्रमुख संगठन श्री नारायण परिपालन योगम के उपाध्यक्ष भी हैं। इसी संगठन की राजनीतिक इकाई बीडीजेएस है। खलीज टाइम्स ने बीडीजेएस के स्थानीय सूत्रों के हवाले से बताया है कि वेल्लापल्ली को मंगलवार को यूएई के अजमान में एक होटल से गिरफ्तार किया गया। अजमान पुलिस ने भी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। इसी मामले में बातचीत करने के लिए उन्हें होटल बुलाया गया था। वहीं, केरल से मिली खबर के मुताबिक वेल्लापल्ली को जमानत मिल गई है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले का राजनीति से कुछ लेना-देना नहीं है। यह पूरी तरह से कारोबार से जुड़ा मामला है।

- 19 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में अजमान में हुई गिरफ्तारी
- त्रिचूर के ठेकेदार ने वेल्लापल्ली के खिलाफ दर्ज कराई थी थी शिकायत

केरल के सीएम ने जताई चिंता

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तुषार वेल्लापल्ली की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। पत्र में उन्होंने वेल्लापल्ली की कुशलता को लेकर चिंता व्यक्त की है।

रिपोर्ट के मुताबिक वेल्लापल्ली अजमान में अपनी बोइंग कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएलसी नामक कंपनी के जरिए निर्माण का काम करते थे। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाला त्रिचूर निवासी ठेकेदार भी उनकी कंपनी का सब-कांट्रैक्टर था। 10 साल पहले उन्होंने शिकायतकर्ता की कंपनी को 19 करोड़ रुपये का चेक जारी किया था, जो बाउंस हो गया था। इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई।

मोदी की बिगड़ी तस्वीर प्रोफाइल पर लगाने वाला छात्र निलंबित

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वायरल हुई बिगड़ी हुई तस्वीर लगाने के आरोप में जेल गए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के छात्र को प्रबंधन ने निलंबित कर दिया है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हुई थी। लोगों ने ट्विटर पर एएमयू के खिलाफ तीखी टिप्पणी भी की थी।

कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में लंदन में हुए विरोध प्रदर्शन में विवादित बैनर का इस्तेमाल किया गया था। इसी बैनर को सबसे पहले एएमयू के किशनगंज (बिहार) सेंटर से एमबीए कर रहे मोहम्मद जैद ने फेसबुक प्रोफाइल बनाई थी। जैद अलीगढ़ के हमदर्द नगर डी का रहने वाला है। इसकी शिकायत एएमयू के पूर्व छात्र जट्टारी निवासी राजेश्वर सिंह ने ट्वीट कर पुलिस से की थी। इसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने बुधवार को जैद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बुधवार तक एएमयू पता नहीं कर पाया था कि जैद यूनिवर्सिटी का छात्र ह या नहीं। एएमयू प्रवक्ता प्रो. शाफे किदवई ने बताया कि मोहम्मद जैद को गुरुवार को निलंबित कर दिया गया है। कैंपस में प्रवेश पर रोक भी लगा दी गई है।

छग में 13 लाख के इनामी पांच नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

नईदुनिया, जगदलपुर

पुलिस के बढ़ते दबाव और नक्सली लीडर की तानाशाही के चलते बस्तर संभाग में पांच इनामी नक्सलियों ने फिर आत्मसमर्पण किया है।

इनमें सुकमा में पांच लाख का इनामी नक्सली मेहतर कोर्राम उर्फ रोंडा ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के बीच पहुंच कर आत्मसमर्पण कर दिया। ओडिशा में सक्रिय तीन-तीन लाख के इनामी नक्सली दंपती सोनारू पोयाम और मंजू मंडावी ने आइजी व एसपी के समक्ष सरेंडर किया। वहीं दंतेवाड़ा में एक-एक लाख रुपये के इनामी नक्सली बुधराम मंडावी और सन्नू कुंजाम संगठन छोड़कर मुख्यधारा में लौट आए।

इन सभी को शासन की ओर से 10-10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। नियमानुसार उन्हें अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। 12 बोर रायफल और थ्री नाट थ्री हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने वाला कोर्राम उर्फ रोंडा कुवानार नदी में सुरक्षाबलों पर घात लगाकर हमला करने समेत कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है। समर्पण के बाद उसे मुख्य धारा में लाया जाएगा।

झारखंड के सिमडेगा व खूंटी से पांच उग्रवादी गिरफ्तार

जेएनएन, सिमडेगा : झारखंड में सिमडेगा व खूंटी जिले की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर पीएलएफआइ (पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया) के पांच उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। सिमडेगा की कोलेबिरा पुलिस ने पीएलएफआइ के तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें भाजपा नेता मनोज नागेशिया हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त सह जिला बाल संप्रेक्षण गृह से फरार कैदी जलडेगा के कोलेमडेगा निवासी अनूप टोपनो व कोलेबिरा थाना के झपला, पाकरटोली निवासी रंजीत कंडुलना और आमुस कंडुलना शामिल हैं। खूंटी पुलिस ने भी पीएलएफआइ के दो उग्रवादियों जेवियर सरूकद और रामू सुरीन उर्फ नीसीत सुरीन को गिरफ्तार किया। सिमडेगा एसपी संजीव कुमार ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी अनूप टोपनो से 9 एमएम की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 4 कारतूस बरामद हुए हैं।

छह हवाईअड्डों पर एयर इंडिया के विमानों की ईंधन आपूर्ति रोकी

नई दिल्ली, आइएएनएस : बकाया भुगतान न होने के कारण सरकारी आयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) ने गुरुवार की शाम देश के छह हवाई अड्डों पर एयर इंडिया के विमानों की ईंधन आपूर्ति रोक दी है। इनमें रांची, मोहाली, पटना, विशाखापट्टनम, पुणे और कोचीन हवाईअड्डे शामिल हैं। इंडियन आयल के एक अधिकारी ने कहा, 'हम लोग एयरलाइन के संपर्क में हैं और समस्या का समाधान होने की उम्मीद है।' दूसरी तरफ, एयर इंडिया के एक अधिकारी ने बताया, 'हमने गुरुवार को ओएमसी को 60 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। गतिरोध दूर करने के लिए बातचीत जारी है। विमानों में पर्याप्त ईंधन उपलब्ध है और उम्मीद है कि परिचालन प्रभावित नहीं होगा। फिलहाल, विमानों का ईंधन परिचालन लागत का सबसे बड़ा हिस्सा है।' एयर इंडिया के प्रवक्ता धनंजय कुमार के अनुसार, 'बिना इक्विटी समर्थन के एयर इंडिया कर्ज से नहीं उबर सकती है। हालांकि, वित्तीय प्रदर्शन बेहतर हो रहा है।

'जापान के मंदिर में रखी नेताजी की अस्थियों की हो डीएनए जांच'

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुत्री अनीता बोस फाफ ने गुरुवार को जापानी मंदिर में रखी नेताजी की अस्थियों की डीएनए जांच सुनिश्चित कराने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों पर मामले की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि वे कभी नहीं चाहते थे कि इस रहस्य पर से पर्दा उठे। बोस ने नेताजी की मृत्यु से जुड़े रहस्य को सुलझाने के प्रयासों के लिए पीएम मोदी की सराहना भी की।

अनीता ने कहा कि जब तक कि कुछ और साबित नहीं हो जाता, उन्हें लगता है कि उनके पिता की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हुई थी। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से और जापानी अधिकारियों से भी मिलना चाहती हैं ताकि जापान के रेनकोजी मंदिर में रखी अस्थियों के डीएनए परीक्षण की अनुमति के लिए अनुरोध कर सकें। अनीता ने जर्मनी से कहा, जब तक कुछ और साबित नहीं हो जाए, मुझे विश्वास है कि उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हुई, लेकिन बहुत लोग इसे नहीं मानते। बोस ने कहा, मैं चाहूंगी कि रहस्य सुलझ जाए। रहस्य को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका जापान में मंदिर में रखी अस्थियों का डीएनए परीक्षण करना है। डीएनए परीक्षण से सच साबित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वह केंद्र सरकार के पास रखी गई फाइलों को सार्वजनिक करके रहस्य को सुलझाने के प्रयासों को लेकर धन्यवाद देने के लिए पीएम मोदी से मिलना चाहेंगी। कहा कि वह जापानी अधिकारियों से भी अनुरोध करेंगी कि अगर उनके पास नेताजी से जुड़ी कोई फाइल है तो वे उसे सार्वजनिक करें।

पीआइबी के ट्वीट के बाद दी प्रतिक्रिया

प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआइबी) के एक ट्वीट पर पैदा हुए विवाद के बाद अनीता बोस ने यह टिप्पणी की है। बता दें कि पीआइबी ने 18 अगस्त को ट्वीट कर कहा था कि वह महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी पुण्यतिथि पर याद करता है। हालांकि, नेताजी के परिवार के एक वर्ग द्वारा विरोध किए जाने के बाद इस ट्वीट को हटा लिया गया।

श्रीकृष्ण जन्माअष्टमी की तैयारी

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर देशभर में भारी उल्लास है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। गुरुवार को लाइट से जगमगाता जन्मभूमि मंदिर। सोलह कलाओं से युक्त भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव 23 और 24 अगस्त को मनाया जाएगा। प्रेट्र

बंगाल में हमले की आशंका, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का आवास बदला

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- आतंकी गिरोह को हत्या की सुपारी दिए जाने के इनपुट
- पहले तैनात थे 18 सुरक्षाकर्मी, अब सुरक्षा करेंगे 30 जवान

बंगाल भाजपा के अध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष की जान का खतरा है। उन पर जानलेवा हमले होने की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों ने उनका आवास बदलवा दिया है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले विदेशी आतंकी संगठन उन पर जानलेवा हमला कर सकता है। इस आशंका के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तुरंत आवास बदलने का निर्देश दिया है। दिलीप घोष ने निर्देश का पालन करते हुए बुधवार की रात ही अपना आवास भी बदल लिया। अब तक वह सॉल्टलेक के डीएल ब्लॉक स्थित एक मकान में रहते थे। जहां से बुधवार की रात उनका ठिकाना बदल कर डीएल ब्लॉक में ही एक बड़े मकान में स्थानांतरित करा दिया गया है। यही नहीं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी और कड़ी कर दी गई है। इस बाबत दिलीप घोष ने कहा कि अब तक सॉल्टलेक के जिस बिल्डिंग में रहता था वहां मेरी सुरक्षा में 18 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था। सुरक्षा कर्मी पहले माले पर रहते थे, जबकि मैं दूसरे माले पर रहता था। पर उनके ऊपर जानलेवा हमले की सूचना मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाते हुए सुरक्षा कर्मियों की संख्या 30 कर दी है।

सुरक्षाकर्मियों की बढ़ी संख्या के कारण उस छोटे से आवास में दिक्कतें हो रही थी। इसी कारण आवास बदला गया है, ताकि सभी को एक साथ एक स्थान पर रखा जा सके।

गौरतलब है कि प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनने के बाद दिलीप घोष पर अब तक छोटे-मोटे कई हमले हो चुके हैं। दार्जिलिंग से लेकर पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना जिले में तक में हमले हुए थे। अक्सर ही सत्तारूढ़ तृणमूल पर हमले का आरोप लगता रहा है। उधर, बंगाल में भाजपा की बढ़ती ताकत में दिलीप घोष की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व घोष की सुरक्षा को लेकर कोई कोताही बरतना नहीं चाह रहा है। इसी कारण आनन-फानन में उसकी सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही आवास बदलने का भी निर्देश दिया है।

पहल

हर मंजिल पर होंगे 12 फ्लैट्स, हिंसक जानवरों से बचाने के लिए जमीन से दस फुट ऊंचाई पर बनेगा आशियाना, चोगा, पानी के साथ होगा इलाज का भी प्रबंध

पक्षियों के लिए बनेगा 21 मंजिला मेरा आशियाना

जागरण संवाददाता, सिरसा

सिरसा में जल्द ही पक्षियों के लिए सभी सुविधाओं से युक्त 21 मंजिला मेरा आशियाना का निर्माण किया जाएगा। बेंगलुरु में बनाए गए पक्षियों के आशियाने की तर्ज पर यह उत्तर भारत का पहला आशियाना होगा। पक्षियों का आशियाना जमीन से करीब दस फुट ऊंचा होगा, ताकि कुत्ता, बिल्ली जैसे जानवर पक्षियों को नुकसान न पहुंचा सके। इस भवन में पक्षियों के रहने के लिए 252 कमरे बनेंगे, जिनमें रोशनी, हवा का प्रबंध होगा साथ ही समय-समय पर सफाई भी होगी। आशियाने के नीचे पक्षियों के लिए चोगा पानी का प्रबंध होगा, फव्वारे लगाए जाएंगे ताकि गर्मी के मौसम में पक्षी राहत पा सके। घायल पक्षियों के उपचार की भी सुविधा रहेगी।

बेंगलुरु में पक्षियों का आशियाना देख आया मन विचार : चंद्रयश जैन : रानियां रोड पर स्थित जैन समुदाय के संत जिनदत्त सूरी महाराज के ऐतिहासिक दादाबाड़ी मंदिर में पक्षियों के आशियाने का निर्माण किया जा रहा है। आशियाना प्रोजेक्ट के प्रधान चंद्रयश जैन व महासचिव संदीप नाहटा ने बताया कि जैन धर्म जीवों पर दया करने का संदेश देता है। उन्होंने बेंगलुरु में इस तरह का पक्षियों का आशियाना देखा था, जिसके बाद उन्होंने सिरसा में भी इसे बनाने का निर्णय लिया। अब तक आशियाने की आठ मंजिलें बन चुकी है तथा संभवतः अक्टूबर महीने तक यह बनकर तैयार हो जाएगा।

हर मंजिल में होंगे 12 फ्लैट, हवा और रोशनी का होगा प्रबंध: पक्षियों के लिए बनाए जा रहे मेरा आशियाना जमीन से करीब दस फुट की ऊंचाई पर बनाया जाएगा। 21 मंजिला आशियाने का कुल क्षेत्रफल आठ फुट गुणा आठ फुट तथा ऊंचाई 36 फुट रहेगी। आशियाने की हर मंजिल पर 12 फ्लैट बनेंगे जो एक फुट चौड़े, चार फुट गहरे व पंद्रह इंच ऊंचे होंगे। इस आशियाने में 252 फ्लैट बनेंगे। जिनमें हवा व रोशनी के लिए समुचित प्रबंध है। इनकी सफाई के लिए भी प्रबंध किए गए हैं। अब तक आठ मंजिलें बन कर तैयार हो चुकी है तथा कार्य तेज गति से जारी है।

घायल पक्षियों के उपचार के लिए भी होगी सुविधा : आशियाना में रहने वाले पक्षियों में से अगर कोई घायल हो जाएगा या बीमार हो जाएगा तो उसके लिए चिकित्सक की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही शहर में कहीं भी कोई पक्षी घायल हो जाएगा तो उसके इलाज का भी यहां प्रबंध होगा।

सिरसा में पक्षियों के इस डिजाइन में बनेगा मेरा आशियाना। फाइल फोटो

गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खां ने ली हाई कोर्ट की शरण

विधि संवाददाता, प्रयागराज

रामपुर सांसद आजम खां ने अपने विरुद्ध रामपुर में दर्ज 27 एफआइआर रद करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है।

हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की पीठ ने 29 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की है। आजम पर जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के पक्ष में दर्जनों किसानों की जमीन हड़पने का आरोप है। विपक्षी किसानों की तरफ से अधिवक्ता विजय गौतम व वीके मिश्र ने याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की। इनका कहना था कि 27 प्राथमिकियों को एक याचिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। हर एफआइआर को अलग याचिका में चुनौती दी जानी चाहिए। याचिका पर आजम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रविकिरण जैन, सैयद सफदर अली काजमी व कमरुल हसन सिद्दीकी ने पक्ष रखा। याची का कहना है कि राजनीतिक विद्वेष के चलते उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए गए हैं। याची की पत्नी डॉ. ताजीन फातिमा भी राज्यसभा सदस्य हैं। याची का कहना है कि एमएलसी घनश्याम सिंह ने डीएम की शिकायत मुख्य चुनाव आयुक्त से की है। डीएम अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी फर्जी मुकदमे दर्ज करने में लगे हैं। याची की पत्नी ने भी मुख्य चुनाव अधिकारी से असुरक्षा के भय के चलते सुरक्षा की मांग की है। याची का कहना है कि विश्वविद्यालय 350 एकड़ में फैला है, सारी जमीन ट्रस्ट के नाम खरीदी गई है। प्रशासन के इशारे पर 13 से 20 जुलाई 2019 जुलाई के बीच 26 प्राथमिकियां दर्ज कराई गई है। फिर तीन अगस्त को एफआइआर दर्ज की गई। याची के बेटे अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ भी शिकायत दर्ज है। याचिका में राज्य सरकार के अलावा लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहीं जयाप्रदा, अनंजय कुमार डीएम, अजय पाल शर्मा एसएसपी, एसओ व राजस्व निरीक्षक को पक्षकार बनाया गया है।

पशु चोरी करने आए बदमाशों ने की गोली मारकर युवक की हत्या

जासं, पीलीभीत : उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पशु चोरी करने आए बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मोहनपुर बबूरा गांव निवासी सोनू 21 अगस्त की रात सड़क पर खटपट की आवाज आने पर वह जागे तो देखा कि सामने कुछ बदमाश पशु चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने टोका तो बदमाशों ने सोनू को गोली चला दी, पेट में गोली लगने से सोनू की मौत हो गई।

जनमत
मुद्दा

क्या भारत का बड़ा घरेलू उपभोक्ता बाजार आर्थिक मंदी से लड़ने में कारगर हथियार साबित होगा?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। MUDDA लिखें, स्पेस देकर YES या NO लिखकर 57272 पर भेजें।

Downloaded from: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 23 अगस्त 2019

दैनिक जागरण

प्रेम के बिना जीवन वैसा ही है, जैसे फल-फूल के बिना वृक्ष

चिदंबरम की गिरफ्तारी

आखिरकार पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआइ की गिरफ्त में जाना ही पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि न तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और न ही सीबीआइ की विशेष अदालत से। अच्छा यह होता कि दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद वह खुद को सीबीआइ के हवाले कर देते, लेकिन उन्होंने उसे चकमा देकर छिपना जरूरी समझा। 24 घंटे से अधिक समय तक लापता रहने के बाद उन्होंने कांग्रेस के मुख्यालय में उपस्थित होकर जिस तरह अपनी सफाई पेश की उससे यही जाहिर हुआ कि वह केवल खुद को निर्दोष ही नहीं बताना चाहते थे, बल्कि यह भी प्रकट करना चाहते थे कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। पार्टी दफ्तर में उनकी प्रेस कांफ्रेंस से यह भी साफ हुआ कि खुद कांग्रेस यह संदेश देना चाह रही थी कि वह घपले-घोटाले के गंभीर आरोपों से घिरे पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ है। समस्या केवल यह नहीं कि कांग्रेस के छोटे-बड़े नेता चिदंबरम का बचाव कर रहे हैं, बल्कि यह है कि वे उन्हें क्लीनचिट भी दे रहे हैं। आखिर जो काम अदालत का है वह कांग्रेसी नेता क्यों कर रहे हैं? आखिर उनके मामले में अदालत के फैसले मान्य होंगे या फिर कांग्रेसी नेताओं के वक्तव्य? एक सवाल यह भी है कि सीबीआइ से लुका-छिपी का खेल खेलकर चिदंबरम को क्या हासिल हुआ? आखिर उन्होंने पार्टी दफ्तर में प्रेस कांफ्रेंस करने के बाद अपने घर जाकर दरवाजा बंद कर लेना जरूरी क्यों समझा? क्या यह अच्छी बात है कि देश के पूर्व गृह मंत्री, राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वकील को हिरासत में लेने के लिए सीबीआइ अफसरों को उनके घर की दीवार फांदनी पड़ी?

चूंकि सीबीआइ के बाद प्रवर्तन निदेशालय को भी चिदंबरम से पूछताछ करनी है इसलिए उन्हें लंबे समय तक जांच एजेंसियों से दो-चार होना पड़ सकता है। पता नहीं आइएनएक्स मीडिया घोटाले में चिदंबरम की क्या और कैसी भूमिका है, लेकिन यह उनके अपने हित में है कि इस मामले का निस्तारण जल्द हो। यह तभी होगा जब वह जांच में सहयोग करेंगे। मामले का जल्द निस्तारण जांच एजेंसियों के साथ ही अदालतों को भी सुनिश्चित करना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि आम तौर पर नेताओं के मामलों में जांच के साथ ही अदालती कार्यवाही भी लंबी खिंचती है। निःसंदेह ऐसा इसलिए भी होता है, क्योंकि घपले-घोटाले से घिरे नेता बड़ी आसानी से अदालत-अदालत खेलते रहते हैं। क्या यह सहज-सामान्य है कि चिदंबरम को बार-बार अग्रिम जमानत मिलती रही? क्या ऐसी ही सुविधा आम लोगों को भी मिलती है? बेहतर हो कोई यह सुनिश्चित करे कि रसूख वालों के मामलों का निस्तारण एक तय समय में हो।

डेंगू का डंक

उत्तराखंड में डेंगू थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका दायरा तेजी से बढ़ रहा है। यह स्थिति स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रही है। भले ही विभाग इसमें कितनी भी सक्रियता का दावा कर रहा हो, लेकिन जिस तरह से इसका प्रकोप बढ़ रहा है, उससे यह साफ है कि डेंगू पर रोकथाम का काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। चिंता की एक बात अब और निकल कर सामने आ रही है और वह यह कि डेंगू अब खतरनाक होने लगा है। शुरुआत में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह ही हो रहा था, लेकिन अब इससे लोगों को लिवर और श्वास संबंधी दिक्कतें होने लगी हैं। यह स्थिति सही नहीं कही जा सकती। दरअसल बीते एक माह के आंकड़ों को उठा कर देखें तो प्रदेश में अब तक डेंगू के 493 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 319 पुरुष और 174 महिलाएं शामिल हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। यह हालत तब है जब डेंगू को लेकर विभाग महीनों पहले से कार्ययोजना तैयार करने में जुटा हुआ था। जगह-जगह फॉगिंग कराने का दावा भी किया गया। बावजूद इसके डेंगू का लगातार बढ़ना विभागीय तैयारियों पर सवाल उठा रहा है। अब स्थिति यह हो गई है कि सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्लेटलेट्स कम पड़ने लगे हैं। इसकी कमी को पूरा करने में स्वास्थ्य महकमे के पसीने छूट रहे हैं। तिमारदारों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी और अव्यवस्था दुश्वारियां और बढ़ा रही है। डेंगू के प्रकोप में जो एक बात प्रमुख रूप से सामने आई है, वह यह कि विभाग इस बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक करने में नाकाम रहा है। यह इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि जहां भी स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे पर जा रही है, वहां उन्हें डेंगू के लार्वा मिल रहे हैं। डेंगू के लार्वा को पनपने के लिए के लिए टंकियों और कूलरों में रुका पानी सबसे अधिक मुफीद रहता है और ऐसा ही सर्वे के दौरान देखने को मिल रहा है। सरकार एवं विभाग को अब डेंगू पर रोकथाम के लिए फॉगिंग और सफाई कराने के साथ ही व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। सामूहिक प्रयास से ही डेंगू पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सरकार को इस बार के अनुभव को देखते हुए भविष्य में डेंगू से निपटने को और अधिक कारगर कदम उठाने की जरूरत है।

मजबूत इच्छाशक्ति से बदलाव लाते मोदी

अमित शाह

मोदी सरकार की कार्य पद्धति का मूल्यांकन करें तो ऐसे अनेक कदम नजर आएंगे, जिन पर कभी किसी सरकार ने कदम उठाना तो दूर, सोचा तक नहीं था

अवधेश राजपूत

आजादी के बाद हुए 17 लोकसभा चुनावों में देश ने 22 सरकारें और 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। निःसंदेह इन सभी सरकारों ने राष्ट्र निर्माण में अपने विवेक के अनुसार कुछ न कुछ किया, परंतु ऐसी सरकारें विरली रहीं जो दूरगामी परिणाम लाने वाले काम कर सकीं। अपने 55 वर्षों के शासन में कांग्रेस को आठ बार पूर्ण बहुमत वाला जनादेश मिला, लेकिन उसने शायद दस काम भी ऐसे नहीं किए जिनसे देश को निर्णायक दिशा मिली हो। हालांकि वाजपेयी सरकार ने अल्पकाल में कई बड़े काम करने के प्रयास किए, परंतु बहुमत के अभाव में उनका प्रभाव सीमित रहा। देश में पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में परिवर्तन की जो बयार बहती दिख रही है उसके पीछे मजबूत नेतृत्व और विकासोन्मुख नीतियां हैं। मोदी सरकार ने अब तक के अपने कार्यकाल में ही दर्जनों ऐसे काम किए हैं जिनसे न केवल सामान्य जन के जीवन-स्तर में गुणात्मक सुधार आया है, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा भी विश्व में फिर से स्थापित हुई है। मोदी जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अतुलनीय दृढ़ इच्छाशक्ति है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण राज्यसभा में संख्याबल न होने के बावजूद अनुच्छेद-370 और 35-ए को समाप्त करना रहा। इन दोनों अनुच्छेदों के कारण कश्मीर देश की विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया जिससे वहां आतंकी और अलगाववादी शक्तियां फल-फूल रही थीं। आतंकी हिंसा से 41 हजार कश्मीरी मौत का शिकार हुए, केंद्र से भेजी जाने वाली विकास की राशि गिने चुने लोगों की जेब भरती रही और कई पीढ़ियां गरीबी और अशिक्षा का दंश झेलती रहीं। तुष्टीकरण की राजनीति और इच्छाशक्ति की कमी के कारण किसी भी नेता या सरकार ने जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद-370/35-ए से मुक्ति दिलाने का साहस नहीं किया। यह एक देश एक संविधान के सपने को पूरा करने की मोदी जी की मजबूत इच्छाशक्ति ही थी कि जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद-370/35-ए से मुक्ति मिल सकी।

यह भी मोदी जी की दृढ़ इच्छाशक्ति ही है कि वह विषम राजनीतिक परिस्थितियों में भी अनेक कठिन फैसले ले सके। कभी असंभव से दिखने वाले सर्जिकल एवं एयर स्ट्राइक जैसे फैसले लेना मोदी जी को देश का अब तक का सबसे मजबूत इच्छाशक्ति वाला प्रधानमंत्री साबित करता है। स्वतंत्रता के बाद देश की सरकारें अमीर-गरीब, शहर-गांव, कृषि-उद्योग जैसे अनेक विरोधाभासों से ग्रस्त रहीं। कुछ शक्तियों ने ऐसा वैचारिक वातावरण बना दिया था जिससे ये भ्रामक द्वंद्व देश के विकास में एक बड़ी बाधा बन गए। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तत्काल इस द्वंद्व को खत्म किया। अमीर और गरीब की खाई पाट कर सबको एक साथ लेकर चलने की नीति प्रधानमंत्री मोदी के इस कथन से स्पष्ट होती है कि देश में सिर्फ दो वर्ग हैं, एक गरीब और दूसरा गरीबी हटाने वाला।

मोदी सरकार की नीतियों में गरीबों के कल्याण के प्रति चिंता और अन्तोदय का भाव स्पष्ट नजर आता है। सामान्य जन के जीवन में बदलाव लाना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। जनधन, मुद्रा, सौभाग्य, स्वच्छ भारत, श्रमयोगी मानधन पेंशन, किसान पेंशन और लघु व्यापारी मानधन जैसी दर्जनों योजनाओं के माध्यम से सरकार ने आमजन के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें सामाजिक-आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें नीम कोटेड यूरिया लाना, समर्थन मूल्य में डेढ़ गुना वृद्धि, समर्थन मूल्य दायरे का विस्तार, यूरिया सब्सिडी में वृद्धि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना आदि प्रमुख हैं। तीन तलाक उन्मूलन, उज्ज्वला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, मातृत्व अवकाश में वृद्धि जैसे निर्णयों के जरिये भी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। मोदी सरकार का मानना है कि व्यवसायी के विकास के बिना गरीबों का कल्याण संभव नहीं है। मोदी जी ने वेल्थ क्रिएटर के महत्व को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया है। चरमराई बैंकिंग प्रणाली के पुनरुत्थान, भ्रष्टाचार पर प्रहार के कानून, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, कानूनों के सरलीकरण, जीएसटी इत्यादि जैसे अनेक प्रयास व्यापार को सुगम बना रहे हैं और भारत आज सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन कर पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। करदाताओं की संख्या और कर प्राप्ति में जिस तरह वृद्धि हुई है वह मोदी सरकार पर विश्वास और देश के विकास में भागीदारी का प्रतीक है।

पाकिस्तान की आतंकी नीतियों का जवाब देने के लिए जब देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की तब एक तरफ दुनिया के प्रभावी देश भारत के साथ थे तो वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क अलग-थलग पड़ा हुआ था। कश्मीर के मुद्दे पर भी स्थिति वही है। विश्व पटल पर भारत की ऊंची होती साख का एक और उदाहरण अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हमारे सामने है। प्रधानमंत्री मोदी पर्यावरण के मुद्दे पर विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। आज भारत अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का नेतृत्व कर रहा है। चंद्रयान के सफल प्रक्षेपण और एक बार में सर्वाधिक सेटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने के कीर्तिमान ने भी देश का अंतरराष्ट्रीय गौरव बढ़ाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति मोदी सरकार की मंशा और नीति, दोनों स्पष्ट हैं। जहां सेना के आधुनिकीकरण का काम जारी है वहीं अंतरिक्ष में एंटी सेटेलाइट मिसाइल के सफल परीक्षण से स्पष्ट होता है कि राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर यह सरकार जल, थल और नभ के साथ-साथ अंतरिक्ष तक जुटी हुई है। सेना के तीनों अंगों में समन्वय के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाने का फैसला भी ले लिया गया है। मोदी सरकार ने सैनिकों की वर्षों से लंबित ओआरओपी की मांग को भी पूरा करके उनके मनोबल को बढ़ाया।

मोदी सरकार की कार्य पद्धति का बारीकी से मूल्यांकन करें तो ऐसे अनेक कदम नजर आएंगे, जिन पर कभी किसी सरकार ने कदम उठाना तो दूर, सोचा तक नहीं था। नरेंद्र मोदी ने सत्ता की परवाह किए बगैर देशहित को ध्यान में रखते हुए कठिन और मूलभूत परिवर्तन लाने वाले साहसिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने ऐसे फैसले लिए जो आमजन के हित में हों और जरूरी नहीं कि वह लोक लुभावने और देखने में अच्छे लगने वाले हों। इस सरकार ने सिद्ध किया है कि जब देशहित में कठिन निर्णय लिए जाते हैं तो जनता भी समर्थन देने में पीछे नहीं हटती। इसका सबसे ज्वलंत प्रमाण 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी का 2014 के जनादेश से बड़े जनादेश के साथ दोबारा प्रधानमंत्री बनना है।

(लेखक केंद्रीय गृहमंत्री हैं)

response@jagran.com

अनुदारता से भरे उदारवादी

प्रो. निरंजन कुमार

हमारे तथाकथित लिबरल तो सही मायने में उदारवादी हैं ही नहीं, वास्तव में वे छद्म उदारवादी हैं

आजादी के बाद से ही बौद्धिक-अकादमिक और विश्वविद्यालयी विमर्शों में लेफ्ट-लिबरल यानी वामपंथियों-उदारवादी बुद्धिजीवियों का एकाधिकार रहा है जिन्होंने शिक्षा-ज्ञान, पाठ्यक्रमों और बौद्धिक विमर्शों में एक खास एजेंडा के तहत उसके स्वरूप को एक तरह से अ-भारतीय कर दिया। पिछले कुछ समय से वामपंथियों की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी है, लेकिन तथाकथित उदारवादियों का कब्जा बरकरार है। वामपंथियों-उदारवादियों के बरक्स एक वैकल्पिक भारतीय मॉडल स्थापित करने की कोशिश को ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई। इसका एक बड़ा कारण है भारतीय मॉडल की वकालत करने वालों में विजन का अभाव। इसकी वजह से वे वामपंथियों-उदारवादियों के बनाए सैद्धांतिकी एवं पारिभाषिक शब्दावलियों के भ्रमजाल में ही फंस कर रह जाते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है उनकी वैचारिक शब्दावली लिबरल और लिबरलिज्म।

यूरोप में उदारवाद की सैद्धांतिकी का उदय सामंतवाद के पतन के साथ हुआ जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और सहिष्णुता आदि की वकालत की गई। ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक उदारवाद के जनक माने जाते हैं। आगे चलकर जेएस मिल, टीएच ग्रीन आदि के प्रभाव से उदारवाद के अंतर्गत तर्कबुद्धि और विवेकशीलता, बहुलतावाद के साथ-साथ कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को भी शामिल किया गया। पश्चिमी परिवेश में उपजे उदारवाद (लिबरलिज्म) के भारतीय प्रवक्ता अपनी मान्यताओं-सिद्धांतों का विरोध करने वालों को अनुदारवादी एवं संकीर्ण मानते हैं। विडंबना यह है कि उनकी इस मान्यता को भारतीय या राष्ट्रवादी मॉडल के विचारक भी स्वीकार कर बैठे हैं। एक तरफ तथाकथित लिबरलिज्म का मॉडल है जो कथित तौर पर श्रेष्ठ है, दूसरी तरफ भारतीय चिंतन-परंपरा है जो अनुदार एवं संकीर्णतावादी और इसलिए निम्नतर है। यह समझ न सिर्फ भ्रामक है, बल्कि भारतीय चिंतन-परंपरा के लोगों में एक हीनभावना का संचार करती है। यहां सवाल पूछना चाहिए कि क्या तथाकथित भारतीय लिबरल सचमुच उदारवादी हैं? क्या भारतीय मॉडल के विचारक अनुदार एवं संकीर्णतावादी हैं?

स्वतंत्र अभिव्यक्ति उदारवाद का प्रमुख लक्षण है। इस चीज को पश्चिम से आक्रांत भारतीय लिबरल विचारक ऐसे गौरवान्वित करते हैं जैसे वे एक नई-अनोखी अवधारणा प्रस्तुत कर रहे हों। पश्चिम में यह जरूर अनोखा था, जहां सामंती और चर्च व्यवस्था ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्राचीनकाल में जहां तरुणों को बिगाड़ने और नास्तिकता का आरोप लगाकर सुकरात को जहर दे दिया गया था, वहीं 1633 में वृद्ध गैलीलियो को उनकी मान्यताओं के कारण चर्च की ओर से कारावास दिया गया था, जबकि भारतीय समाज में अभिव्यक्ति की आजादी की सुदीर्घ प्राचीन परंपरा है। आदिग्रंथ ऋग्वेद में कहा गया है कि हम सब एक साथ आएं, आपस में बात करें, एक-दूसरे को समझें। यही आचरण वंदनीय और श्रेष्ठ है।

इसी तरह वैदिक 'न्याय दर्शन' में विचार-विमर्श के सूत्रों में 'वाद', 'जल्प' और 'वितंडा' का उल्लेख है जो संवाद-विवाद के विभिन्न रूप हैं। हमारे शास्त्रार्थ, खंडन-मंडन की परंपरा में स्त्रियों की भी सक्रिय भूमिका थी। याज्ञवल्क्य एवं गार्गी अथवा आदि शंकराचार्य एवं भारती के बीच हुए शास्त्रार्थ जगप्रसिद्ध हैं। ऐसे में भारतीय चिंतन परंपरा को क्या माना जाए उदारवादी अथवा अनुदारवादी? जहां पश्चिम और पश्चिम-परस्त तथाकथित भारतीय उदारवादियों के बहुत पहले प्राचीन काल से ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या वाद-संवाद की प्रतिष्ठा है। वहीं दूसरी तरफ तथाकथित भारतीय उदारवादियों और उनके वामपंथी सहचरों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दोहरे मानदंड की कलई तब खुल जाती है जब एमएफ हुसैन के प्रतिबंध पर तो वे हो-हल्ला मचाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तसलीमा नसरीन के मुद्दे पर मौन साध लेते हैं।

उदारवाद का अन्य लक्षण है व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो व्यापक अर्थ में व्यक्ति की पूर्ण सत्ता की प्रतिष्ठा है। दिलचस्प है कि यूरोप में व्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रतिष्ठा के जो स्वर 17वीं-18वीं सदी में जाकर उठे, उसके बरक्स भारतीय परंपरा में व्यक्ति की प्रतिष्ठा या आजादी का उद्घोष प्राचीन काल से है। वृहदारण्यक उपनिषद का महावाक्य 'अहं ब्रह्मास्मि' अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, की व्याख्या व्यक्ति और व्यक्ति-स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा है, जहां व्यक्ति में ही ईश्वर का निवास मान लिया गया है। इसी तरह शास्त्रों में उल्लिखित वाक्य 'यत् पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे' अर्थात जो ब्रह्मांड (संसार) में है वही पिंड (मनुष्य) में भी है। बहुलतावाद भी उदारवाद का एकमहत्वपूर्ण लक्षण है, लेकिन विसंगति यह है कि आजादी के बाद से शिक्षा-ज्ञान और पाठ्यक्रमों से लेकर बौद्धिक-सांस्कृतिक विमर्शों में इस बहुलतावाद को ढूंढा जाए तो एक निराशा होती है। इन सबमें भारतीय परिप्रेक्ष्य और भारतीय दृष्टिकोण शायद ही कहीं नजर आता हो। मिसाल के तौर पर पश्चिमी चश्मे के प्रभाव में हम कालिदास को भारत का शेक्सपीयर और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, जबकि कालक्रम, प्रतिभा और उपलब्धि में दोनों भारतीय ऊपर हैं। यहां तथाकथित भारतीय लिबरल अनुदारवादी दिखाई पड़ते हैं। एक विडंबना यह भी है कि हमारे तथाकथित बुद्धिजीवियों को बहुलतावाद का सबक पश्चिम में ही दिखाई पड़ता है, जबकि ऋग्वेद के 'एकं सत् विप्राः बहुधा वदंति' अर्थात सत्य एक है, परंतु ज्ञानी उसे विभिन्न तरीकों से व्याख्या करते हैं, से बड़ा बहुलतावाद का संदेश और क्या होगा? वायु पुराण में उल्लिखित है 'मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना' और 'नवा वाणी मुखे मुखे' अर्थात जितने मनुष्य हैं, उतने विचार हैं। एक ही घटना का बयान हर व्यक्ति अपने-अपने तरीके से करता है।

तर्कबुद्धि और विवेकशीलता उदारवाद का एक अन्य लक्षण है। उदारवादी किसी भी समस्या को अड़ियल या पूर्वाग्रह नजरिये से नहीं देखता। इस कसौटी पर तथाकथित भारतीय उदारवादी फिर बेनकाब हो जाते हैं। इसका उदाहरण तीन तलाक और फिर कश्मीर के मसले पर उनके कुतर्कों में देखा जा सकता है। पश्चिमी कसौटियों पर भी भारतीय चिंतन पद्धति पूर्ण उदारवादी है। हमारे तथाकथित लिबरल तो सही मायने में उदारवादी हैं ही नहीं, वे छद्म उदारवादी हैं। असली लिबरल तो भारतीय चिंतन है।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सतर्कता

जब भी कभी हमारा कोई प्रिय एक-दो दिन की यात्रा पर जाता है, तब हम यात्रा के दौरान उसे बार-बार सतर्क रहने के लिए कहते हैं। उसे यह बताते हैं कि वह यात्रा के दौरान किसी भी अपरिचित से मेल न करे, किसी का दिया हुआ खाए नहीं और किसी अपरिचित के साथ कहीं अज्ञात स्थान पर भी न जाए। यह सब हम तब कहते हैं, जब जाने वाले का गंतव्य स्थान निश्चित होता है। यात्रा अल्पकालिक होने के साथ ही साथ यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति के लौटने का समय भी निश्चित होता है। व्यवहार-दृष्टि से इसे नकारा नहीं जा सकता और ऐसा करना अनुचित भी नहीं है, किंतु जीवन-व्यवहार में हम अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहते हुए यह भूल जाते हैं कि मनुष्य की जीवन यात्रा केवल इसी लोक तक सीमित नहीं है, अपितु इसे एक न एक दिन अपना शरीर छोड़कर उस अनंत यात्रा पर निकलना है, जिस यात्रा का न तो आरंभ करने का समय निश्चित होता है, न यह जानकारी होती है कि यात्रा करने वाले को जाना कहां है, किससे मिलना है, वहां पहुंचकर क्या करना है, लौटकर आना भी है अथवा नहीं आना है। जाने का रास्ता भी ज्ञात नहीं होता और साथ में किसी तरह का सामान भी नहीं होता।

यह सब देख-सुनकर ही शास्त्र और शास्त्रकार कहते हैं कि लोक जीवन की सभी यात्राओं में सतर्क रहते हुए हमें अपने परलोक जीवन की यात्रा के लिए भी सतर्क रहना चाहिए और यह विचार करते रहना चाहिए कि उस यात्रा पर जाने के लिए हम कैसी तैयारी करें, क्योंकि उस यात्रा में इस संसार की कोई भी सामग्री हमारे साथ नहीं जाएगी और न ही कोई हमारा प्रिय से प्रियतम भी हमारे साथ जा सकेगा। इतना ही नहीं, हमारा अपना यह शरीर भी हमें यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। यह यात्रा केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, अपितु जीवमात्र के लिए अनिवार्य है। इसी कारण ऋषियों ने कहा है कि मनुष्य! अपने जीवन में धर्म का आचरण करो, क्योंकि शरीर के अंत के बाद उस अनिवार्य अनंत यात्रा पर केवल धर्म ही साथ जाता है और वही कल्याणकर होता है।

डॉ. गदाधर त्रिपाठी

पर्यटन से खुलेगी रोजगार की राह

सौरभ सिंह

पर्यटन देश को राजस्व तो प्रदान करता ही है, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर कहा कि साल 2022 तक प्रत्येक देशवासी को कम से कम 15 पर्यटक स्थलों पर जाना चाहिए। इस तरह उन्होंने घरेलू पर्यटकों को अपने यहां के महत्वपूर्ण स्थलों को देखने-समझने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है। देखा जाए तो पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जो देश को राजस्व तो प्रदान करता ही है साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अनेक अवसर भी उपलब्ध कराता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पर्यटन का 9.6 फीसद योगदान है। इसका 88 फीसद घरेलू पर्यटन से प्राप्त होता है। देश के कुल रोजगार अवसरों में से 9.3 फीसद पर्यटन के माध्यम से ही आते हैं। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2028 तक इस उद्योग के माध्यम से वर्तमान में उत्पन्न होने वाले 42.9 करोड़ रोजगार के अवसरों की तुलना में 52.3 करोड़ रोजगार उत्पन्न होंगे। वैश्विक स्तर पर पर्यटन एक बड़ा उद्योग है। यह कई क्षेत्रों में अवसर सृजित करता है। बड़े पैमाने पर नौकरियां प्रदान करता है।

भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति के चलते इसे अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। हालांकि इस दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, जिसके कारण 2016 में पूरे विश्व में पर्यटन की 4 फीसद वृद्धि की तुलना में भारत में यह 9.7 फीसद दर्ज की गई। वर्ष 2017 में लगभग 1.4 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत आए, जबकि 2014 में यही आंकड़ा 76.8 लाख था। इसके बावजूद भारत इस मामले में अभी भी कई देशों से पीछे है। जैसे कि चीन विश्व पर्यटन के आकर्षण का केंद्र माना जाने लगा है। वर्ष 2010 में चीन ने पर्यटन के जरिये 4580 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए। विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले देशों में चीन चौथे स्थान पर रहा है। इसी प्रकार यूरोप में स्विट्जरलैंड छोटा सा खूबसूरत देश है उसकी जनसंख्या से अधिक तो वहां पर्यटक ही आते रहते हैं। वहां के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन उद्योग 2.9 फीसद का योगदान रहता है।

जाहिर है आज भारत में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्य योजना की दरकार है। आज जब सरकार पर्यटन उद्योग को प्राथमिकता दे रही है तो इसके लिए सबसे पहले उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए कुछ समय तक वीजा शुल्क माफ किया जाना चाहिए। साथ ही तटीय क्षेत्रों में पर्यटन के उद्देश्य से विशेष परियोजनाएं लाने की आवश्यकता है। होटलों पर टैक्स की दरें तर्कसंगत बनाई जानी चाहिए। पर्यटन को बढ़ावा मिल सके इसके लिए निजी क्षेत्र से भी सामंजस्य बैठाना चाहिए। पर्यटन स्थलों तक आने जाने और वहां ठहरने की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। पर्यटकों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत में पर्यटक स्थलों की कमी नहीं है। इनको विश्व पटल पर उभारने की दरकार है। एक बार जब घरेलू पर्यटक वहां जाने लगेंगे तब विदेशी पर्यटकों में भी उनके प्रति दिलचस्पी बढ़ेगी। उम्मीद है पीएम मोदी की मुहिम जल्द ही रंग लाएगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी

राष्ट्रीय समृद्धि से जुड़ा है जनसंख्या नियंत्रण शीर्षक से लिखे अपने लेख में हृदयनारायण दीक्षित ने देश की बढ़ती जनसंख्या पर जो चिंता व्यक्त की है, वह राष्ट्रहितैषी है। दुनिया के कई देश जहां जनसंख्या नियंत्रण के प्रति सचेत रहकर कारगर कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। जिसका परिणाम आज जनसंख्या विस्फोट के रूप में देश के सामने है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की बढ़ती जनसंख्या पर जो चिंता व्यक्त की है, वह इस दृष्टि से उचित है कि राष्ट्र के समेकित विकास में बाधक बनने वाली जनसंख्या वृद्धि को यदि समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो तमाम संसाधनों और उपायों के बाद भी भारत को विकसित राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि देश के सीमित संसाधन जब बढ़ती जनसंख्या की न्यूनतम आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति में ही व्यय हो जाएंगे तो विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कैसे संभव है? फिर राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर होने वाले भारी-भरकम व्यय की आपूर्ति कैसे होगी? इसके लिए यदि राष्ट्रीय उत्पाद और व्यक्तिगत आय पर कर का बोझ बढ़ाया जाएगा तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में यह जरूरी है कि देश का आम जन-मानस स्वतः प्रेरित होकर प्रजनन दर को कम करने में सहयोगी बने। क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से जो नसबंदी कार्यक्रम चलाया था, उससे उपजे जनाक्रोश ने इसकी उपयोगिता को नकारात्मकता में बदल दिया था। जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाया गया यह प्रयास विफल हो गया था। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की प्रोत्साहन नीति लागू करके स्वतः प्रेरणा से प्रजनन दर को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

pandeyvp1960@gmail.com

आतंक है कश्मीर की समस्या

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि कश्मीर में मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रहना चाहते, यह बयान भ्रामक तथा यथार्थ से हटकर है। ट्रंप को मालूम होना चाहिए कि भारत के अनेक भागों में हिंदू एवं मुसलमान सदियों से एक साथ रह रहे हैं। यदाकदा कभी किसी इलाके में भले ही विवाद हो जाए, वरना दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे के तीज-त्योहार में शामिल होते हैं। एक दूसरे की मदद भी करते हैं। कश्मीर में तो बहुत थोड़े से मुसलमान हैं, बाकी राज्यों में तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। लोगों का एक साथ उठना-बैठना है। कश्मीर की समस्या हिंदू-मुसलमान नहीं हैं। वहां की समस्या पाकिस्तान है, जो वहां के कुछ लोगों को बरगलाकर आतंक को बढ़ावा दे रहा है।

आमोद शास्त्री, दिल्ली

मोदी का सारगर्भित भाषण

प्रधानमंत्री मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से देश की जनता के नाम जो संदेश दिया वह सारगर्भित एवं प्रभावशाली था। उन्होंने अपने भाषण में एनडीए सरकार के 10 सप्ताह के कार्यकाल के महत्वपूर्ण निर्णयों से जनता को अवगत करवाया। उन्होंने अपने भाषण में अधोसंरचना गत विकास और एक चुनाव जैसे मुद्दों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। छोटे परिवार की महत्ता पर जोर देते हुए उन्होंने देशवासियों से इसे अपनाने की अपील भी की। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए उन्होंने प्लास्टिक मुक्त भारत की परिकल्पना पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की बात की और जल संरक्षण पर भी गौर किया। देशवासियों को राष्ट्रहित में अपना दायित्व निभाते हुए छोटे परिवार, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल भुगतान एवं जल संरक्षण के प्रति जागरूक होकर पहल करते हुए इन्हें अपनाना चाहिए।

lalit.mahalkari@gmail.com

अर्थव्यवस्था में सुधार

वर्ष 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन डॉलर तक कैसे हो पाएगी? कायदे में उद्योगों के लिए पहले से आ रही कठोर शर्तों और नियमों में शिथिलता लानी होगी और उन्हें आसान बनाना होगा, जिससे एक प्रशिक्षित इंजीनियर कम लागत में भी खुद एक छोटा-मोटा उद्योग स्थापित करके कुछ प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार दे सके।

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

70 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं भारत में वाहन चालकों द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण होती हैं, जबकि लगभग 10 प्रतिशत दुर्घटनाएं वाहनों की तकनीकी खामी के चलते होती हैं। छह प्रतिशत मौसम की खराबी के कारण और चार प्रतिशत के लिए खराब सड़कें जिम्मेदार हैं।

आजकल

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की तैयारी

भारत में लगातार बढ़ते वाहनों के बीच हादसों पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा को राष्ट्रीय चिंता का विषय मानते हुए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 में कड़े प्रावधान किए हैं। इस अधिनियम में खतरनाक ढंग से वाहन चलाने, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बैठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है

कैलाश बिश्नोई
अध्येता,
दिल्ली विश्वविद्यालय

दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क वाले देश भारत में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं वाहन चालकों की लापरवाही और चूक तथा नियम-कायदों की अनदेखी की वजह से होती हैं। इस गलती के पीछे शराब का सेवन सबसे प्रमुख कारण है। देश में 70 फीसद दुर्घटनाएं वाहन चालकों की लापरवाही से होती हैं। करीब 10 फीसद दुर्घटनाएं वाहनों की तकनीकी खराबी के कारण, छह फीसद खराब मौसम के कारण और शेष चार फीसद के लिए खराब सड़कें जिम्मेदार हैं। जाहिर है कि वाहन चालकों की लापरवाही इन दुर्घटनाओं में सबसे अहम है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि देश का तकरीबन पूरा यातायात महकमा भारी भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। विकसित देशों के बारे में कहा जाता है कि वहां ड्राइविंग लाइसेंस लेना डिग्री हासिल करने जैसा काम होता है। जबकि अपने यहां भ्रष्ट व्यवस्था में यह संभव है कि बुनियादी शर्तों को पूरा किए बिना भी लाइसेंस मिल जाए। बल्कि यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तमाम नियमों को दरकिनार करते हुए हमारे यहां लोगों को आसानी से लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी नियमों को और सख्त बनाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें लाइसेंसिंग प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी की शुरुआत करके कई चुनौतियों का समाधान किया गया है।

तकनीकी खामी दुरुस्त करने पर जोर : भारत में सड़क दुर्घटनाओं की प्रमुख वजहों में एक यह भी है कि तकनीकी खराबी के बावजूद वाहन का इस्तेमाल होता रहता है। लेकिन अब संशोधित अधिनियम में अंतरराष्ट्रीय मानकों को लागू करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई वाहन तकनीकी या यांत्रिक रूप से खराब निकलता है तो संबंधित निर्माता कंपनी को उसे वापस मंगाना होगा। नए वाहनों की जांच प्रणाली को बदल कर और दुरुस्त किया जाएगा। टायर कंपनियों पर भी नकेल कसने की बात है। अगर गाड़ी या टायर की खराबी की वजह से कोई हादसा होता है तो संबंधित कंपनियां जिम्मेदार होंगी। इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण वाली कंपनियों पर भी शिकंजा कसा गया है। खराब सड़कों की वजह से अगर कोई हादसा होता है तो इस पर वर्तमान में सड़क बनाने वाले इंजीनियरों की कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन इस संशोधन में उन्हें भी कानून के दायरे में लाया जा रहा है और उन पर भारी जुर्माने की व्यवस्था की जा रही है।

यातायात नियमों का सख्ती से पालन : सड़क हादसों का एक अन्य कारण बहुत आम है और वह है यातायात नियमों की अनदेखी की प्रवृत्ति। केंद्र सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम में भारी जुर्माना लगाने की व्यवस्था की है। इस विधेयक में यातायात से जुड़े कुछ नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने के तौर पर एक लाख रुपये तक का भुगतान करना पड़ सकता है। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा और उस पर 25,000 रुपये जुर्माने के साथ तीन साल की जेल और वाहन का पंजीकरण भी रद हो सकता है। इसके अलावा बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाना शामिल है। इस मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 में ऐसे सभी कदम उठाए गए हैं, जिससे सड़क हादसों में निश्चित रूप से कमी आ सकती है। बस जरूरत इस बात की है कि इन उपायों को सख्ती से लागू किया जाए।

बीमा और मुआवजा : मोटर वाहन संशोधन अधिनियम का एक प्रावधान तीसरे पक्ष के बीमा के बारे में भी है, जिसमें मुआवजे की राशि बढ़ाई गई है ताकि हादसा होने पर प्रभावित पक्ष को राहत पहुंचाई जा सके। इस बारे में बीमा कंपनियों और गाड़ी मालिकों की ईमानदारी को भी कायम करने की जरूरत है, क्योंकि बीमा के तहत कई बार जरूरतमंद लोग मुआवजा नहीं उठा पाते, जबकि पहुंच वाले लोग मामूली हादसे में भी भारी राशि वसूल लेते हैं। यह कार्य तभी संभव है जब सरकार और बाजार की कार्यप्रणाली में काम करने की जवाबदेह और पारदर्शी संस्कृति का विकास हो।

संशोधन अधिनियम का एक पहलू यातायात के नियमों के उल्लंघन पर कठोर दंड देने से भी जुड़ा है। क्या नियम कड़े कर देने से लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे? क्या कानून लागू करने वाली एजेंसियों का सामर्थ्य इतना है कि वे देश की सभी सड़कों के हर बिंदु पर कानून लागू करवाने के लिए उपलब्ध हो सकें? हालांकि इन सवालों के जवाब अनुत्तरित हैं। लोगों को लगता है कि वे पैसे देकर छूट जाएंगे। लोग दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की मदद के लिए आगे नहीं आते, क्योंकि पुलिस उन्हें तरह-तरह से परेशान करती है। यह संकट दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों में समन्वय आवश्यक है। उन्हें नियमों का सख्ती से पालन कराना होगा और लोगों को जागरूक बनाना होगा। आम लोगों से इस भय को दूर करना होगा कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने से पुलिस उन्हें परेशान नहीं करेगी।

इसके अलावा इंजीनियरिंग पहलू को देखें तो यह रोड के डिजाइन तथा सड़क पर यातायात प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इस पहलू का पूर्व के कानून में विस्तृत रूप से प्रावधान नहीं किया गया है। किंतु इस संशोधित अधिनियम में रोड डिजाइनर, कंसल्टेंट्स तथा स्टेकहोल्डर एजेंसी को डिजाइन तथा ऑपरेशन के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। निश्चित रूप से इस अधिनियम से सड़कों को और अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक मजबूत पक्ष नागरिकों का राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को समझने और यातायात नियमों के समुचित पालन से जुड़ा है। देश में सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वाले रहम दिल लोगों को कानूनी सुरक्षा देकर, अन्य लोगों को भी घायलों के प्रति संवेदनशील बनने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किए जाने की व्यवस्था इस संशोधित अधिनियम में की गई है जो काफी महत्वपूर्ण है।

यह सच है कि सड़क हादसे पूरी तरह समाप्त नहीं किए जा सकते, पर उन्हें कम करके लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। इसके लिए संबंधित महकमों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ जनजागृति जरूरी है। इसके अलावा वाहनों के रख-रखाव, उनके परिचालन, ड्राइवरों की योग्यता व अन्य मामलों में एक-समान मानक लागू करने की जरूरत है।

नियमों के पालन से हादसों में होगी कमी

अरविंद जयतिलक

सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के मकसद से केंद्र सरकार ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम में अनेक नए प्रावधान किए हैं जिनसे निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। इस संशोधित अधिनियम में यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्मानों में कई गुना बढ़ोतरी के अलावा परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार रोकने और हादसों पर अंकुश लगाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। नए कानून में मोटर दुर्घटना कोष की स्थापना की व्यवस्था भी की गई है जो सड़क इस्तेमाल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य बीमा कवर देगा। साथ ही घायल होने की दशा में भी पीड़ित को एक तय राशि मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार, देश में सड़क नियम का पालन न होने के कारण पिछले एक दशक में 13 लाख से अधिक लोग सड़क हादसे में मारे गए हैं। साथ ही 50 लाख से अधिक लोग अपंगता के शिकार हुए हैं। दुनिया की कुल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में भारत का हिस्सा 10 प्रतिशत है। वर्ष 2015 में भारतीय सड़कों पर तकरीबन 1,46,133 लोग सड़क हादसे में मारे गए जिनमें 12,589 बच्चे थे। दुनिया भर में जितनी मौतें सालाना आतंकवाद से होती है उससे कई गुना अधिक केवल भारत में सड़क हादसे में होती है।

दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह भी है कि अधिकांश सड़क हादसे एक्सप्रेस-वे पर हो रहे हैं। उनमें भी जान गंवाने वाले लोगों में सर्वाधिक तादाद युवाओं की होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानें तो विश्व भर में किशोरवय के लड़के-लड़कियों की मौत का सबसे बड़ा कारण दुर्घटनाओं में उनका घायल होना है। गत वर्ष ही सड़क सुरक्षा को लेकर सर्वोच्च अदालत द्वारा कहा गया था कि सड़कों के गड्ढे आतंकी हमलों से भी ज्यादा नुकसानदेह हैं। अदालत ने पाया कि वर्ष 2017 में 3,597 लोगों की मौत गड्ढों के कारण सड़क दुर्घटना में हुई जबकि उसी वर्ष आतंकी हमलों में 803 लोगों की मौत हुई।

गौर करें तो सड़क सुरक्षा को लेकर अदालत की चिंता नाहक नहीं है। कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा जारी एक रिपोर्ट से उद्घाटित हो चुका है कि बीते पांच वर्षों के दरम्यान अकेले उत्तर प्रदेश राज्य में ही सड़क पर गड्ढों की वजह से 4,415 लोगों की जान गई है। रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जहां 2,136 लोग काल के ग्रास बने हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में 1,385, गुजरात में 825, पश्चिम बंगाल में 793, बिहार में 775, तमिलनाडु में 654 और आंध्र प्रदेश में 605 लोगों की जिंदगी गड्ढे में सदा के लिए समा चुकी है। उल्लेखनीय है कि कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2013 से 2017 तक की उन दुर्घटनाओं का जिक्र है जिनमें सड़कों पर गड्ढों की वजह से असमय लोग काल के गाल में समा गए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2015 के अनुसार सड़क हादसों में मारे जाने वालों की संख्या के आधार पर भारत दुनिया में शीर्ष पर है। यहां हर मिनट सड़क हादसे होते हैं और प्रत्येक चार मिनट में एक व्यक्ति की जान जाती है। इंडियन जर्नल ऑफ सर्जरी के एक शोध में बताया गया है कि देश में हादसे के 80 प्रतिशत पीड़ितों को एक घंटे के गोल्डेन आवर में आपात चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है। हर दुर्घटना की जगह पर सरकारी मदद पहुंचने की बात तो दूर वहां मौजूद आम लोग भी पीड़ित को तत्काल अस्पताल पहुंचाने से हिचकिचाते हैं।

सड़क हादसों में सिर्फ मौत ही नहीं होती है, बल्कि बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान भी होता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक सड़क हादसों में हर वर्ष भारत को 58 अरब डॉलर यानी तकरीबन चार लाख करोड़ रुपये का नुकसान होता है।

दुनिया भर में सड़क हादसों में मारे जाने वाले कुल लोगों में सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों, साइकिल सवारों, मोटरसाइकिल चालकों और स्कूली वाहनों की आधी हिस्सेदारी होती है। इस संदर्भ में स्वीडन ने 1997 में 'विजन जीरो' लक्ष्य के साथ सड़क ट्रैफिक सुरक्षा बिल को मंजूरी दी और स्वीडिश नेशनल रोड एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया। भारत की बात करें तो यहां मोटर वाहन अधिनियम 1988 से यातायात का नियमन किया जाता रहा है जो कि आज की चुनौतियों से लड़ने में पूरी तरह से असमर्थ है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार नए मोटर वाहन कानून के जरिये सड़क यातायात नियमों को कड़ाई से पालन करने के लिए कृतसंकल्प है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

खरी-खरी

मेरी आंखों के सिवा...

सुधीर कुमार चौधरी

जिन्हें गरीबी के घुप्प अंधेरे ने पहले ही अंधा बना रखा हो, उनकी धुंधली आंखों में रोशनी की क्या आवश्यकता? जब जीवन ही अंधेरे में डूबा है तो आंखों में उजाले का क्या काम! आंखें रहें न रहें, क्या फर्क पड़ता है। हमारी अंधी व्यवस्था का यही दस्तूर है।

उजाले की बेटी आंखें हमेशा के लिए अंधेरे की बोटी बन गईं। अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर में फैला लापरवाही का अंधकार मरीजों की आंखों में उतर आया। मानव सेवा का मुखौटा पहना अस्पताल उजाले के कत्लगाह में तब्दील हो गया। वैसे भी अस्पताल नोट छापने के टकसाल हो चुके। यहां कभी जिंदा आदमी लाश में बदल जाता है, तो कभी लाश वेंटिलेटर पर भुगतान की स्वाइप मशीन बनकर पड़ी रहती है। संवेदनाएं बाजार हो गई हैं, जो कभी मसीहाई थी, वो व्यापार हो गई है।

देश में ऐसी घटनाएं इतनी हुई हैं कि अब कुछ दिनों तक कुछ न हो, तो लगने लगता है कि कुछ हुआ क्यों नहीं? अब हाल इतने बिगड़ चुके कि कहां तक सियापा करें? यहां तो आंखें ही गई हैं, वरना जान तक मुस्कुराते हुए निकाल ली जाती हैं। गैरेज में सर्विसिंग के लिए गई कार से तो फिर भी नए पार्ट्स निकालकर पुराने डाले जाते हैं, यहां इंसानों के गैरेज में तो किडनी निकालकर दूसरी फटी-पुरानी भी नहीं डाली जाती। अस्पतालों में बीमारी से मौत के अलावा भी इतना कुछ मरता रहता है कि रोने का 'नियमित प्रसारण' चलता रहता है। कभी अस्पताल में सांसों के सिलेंडर खत्म हो जाते हैं तो कभी उन्नत चिकित्सा व्यवस्था को चमकी बुखार धमका जाता है। मुस्कराते बच्चे देखते-देखते मांस के लोथड़ों में बदल जाते हैं और उनकी माताएं मौन-बुत में। शुक्र मनाओ कि आंखें ही लुटी हैं, वरना चलती बस में जो अस्मत लुटती है, उसके चटखारे अखबारों में नहीं पढ़े क्या?

व्यवस्था भी कहां तक लाशों का हिसाब रखे, जब वह खुद लाश हो चुकी? जांच की रस्म जरूरी होगी... बराबर होगी! मगर सबसे बड़ी रस्म मृत्यु के बाद और किसी रस्म का कोई मतलब है क्या? और जब आंखें ही चली गई हैं तो जांच रिपोर्ट कैसे पढ़ोगे भाई? तो फिर जांच की धुनकी धुनने का क्या मतलब? सरकार का प्रिय काम है मुआवजा देना, सो, लो और आराम से सो लो।

अस्पताल बूचड़खानों में बदल गए हैं। गनीमत है तुझे अंधा ही किया है, वरना अभी तो उनके पास तुम्हें बहरा, गूंगा, किडनी विहीन कर देने की योग्यता भी है! तो शुक्र मनाओ और गाओ कि... मेरी आंखों के सिवा दुनिया में रक्खा क्या है!

ट्वीट-ट्वीट

शर्म बिहार पुलिस को नहीं, उनके हाथों में जंग लगी खटारा बंदूकें थमाने वालों को आनी चाहिए। अंतिम संस्कार में गोली नहीं चली कोई बात नहीं, पर जब सामने दुर्दांत अपराधी एके 47 से गोली चलाएंगे तो कैसे करेंगे रक्षा?

समीर अब्बास@TheSamirAbbas

बीएसपी के लोगों द्वारा कानून को अपने हाथ में नहीं लेने की जो परंपरा है वह पूरी तरह से आज भी बरकरार है, जबकि दूसरी पार्टियों एवं संगठनों के लिए यह आम बात है। हमें अपने संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों के सम्मान में बेकसूर लोगों को किसी भी प्रकार की तकलीफ एवं क्षति नहीं पहुंचानी है।

मायावती@Mayawati

कांग्रेस का तर्क है कि चूंकि इंद्राणी मुखर्जी पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप है इसलिए उनके बयान पर यकीन नहीं किया जा सकता। ऐसे तो किसी की भी हत्या करने के बाद कोई जुर्म कबूले तो उसके बयान पर भी यकीन नहीं करना चाहिए? हत्यारे कसाब के कबूलनामे पर भी यकीन न हो?

सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

झारखंड डायरी

प्रदीप शुक्ला
स्थानीय संपादक,
झारखंड

बिखरे कुनबे को सहेजने की चुनौती

झारखंड में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही राज्य में चुनाव कराए जाएं। भाजपा ने तैयारी में फिलहाल बाजी मार ली है। पार्टी की कोर कमेटी लगातार इस दिशा में सक्रिय है। भाजपा ने चुनाव में सटीक रणनीति तैयार करने के लिए ओम माथुर सरीखे अनुभवी नेता को चुनाव प्रभारी बनाया है जबकि बिहार भाजपा के कद्दावर नेता नंदकिशोर यादव सहप्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जितनी एकजुटता भाजपा के खेमे में दिख रही है उससे ज्यादा बिखराव विपक्ष में है। लोकसभा चुनाव में चारों खाने चित गिरे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अपना कुनबा संभालने में जुटे हैं। बाबूलाल मरांडी की त्रासदी भी अजीब है। बीते लोकसभा चुनाव में वे खाता नहीं खोल पाए। पिछले विधानसभा चुनाव में उनके दल झारखंड विकास मोर्चा से आठ विधायक चुनकर आए, जिसमें से छह ने भाजपा का रुख कर लिया। बचे हुए दो विधायकों में से एक को पार्टी विरोधी गतिविधियों में निलंबित किया गया है जबकि एक अन्य विधायक प्रदीप यादव, जो बाबूलाल मरांडी के खास सिपहसालार हैं, सलाखों के पीछे हैं। उन पर लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी की एक महिला नेत्री ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। बदली राजनीतिक परिस्थितियों में बाबूलाल मरांडी के समक्ष यह बड़ी चुनौती है कि वे अपना अस्तित्व कायम रख सकें। संगठन से जुड़े कई नेता भी अन्य दलों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में बाबूलाल मरांडी अकेले पड़ गए हैं। हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने हार नहीं मानी है। लेकिन राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा भी जोरों पर है कि वे किसी दल में अपने संगठन का विलय कर सकते हैं। कांग्रेस ने उन्हें इसके लिए खुला आफर भी दिया है। कभी भाजपा भी उन्हें अपने साथ आने का निमंत्रण दे चुकी है। हालांकि बाबूलाल इससे इन्कार करते हैं।

जेवीएम कार्यालय में प्रेस वार्ता करते बाबूलाल मरांडी और साथ में अन्य।

वे राज्य सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। देखना होगा कि उनकी यह रणनीति कितनी कारगर साबित होती है।

गठबंधन का पेंच : झारखंड में विपक्षी गठबंधन का हाल सौ दिन में चले अढ़ाई कोस जैसा है। कोई आगे बढ़ता है तो दूसरा टांग खींचने से गुरेज नहीं करता। ताजा विवाद राजद ने पैदा किया है। राजद ने खुलकर कहा है कि विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की कोई खास आवश्यकता नहीं होगी। वैसे राजद महागठबंधन का पक्षधर है और अपने आधार क्षेत्र वाले हिस्सों में सम्मानजनक हिस्सेदारी की उम्मीद कर रहा है। राजद को कांग्रेस के रुख की परवाह नहीं है। पार्टी के नेताओं के मुताबिक कांग्रेस के बारे में क्या कहा जाए, अब तक उसने अपना अध्यक्ष तक नहीं चुना है। राजद ने झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को गठबंधन का नेता स्वीकार करते हुए कांग्रेस को धर्मसंकट में डाल दिया है। दरअसल राजद झारखंड में क्रमिक रूप से मद्धिम पड़ती जा रही लालटेन की लौ को तेज करने की कवायद में है। दावा और लक्ष्य पांच लाख नए सदस्य बनाने का है। ऑनलाइन सदस्य बनाए जाने का तंत्र भी विकसित हो चुका है। सक्रिय कार्यकर्ताओं को इसका प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

पड़ोस से किचकिच : देश में नदियों के जल को लेकर कई राज्यों में विवाद है। लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच का विवाद जलाशय बनाने के बाद दिए जाने वाले मुआवजे एवं अन्य दायित्वों का भी है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर दुमका जिले में मौजूद मसानजोर दोनों राज्यों के बीच किचकिच का मसला बना हुआ है। एक दफा तो इसे लेकर दोनों राज्यों के हुक्मरान भिड़ गए थे। लेकिन अब आपसी सुलह से मामले के निपटारे की कवायद चल रही है। इस सिलसिले में झारखंड ने पश्चिम बंगाल सरकार पर तयशुदा एकरारनामे के अनुरूप काम न करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है। झारखंड का तर्क अंतरराज्यीय नदी परियोजनाओं की विसंगतियों पर है, जिसमें झारखंड ने बिंदुवार तार्किक तरीके से सरकार का पक्ष रखा। जिक्र किया गया कि झारखंड की शंख नदी में बरटोली गांव के समीप बराज निर्माण कर करीब 41 किलोमीटर लंबी लिंक नहर के माध्यम से दक्षिण कोयल नदी को जोड़ा जाना है। इसी प्रकार दक्षिण कोयल नदी पर पदयार गांव के समीप बराज का निर्माण कर करीब 76 किलोमीटर लंबी लिंक नहर के माध्यम से स्वर्णरेखा नदी को जोड़ा जाना है। बराकर नदी में बाल पहाड़ी के समीप डैम बनाकर दामोदर और स्वर्णरेखा नदी को 114 किलोमीटर लंबी लिंक नहर के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव है। इन प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने पर झारखंड को करीब 33,424 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई सुविधा के साथ-साथ 270 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन संभव हो सकेगा। गौरतलब है कि इन परियोजनाओं को लेकर पड़ोसी राज्य ओडिशा के साथ-साथ पश्चिम बंगाल गंभीर नहीं दिख रहे हैं।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आपको लगता है कि पी. चिदंबरम के खिलाफ कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है?

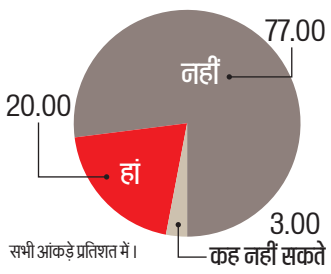

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या अनिल कुंबले को भारतीय टीम का मुख्य चयनकर्ता बनाया जाना चाहिए?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y –हां, **N**–नहीं, **C**–कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

लूटा जमकर पेट भर जब जनता का माल,
क्या होगा आगे तभी तनिक न आया ख्याल।
तनिक न आया ख्याल चढ़े हो अब जो हत्थे,
होंगे ही श्रीमान दांत बत्तीसो खट्टे।
किया जिन्होंने पाप न कोई अब तक छूटा,
हो जाओ तैयार देश जिस-जिस ने लूटा!

– ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

गुलाम कश्मीर भी है भारत का हिस्सा

जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत में शामिल करने के बाद अब बारी उससे आगे बढ़ने की है। हमारा अगला लक्ष्य गुलाम कश्मीर को भारत में शामिल करना होना चाहिए

आशुतोष भटनागर
निदेशक,
जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र, दिल्ली

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बीते दिनों पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी कर जहां पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है वहीं देश के भीतर भी एक नई चर्चा प्रारंभ हो गई है। जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही गुलाम कश्मीर पर भी बड़ा कदम उठा सकती है। वह हमारे देश का हिस्सा है और उसे भारत में मिलाना हमारा काम है। अनुच्छेद 370 के हटाए जाने से देश में जारी बहस के बीच इसे भी सरकार के अगले कदम के रूप में देखा जाने लगा है।

जम्मू कश्मीर के अधिमिलन के साथ ही पूरी जम्मू कश्मीर रियासत भारत में शामिल हो गई। यह अधिमिलन ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत तय किए गए प्रावधानों के अनुसार हुआ था और पूरी तरह विधिसम्मत था। देश की अन्य सभी रियासतें भी इसी प्रक्रिया से भारत में शामिल हुई थीं। यदि उनके अधिमिलन या विलय पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं हैं तो जम्मू कश्मीर पर प्रश्न खड़ा करना असंभव है। पिछले एक दशक में जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर अकादमिक समझ में बड़ा बदलाव आया है। उससे पहले ज्यादातर बहस स्थितियों की अपनी समझ और आधी-अधूरी जानकारी पर आधारित थी। आज गोपनीय ब्रिटिश दस्तावेज सार्वजनिक होने के बाद समूचे घटनाक्रम से आवरण हट गया है और सच सामने है।

तथ्य बताते हैं कि पूरे घटनाक्रम में कश्मीर को पाना पाकिस्तान की महत्वाकांक्षा तो थी, लेकिन उसे परवान चढ़ाने का काम एंग्लो-अमेरिकन ब्लॉक ने किया था जो तत्कालीन सोवियत संघ और चीन की सीमा पर अपने लिए एक अड्डा चाहता था। विश्व व्यवस्था को अपने इर्द-गिर्द घुमाने की कोशिश में जुटे एंग्लो-अमेरिकन गठजोड़ को यह स्पष्ट था कि उसकी इस योजना में कठपुतली की भूमिका में पाकिस्तान ही आ सकता है, भारत जैसा बड़ा देश नहीं। यह आश्चर्यजनक ही था कि विश्व मंच पर भारत की भूमिका सिमटती गई और पाकिस्तान के मित्रों की संख्या बढ़ती गई। निस्संदेह इसमें भारत द्वारा की गई कूटनीतिक चूकों का बड़ा योगदान है। लेकिन कड़वा सच यही है कि 1940 के दशक के अंतिम वर्षों और 1950 के दशक में यदि पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करने, उसके एक भाग पर कब्जा करने तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के बावजूद उसका पालन न करने और विश्व जनमत को ठेंगा दिखा कर भी वैश्विक मंचों पर समर्थन पाने में सफल रहा तो उसका कारण इन महाशक्तियों द्वारा उसे दिया गया खुला संरक्षण ही था। जिस समय पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के वेश में हमला किया, उस समय भारतीय सेना के प्रमुख अंग्रेज थे, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख अंग्रेज थे, और दोनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी अंग्रेज थे। ब्रिटिश राजघराने से निकट संबंध रखने वाले माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे। इसके बावजूद अंग्रेज सेनाधिकारियों वाली पाकिस्तान और भारत की सेनाएं आपस में जूझ रही थीं और ब्रिटिश प्रधानमंत्री इससे निजात पाने के लिए नेहरू को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाने की सलाह दे रहे थे। पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कब्जा किया उसे दो हिस्सों में बांट दिया। गिलगित और बाल्तिस्तान को उसने अलग कर नॉर्दर्न एरिया का नाम दे दिया। जम्मू का जो क्षेत्र उसने कब्जाया था उसमें कश्मीर का मुजफ्फराबाद क्षेत्र जोड़ कर आजाद कश्मीर के नाम से प्रचारित किया गया। वहां पर उसने आजाद जम्मू कश्मीर नाम से एक सरकार बना दी। दुर्भाग्य से आजाद शब्द की प्रतिक्रिया में भारत में उसे गुलाम कश्मीर कहा जाने लगा। इस तथ्य को भुला कर कि इस तथाकथित आजाद जम्मू कश्मीर में कश्मीर का एक छोटा हिस्सा मुजफ्फराबाद शामिल है जहां कश्मीरी भाषा बोलने वाले लोग नहीं हैं। यहां ज्यादातर लोग पहाड़ी-पंजाबी बोलते हैं।

आजाद कश्मीर का क्षेत्रफल केवल 13 हजार वर्ग किमी है जबकि गिलगित बाल्तिस्तान का 73 हजार वर्ग किमी। करीब 13 हजार वर्ग किमी के कथित कश्मीर की आजादी और गुलामी बहस के केंद्र में रही। गिलगित बाल्तिस्तान पर पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली तो हमने भी उसका नाम तक नहीं लिया। आश्चर्य कि पूरे पाक अधिकृत कश्मीर को कोई अधिकृत संज्ञा भी भारत सरकार की ओर से नहीं दी गई। नेहरू की नीतियों की आलोचना करने वाले भी यह तो कहते हैं कि सेना को अगर 48 घंटे दे दिए जाते तो इतिहास कुछ और होता, लेकिन शायद उनकी नजर भी गिलगित-बाल्तिस्तान के विशाल क्षेत्रफल पर नहीं जाती। पाकिस्तान पर बढ़त बनाए रखने के बावजूद भारत के नीति निर्माताओं के मन में काल्पनिक भय बना रहा। सेना जीतती रही, राजनीति हारती रही।

वर्तमान सरकार का पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर नजरिया स्पष्ट है। नीतिगत स्तर पर इसमें किसी बदलाव की कोई संभावना भी नहीं है। भाजपा और उसके पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ का शुरू से यह मानना रहा है। हाल की घटनाओं ने सिद्ध किया है कि सरकार वोटबैंक को दांव पर लगा कर भी अपनी नीतियों को लागू करने के लिए तत्पर है। भाजपा और उसके समविचारी संगठनों का काम करने का एक निश्चित तरीका है। वही उनकी सफलता का कारण भी है। वे किसी काम को जल्दी में, आधी-अधूरी तैयारी से करने के बजाय किसी मुद्दे को पहले समाज के बीच स्थापित करते हैं। विरोधियों का मत कुछ भी हो, वे एक बड़े वर्ग को विश्वास में लेकर ही निर्णायक कदम बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 370 के मामले में भी यह देखा गया है।

पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लिए बिना भारत अधूरा है। उसकी सुरक्षा और क्षेत्रीय हित दांव पर है। इसलिए आज नहीं तो कल, यह काम पूरा करना ही होगा। देखना यह है कि बिना हिंसा के, युद्ध की संभावना को टालते हुए यह कब और कैसे संभव होगा। यह कदम जब भी उठाया जाएगा, संबंधित पक्षों और वैश्विक शक्तियों को विश्वास में लेकर पूरी तैयारी के साथ ही उठाया जाएगा।

पूर्वांचल के कालीन उद्योग को पैट यार्न ने दिए नए पंख

नई तकनीक ▶ प्लास्टिक कचरे से बन रहे ईको फ्रेंडली कालीन, लागत कम और मांग अधिक, कारोबारियो में जगी नई उम्मीद

कैसर परवेज, भदोही

पश्चिमी देशों में पैट यार्न यानी प्लास्टिक के धागों से तैयार कालीन की मांग तेजी से बढ़ी है। भारत के परंपरागत कालीन उद्योग पर इसका असर देखा जा सकता है। पानीपत (हरियाणा) और बीकानेर (राजस्थान) के बाद अब उप्र के भदोही, मीरजापुर, बनारस का पारंपरिक कालीन उद्योग भी नए ढांचे में ढलने को तैयार है।

प्लास्टिक कचरे से बने पैट यार्न से बनने वाले इन आधुनिक कालीनों को ईको फ्रेंडली भी बताया जा रहा है। लागत कम और मांग अधिक होना भी कारोबारियों के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ है। भदोही और मीरजापुर परिक्षेत्र के कई कालीन निर्यातक पैट यार्न से कालीन बनाकर निर्यात करने लगे हैं। कारोबारी इससे नई उम्मीद बांधे हुए हैं, लिहाजा इसे प्रमोट भी खूब किया जा रहा है। दरी जैसी इन कालीनों की डिमांड यूरोप और अमेरिका में बहुत है। वस्त्र मंत्रालय और कालीन निर्यात संवर्धन परिषद ने भी इसे हाथों हाथ लिया है। बनारस, मीरजापुर व भदोही को केंद्र बिंदु बनाया गया है।

जागरण विशेष

- यूरोप और अमेरिका में बढ़ी डिमांड, स्थानीय निर्यातकों को आर्डर और निर्माताओं को मिलने लगा काम
- परंपरागत उद्योग की बदल रही सूरत-सीरत, बदला कालीन बनाने का तरीका

यहां के गोपीगंज की ओवरसीज ग्लोबल कंपनी इसका उत्पादन पिछले चार वर्ष से कर रही है। पैट यार्न से कालीन तैयार करने वाली वाराणसी जनपद की संभवतः यह पहली कंपनी है। इसके मालिक संजय कुमार गुप्ता बताते हैं कि चार वर्ष पहले शुरुआत की थी। कई देशों में इसकी मांग को देखते हुए अब वे बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। निर्यात में पैट यार्न से तैयार कालीनों की भागीदारी 10 फीसद है, इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले दिनों ही उन्हें जर्मनी से बड़ा आर्डर मिला है। पैट यार्न से तैयार कालीनों को विदेश में आउटडोर कारपेट कहते हैं। इसके खरीदार लान, छत, बरामदे व पार्क में इसका उपयोग करते हैं। पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कम लागत में तैयार होने वाली कालीन जल्दी खराब भी नहीं होती।

पैट यार्न से बने कालीन। जागरण

बाजार विकसित करने की जरूरत : प्रमुख कालीन निर्यातकों की मानें तो पैट यार्न से तैयार कालीन मंदी से जूझ रहे कालीन उद्योग को सहारा दे रही है। अभी इसके लिए बाजार विकसित करने की जरूरत है। अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ के संयुक्त सचिव आलोक बरनवाल ने बताया कि पैट यार्न से दरी जैसी कालीनों का निर्माण किया जा रहा है लेकिन इसका दायरा सीमित है। धागा सस्ता होने के कारण डिमांड भी है। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।

रुचि बढ़ने से उद्योग को बल : कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, सीईपीसी) के वरिष्ठ प्रशासनिक समिति सदस्य उमेश कुमार गुप्ता का कहना है कि पैट यार्न से निर्मित उत्पादों के लिए आयातकों में रुचि बढ़ी है। निःसंदेह इसका लाभ उद्योग को मिलेगा। सीईपीसी इस दिशा में प्रयासरत भी है। इस तकनीक से तैयार उत्पाद के ईको फ्रेंडली होने के कारण वस्त्र मंत्रालय भी रुचि ले रहा है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

भदोही, उप्र : पैट यार्न से तैयार कालीन दिखाता एक बुनकर। जागरण

पैट यार्न के कालीनों का उत्पादन पहले पानीपत से शुरू हुआ था, जिसे बाद में भदोही-मीरजापुर के निर्यातकों ने भी अपनाया। चार वर्ष पहले शुरू हुआ उत्पादन अब तेजी से पांव पसार रहा है। देश के दस हजार करोड़ के निर्यात में पैट यार्न से तैयार कालीनों की भागीदारी 50 करोड़ रुपये है। यह अभी आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि ग्राहक अब फैंसी व सस्ते आइटम अधिक पंसद कर रहे हैं। पैट यार्न से बनी कालीन ईको फ्रेंडली होने के साथ सुविधाजनक है। **- सिद्धनाथ सिंह, चेयरमैन, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद**

पीएम संग चंद्रयान-टू की लैंडिंग देखेंगे पिथौरागढ़ के दो छात्र

जासं, पिथौरागढ़ : चंद्रयान-टू के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो टीम को शुभकामना संदेश भेजने वाले मानस एकेडमी के दो विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री के साथ लाइव लैंडिंग देखने का अवसर मिलेगा। इसरो की ओर से आभार जताते हुए विद्यालय को गिफ्ट पैक भेजा गया है।

विद्यालय के 2500 छात्र-छात्राओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं ने चंद्रयान टू के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो की टीम को हस्ताक्षरयुक्त फ्लैक्सी भेजकर शुभकामना संदेश दिया था। उत्तराखंड से इसरो टीम को शुभकामना संदेश भेजने वाला मानस एकेडमी इकलौता स्कूल था। इसरो अध्यक्ष के. शिवन ने विद्यालय का आभार जताते हुए विद्यालय के संस्थापक निदेशक डॉ. अशोक कुमार पंत को आभार पत्र भेजा है। विद्यालय के लिए इसरो की ओर से स्पेस क्विज-चंद्रयान-टू क्विज मैटेरियल भी भेजा गया है। विद्यालय स्तर पर चयनित 100 विद्यार्थी क्विज कोड को ऑनलाइन स्कैन कर प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इनमें से पहले दो स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को सात सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चंद्रयान-2 की लाइव लैंडिंग देखने का मौका मिलेगा। क्विज का आयोजन 26 अगस्त को होगा।

फ्लोराइड लेवल की जांच अब चुटकियों में

बंगाल के दुर्गापुर स्थित केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमईआरआइ) के वैज्ञानिकों की बनाई किट। जागरण

डॉ. हरीश हिरानी, निदेशक, केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर

हृदयानंद गिरि, दुर्गापुर

- सीएमईआरआइ दुर्गापुर ने बनाई सस्ती और इस्तेमाल में आसान फ्लोराइड डिटेक्शन किट

सीएमईआरआइ, दुर्गापुर के वैज्ञानिकों ने सस्ती-कारगर फ्लोराइड डिटेक्शन किट विकसित की है। इससे शरीर में फ्लोराइड की मात्रा जांचना आसान हो जाएगा और खर्च होंगे सिर्फ 10 रुपये। फ्लोराइडयुक्त पानी वाले इलाकों के लिए इसे उपयोगी माना जा रहा है।

दुर्गापुर (बंगाल) स्थित केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूय, सीएमईआरआइ) ने तीन संस्थाओं प्रौद्योगिकी सौंप दी है। आमजन के लिए यह किट जल्द उपलब्ध होगी। झारखंड और बंगाल सहित देश के कई इलाकों में लोग भूजल में घुले खतरनाक रसायन फ्लोराइड से परेशान हैं। यह ऐसा घातक रसायन है, जो इंसान के शरीर में पहुंचकर धीमे जहर की तरह हड्डियों और अन्य अंगों को बेकार करता चला जाता है। फ्लोराइड प्रभावित इलाकों में सैंकड़ों लोग इसे दुष्प्रभाव से अपाहिज हो चुके हैं। ऐसे में सीएमईआरआइ के वैज्ञानिकों ने यह फ्लोराइड डिटेक्शन किट तैयार की है, जो घर बैठे ही पल भर में बता देगी कि शरीर में फ्लोराइड की मात्रा कितनी है। इसके बढ़े होने की दशा में व्यक्ति तुरंत चिकित्सकीय परामर्श ले सकेगा।

स्वस्थ समाज

तीन साल के गहन शोध और कई परीक्षणों के बाद यह किट बन सकी है। संस्थान ने किट बनाने की प्रौद्योगिकी तीन कंपनियों को दी है, जो अब सस्ती और सुविधाजनक किट आमजन को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगी। एक पैकेट में दो किट उपलब्ध होंगी। पैकेट की कीमत महज 20 रुपये होगी। यानी एक बार की जांच में 10 रुपये खर्च आएगा।

थूक का रंग हो जाए गहरा नारंगी तो समझिए खतरा है : संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. प्रियव्रत बनर्जी ने बताया कि सामान्य तौर पर शरीर में फ्लोराइड की मात्रा की जांच के लिए खून और मूत्र का प्रयोग होता है। उसे पैथॉलाजी लैब भेजा जाता है। वहां खून या मूत्र में मौजूद फ्लोराइड की मात्रा का कई प्रकार के परीक्षण के बाद आकलन होता है। अब इस किट के जरिये घर बैठे जांच हो सकेगी। किट में कांच की दो छोटी शीशी हैं। एक में विशेष प्रकार का रसायन होता है, वहीं दूसरी शीशी खाली होती है। शरीर में फ्लोराइड की मात्रा की जांच करने के लिए थूक का कुछ हिस्सा खाली शीशी में लेना होगा। इसके बाद दूसरी शीशी में मौजूद रसायन उसमें डालकर कुछ देर हिलाने के बाद परिणाम रंग के रूप में सामने आ जाएगा। मिश्रण यदि गहरे नारंगी रंग में तब्दील हो जाए तो समझ जाएं कि शरीर में सामान्य से ज्यादा फ्लोराइड है। किट के साथ एक स्केल भी मिलता है जो रंग के आधार पर बताता है कि फ्लोराइड की मात्रा मानक से कितनी कम या ज्यादा है।

20 राज्य प्रभावित हैं समस्या से : देश के 20 राज्यों के लोग फ्लोराइडयुक्त भूजल की समस्या से जूझ रहे हैं। शरीर में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ते जाने पर इंसान के दांत टेढ़े-मेढ़े और खराब हो जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी होने के साथ ही कमजोर भी हो जाती हैं। इंसान चलने-फिरने में लाचार हो जाता है। फ्लोराइड की जांच से लोग पानी के शुद्धीकरण या फ्लोराइडयुक्त पानी के त्याग जैसे समाधान पर आसानी से विचार कर सकेंगे।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

- डॉ. हरीश हिरानी, निदेशक, सीएमईआरआइ, दुर्गापुर।

ट्रेनों पर नक्सलियों का कहर रोकेगा कोरस

रमेश यादव, प्रयागराज

- कोरस में उत्तर मध्य रेलवे के छह आरपीएफ अधिकारी शामिल
- दंतेवाड़ा और धनबाद में लगाया गया कमांडो ड्यूटी पर

ट्रेनों पर होने वाले नक्सली हमलों को रोकने और विषम परिस्थितियों में लड़ने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके लिए आरपीएफ में कोरस (कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी) का गठन किया गया है। इसमें उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के छह आरपीएफ अधिकारियों को कमांडो ट्रेनिंग दिलाकर उनकी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़), डुमरी धनबाद (झारखंड) में तैनाती की गई है। इसमें तीन प्रयागराज (इलाहाबाद) से हैं।

आरपीएफ के जवानों को अंबाला के पास जगाधरी सेंटर में कमांडो ट्रेनिंग दी गई। उन्हें नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम के तरीके और नक्सली हमले की स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया। छह आरपीएफ अधिकारियों ने यह प्रशिक्षण हासिल किया। इनमें एनसीआर मुख्यालय से निरीक्षक बबलू कुमार, इलाहाबाद मंडल प्रयागराज से उप निरीक्षक नंद किशोर यादव, सचिन राठी, झांसी से अमित यादव, मीरजापुर से अभिषेक यादव और इटावा से रमेश चौधरी हैं। अब इन्हें ड्यूटी पर भेजा जा रहा है।

एनसीआर के प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त एसएन पांडेय का कहना है कि तीन अधिकारी दंतेवाड़ा और तीन डुमरी, धनबाद जा रहे हैं। तीन अधिकारी जा चुके हैं। बाकी 25 अगस्त को जाएंगे।

चुनार-चोपन खंड नक्सल क्षेत्र : उत्तर मध्य रेलवे में चुनार-चोपन रेल खंड नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। यहां कई बार ट्रेन पर हमले हो चुके हैं। इस खंड में ट्रेन चलाना चुनौतीपूर्ण है। उत्तर मध्य रेलवे के जो अधिकारी कमांडो ड्यूटी करके लौटेंगे, उनकी तैनाती इस क्षेत्र में की जाएगी ताकि वह अन्य को ड्यूटी पर समझा सकेंगे कि किस तरह नक्सली हमलों को विफल करना है और उनसे निपटना है।

संकट खत्म : आइसीएआर की ऑर्गेनिक दवा से 'तंदुरुस्त' बना रहेगा केला

रूमा सिन्हा, लखनऊ:

- वैज्ञानिकों ने केले के पेड़ में लगने वाली फंगस का खोजा हल
- फ्यूजेरियम टीआर-4 से दो-दो हाथ करेगा आर्गेनिक आइसीएआर फ्यूजीकॉन

हर किसी का पसंदीदा फल केला क्या फंगस फ्यूजेरियम टीआर-4 के आक्रमण के चलते दुनिया से खत्म हो जाएगा...? चीन, कोलंबिया यहां तक कि अमेरिका में केले की खेती पर मंडरा रहे संकट के बाद यह सवाल पूरी दुनिया में गूंज रहा है। हालांकि, भारतीयों को ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के वैज्ञानिकों ने केले को तंदुरुस्त बनाए रखने का तोड़ ढूंढ निकाला है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (सीआइएसएच) और केंद्रीय मृदा लवणता संस्थान ने फंगस के खात्मे के लिए आर्गेनिक आइसीआर फ्यूजीकॉन तैयार कर लिया है। इस बाबत शोध अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'प्लांट डिजीज' में प्रकाशित किया गया है।

सीआइएसएच के निदेशक डॉ. शैलेंद्र राजन ने बताया कि विदेश में केले को नुकसान पहुंचाने वाले जिस फंगल रोग को लेकर इमरजेंसी जैसी स्थिति बनी हुई है, उसका प्रकोप उत्तर प्रदेश व बिहार में भी हो चुका है। उप्र में महराजगंज के सुहावल, मेगावल व सिसवां बाजार और बिहार के कटियार, सीतामणि व पुर्णिया के किसान भी इससे त्रस्त थे। हालांकि भारत के जिन भागों में केले की जी-9 किस्म का उत्पादन हो रहा है, वहां बीमारी नहीं पहुंची है।

नेपाल से संकट आने की संभावना : डॉ. राजन ने बताया कि दोनों संस्थानों ने फंगस की दवा आइसीआर फ्यूजीकॉन का सिसवां बाजार स्थित केले बाग में सफल परीक्षण किया। नतीजे सफल रहे। उन्होंने बताया कि भारत में फंगस नेपाल की नदियों में आने वाली बाढ़ के पानी संग आता है। इसीलिए नेपाल एग्रीकल्चर काउंसिल से संपर्क कर फंगस के प्रकोप का पता लगाया गया।

फ्यूजेरियम टीआर-4 से प्रभावित केले के बाग की जांच करते डॉ. शैलेंद्र राजन व डॉ. दामोदर। जागरण

डॉ. राजन बताते हैं कि फंगस का प्रकोप होने के बाद पेड़ नीचे से गलने लगता है। अंत में पूरा पेड़ ही गिर जाता है। उन्होंने बताया कि आइसीएआर फ्यूजीकॉन का प्रयोग गुड़ के साथ फरमेंट (किण्वन) किया जाता है। यह पूरी तरह से आर्गेनिक है। महज 125 रुपये प्रति किलो में दवा उपलब्ध है।

यहां कभी भी समा सकते हैं दहकती आग और धरती में...

झारखंड में झरिया की कुकुरतोपा बस्ती में दीवारों पर चेतावनी लिखी हुई है, यहां न रहें, कभी भी दहकती आग और धरती में समा सकते हैं। फिर भी लोग कुकुरतोपा बस्ती में रह रहे हैं। वजह है, गरीबी। इधर-उधर कोयला मिल जाता है जिसे इकट्ठा कर बेचने से पेट भर जाता है। मगर धरती के अंदर धधकते कोयले का भयावह मंजर हर पल उनके रोंगटे खड़े करता रहता है। जहां देखिए, वहां आग और धुआं। हर दस कदम पर फटी हुई जमीन। यह सिर्फ कुकुरतोपा में नहीं बल्कि आसपास की दर्जनों बस्तियों में ऐसा ही मंजर दिखेगा। यहां रहने वालों को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल, सरकार उन्हें बेहतर आवास देगी और रोजगार भी। तब उनकी नजर से हमेशा के लिए मौत का मंजर दूर हो जाएगा। जगदीश यादव

2525 किमी गंगा, संरक्षित क्षेत्र महज 9.16 फीसद

- भारतीय वन्यजीव संस्थान में आयोजित सेमिनार में गंगा संरक्षण की नीति पर उठाए गए सवाल
- शोध में स्पष्ट किया गया, 50 फीसद संकटग्रस्त प्रजातियों के लिहाज से ना के बराबर हैं संरक्षित क्षेत्र

गंगा नदी फाइल फोटो

सुमन सेमवाल, देहरादून

गंगा नदी के संरक्षण के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें नीतिगत रूप में सुधार लाने की जरूरत है। यह महज एक विचार नहीं, बल्कि भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआइआइ) ने करीब चार साल के अध्ययन के बाद इस बात को पुष्ट किया है। गुरुवार को बायोडायवर्सिटी एंड गंगा कंजर्वेशन सेमिनार में 'क्रिटिकल पॉलिसी रिव्यू फॉर गंगा रिवर कंजर्वेशन' नामक इस शोध को साझा भी किया गया।

शोधकर्ता मिशेल इरेंगबम ने बताया कि गंगा की लंबाई करीब 2525 किलोमीटर है, मगर इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 के अनुसार महज 9.16 फीसद ही संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। वर्ष 2010 के कंवेंशन ऑन बायलॉजिकल डायवर्सिटी (सीबीडी) की बात करें तो यह संरक्षित क्षेत्र कम से कम 17 फीसद होना जरूरी है। दूसरी अहम बात यह है कि गंगा नदी में 50 फीसद ऐसी प्रजातियों का वासस्थल है, जो संकटग्रस्त श्रेणी की हैं। इस लिहाज से भी 9.16 फीसद संरक्षित क्षेत्र काफी कम हैं। यदि सही अर्थों में गंगा नदी की पारिस्थितिकी को बेहतर बनाना है तो संरक्षित क्षेत्र में इजाफा किया जाना चाहिए।

इसलिए भी प्रभावी नहीं हो पा रही नीति, नदी पारिस्थितिकी को प्राथमिकता नहीं : अध्ययन में बताया गया कि राष्ट्रीय जल नीति में पहली प्राथमिकता सिंचाई को दी गई है। इसके बाद घरेलू उपयोग के पानी और अंतिम स्तर पर नदी व इसके जलीय जीवन पर ध्यान दिया जाता है। ऐसे में कई दफा जलीय जीवन की बेहतरी के लायक भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता।

संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षित क्षेत्र और भी कम

- प्रजाति, संरक्षित क्षेत्र (फीसद में)
- डॉल्फिन, 8.9
- स्मूद ऑटर (ऊदबिलाव), 9.2
- यूरेशियन ऑटर (सामान्य ऊदबिलाव), 3.2

सूचनाओं का अभाव: अध्ययन के मुताबिक नदी संरक्षण को लेकर किए जा रहे कार्यों की सूचनाओं की कमी नजर आती है। रिवर कनेक्टिविटी को लेकर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। सिर्फ राष्ट्रीय पर्यावरण नीति-2006 में ही कुछ हद तक स्थिति स्पष्ट है।

क्रियान्वयन का अभाव: नदी संरक्षण को लेकर जो भी काम किए जा रहे हैं या जो नियम बने हैं, उनकी तरफ उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि ऐसा होता तो 2525 किलोमीटर लंबी गंगा नदी में महज 9.16 फीसद संरक्षित क्षेत्र नहीं होते।

वाणिज्य के केंद्र में नहीं: भारतीय वन्यजीव संस्थान के शोध में बताया गया है कि नदी की परिस्थितिकी को वाणिज्य के केंद्र में नहीं रखा गया है। इस दिशा में जो भी मंत्रालय व विभाग काम कर रहे हैं, उनके बीच उचित तालमेल भी नहीं दिखता। ऐसे में जलीय पारिस्थितिकी को बेहतर बनाने व उनके समुचित उपयोग की योजनाओं को आकर्षित करना संभव नहीं हो पा रहा।

योजना

स्वेच्छा से गांव छोड़ने पर मिलेगी जमीन या 10 लाख की राशि, यदि ग्रामीण 10 लाख रुपये नहीं लेना चाहेंगे तो उन्हें खेती के लिए पांच एकड़ जमीन, 50 हजार रुपये नकद, कॉलोनी और स्कूल, हॉस्पिटल की व्यवस्था प्रदान की जाएगी

एलिफैंट रिजर्व के लिए विस्थापित होंगे 140 गांवों के लोग

श्रीशंकर शुक्ला, रायपुर

छत्तीसगढ़ के लेमरू अभयारण्य को एलिफैंट रिजर्व बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके लिए जंगल में बसे 140 गांवों के लोगों को विस्थापित किया जाएगा।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक विस्थापित किए जाने वाले गांवों के बाशिंदों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यदि ग्रामीण 10 लाख रुपये नहीं लेना चाहेंगे तो उन्हें खेती के लिए पांच एकड़ जमीन, 50 हजार रुपये नकद, कॉलोनी और स्कूल, हॉस्पिटल की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीण स्वेच्छा से दूसरी जगह बसना चाहेंगे तो उनको व्यवस्थापन नीति के तहत सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

लेमरू एलिफैंट रिजर्व 195 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत बनाया जा रहा है, जिसमें बादलखोल, तमोरपिंगला, सेमरसोत और लेमरू वनक्षेत्र शामिल है। एलिफैंट रिजर्व बनने से अलग से अधिकारी-कर्मचारी तैनात रहेंगे। वर्तमान में हाथी प्रभावित गांवों की सुरक्षा नहीं हो पाती, लेकिन रिजर्व बनने से उन गांवों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा।

लेमरू एलिफैंट रिजर्व में विचरण करते हाथियों का झुंड। फाइल फोटो

लेमरू प्रोजेक्ट बनने के बाद हाथियों को नहीं होगी दिक्कत : वन अधिकारियों का मानना है कि यह अलग तरह का अभयारण्य होगा। अभयारण्य में हाथियों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी की व्यवस्था की जाएगी। प्रभावित गांवों की सुरक्षा के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। हाथियों पर नजर रखने के लिए अलग से कर्मचारी 24 घंटे नजर रखते हैं।

प्रदेश में हैं 254 हाथी, 27 जिले हैं हाथी-मानव द्वंद्व से प्रभावित

छत्तीसगढ़ में अभी हाथियों की अनुमानित संख्या 254 है, जिसमें सरगुजा वन वृत्त में 110, बिलासपुर वृत्त में 121 व रायपुर वन वृत्त में 23 हाथी हैं। 20 साल में हाथियों ने सैकड़ों की संख्या में रूट बनाए हैं, जहां हाथी एक बार जाने के बाद उसी रूट पर दोबारा जाते हैं। वनमंडल सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, धरमजयगढ़, कटघोरा, मरवाही, कोरबा, रायगढ़, महासमुंद, बलौदा बाजार, खैरागढ़ सबसे प्रभावित हैं।

स्वेच्छा से विस्थापित होने वाले परिवार को विस्थापन नीति के तहत वह पैसा चाहेंगे तो पैसा, अन्यथा विस्थापन नीति के रहवास के लिए कॉलोनी और कृषि भूमि आवंटित की जाएगी। **- अतुल शुक्ला, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ छत्तीसगढ़**

दैनिक जागरण
सबरंग

प्लान वीकेंड के

नई दिल्ली, शुक्रवार, 23 अगस्त,2019

सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें :sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

इस बार यहां चलें

द नेचर ऑफ थिंग्स

ग्रामीण संकट की ओर ध्यान आकर्षित कराती यह प्रदर्शनी संवेदनशील मसले उठाती है। डॉ कोटा नीलिमा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में बीड जिले में प्रकृति की चीजों पर कलाकृतियां प्रदर्शित करेंगी। यहां किसानों के आत्महत्या से उनके घरों पर पड़ने वाला प्रभाव दिखेगा।

- **कहां** : विजुअल आर्ट गैलरी, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोदी रोड, दक्षिणी दिल्ली
- **कब** : 23 से 29 अगस्त, सुबह दस से शाम साढ़े छह बजे तक
- **प्रवेश** : निश्शुल्क

शुद्ध ध्वनि की सुरमयी शाम

तीन दिवसीय शुद्ध ध्वनि कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कलाकारों की प्रस्तुति सारे तनाव दूर कर देगी। सरोद-सितार की जुगलबंदी, तबला, सारंगी, बांसुरी जैसे वाद्ययंत्रों पर डॉ देवाशीष अधिकारी, उस्ताद साबिर खान जैसे कलाकार सुरों की तान छेड़ेंगे।

- **कहां** : त्रिवेणी कला संगम, नई दिल्ली
- **कब** : 24 से 26 अगस्त, शाम छह बजे से
- **प्रवेश** : निश्शुल्क

देव-गीता

केरल की मंदिर परंपराओं से प्रेरित यह आयोजन सेंटर फॉर मोहिनीअट्टम द्वारा आयोजित किया जा रहा है। देव-गीता में मोहिनीअट्टम और गाया गया सोपान, संगीत परंपरा को जीवंत करने बनाता है। गीत गोविंदम के गीतों पर यादगार प्रस्तुति भी होगी।

- **कहां** : आइजीएनसीए, नई दिल्ली
- **कब** : 23 अगस्त, शाम छह बजे
- **प्रवेश** : निश्शुल्क

हजरत-ए-कृष्ण

दास्तानगोई के जरिए भारत की पुरातन संस्कृति, कला और रहन-सहन को कुछ इस अंदाज में पेश किया जाएगा कि दर्शक हजरत-ए-कृष्ण के मुरीद हो जाएंगे। केएल सहगल पर आधारित नाटक भी भरपूर मनोरंजन करेगा। तो सोचिए मत सप्ताहांत नाटक देखने की तैयारी कर लें।

- **कहां** : श्रीराम सेंटर, मंडी हाउस, नई दिल्ली
- **कब** : 25 अगस्त, शाम पांच एवं सात बजे
- **प्रवेश** : ऑनलाइन बुकिंग द्वारा, टिकट 100 रुपये से 1000 रुपये तक

मैं बंसी तुम तान, मैं भक्त तुम भगवान। कहने को तो दो जान हैं हम, मगर एक है प्राण। नई दिल्ली कमानी सभागार में संगीतमय नृत्य नाटिका कृष्णा में मनमोहक प्रस्तुति देते कलाकार। सभी फोटो : ध्रुव कुमार

ये अनूठा रहा

दृश्यों में और अधिक जीवतंता भरने के लिए एलईडी स्क्रीन का भी इस्तेमाल किया गया। शोभा दीपक कहती हैं कि इसके अलावा पहली बार इस आयोजन में ऑडियो, वीडियो का प्रयोग किया गया। कृष्ण के जन्म आदि दृश्य को मयूरभंज छउ और कलारिपट्टू के जरिए दर्शाया गया। गीतों की बात करें तो सूरदास की रचनाओं के साथ ही लोकगीतों के जरिए यह प्रस्तुति शानदार बनी।

आयोजन : कृष्णा
कहां : कमानी आडिटोरियम, मंडी हाउस।
कब : 19 से 24 अगस्त, शनिवार को दोपहर 3 बजे से।
नजदीकी मेट्रो स्टेशन : मंडी हाउस।
प्रवेश : 300 रुपये, आनलाइन बुकिंग द्वारा।

कृष्ण जन्मोत्सव

अधरों पर मुरली बन जाऊं भक्त हूं चरणों में सज जाऊं

हॉल में अंधेरा था। कुर्सियों पर बैठे दर्शकों की उत्सुकता भरी नजरें काले पर्दे पर टिकी थीं। इंतजार था...अब दृश्य उभरकर आएंगे। खचाखच भरे हॉल में दर्शकों की बेसब्री के बाद अचानक तेज बिजली चमकती है। बादलों में गड़गड़ाहट गूंजती है। मंच की काली घनी छाया के बीच से लाल, नीली, पीली रोशनी की किरणों में जेल का दृश्य उभरता है। कृष्ण का जन्म होता है.... सबरंग के इस अंक में कृष्ण लीला दर्शकों को किस तरह विमुग्ध करती है इसी से रूबरू करा रहे हैं संजीव कुमार मिश्र :

मंच पर देवकी और वासुदेव बात कर रह थे। यहां से कृष्ण की जिंदगी का जो सफर शुरू हो चुका था और वो गांधारी के कृष्ण को श्राप देने तक चलता है। इस दौरान दर्शक दिल थामे बैठे रहते हैं एवं हर क्षण को अपने मानस पटल पर कैद कर रहे थे। शोभा दीपक सिंह के उत्कृष्ट निर्देशन, एलईडी लाइट-स्क्रीन के बेहतरीन इफेक्ट, कलाकारों के अभिनय, नृत्य और अभिनय समेत गीतों के बोल ने दर्शकों को करीब दो घंटे बांधे रखा। कहानी के दृश्य कहीं टूटते नहीं हैं। क्रमवार जिस तरह वासुदेव कृष्ण को यशोदा के जन्मे बच्चे संग बदलने जाते हैं। और बादलों से तेज बिजली की गड़गड़ाहट के बीच कंस बने उपेंद्र का आगमन होता है। आकाशवाणी होती है। कंस बेचैन सा नजर आता है, जो उसके चेहरे से साफ झलकती है।

उधर कान्हा का जन्म का उत्सव यानी जन्माष्टमी धूमधाम से मनती है। गाना-बजाना...गोपियों का नृत्य मतलब दर्शकों के समक्ष एक फिल्म की कहानी की तरह कृष्ण की लीला चल रही थी। ग्वाल सफेद और ग्वालिन लाल नीले रंग का वस्त्र धारण किए रहती हैं। ग्वाल और गोपियों के पदचाप से हॉल में गूंजता संगीत दर्शकों को मनमुग्ध कर देता है। नृत्य के बाद अगला दृश्य शुरू होता है तो बैकग्राउंड के एलईडी स्क्रीन पर झोपड़ी की तस्वीर उभरती है। लाल रंग की मिट्टी की यह तस्वीर मंच के अभिनय को और जीवंत बना देती है। और गीत के बोल कुछ इस तरह होते हैं

पालना श्याम झुलावत जननी : यशोदा बड़े चाव से कृष्ण का पालना झुलाती हैं। यशोदा के रूप में मनु नेगी का बेमिसाल अभिनय दर्शकों को भाव विभोर कर रहा था। ऑडिटोरियम वात्सल्य रस में मानों भीग रहा था। लेकिन कुछ क्षण बाद ही मंच पर घुप अंधेरा होता है और इस अंधकार को एक सफेद प्रकाश की छटा दूर करती है। मटकियां लटकी दिखाई देती हैं अब मटकी के दृश्य से समझ गए होंगे कि कान्हा भी कहीं आसपास ही हैं। बिलकुल ऐसा ही होता है और तभी अपने दोस्तों के संग कान्हा मटकी के नीचे पहुंचते हैं। पीले रंग का वस्त्र पहने, कमर में करघनी पहने एवं मोर का पंख माथे पर साजे कृष्ण की वेशभूषा दर्शकों को आनंदित कर रही थी। कृष्ण, सखा संग मटकी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सफल नहीं होते हैं। जिसके बाद सभी दोस्त मिलकर कान्हा को पांव से पकड़कर उठाते हैं और फिर क्या...कान्हा माखन चुरा लाते हैं अपने सखों में बांटकर खाते हैं। तभी यशोदा कान्हा को पकड़ लेती हैं, गोपियां भी उनसे शिकायत करती हैं। तो कन्हैया कहते हैं कि

मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो
भोर भयो गैयन के पीछे
मधुबन मोहि पठायो।।

कृष्ण के रूप में सिबुराम मोहंता की भाव भंगिमाएं दर्शकों को आह्लादित कर रही थीं। अगले ही दृश्य में गोपियां भी आती हैं एवं कोई कान्हा के कान पकड़ती हैं तो कोई यशोदा से शिकायत करती है। इस पर यशोदा कान्हा के हाथ बांध देती है। बैकग्राउंड में एलईडी स्क्रीन पर ब्रह्मांड का दृश्य चलता है। यशोदा खुद को धन्य मानती है।

कान्हा और राधा का मिलन : राधा और कान्हा का मिलन भी तकरार के साथ होता है। श्वेत श्याम कृष्ण अपने सखा संग तालाब के किनारे होते हैं गोपियां पानी भरने आती हैं। कृष्ण राधा को देखते हैं। पूछते हैं--

बूझत स्याम कौन तू गोरी।
कहां रहति काकी है बेटी देखी नहीं कहूं ब्रज खोरी।।

राधा बनी अनसुइया चौधरी का नृत्य यहां दर्शकों के दिल को छू जाता है। कृष्ण और राधा की मीठी नोंकझोंक दर्शकों को खूब रास आती है। कृष्ण बांसुरी बजाने लगते हैं तो गोपियां और राधा मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। कृष्ण इसका फायदा उठाकर राधा की मटकी लेकर भाग जाते हैं। फिर, मटकी लेने के लिए जो रस्साकशी होती है वो दर्शकों को भी तालियां बजाने पर मजबूर कर देती है। अब तक दर्शक भक्ति भाव में पूरे डूब चुके होते हैं। अंधेरे में गुम ऑडिटोरियम की सीट पर दर्शक कृष्ण की भक्ति भावना में बह रहे थे। कोई दोनों हाथ जोड़ प्रणाम की मुद्रा में बैठा था तो किसी की जुबां पर राधा-कृष्ण थे।

एक के बाद एक दृश्य चलते जाते हैं और कृष्ण लीला का पड़ाव कालिया नाग से युद्ध तक पहुंचता है। कृष्ण और कालिया के बीच युद्ध को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया...दर्शकों के लिए ऐसे दृश्य विस्मरणीय रहेंगे। इसके ठीक बाद फाग खेलते कृष्ण और राधा का नृत्य होता है। ऐसा लगा दिल्ली की उमस भरी गर्मी में लाल, नीला रंग घुल गया हो और मौसम खुशनुमा हो गया है।

कभी नहीं बजाउंगा बांसुरी : पूर्ण चंद्र था। कभी लाल तो कभी पूरा सफेद प्रकाश एलइडी के जरिए आंखों को भा रहा था। सफेद वस्त्र पहने गोपियां, पीला वस्त्र पहने कृष्ण नृत्य कर रहे थे। हर गोपी के साथ कृष्ण रूप था। लेकिन इसके बाद अगला दृश्य भावुक करने वाला था। कृष्ण और दाउ जा रहे थे। राधा फूट फूटकर रो रही थीं। राधा कहती हैं मत जाओ कृष्ण। इस पर कृष्ण कहते हैं कि हे सखी, विदा की इस बेला में तुम्हारे सर्वस्व को स्वीकारते हुए। तुम्हें समर्पित है, मेरी अंतरंग सखी बांसुरी। अब ये अधर, इस बांसुरी से कभी नहीं मिलेंगे। युग धर्म के आह्वान को मैं तुमसे बिछड़ने के लिए बाध्य हूं। राधा गाती हैं...

मत जा
जोगी मत जा
पांव पड़ूं मैं तेरे जोगी
अगर चंदन की चित रचाउं
अपने हाथ जला जा।।

उधर मथुरा में धूम मची हुई है। कृष्ण का स्वागत होता है। कृष्ण, कंस के दो सैनिकों को मार देते हैं एवं कंस रोष में आकर तलवार लेकर कूद पड़ता है। कृष्ण से युद्ध करता है एवं अंत में मारा जाता है। इसके बाद कृष्ण का चहुंओर जयकारा होता है।

कागज की कश्ती पर दौड़ेगी जीवन की नैया

द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में कान्हा के लिए तैयार हो रहा छप्पन भोग। सौजन्य : इस्कॉन

बाल गोपाल कृष्ण का प्राकट्य होने ही वाला है। बस कुछ घंटे शेष हैं। कान्हा के स्वागत में तन-मन प्रफुल्लित हो रहा है। हर कोई अपनी मुराद लिए कृष्ण के दरबार में पहुंच रहा है। इस बार कागज की नाव के मार्फत कृष्ण आपकी फरियाद सुनेंगे। लीलाधारी कृष्ण तक अपनी बात पहुंचाने का यह बेहद रोचक और दिलचस्प जरिया है, जो शायद कान्हा के भी मन को खूब भाएगा।

द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में 22 से 24 अगस्त तक चलने वाले तीन दिवसीय मानसून उत्सव में कृष्ण जन्मोत्सव पर मंदिर की विशेष साज-सज्जा की गई है। छत्र को कुछ इस तरह सजाया गया है, जिससे भगवान श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने के दृश्य का सुंदर चित्रण होता है। भक्तों को लुभाने के लिए विविध रंगों से एक इंद्रधनुष पुल भी बनाया गया है। लेकिन इस बार खास आकर्षण कागज की नाव के जरिए कृष्ण तक अपनी बात पहुंचाना है। इसके लिए आपको कागज की कश्ती में प्रार्थना पत्र डालकर कृष्ण तक पहुंचाना होगा।

कृष्ण के साथ ले सकेंगे सेल्फी : खुशी के इस अवसर पर सेल्फी न ली जाए ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए मंदिर में सेल्फी लेने और उसे सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए सेल्फी प्वाइंट भी बनाए गए हैं। यहां आने वाले लोग वर्चुअल रियलिटी और रोशनी के माध्यम से तैयार श्रीकृष्ण की उपस्थिति का एहसास कर पाएंगे। इन सबके साथ ही आत्मा को छू लेने वाले भजन-कीर्तन और गीता के पाठ से आपका मन भी कृष्ण भक्ति में लीन हो जाएगा।

मानसून स्नैक्स का भी ले सकेंगे सुस्वाद

मानसून को देखते हुए कुछ यूं की गई है सजावट

कहां : इस्कॉन मंदिर
कब : 22 से 24 अगस्त, देर रात तक
प्रवेश : निश्शुल्क

आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को जानना-समझना चाहते हैं तो प्रसिद्ध वक्ताओं के साथ वार्ता सत्र में अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। आप चाहें तो गोविंदा रेस्त्रां में दोस्तों और परिवार संग स्वादिष्ट मानसून स्नैक्स का आनंद ले सकते हैं। भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के मौके पर भक्ति और उत्साह का आनंद लेने के लिए इस महीने मंदिर आएं और इस्कॉन में चल रहे मानसून उत्सव का हिस्सा बनें।

कई प्रतियोगिताएं भी : द्वारका के स्थानीय लोग नाटक, संगीत व अन्य गायन-वाचन के माध्यम से अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। जन्माष्टमी का दिन आध्यात्मिक आयोजनों और मधुर कीर्तन से ओतप्रोत होगा।

फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, अंब्रेला पेंटिंग प्रतियोगिता में बच्चे हिस्सा लेकर कृष्ण से रूबरू हो रहे हैं। आप चाहे तो मक्खन मंथन प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपने बाल-गोपाल के लिए उनका पसंदीदा भोजन भी तैयार कर सकते हैं।

परंपराओं का स्वाद...आज भी बरकरार

जायका

चूल्हा-चौका संभालते हुए करियर में नाम कमाना कैसे संभव है। आप भी कुछ ऐसा ही सोचती होंगी। है न, लेकिन तरह-तरह के व्यंजन बनाने के शौक ने निशा मधुलिका को आज सफलता के उस मुकाम पर पहुंचा दिया है, जहां पहुंचना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं। रसोई की जिम्मेदारियों को शिद्दत से निभाते-निभाते घर ही नहीं, देश-विदेश के फूड-प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली निशा आज उन तमाम महिलाओं के लिए नजीर बन गई हैं, जो यह सोचती हैं कि चूल्हा-चौका उनकी कामयाबी की राह में बाधा है।

मां को देखकर जागा शौक : निशा को बचपन से ही रसोई में समय बिताना पसंद था। जिस उम्र में बच्चे दोस्तों संग खेलने-कूदने में व्यस्त रहते हैं, वह मां के साथ रसोई में तरह-तरह के जायकेदार व्यंजन बनाना सीखती थीं। मां कुछ भी बनातीं तो उस डिश के बारे में जानने की जिज्ञासा में वह मां से उसके बारे में पूछती रहतीं। इतना ही नहीं, मां की अनुपस्थिति में उसे बनाने की कोशिश भी करतीं और बिल्कुल वैसा ही बन जाना निशा को किसी किले को फतह करने जैसा महसूस होता।

शेफ निशा मधुलिका डिश तैयार करते हुए।

ब्लॉगर से यूट्यूब शेफ तक : घर-परिवार व बच्चों की जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद जब निशा दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हुईं तो उनके पास काफी सारा खाली समय होता था। खाना बनाने का शौक था, इसलिए खाली समय में इंटरनेट पर फूड ब्लॉग पढ़ती रहतीं। उससे प्रेरित होकर 2007 में उन्होंने भी अपना एक ब्लॉग बनाया और उसमें खाने की रेसिपी शेयर करनी शुरू की। कुछ ही दिनों में अप्रत्याशित लोकप्रियता मिलती देख निशा ने यूट्यूब चैनल भी बना लिया।

हर प्रकार की डिशेज : वैसे तो निशा उत्तर भारतीय भोजन में पारंगत हैं, लेकिन धीर-धीरे हर तरह की डिश पर उन्होंने शोध किए। एक डिश को कई-कई बार बनाया और बेहतरीन स्वाद आने के बाद उसकी रेसिपी तैयार कर ली। धीरे-धीरे उनकी रेसिपी हिट होने लगी। निशा कहती हैं आज पढ़ाई व नौकरी में व्यस्त होने के कारण बच्चे आमतौर पर मां के साथ किचन में बहुत कम ही जा पाते हैं। ऐसे में सीखने के बाद भी उन्हें पाक कला का सही ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए उन्होंने यूट्यूब पर ठीक उसी प्रकार से रेसिपीज डालनी शुरू की जैसे किसी के साथ किचन में खड़े होकर खाना बना रही हों।

प्रयोगों से बनता है मजेदार जायका : निशा कहती हैं, 'हर चीज मैं अपने तरीके से बनाती हूं। पारंपरिक विधि व सामग्री को वैसा ही रखती हूं, लेकिन उसके बनाने के तरीके में बदलाव मात्र से बेहतरीन स्वाद आ जाता है।' निशा के मुताबिक वे हर साग-सब्जी, फल व अनाज से डिश बनाती हैं। चाहे वे अरबी के पत्ते हों, बैंगन हो या फिर सूरन, हर चीज की ऐसी डिश बना देती हैं कि वह हर किसी को पसंद आती है। वे आंवले का मुरब्बा पारंपरिक तरीके से उबालकर फिर चाशनी बनाकर नहीं बनातीं, इसके लिए वे आंवले को गोदकर उसे कड़ाही में डालकर बिना पानी डाले चीनी के साथ गरम करती हैं और चाशनी आंवले के रस से ही तैयार हो उसी के खट्टे-मीठे स्वाद में समा जाती है। इससे उसी मुरब्बे का बेहतरीन स्वाद मिलता है। इसी तरह फ्रेंचफ्राई बनाने के लिए आलू को काटकर सूजी मिलाकर सीधे ही तल लेती हैं। इसमें समय भी बचता है और स्वाद भी बढ़ता है।

– प्रियंका दुबे मेहता

पोहा कटलेट।

सदर्न बाइट फ्रूट सैलेड।

बैंगन पकौड़ा।

राधा माधव

कथक और ब्रज रास स्टाइल में उमा शर्मा की मनमोहक प्रस्तुति होगी। जिसे खुद उमा ने ही कोरियोग्राफ भी किया है। इसमें राधा और कृष्ण के भावनात्मक रिश्ते की झलक और उनका दिव्य प्रेम देख सकेंगे। इस जन्माष्टमी को यादगार बनाना चाहते हैं तो इससे बेहतर भला क्या हो सकता है।

- **कहां** : सीडी देशमुख ऑडिटोरियम, दक्षिणी दिल्ली
- **कब** : 24 अगस्त, शाम साढ़े छह बजे
- **प्रवेश** : निश्शुल्क

तुर्की फूड फेस्टिवल

पुलमैन नई दिल्ली एयरोसिटी, स्विसोटेल द बोस्फोरस, इस्तांबुल और तुर्की एयरलाइंस के सहयोग से तुर्की फूड फेस्टिवल की मेजबानी कर रहा है। जिसमें तुर्की के चुनिंदा डिश अदाना कबाब, मुहम्मरा, हैदरी समेत मिठाई पाइन नट, इरमिक हलवा का लाजवाब स्वाद ले सकते हैं।

- **कहां** : प्लक, पुलमैन नई दिल्ली एयरोसिटी
- **कब** : 23 अगस्त से 1 सितंबर तक। शाम सात बजे से
- **शुल्क** : उपयोग आधारित

द ग्रेट कबाब फैक्ट्री

पंजाब के जायके की बात ही निराली है। फिर चाहे लाहौरी चरगा, पटियाला भट्टी पनीर, रावलपिंडी मटन, गुजरांवाला की चाट हो या अमृतसरी आलू, रांझे का मुरग। द ग्रेट कबाब फैक्ट्री में इसका वहीं पारंपरिक स्वाद चखने को मिलेगा।

- **कहां** : द ग्रेट कबाब फैक्ट्री, रेडिसन ब्लू, फरीदाबाद
- **कब** : 25 अगस्त तक, शाम साढ़े सात से रात साढ़े ग्यारह बजे तक
- **शुल्क** : प्रति व्यक्ति 1800 रुपये

राष्ट्रीय संस्करण
शुक्रवार 23 अगस्त 2019
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

टीवीएस श्रीचक्रा ने लांच किया नया ब्रांड

नई दिल्ली (वि) : देश की प्रमुख टायर निर्माता कंपनी टीवीएस श्रीचक्रा लिमिटेड ने दो पहिया और तिपहिया बाजार को ध्यान में रखते हुए 'टीवीएस यूरोग्रिप' के नाम से एक नया ब्रांड लांच किया है। कंपनी ने देश व विदेश के ग्राहकों के बीच काफी शोध करने के बाद यह ब्रांड शुरू करने का फैसला किया है। कंपनी ने बताया है कि भारतीय बाजार के साथ ही दुनिया के 70 देशों में इन टायरों का निर्यात किया जाएगा। कंपनी की मदुरै और रूद्रपुर में दो निर्माण इकाई है।

करदाताओं की कमाई से निजी क्षेत्रों को उबारते रहे, तो प्रॉफिट हमेशा कंपनियों के खाते में जाएगा और लॉस हमेशा समाज को उठाना पड़ेगा।
— कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन, केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार

सेंसेक्स 36,472.93 ▼ 587.44	निफ्टी 10,741.35 ▼ 177.35	सोना प्रति दस ग्राम ₹ 38,970 ▲ ₹150	चांदी प्रति किलोग्राम ₹ 45,100 ▲ ₹60	डॉलर ₹71.81 ▲ ₹0.26	क्रूड (ब्रेंट) $ 59.58 प्रति बैरल

कारपोरेट हलचल

पोसोको को विश्वसनीय संस्था की मान्यता

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (पोसोको) को विद्युत ट्रांसमिशन सेवा के क्षेत्र में दुनिया की सबसे विश्वसनीय संस्था होने का पुरस्कार मिला है। वर्ष 2019 के लिए अमेरिका की इंटरनेशनल ब्रांड कंसल्टिंग कॉरपोरेशन (आइबीसी) ने अपने आकलन के पश्चात इस पुरस्कार की घोषणा की। पोसोको की ओर से निदेशक (एचआर) मीनाक्षी डावर और निदेशक (वित्त) रंजन कुमार श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से प्राप्त किया।

ईएसआइ अस्पताल का शिलान्यास

हैदराबाद के सनत नगर में केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने ईएसआइ के मेडिकल कॉलेज व अस्पताल और नए ओपीडी ब्लॉक का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी मुख्य अतिथि थे। मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की इस परियोजना पर 534 करोड़ रुपये की लागत आएगी। कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी।

ग्रोवर सीआरडब्ल्यूसी के एमडी

नरिंदर कुमार ग्रोवर ने सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड में प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण किया है। यह कंपनी देश में प्रमुख रेल टर्मिनलों पर रेल आधारित लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करती है। इससे पूर्व ग्रोवर सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में समूह महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे।

उरे महिला कल्याण संगठन का स्वतंत्रता दिवस आयोजन

उत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का आयोजन अनोखे अंदाज में किया। संगठन की अध्यक्ष हरिंदर कौर ने नई दिल्ली के केंद्रीय अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को उपहार वितरित किए और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर संगठन की उपाध्यक्ष व उत्तर रेलवे की अपर महाप्रबंधक अर्चना जोशी व संगठन की सचिव डॉ. रेणु कपूर समेत सभी सदस्य भी उपस्थित थे।

फिर पेंशन के बदले ले सकेंगे एकमुश्त रकम

वापसी ▶ वर्ष 2009 से पहले तक सरकार ने दे रखा था एक-तिहाई पेंशन के बदले एकमुश्त रकम लेने का विकल्प

'कम्यूटेशन' बहाल होने से निजी क्षेत्र के 6.3 लाख पेंशनभोगी होंगे लाभान्वित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की एक-तिहाई रकम एकमुश्त निकालने की सुविधा फिर से मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सेंट्रल ट्रस्टी बोर्ड ने इंप्लॉयी पेंशन स्कीम (ईपीएस) के सदस्यों को सेवानिवृत्ति के वक्त अपनी तिहाई पेंशन के एवज में एकमुश्त रकम लेने का विकल्प फिर से देने का निर्णय लिया है। इससे सवा छह लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

बुधवार को केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में हैदराबाद में हुई ईपीएफओ के बोर्ड की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें से एक निर्णय ईपीएस में कम्यूटेशन अर्थात पेंशन की आंशिक रकम एकमुश्त लेने का विकल्प बहाल करने के लिए ईपीएस-95 में संशोधन करने का है। भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की तरह पहले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी ईपीएस के तहत कम्यूटेशन की सुविधा मिलती थी। जिसमें रिटायर होने वाले कर्मचारी को 10 वर्ष तक एक-तिहाई पेंशन छोड़ने और बदले में एकमुश्त राशि लेने का विकल्प दिया जाता था। विकल्प चुनने वाले कर्मचारी को सिर्फ दो-तिहाई पेंशन मिलती थी जो 15 वर्ष बाद फिर पूरी हो जाती थी। लेकिन 2009 में इस विकल्प को समाप्त कर दिया गया था। अब इसे पुनः प्रारंभ करने का निर्णय हुआ है। ईपीएफओ के मुताबिक कम्यूटेशन का विकल्प बहाल होने से 2009 से पहले सेवानिवृत्त हुए तकरीबन 6.3 लाख पेंशनभोगी इसका लाभ ले सकेंगे। इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के 15 साल बाद अब पूरी पेंशन मिलेगी।

ईपीएफओ फंड का निवेश : एक अन्य निर्णय के तहत सीबीटी ने ईपीएफओ फंड के निवेश को बाजार के जोखिमों से बचाने के लिए नये पोर्टफोलियो मैनेजरों का चुनाव करने तथा डेट और इक्विटी में निवेश के तौरतरीकों में सुधार का निर्णय भी लिया है। अभी इस फंड का प्रबंधन एचएसबीसी एएमसी और यूटीआइ एएमसी के पास है। भविष्य में ईपीएफ फंड का निवेश निजी बांडों में नहीं किया जाएगा तथा पीएसयू बांड में निवेश से पहले जरूरी दो रेटिंग में से एक रेटिंग क्रिसिल, केयर या इकरा की अवश्य होगी। यही नहीं, पीएसयू के डेट प्रपत्रों में निवेश के लिए भी नया कस्टोडियन चुना जाएगा।

ऐसा मुख्यतया आइएलएंडएफएस के बांडों में 574 करोड़ तथा दीवान हाउसिंग फाइनेंस (डीएचएफसी) के बांडों में 700 करोड़ रुपये के निवेश से हुए नुकसान के मद्देनजर किया गया है। अब डेट में निवेश के लिए नए कस्टोडियन का चयन किया जाएगा और इसके लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी। जबकि इक्विटी में होने वाले निवेश को निफ्टी और सेंसेक्स से जुड़े ईटीएफ में 50:50 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। सीबीटी ने ईटीएफ संचालक कंपनियों का चयन सार्वजनिक निविदा के जरिये करने का निर्णय भी किया है।

ट्रस्टी बोर्ड ने ईपीएफ फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित समिति में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों को नामित किए जाने को भी मंजूरी दी। ये समिति क्रिसिल के अलावा एक पृथक एजेंसी का चयन एवं नियुक्ति करने के अलावा ईटीएफ को भुनाने में निवेश समिति की सहायता करेगी। ईपीएफ ने गुजरात पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (जीएसपीसी) के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचरों में 2,300 करोड़ का निवेश कर रखा है। सीबीटी ने इस निवेश को गुजरात स्टेट इंवेस्टमेंट लिमिटेड (जीएसआइएल) में स्थानांतरित करने को भी मंजूरी दी है। गुजरात सरकार की इस कंपनी ने सरकार के बजटीय समर्थन से जीएसपीसी के कर्ज को खरीदने का प्रस्ताव किया था।

पीएसयू के डेट प्रपत्रों में निवेश के लिए भी नया कस्टोडियन चुना जाएगा। प्रतीकात्मक

अभी यह हो रहा

इस समय ईपीएफओ 4.5 करोड़ से ज्यादा सदस्यों से एकत्रित 13.50 लाख करोड़ से अधिक के प्रोविडेंट फंड तथा 2.75 लाख करोड़ से अधिक के पेंशन फंड का प्रबंध संभाल रहा है। फिलहाल ईपीएफ के 85 परसेंट फंड का निवेश डेट इंस्ट्रूमेंट्स में तथा 15 परसेंट का निवेश इक्विटी में एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) के मार्फत करने का प्रावधान है। लेकिन जोखिम के डर से ईपीएफओ ने केवल 70 हजार करोड़ रुपये का निवेश ही ईटीएफ में किया है।

अभी आरबीआइ ही निपटेगा मंदी से

नितिन प्रधान, नई दिल्ली

खर्च के सीमित संसाधन और तेजी से घटती मांग को देखते हुए सरकार के पास मंदी की रफ्तार को थामने के लिए रिजर्व बैंक की मोनेटरी पॉलिसी ही प्रमुख हथियार रहेगी। मांग को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक की नीति न केवल आने वाले कुछ समय तक नरम ब्याज दर की स्थिति को बनाए रखने वाली हो सकती है बल्कि आरबीआइ नीति के जरिए मंदी से प्रभावित कुछ इंडस्ट्री सेक्टर के लिए अलग कदम भी उठा सकता है। गौरतलब है कि मार्केट में कैपिटल इनफ्लो के लिए आरबीआइ इस वर्ष अब तक रेपो रेट में 1.10 परसेंट की कटौती कर चुका है।

जानकार मान रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में सरकार के पास मंदी की रफ्तार को रोकने के उपाय बेहद सीमित हैं। रेवेन्यू में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं होने के चलते सरकार के खजाने पर काफी दबाव है। इसलिए, इकोनॉमी के लिए किसी तरह के राहत पैकेज की संभावना नहीं है। एसएंडपी समूह की रेटिंग और वित्तीय एजेंसी क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी का कहना है 'सरकार के पास राहत पैकेज देने की गुंजाइश वर्तमान में नहीं के बराबर है। इसलिए, रिजर्व बैंक की मोनेटरी पॉलिसी कुछ करने की स्थिति में हो सकती है।'

क्रिसिल की एक ताजा रिपोर्ट में इकोनॉमी के मौजूदा हालात को देखते हुए जीडीपी की वृद्धि दर के अनुमान को 7.1 परसेंट से घटाकर 6.9 परसेंट कर दिया है। एजेंसी का मानना है कि सभी तरह के उपाय करने के बावजूद जीडीपी की दर का सात परसेंट से ऊपर जाना मुश्किल है। इकोनॉमी के कई सेक्टर मांग की कमी से जूझ रहे हैं। ग्रामीण बाजार में भी मांग में कमी बनी हुई है। इसके चलते चालू वित्त वर्ष में कंपनियों का प्रदर्शन भी पिछले साल के मुकाबले कमजोर रह सकता है। क्रिसिल का मानना है साल 2019-20 में कॉरपोरेट रेवेन्यू में 7.5 से 8 परसेंट की बढ़त रहने की उम्मीद है। बीते दो वित्त वर्ष में कंपनियों के रेवेन्यू में डबल डिजिट ग्रोथ रही है। लेकिन इस साल पहली तिमाही के आकलन में कंपनियों का प्रदर्शन पिछले साल के मुकाबले निराशाजनक रहा है।

सरकार ने अगले पांच साल में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है। लेकिन जोशी मानते हैं कि जीडीपी की मौजूदा ग्रोथ रेट पर इसे पाना संभव नहीं है। इसके लिए हर साल कम से कम 8 परसेंट की जीडीपी दर की आवश्यकता होगी। 'सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पिछले ही साल यह सात परसेंट से कम हो रही है। इसे अगर दुरुस्त नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में जीडीपी की अपेक्षित दर में बढ़ोतरी होती होगी।'

अभी ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग समेत घरेलू इंडस्ट्री के कई सेक्टर मंदी से जूझ रहे हैं। ग्रामीण बाजार समेत पूरे देश में मांग बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसे देखते हुए क्रिसिल का मानना है कि इस वित्त वर्ष में ऐसे सभी सेक्टर में रेवेन्यू में सिंगल डिजिट में बढ़ोतरी होने की आशंका है। जोशी मानते हैं कि इकोनॉमी को गति देने के लिए सरकार को रिफॉर्म पर फोकस करना होगा। खासतौर पर भूमि और श्रम सुधारों पर बल देने की जरूरत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार का फोकस पहले ही बना हुआ है।

मोनेटरी पॉलिसी के माध्यम से आरबीआइ बाजार में और ज्यादा कर्ज मुहैया करा सकता है। प्रेट्र

राहत पैकेज से नाउम्मीद शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट

- 587.44 अंकों की गिरावट के साथ 36,472.93 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स
- 177.35 अंक लुढ़ककर 10,741.35 अंकों पर आ गया निफ्टी

मुंबई, प्रेट्र : सुस्त अर्थव्यवस्था के बीच सरकार से कई सेक्टरों के लिए राहत पैकेज की उम्मीद कर रहे निवेशकों को गुरुवार को तगड़ा झटका लगा। केंद्र सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों से शेयर बाजारों को ऐसा संदेश गया कि सरकार किसी भी सेक्टर विशेष को राहत पैकेज देने के बारे में नहीं सोच रही है। इसके चलते गुरुवार को बीएसई का 30-शेयरों वाला सेंसेक्स 587.44 अंकों यानी 1.62 फीसद की गिरावट के साथ 36,472.93 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 177.35 अंक यानी 1.62 फीसद लुढ़ककर 10,741.35 अंकों पर आ गया।

दोनों प्रमुख इंडेक्स की यह लगातार तीसरे कारोबारी सत्र की गिरावट थी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने गुरुवार को कहा कि मंदी से गुजर रही कंपनियों को उबारने के लिए करदाताओं के पैसे का उपयोग करना अच्छी बात नहीं है। इससे नैतिक स्तर पर कई बाधाएं आएंगी और इसे मार्केट इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। वहीं, ऊर्जा सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का कहना था कि सरकार की तरफ से राहत पैकेज देने से बेहतर यह है कि निजी क्षेत्र को कम दरों पर आसानी से कर्ज मुहैया कराया जाए। जानकारों का कहना था कि इन बयानों के चलते उद्योग जगत की सेक्टर विशेष को राहत पैकेज की उम्मीदें धूमिल होने लगी हैं। दिन के कारोबार में सेंसेक्स पैक में सबसे बड़ा झटका यस बैंक के शेयरों को लगा, जो 13.91 फीसद तक टूट गए। वेदांता, बजाज फाइनेंस और टाटा मोटर्स के शेयरों में 7.76 फीसद तक की गिरावट आई। ओएनजीसी, एसबीआइ, हीरो मोटोकॉर्प, आइसीआइसीआइ बैंक, एचडीएफसी बैंक, आरआइएल व एचडीएफसी के शेयर भी टूटे। सेंसेक्स में 30 शेयरों में से सिर्फ टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचयूएल और एचसीएल टेक के शेयर हरे निशान के साथ बंद होने में कामयाब रहे।

दिन के कारोबार के बारे में बीएनपी पारिबा के एडवाइजरी हैड हेमांग जानी ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपये के और गिर जाने के चलते घरेलू शेयर बाजार पहले से ही दबाव में थे। रही-सही कसर कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन और सुभाष चंद्र गर्ग के बयानों ने पूरी कर दी। दोनों ने कहा है कि सेक्टर विशेष को राहत पैकेज की जगह अन्य तरीके अपनाए जा सकते हैं। घरेलू बाजारों में अन्य अनिश्चितताओं, विदेशी फंड्स का निवेश घटने तथा डॉलर के मुकाबले रुपये के टूटने का भी बाजारों पर बुरा असर पड़ा।

मंदी से निपटने को उपायों पर विचार जारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने गुरुवार को कहा है कि मौजूदा आर्थिक सुस्ती ने निपटने के लिए कई उपायों पर विचार जारी है। ये उपाय सही समय आने पर किए जाएंगे, ताकि इकोनॉमी के जुझारूपन को सामने लाया जाए। उनका कहना था कि आइएलएंडएफएस और उसकी ग्रुप कंपनियों के डिफॉल्टर होने के बाद से सरकार और आरबीआइ ने फाइनेंशियल सेक्टर को मदद करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकारी बैंकों ने एनबीएफसी को आसान कर्ज मुहैया कराया है।

वित्तीय क्षेत्र में दबाव से अर्थव्यवस्था में नरमी के बारे में बताते हुए कुमार ने कहा कि पूरी स्थिति 2009-14 के दौरान बिना सोचे-समझे दिए गए कर्ज का नतीजा है। इससे 2014 के बाद एनपीए बढ़ा है। कुमार ने यह भी कहा कि सरकार को ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे निजी क्षेत्र की कंपनियों की आशंकाओं को दूर किया जा सके और वे निवेश के लिए प्रोत्साहित हों। आर्थिक नरमी को लेकर चिंता के बीच उन्होंने यह बात कही। उन्होंने वित्तीय क्षेत्र में बने अप्रत्याशित दबाव से निपटने के लिए लीक से हटकर कदम उठाने पर जोर दिया। कुमार ने फाइनेंशियल सेक्टर पर दबाव को अप्रत्याशित बताते हुए कहा कि किसी ने भी पिछले 70 साल में ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया, जब पूरा फाइनेंशियल सिस्टम दबाव में है।

पहली तिमाही में ग्रोथ रेट छह परसेंट तक रहने का अनुमान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जीडीपी ग्रोथ रेट धीमी पड़ने का संकेत देते हुए चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 5.5 से छह परसेंट के बीच रह सकती है। ग्रोथ को लेकर यह अनुमान ऊर्जा सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने व्यक्त किया है, जो इससे पहले वित्त सचिव भी रह चुके हैं। उनका कहना है कि चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में ग्रोथ रेट धीमी रहने की वजह मांग में कमी आना और चुनाव के चलते सरकारी खर्च कम रहना है।

गर्ग ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है जब इंडस्ट्री से लेकर विशेषज्ञों तक हर कोई इकोनॉमी के अलग-अलग क्षेत्रों में मंदी की आहट की चर्चा कर रहा है। रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक में भी गवर्नर तथा अन्य सदस्यों ने इकोनॉमी में धीमेपन को लेकर चिंता जतायी है। गर्ग ने ट्वीट कर कहा, ''आज माइंडमाइन समिट में मैंने कहा है कि पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 5.5 से छह परसेंट रहने का अनुमान है। इसकी वजह चुनाव के चलते सरकारी खर्च कम रहना और मांग में कुछ कमी आना है।'

गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष में ग्रोथ रेट घटकर 6.8 परसेंट रह गया था जो गत पांच वर्षों में न्यूनतम है। हाल यह है कि पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च) में ग्रोथ रेट घटकर मात्र 5.8 परसेंट रह गया है। ऐसे में चालू वित्त वर्ष में अगर ग्रोथ रेट साढ़े पांच परसेंट के आस-पास रहता है तो इसे ऊपर उठाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। आरबीआइ की एमपीसी बैठक में भी इकोनॉमी के ग्रोथ रेट में कमी आने को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। एमपीसी की मिनट्स से साफ है कि कई सदस्यों ने इस संबंध में चिंता जताई। एमपीसी सदस्य डा. पामी दुआ ने आइआइपी में गिरावट का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी में धीमेपन की ओर ध्यान आकर्षित भी किया।

एमएसएमई के लिए बनेगा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म

- भारतक्राफ्ट नाम से नया पोर्टल शुरू करने की तैयारी में सरकार
- एनएसई एमर्ज में लिस्ट कंपनियों का मार्केट कैप 8,800 करोड़ रुपये

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार लघु और मझोली कंपनियों के लिए ई-कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म शुरू करने पर विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि भारतक्राफ्ट नाम से शुरू होने वाले इस पोर्टल से अगले दो तीन साल में 10 लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलने की संभावना बनेगी। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक यह पोर्टल अलीबाबा और अमेजन की तर्ज पर काम करेगा और एमएसएमई इकाइयों को उत्पादों की बिक्री का प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमएसएमई प्लेटफॉर्म एनएसई एमर्ज में 200वीं कंपनी के लिस्टिंग के मौके पर गडकरी ने मुंबई में कहा कि सरकार एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देना चाहती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह सेक्टर मैन्यूफैक्चरिंग में 29 परसेंट का योगदान कर रहा है। इसके अलावा एक्सपोर्ट में इसकी हिस्सेदारी 40 परसेंट की है। एनएसई में गुरुवार को वंडर फाइब्रोमैट की लिस्टिंग हुई।

गडकरी ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर में अगले पांच साल में पांच करोड़ अतिरिक्त रोजगार देने की संभावना है। इसलिए सरकार ने अगले पांच साल में एमएसएमई सेक्टर की मैन्यूफैक्चरिंग में हिस्सेदारी 50 परसेंट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने एमएसएमई सेक्टर की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि इन कंपनियों के लिए भुगतान प्राप्त करना सबसे बड़ी दिक्कत है। सरकार और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से इन्हें मिलने वाले भुगतान में आमतौर पर देरी होती है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। अगले कुछ दिनों में इसकी रिपोर्ट आने की उम्मीद है।

छह करोड़ में सिर्फ 200 लिस्टेड : गडकरी ने कहा कि देश में इस वक्त करीब छह करोड़ एमएसएमई हैं। लेकिन इनमें से केवल 200 एमएसएमई ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो पाई हैं। साल 2012 में इन कंपनियों की लिस्टिंग शुरू होने के बाद ये बाजार से 3,100 करोड़ रुपये जुटा पाई हैं। इन कंपनियों का मार्केट कैप 8,800 करोड़ रुपये के आसपास बना हुआ है। इनमें से भी 22 कंपनियां एनएसई के मुख्य स्टॉक एक्सचेंज में अपग्रेड हो चुकी हैं।

एनएसई के एमडी व सीईओ विक्रम लिमये ने इस मौके पर कहा कि एनएसई हमेशा से छोटी और मझोली कंपनियों के विकास की दिशा में काम करता रहा है। ये कंपनियां न केवल इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने में मददगार हैं बल्कि रोजगार भी उपलब्ध कराती हैं।

प्रतीकात्मक

बेपरवाही

जीडीपी के अनुपात में आरएंडडी पर खर्च करने के मामले में भारत काफी पीछे, आरएंडडी पर होने वाले खर्च में सरकार की अपेक्षा कंपनियों का कम योगदान

आरएंडडी पर खर्च करने में भारतीय कंपनियां कंजूस

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली

इकोनॉमी की रफ्तार जरा सी धीमी पड़ने पर मंदी का हौवा दिखाकर भारतीय कंपनियां अपनी सेल बढ़ाने को सरकार से प्रोत्साहन पैकेज की मांग तो करती हैं। लेकिन वे ग्राहकों की अपेक्षा के अनुरूप प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सुधारने को आरएंडडी पर खर्च करने में कंजूसी बरतती हैं। भारत में आरएंडडी पर जितनी राशि खर्च होती है उसमें इंडस्ट्री का योगदान काफी कम है जबकि अमेरिका व इजरायल जैसे विकसित देशों और पड़ोसी चीन में यह काफी अधिक है। आरएंडडी पर पर्याप्त निवेश के अभाव के चलते भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल ट्रेड में पहचान नहीं बना पाते हैं।

यूनेस्को के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 में भारत में आरएंडडी पर खर्च (पीपीपी आधार पर) 48.1 अरब डॉलर था जिसमें 29 अरब डॉलर सरकार ने खर्च कि। मात्र 17 अरब डॉलर इंडस्ट्री ने खर्च किए। दूसरी ओर चीन के कुल 371 अरब डॉलर आरएंडडी खर्च में सरकार ने सिर्फ 59 अरब डॉलर खर्च किए, जबकि कंपनियों का खर्च 286 अरब डॉलर रहा। इसी तरह अमेरिका में भी आरएंडडी पर हुए कुल 479 अरब डॉलर के खर्च में 54 अरब डॉलर सरकार की ओर से खर्च हुए जबकि बिजनेस एंड इंडस्ट्री सेक्टर ने 341 अरब डॉलर खर्च किए। इसी प्रकार इजरायल के भी कुल आरएंडडी खर्च में लगभग 80 परसेंट बिजनेस सेक्टर ने ही खर्च किया। आरएंडडी पर खर्च के संबंध में यूनेस्को के इन आंकड़ों का जिक्र करते हुए इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 में यह तथ्य रेखांकित किया गया है कि बीते दो दशकों में भारत के आरएंडडी खर्च में कुछ खास वृद्धि नहीं हुई है।

लोकल सर्किल्स के फाउंडर एंड चेयरमैन सचिन तापड़िया का कहना है, 'भारत में सरकार और कारोबार जगत दोनों ही जगह रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस सीमित है, ऐसी स्थिति में जब भी घरेलू इकोनॉमी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती है तो कारोबारियों के पास सीमित विकल्प होते हैं और वे सरकार से प्रोत्साहन पैकेज की मांग उठाना शुरू कर देते हैं। हमारी अधिकांश व्यवसायिक इकाइयां निचले और मध्यम दर्जे के उत्पादन और वैल्यू एडीशन के मामले में अच्छा काम करती हैं। लेकिन ग्राहकों को जिन नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट की तलाश रहती है, उसका उनके पास सर्वथा अभाव है। इस स्थिति में तभी बदलाव संभव है जब सरकार और इंडस्ट्री एक साथ आकर एक एक्शन प्लान बनाकर इनोवेशन को प्रोत्साहित करें।' यूनेस्को के अनुसार जीडीपी के अनुपात में आरएंडडी पर सबसे ज्यादा खर्च इजरायल का है। वर्ष 2015 में इजरायल ने आरएंडडी पर उसके जीडीपी का 4.28 परसेंट खर्च किया। इसी तरह जापान अपने जीडीपी का 3.28, डेनमार्क 3.07, ऑस्ट्रिया 3.05, जर्मनी 2.92 और चीन 2.06 परसेंट राशि आरएंडडी पर खर्च करता है। हालांकि भारत अपने जीडीपी का मात्र 0.62 परसेंट ही आरएंडडी पर खर्च करता है।

चौंकाने वाली बात यह है कि बीते दो दशकों से भारत का आरएंडडी खर्च जीडीपी के अनुपात में लगभग स्थिर बना हुआ है। इस अवधि में जहां अन्य देशों ने आरएंडडी पर खर्च बढ़ाया है वहीं भारत में यह स्थिर रहा है। उदाहरण के लिए 1996 में भारत अपने जीडीपी के अनुपात में आरएंडडी पर 0.65 परसेंट राशि खर्च करता था जबकि चीन का खर्च मात्र 0.56 परसेंट था। हालांकि 1999 में चीन ने इस मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया और अब वह काफी आगे निकल चुका है। इस अवधि में चीन कारोबारी गतिविधियों के मामले में भी भारत से काफी आगे निकल गया है।

सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत सभी देशों को 2030 तक न सिर्फ आरएंडडी पर खर्च बढ़ाना है बल्कि रिसर्च और इनोवेशन में लगे लोगों की संख्या भी बढ़ानी है। हालांकि भारत में इस दिशा में कुछ खास प्रगति नहीं हुई है। वर्ष 2015 में अमेरिका में दस लाख की आबादी पर 4,231 रिसर्चर (शोधार्थी) थे। जबकि इजरायल में यह आंकड़ा 8,255, चीन में 1,113 और भारत में मात्र 156 था।

प्रतीकात्मक

सोना 39,000 रुपये के करीब, चांदी भी मजबूत

- 150 रुपये चढ़कर 38,970 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोने का भाव
- 60 रुपये प्रति किलोग्राम का उछाल दर्ज किया गया चांदी के भाव में

नई दिल्ली, प्रेट्र : घरेलू सराफा कारोबारियों द्वारा लगातार खरीदारी के चलते गुरुवार को सोना 150 रुपये उछलकर 38,970 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। चांदी के भाव में भी 60 रुपये प्रति किलोग्राम का उछाल आया। इस उछाल के साथ गुरुवार को कारोबार के आखिर में चांदी 45,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। पिछले कुछ दिनों के दौरान सोना और चांदी के भाव में रह-रहकर बड़ा उछाल आया है।

विदेशी बाजारों में सोने और चांदी के भाव में सुस्ती दिख रही थी। इसके बावजूद घरेलू बाजार में निवेशकों ने दोनों बहुमूल्य धातुओं में दिलचस्पी बरकरार रखी। घरेलू इक्विटी बाजारों की हालत अच्छी नहीं होने और डॉलर के मुकाबले रुपये के टूटने की वजह से भी निवेशकों ने सोने में निवेश जारी रखा। जानकारों के मुताबिक सिक्का निर्माताओं और औद्योगिक इकाईयों के भरपूर समर्थन की बदौलत ही चांदी और सुधरकर बंद होने में कामयाब रही।

न्यूयॉर्क में सोने का भाव सुस्ती के साथ 1,498.80 डॉलर, जबकि चांदी का भाव मामूली टूटकर 17.09 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) रह गया। नई दिल्ली में 99.9 फीसद खरा सोना 38,970 रुपये, जबकि 99.5 फीसद खरा सोना 38,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। आठ ग्राम सोने की गिन्नी का भाव 28,800 रुपये के पिछले स्तर पर बना रहा। चांदी हाजिर 60 रुपये मजबूत होकर 45,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर जा पहुंची। चांदी का सप्ताह आधारित डिलिवरी भाव 133 रुपये सुधरकर 43,765 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। चांदी के सिक्कों का भाव प्रति सैकड़ा 91,000 रुपये खरीद और 92,000 रुपये बिक्री के पिछले स्तर पर बना हुआ था।

233 करोड़ रुपये दिए हैं भारत ने नेपाल को सड़क और 2015 में आए भूकंप में ध्वस्त हुए घरों के पुनर्निर्माण के लिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गत दिवस अपने नेपाली समकक्ष प्रदीप ज्ञवाली के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक और सार्थक बातचीत की है।

भारत के साथ वार्ता करने से पीछे हट रहा है पाकिस्तान

चौतरफा दबाव झेल रहे पाक के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच युद्ध भड़कने की आशंका जताई

इस्लामाबाद, आइएएनएस : भारत के साथ वार्ता करने के लिए चौतरफा दबाव झेल रहे पाकिस्तान ने नई दिल्ली के साथ बातचीत करने से इन्कार किया है। इस्लामाबाद ने कहा है कि नई दिल्ली से बातचीत करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। इसके साथ ही उसने परमाणु शक्ति से लैस दोनों देशों के बीच युद्ध भड़कने की आशंका जताई है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने न्यूयार्क टाइम्स को दिए गए साक्षात्कार में कहा है, 'भारत के साथ बातचीत का कोई फायदा नहीं है। उनके साथ बातचीत के लिए मैं सब कुछ कर चुका हूं। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि जब मैं वार्ता और शांति की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने इसे तुष्टिकरण की कोशिश के तौर पर लिया। अब बातचीत का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो हम कर सकते हैं।'

इस्लामाबाद स्थित अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में साक्षात्कार देने के एक दिन बाद इमरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संवाद बहाली की हर अपील ठुकराने की शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्त करने से पहले और बाद में अपील की थी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि परमाणु हथियार से लैस दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच कुछ भी हो सकता है। हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह दुनिया के लिए चेतावनी है।

भारत ने इमरान की आलोचना को खारिज किया : न्यूयार्क टाइम्स संपादकीय बोर्ड में पहुंचे अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन ने इमरान की आलोचना को खारिज किया। भारतीय राजदूत ने कहा, 'हमारा अनुभव यह है कि जब भी हमने शांति की दिशा में पहल की, हमारे लिए उसका परिणाम बुरा ही रहा। हम पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय, स्थिर और पुष्टि योग्य कार्रवाई की उम्मीद करते हैं।'

कश्मीर मुद्दे पर प्रवासी पाकिस्तानियों से मदद मांगी : इमरान ने विदेश में रहने वाले अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने में मदद करने की मांग की है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने सभी विश्व मंचों पर कश्मीर मुद्दे को उठाने का फैसला लिया है।

मोदी की न्यूयार्क यात्रा के दौरान प्रदर्शन करेंगे पाकिस्तानी : इमरान खान ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूयार्क यात्रा के दौरान प्रदर्शन करने को कहा है। इमरान फैसला लिया है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता दुनिया के मंच पर उत्तर देने के लिए विशाल प्रदर्शन करेंगे।

भारत स्वीकार करे तो मध्यस्थता प्रस्ताव पर प्रगति संभव : पाक के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा है कि कश्मीर मामले पर मध्यस्थता के कई प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन इस दिशा में कोई भी प्रगति तभी होगी जब भारत उन्हें स्वीकार करे। प्रवक्ता ने कहा कि करतारपुर गलियारे की परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बांग्लादेश से म्यांमार जाने को राजी नहीं है कोई भी रोहिंग्या

ढाका, एएफपी : बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार ले जाने की कोशिशें फिर नाकाम होती दिख रही हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार वापस भेजने के लिए गुरुवार को पांच बसें और दस ट्रक बांग्लादेश के टेकनाफ शरणार्थी शिविर पहुंचे। लेकिन एक भी रोहिंग्या परिवार म्यांमार जाने को राजी नहीं हुआ। इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी शरणार्थियों को वापस भेजने की कोशिश विफल रही थी।

बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों में म्यांमार में अपनी सुरक्षा और नागरिकता को लेकर संशय बरकरार है। वर्ष 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए लाखों रोहिंग्या मुसलमान पड़ोसी देश बांग्लादेश आ गए थे। तब से उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर कई बार प्रयास किए जा चुके हैं। म्यांमार के शीर्ष अधिकारियों ने हाल में बांग्लादेश आकर शरणार्थियों को वापस लेने का आश्वासन भी दिया था। रोहिंग्या विस्थापन मुद्दे पर नजर रख रहे संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने बुधवार को कहा था कि शरणार्थियों की वापसी उनकी इच्छा से होनी चाहिए।

चीन में तूफान ने मचाई तबाही

चीन के दक्षिण-पश्चिमी सिचुआन प्रांत के वेनचुआन काउंटी में बुधवार देर रात भारी बारिश और तूफान के कारण नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन के कर्मचारी उनकी खोजबीन में लगे हुए हैं। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कें टूट गईं तो कई क्षेत्रों में पानी भरने से लोगों परेशानी का सामना करना पड़ा। एएफपी

न्यूज गैलरी

अमेरिका में दुष्कर्मी हत्यारे को दी गई मौत

वाशिंगटन : अमेरिका के टेक्सास प्रांत में दुष्कर्म के बाद हत्या को अंजाम देने वाले लैरी स्वीयरिंजेन(48) को जहर का इंजेक्शन देकर बुधवार को मौत की सजा दी गई। इस साल टेक्सास में मौत की सजा का यह चौथा मामला है। 1998 में लैरी ने एक 19 साल की युवती के साथ इस अपराध को अंजाम दिया था। मामले में उसे दो साल बाद दोषी करार दिया गया था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की फांसी की सजा पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। इसे मिलाकर अमेरिका में इस साल 12 लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है। (एएफपी)

इंडोनेशिया ईस्ट कलिमांतन प्रांत में बनाएगा नई राजधानी

जकार्ता : इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी बोर्नियो द्वीप स्थित ईस्ट कलिमांतन प्रांत में बनाने का निर्णय लिया है। देश के भूमि योजना मंत्री सोफयां जलील ने गुरुवार को यह बात बताई। पिछले हफ्ते इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने देश की राजधानी जकार्ता से बदलकर दूसरी जगह करने का इरादा जताया था। इसके पीछे वर्तमान राजधानी जकार्ता में अधिक आबादी और भारी प्रदूषण वजह माने जा रहे हैं। (रायटर)

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सोहो हाउस विश्व के श्रेष्ठ स्थलों में

न्यूयार्क : टाइम पत्रिका की ओर से 2019 में विश्व के महानतम स्थानों को लेकर जारी दूसरी वार्षिक सूची में गुजरात की 597 फुट ऊंची 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' और मुंबई के सोहो हाउस ने अपनी जगह बनाई है। यह सूची 100 नए और नए गौर करने लायक गंतव्य स्थानों का संकलन है जिनका तत्काल अनुभव किया जाना चाहिए। 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो आजाद भारत के पहले गृह मंत्री के साथ ही उपप्रधानमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि है। मुंबई का फैशनेबल सोहो हाउस 11 मंजिली इमारत में स्थित है जहां से अरब सागर नजर आता है। इसमें एक पुस्तकालय, 34 सीटों वाला एक सिनेमाघर और खुली छत में बना एक बार और पुल है। (प्रेट्र)

लंदन में आंबेडकर स्मारक को बंद करने के खिलाफ

लंदन : भारत सरकार ने यूके काउंसिल द्वारा उत्तरी लंदन में स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर को समर्पित स्मारक को बंद करने के निर्णय के खिलाफ अपील की है। जांच समिति इस पर 24 सितंबर को सुनवाई करेगी। आंबेडकर हाउस उत्तरी लंदन में 10 किंग हेनरी रोड पर स्थित है। 1921-22 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के दौरान वह यहां पर रहा करते थे। इस चार मंजिला आवासीय इमारत को नवंबर 2015 में महाराष्ट्र सरकार ने खरीद लिया था और यहां स्मारक बनाने का निर्णय लिया था। पीएम मोदी ने नंवबर 2015 में इसका उद्घाटन किया था। (प्रेट्र)

जन्मजात नागरिकता के अधिकार को खत्म करने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप

सख्त रुख ▶ अमेरिकी राष्ट्रपति ने जन्म के आधार पर नागरिकता को बताया बकवास

अधिकार समाप्त होने पर बड़ी संख्या में भारतीय भी होंगे प्रभावित

वाशिंगटन, प्रेट्र/आइएएनएस : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता के अधिकार को खत्म करने की तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि वह अमेरिका में जन्म लेने वाले उन बच्चों के नागरिकता के अधिकार को खत्म करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं, जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं हैं। ट्रंप अगर इस अधिकार को समाप्त कर देते हैं तो इससे बड़ी संख्या में भारतीय भी प्रभावित होंगे।

जन्म के आधार पर नागरिकता के बारे में पूछे गए एक सवाल पर ट्रंप ने कहा, 'हम इस पर बेहद गंभीरता से विचार कर रहे हैं। साफ तौर पर कहूं तो यह बकवास है।' ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान यह वादा किया था कि वह जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता के अधिकार को खत्म कर देंगे। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में अमेरिका में जन्म लेने वाले ऐसे बच्चों को भी देश की नागरिकता देने की गारंटी दी गई है, जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं हैं।

डोनाल्ड ट्रंप। रायटर

शरणार्थी परिवारों को बंदी बनाने के नए नियम का एलान : ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को एक नियम का एलान किया, जिससे अमेरिका के इमिग्रेशन अधिकारियों को शरणार्थी परिवारों को अनिश्चितकाल तक बंदी बनाए रखने का अधिकार मिल जाएगा। नए नियमों से शरणार्थी परिवारों के बच्चों को 20 दिन से ज्यादा हिरासत में रखने का प्रावधान भी खत्म हो गया है। वर्ष 2017 में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से ही ट्रंप ने अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल होने वाले शरणार्थियों को लेकर सख्त रुख अपना रखा है।

भारत ने अफगानिस्तान में खास नहीं किया : राष्ट्रपति

वाशिंगटन, प्रेट्र : भारत, ईरान, रूस और तुर्की ने अफगानिस्तान में आतंकवाद से बहुत कम लड़ाई लड़ी जबकि अमेरिका ने सात हजार मील दूर जाकर वहां लड़ाई लड़ी। नजदीक होते हुए भी भारत और पाकिस्तान ने वहां कुछ खास नहीं किया। यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। उन्होंने कहा, अन्य देशों ने अफगानिस्तान में आतंकवाद को खत्म करने के लिए बहुत कम प्रयास किए। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा- रूस, ईरान, इराक और तुर्की अपनी लड़ाई लड़ते रहे लेकिन इस दौरान अमेरिका ने आतंकी संगठन आइएस का खात्मा कर दिया। अमेरिका ने यह कार्य रिकॉर्ड समय में किया। उन्होंने कहा, बाकी के देश जिनके आसपास आइएस अभी मौजूद है, वे यह दावा नहीं कर सकते। भारत अफगानिस्तान में मौजूद है, काम कर रहा है लेकिन पाकिस्तान ने जो किया वह बहुत कम किया।

ट्रंप ने कहा, चीन से ट्रेड वार में हो रहा नुकसान

वाशिंगटन, एपी : कई मौकों पर चीन को ट्रेड वार में खून के आंसू रुलाने और जबर्दस्त आर्थिक झटका देने का दावा करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार माना है कि इस लड़ाई से उनके देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। ट्रंप ने माना कि उनके इस कदम से अमेरिका की अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर सकती है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि लंबी अवधि के फायदे के लिए छोटी अवधि का यह नुकसान झेलने के लिए वे तैयार हैं। ट्रंप का यह भी कहना था कि घरेलू अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वे अपने नागरिकों पर टैक्स की दर घटाने के बारे में सोच रहे हैं। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि वे यह नहीं मानते कि अमेरिका दो-तीन महीनों में ही आर्थिक मंदी की ओर चला जाएगा। यह सोच अप्रासंगिक है। हम आर्थिक मंदी से बहुत दूर हैं। लेकिन हम मंदी से भी नहीं डरते। सच यह है कि किसी न किसी को चीन से दो-दो हाथ करने ही थे।

ब्रेक्जिट पर ब्रिटेन को बड़ी राहत नहीं देंगे मैक्रों

पेरिस में एक बैठक के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। एएफपी

पेरिस, एएफपी : फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ब्रेक्जिट मामले में विस्तृत चर्चा के विचार का समर्थन किया है लेकिन इसके लिए बहुत विलंब होने की बात भी कही। मैक्रों ने यह बात गुरुवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात के दौरान कही। मुलाकात से पहले मैक्रों ने जॉनसन के साथ कोई बड़ा समझौता होने की संभावना से इन्कार किया था।

मैक्रों ने कहा, वह ब्रेक्जिट (यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन का अलगाव) मसले में 30 दिन की वार्ता की जरूरत महसूस करते हैं लेकिन अब उसमें विलंब हो गया है। उल्लेखनीय है कि ब्रेक्जिट के लिए 31 अक्टूबर की तारीख प्रस्तावित है। इस दौरान ब्रिटिश संसद में अलगाव का मसौदा स्वीकृति के लिए जाएगा। बुधवार को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने जॉनसन से मुलाकात में जटिल मसलों पर वार्ता के लिए 30 दिन की वार्ता का समर्थन किया था।

यह वार्ता आयरलैंड को लेकर होनी है। फिलहाल आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड को यूरोपीय यूनियन की ओर से कई सुविधाएं प्राप्त हैं। लेकिन ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद ये सुविधाएं खत्म हो जाएंगी।

मिसाइल परीक्षण पर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग

यूएनएससी के स्थायी सदस्य रूस और चीन ने की मांग

संयुक्त राष्ट्र, रायटर : रूस और चीन ने मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के विकास और एशिया में इनकी तैनाती की अमेरिका की योजना पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की बैठक बुलाने की मांग की है। अमेरिका ने हाल में ही नई क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। साथ ही, एशिया में अपनी मिसाइलें तैनात करने की मंशा जताई थी।

रूस और चीन अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए उपजे खतरे के एजेंडे के तहत 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाना चाहते हैं। रूस और चीन यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामले के प्रमुख इजुमी नाकामित्सु से यह आग्रह भी किया है कि वह इस बारे में परिषद को अवगत कराएं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने सोमवार को बताया था कि उसने एक पारंपरिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल करीब 500 किलोमीटर दूर लक्ष्य को भेदने में सफल रही।

रूस के साथ परमाणु हथियार संधि खत्म होने के बाद अमेरिका का यह पहला मिसाइल परीक्षण था। इस परीक्षण पर रूस और चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इस परीक्षण के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने एक इंटरव्यू में कहा था, 'हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम अपनी क्षमता के बूते चीन के बुरे बर्ताव को रोक सकें।' बता दें कि पिछले महीने कई मौकों पर अमेरिकी रक्षा विभाग एशिया में अपनी मिसाइलों को तैनात करने की बात कह चुका है।

रूस देगा अमेरिकी मिसाइल का जवाब : पुतिन

हेलसिंकी, आइएएनएस : अमेरिका के हालिया मिसाइल परीक्षण पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में कहा, अमेरिका के इस कदम से हमारे देश को नया खतरा पैदा हो गया है। इसका जवाब दिया जाएगा।

भारत की स्वास्थ्य सेवा वेबसाइट से चोरी हुए 68 लाख रिकार्ड

नई दिल्ली,आइएएनएस : अमेरिकी का साइबर सुरक्षा फर्म फायरआइ ने बताया कि चीनी हैकरों ने भारत की एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा की वेबसाइट को हैक कर लिया है। हैकरों ने मरीजों और डॉक्टरों की जानकारी वाले 68 लाख रिकार्ड चुरा लिए हैं। वेबसाइट का नाम बताए बगैर फायर आइ ने बताया कि ज्यादातर चीनी हैकर भारत सहित दुनिया भर में स्वास्थ्य संगठनों और वेब पोर्टलों से चोरी किए गए डाटा को बेच रहे हैं। यह जानकारियां कई बार दो हजार डॉलर से भी कम कीमत पर बेची जाती हैं।

साइबर सुरक्षा कंपनी ने गुरुवार को बताया कि फरवरी में भारत स्थित स्वास्थ्य सेवा वेबसाइट से जुड़े 6,800,000 रिकार्ड चुरा लिए हैं। इसमें रोगी की जानकारी और व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी (पीआइआइ), डॉक्टर की जानकारी और पीआइआइ और परिचय पत्र शामिल हैं। फायरआई ने एक रिपोर्ट साझा करते हुए कहा कि एक अक्टूबर, 2018 और 31 मार्च, 2019 तक स्वास्थ्य सेवा से जुड़े डाटाबेस देखे, इसके बाद ये बात सामने आई हैं। रिपोर्टों से पता चला है कि हाल के दशकों में कैंसर की मृत्यु दर में वृद्धि हुई है, जिसमें कैंसर चीनी लोगों की मौत का प्रमुख कारण बन रहा है।

अब कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे हांगकांग के छात्र

लोकतंत्र की मांग के आंदोलन को लंबा करने की तैयारी

बैंक और कारोबार जगत हालात से चिंतित अर्थव्यवस्था को पहुंच सकता है नुकसान

हांगकांग, एपी : लोकतंत्र की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हांगकांग विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने कहा है कि चीन सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब वे कक्षाओं के बहिष्कार का आह्वान करेंगे। हांगकांग करीब तीन महीने से आंदोलन का सामना कर रहा है। इसके चलते वहां लगातार अराजक स्थिति बनी हुई है।

हांगकांग के दस विश्वविद्यालयों के छात्र संघ नेताओं ने कहा है कि सितंबर के शुरुआती दो हफ्तों में कक्षाओं का बहिष्कार किया जाएगा। चीन की प्रतिनिधि शीर्ष अधिकारी कैरी लैम ने यदि युवाओं की मांगों पर 13 सितंबर तक सकारात्मक जवाब नहीं दिया तो आंदोलन के अगले चरण पर विचार किया जाएगा। हांगकांग विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यकारी अध्यक्ष डेविन वोंग ने कहा, छात्रों की पांच मांगों पर विचार करने के लिए दो सप्ताह का समय पर्याप्त है। सरकार इस दौरान विचार के बाद फैसला ले सकती है। गुरुवार को हाई स्कूल के छात्रों ने डाउन टाउन स्क्वायर पर जनसभा कर लोकतंत्र संबंधी अपनी मांगों से युवाओं को अवगत कराया। सैकड़ों की संख्या में किशोर काली पोशाक आए इन छात्रों ने हांगकांग की आजादी को लेकर भी नारे लगाए।

आंदोलन से पैदा हुए हालात और हिंसा की हांगकांग की बैंकों ने निंदा की है। एचएसबीसी ने वार्ता के जरिये समस्या के समाधान की अपील की है। बैंकों ने शांतिपूर्ण समाधान के लिए सहयोग देने की भी पेशकश की है। महानगर में होने वाले इंटरनेशनल ज्वेलरी फेयर पर भी संकट के बादल छा रहे हैं। हीरा कारोबार से जुड़े दुनिया के कई संगठनों ने इस फेयर को टालने की अपील की है। आंदोलन के लंबा खिंचने की आशंका के चलते कारोबार जगत भी अपने भविष्य पर विचार करने लगा है।

बता दें कि बीते जून माह से हांगकांग में प्रस्तावित प्रत्यर्पण कानून के विरोध में शुरू हुए आंदोलन के बाद अब वहां लोकतंत्र के समर्थन में भी आवाज उठने लगी है।

राष्ट्रपति उम्मीदवारी की रेस से हटे वाशिंगटन के गवर्नर जे इंसली

ओलंपिया, एपी : वाशिंगटन के गवर्नर जे इंसली ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी का उम्मीदवार बनने की रेस से हटने का एलान कर दिया है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आवाज बुलंद करने वाले 68 वर्षीय इंसली ने हालांकि पिछली दो बहसों में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वह उम्मीदवारी के लिए जरूरी दो फीसद समर्थन हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने एक लाख तीस हजार लोगों से चंदा भी जुटाया था, लेकिन यह उनकी उम्मीदवारी बचाए रखने में नाकाफी रहा।

वाशिंगटन के गवर्नर जे इंसली की फाइल फोटो। एएफपी

अगले चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देने के लिए डेमोक्रेट पार्टी में करीब 20 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी पेश की थी। इंसली से पहले कैलिफोर्निया के सांसद एरिक स्वालवेल और कोलोराडो के गवर्नर जॉन हिकेनलूपर भी मैदान से हट चुके हैं।

चिंताजनक

डिजिटल मुद्रा में लेनदेन को पकड़ना जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती, हाल के दिनों में आतंकियों के डिजिटल लेनदेन के मामलों में आई है तेजी

डिजिटल हो रहे आतंकी, बिटकॉइन से जुटा रहे फंड

न्यूयॉर्क टाइम्स से

सैन फ्रांसिस्को : बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्राओं को लेकर एजेंसियों की मुश्किल और बढ़ती दिख रही है। विभिन्न जांच में सामने आया है कि कई आतंकी संगठन फंड जुटाने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पूरी प्रणाली इतनी जटिल है कि इनमें हुए लेनदेन का पता लगाना एजेंसियों के लिए लगभग असंभव है।

अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियों की आंखें उस वक्त खुली रह गईं, जब फलस्तीनी संगठन हमास का मामला सामने आया। हमास को इजरायल समेत कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित करते हुए इसके लेनदेन को प्रतिबंधित किया हुआ है। अब इस आतंकी संगठन ने बिटकॉइन के जरिये पैसे जुटाने का तरीका अपनाया है। हमास की सैन्य जिम्मेदारियां संभालने वाले विभाग क्वासम ब्रिगेड ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी भी दी है। इस वेबसाइट पर हर विजिटर को अलग-अलग बिटकॉइन एड्रेस देकर पैसा भेजने के लिए कहा जाता है। सात भाषाओं में संचालित हो रही इस वेबसाइट पर एक वीडियो के जरिये यह भी बताया गया है कि

बिटकॉइन के जरिये लेनदेन का पता लगाना भी मुश्किल होता है। फाइल

जांच एजेंसियों की नजर में आए बिना पैसा कैसे भेजा जा सकता है।

बिटकॉइन के जरिये नशीली दवाओं के कारोबार से लेकर मनी लांड्रिंग तक कई अवैध कामों को अंजाम दिया जाता है। जांच एजेंसियां अभी इनसे निपटने के रास्ते तलाश ही रही थीं कि आतंकी संगठन भी इससे जुड़ने लगे। हाल के दिनों में ऐसे मामलों में तेज वृद्धि हुई है, जहां इस्लामिक आतंकी संगठनों द्वारा बिटकॉइन व अन्य डिजिटल मुद्राओं के रास्ते फंड जुटाने का पता चला है।

सीआइए के साथ काम कर चुके एनालिस्ट याया फेनुसी ने कहा, 'आने वाले दिनों में इसमें तेजी दिखेगी। डिजिटल मुद्राएं आतंकी फंडिंग का हिस्सा बनने जा रही हैं। अब लोगों को इस खतरे की ओर से सावधान रहना होगा।' अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन न्यूचिन पिछले दिनों में दो बार इस खतरे का जिक्र कर चुके हैं। वित्त मंत्रालय से जुड़े सिगल मेंडेलकर ने कहा, 'हम इस क्षेत्र को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। अभी यह आतंकियों के लिए नया है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें तेजी दिख सकती है।'

क्या है बिटकॉइन? : बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है। इसमें सॉफ्टवेयर कोड को मुद्रा की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पूरा सिस्टम इतना एनक्रिप्टेड होता है कि किसी के लिए भी इसमें सेंध लगा पाना लगभग असंभव है। यही कारण है कि जांच एजेंसियां भी अब तक इस पर लगाम की दिशा में कुछ खास प्रगति नहीं कर सकी हैं। बिटकॉइन की तरह इस समय कई डिजिटल मुद्राएं अस्तित्व में हैं। दुनिया के किसी देश ने इन्हें आधिकारिक मुद्रा के तौर पर अब तक मान्यता नहीं दी है।

कुछ देश भी विकसित कर रहे अपनी मुद्रा : अमेरिका ने अलग-अलग कारणों से कई देशों पर कारोबारी प्रतिबंध लगाया हुआ है। खबरों में यह दावा भी किया जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहे ईरान, रूस और वेनेजुएला जैसे कुछ देश भी अपनी डिजिटल मुद्रा विकसित करने में लगे हैं।

जेल में बंद आर्ट डीलर सुभाष पर अमेरिका में चोरी का आरोप

न्यूयॉर्क, प्रेट्र : अमेरिकी अभियोजकों ने भारत की जेल में बंद आर्ट डीलर सुभाष कपूर पर लाखों डॉलर की कलाकृतियां चोरी करने और बेचने का आरोप लगाया है। न्यूयॉर्क शहर के मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के अधिकारी इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या कपूर ने चोरी की गईं कलाकृतियां उनके संग्रहालय को भी बेची थीं? इंटरपोल ने 2011 में कपूर को जर्मनी से गिरफ्तार करने के बाद भारत को सौंप दिया था।

मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटार्नी साइरस वांस के कार्यालय ने पिछले महीने कपूर और अन्य के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कपूर पर बेशकीमती कलाकृतियों की चोरी समेत धोखाधड़ी के कई आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार और मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के अधिकारी इस बात का पता लगा रहे हैं कि संग्रहालय ने पिछले तीन दशक में जो प्राचीन बहुमूल्य कलाकृतियां हासिल की हैं, क्या वे कपूर की लूट का नतीजा थीं।

नेपाल और भारत ने की द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा

नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की मुलाकात

काठमांडू, प्रेट्र : विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके नेपाली समकक्ष प्रदीप ज्ञवाली ने संपर्क और आर्थिक साझीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। अधिकारियों ने गुरुवार को यहां यह जानकारी दी। विदेश मंत्री ने गुरुवार को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से उनके सरकारी आवास शीतल निवास पर औपचारिक मुलाकात भी की।

नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि दोनों नेताओं ने पांचवीं नेपाल-भारत संयुक्त आयोग बैठक में अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय स्तर पर सहयोग संबंधी मामलों पर चर्चा की। यह बैठक यहां बुधवार को यहां संपन्न हुई। बयान में कहा गया, 'नेपाल-भारत संयुक्त आयोग की पांचवीं बैठक में संपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई। इस दौरान संपर्क एवं आर्थिक साझेदारी, व्यापार एवं पारगमन, शक्ति एवं जल संसाधन, संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया।' बयान में कहा गया है कि दोनों मंत्रियों ने खासकर 'विजिट नेपाल ईयर 2020' के संदर्भ में पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। नेपाल-भारत संयुक्त आयोग का गठन 1987 में किया गया था जिसकी बैठकें बारी-बारी से नेपाल और भारत में होती हैं। बयान में बताया गया कि बैठक में 1950 की शांति एवं मित्रता संधि की समीक्षा और नेपाल-भारत संबंधों पर प्रख्यात व्यक्तियों के समूह की एक रिपोर्ट पर चर्चा की गई। इसमें कहा गया, 'भारत-नेपाल संयुक्त आयोग ने मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन, हुलाकी सड़कों के चार खंडों और नुवाकोट एवं गोरखा जिलों में भूकंप के बाद निजी आवासों के पुनर्निर्माण जैसी द्विपक्षीय परियोजनाओं की प्रगति पर खुशी व्यक्त की।' इसके अलावा जयनगर-जनकपुर और जोगबनी-बिराटनगर खंडों में सीमा पार रेलवे परियोजनाओं और बिराटनगर में एकीकृत चेक पोस्ट की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

लाल गेंद के सामने नाचे भारतीय बल्लेबाज

उछाल भरी पिच के आगे शीर्ष क्रम ने टेके घुटने मयंक, पुजारा और कप्तान कोहली सस्ते में हुए आउट

शेनॉन गेब्रियल की गेंद नही समझ पाए भारतीय कप्तान विराट कोहली ● एपी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: कैरेबियाई दौरे पर गई भारतीय टीम ने मेजबान वेस्टइंडीज को टी-20 और वनडे सीरीज में हराकर सीमित प्रारूप में अपना दबदबा बनाया था लेकिन लाल गेंद के शुरुआती टेस्ट में ही वह फेल हो गई। बारिश के कारण एंटीगा के नॉर्थ साउंड में टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण 15 मिनट देरी से शुरू हुआ। बारिश बंद होने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और उसके बाद कैरेबियाई गेंदबाज भारतीय शीर्षक्रम के ऊपर जमकर बरसे। पहले दिन लंच तक भारत ने 24 ओवर में तीन विकेट पर 68 रन बना लिए थे। ओपनर केएल राहुल 37 और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे 10 रन पर टिके थे।

भारतीय शीर्ष क्रम उछाल भरी पिच पर लाल गेंद के सामने नाचते नजर आया। भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का शानदार आगाज करने के इरादे से वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में सर विव रिचर्ड्स स्टेडियम में उतरी थी लेकिन मेजबान गेंदबाज भी कुछ अलग ही सोचकर आए थे। कैरेबियाई टीम ने अपनी पिछली घरेलू टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को शिकस्त दी थी और इस बार भी उसे हल्के में लिया जा रहा था लेकिन उसके तेज गेंदबाजों केमार रोच और शेनॉन गेब्रियल ने भारतीय बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ली। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल, टीम के सबसे भरोसेमंद चेतेश्वर पुजारा और कोहली उछाल भरी गेंदों के सामने बेबस नजर आए। तीनों बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट गए।

सात रन पर गंवाए दो विकेट: रोच की गेंद को भारतीय ओपनर मयंक समझ नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर शाई होप के हाथों में चली गई। मयंक पांच रन के निजी स्कोर पर आउट हुए। हालांकि मैदानी अंपायर ने मयंक को आउट नहीं दिया था लेकिन होल्डर ने डीआरएस लिया और तीसरे अंपायर ने मैदानी अंपायर के फैसले को बदल दिया। इसके बाद इस पिच पर 68 टेस्ट मैच खेल चुके पुजारा से बड़ी उम्मीद थी लेकिन वह टीम की उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाए। वह गेब्रियल की गेंद पर होप की कैच दे बैठे। पुजारा सिर्फ दो रन बना पाए। भारतीय टीम सात रन पर दो विकेट गंवा चुकी थी। मेजबान टीम के खिलाफ सीमित प्रारूपों की सीरीज में शानदार फॉर्म में रहे विराट का हवा लाल गेंद के सामने निकल गई। वह मेजबान टीम के तेज गेंदबाजों की गेंदों को समझ नहीं पा रहे थे। वह रोच की गेंद पर चौका निकालने के चक्कर में ब्रूक्स को कैच दे बैठे। वह नौ रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस तरह भारत ने अपने तीन महत्वपूर्ण विकेट 25 रन पर गंवा दिए।

विराट ने रोहित से ज्यादा विहारी को तवज्जो दी

नई दिल्ली: इंग्लैंड में हुए विश्व कप में रिकॉर्ड पांच शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा पर चार टेस्ट मैच खेलने वाले विहारी भारी पड़ गए। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच के शुरू होने से पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि रोहित को कप्तान कोहली मौका नहीं देंगे और अजिंक्य रहाणे को अंतिम एकादश में शामिल करेंगे। कोहली ने ऐसा ही किया। उन्होंने रहाणे के साथ विहारी को भी अंतिम एकादश में रखा और रोहित को निराश होना पड़ा। इसके साथ ही विराट ने रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव को भी अंतिम एकादश में नहीं खिलाया। उन्होंने एकमात्र स्पिनर के तौर पर रवींद्र जडेजा को मौका दिया।

भारतीय क्रिकेटरों को धमकी देने वाला व्यक्ति असम से गिरफ्तार

मुंबई, आइएएनएस: हाल ही में बीसीसीआइ को ईमेल कर भारतीय क्रिकेटरों को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को महाराष्ट्र एटीएस ने असम से गिरफ्तार कर लिया। एटीएस की टीम पूछताछ के लिए मुंबई ले आई है। भारतीय खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी देने वाले इस व्यक्ति को असम के मोरीगांव जिले के शांतिपुर गांव स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि एक स्थानीय कोर्ट ने आरोपी को 26 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजा है। आरोपी की ब्रज मोहन दास के रूप में पहचान की गई है। दास को मंगलवार को गुवाहाटी से लगभग 80 किलोमीटर दूर असम के मोरीगांव जिले के शांतिपुर गांव स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद, उसे जांच के लिए मुंबई लाया गया। दास ने 16 अगस्त को कथित तौर पर बीसीसीआइ को ईमेल करके धमकी भेजी थी। बीसीसीआइ ने मुंबई पुलिस को सूचित किया और एटीएस ने एक जांच शुरू की और दास के स्थान को ट्रैक किया। अधिकारी ने कहा कि एटीएस की एक टीम असम पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी को पकड़ा। मोरीगांव के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद दास को मुंबई लाया गया और मझगांव मजिस्ट्रेट सेकंड कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। एटीएस ने आरोपी से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत उसपर केस दर्ज किया। भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल वेस्टइंडीज दौरे पर है।

मैच से पहले अभ्यास करते 140 किलो के रकहीम कार्नवाल ● एएफपी

140 किलो के कार्नवाल को नहीं मिला पदार्पण का मौका

नई दिल्ली: भारत के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट में सभी की निगाहें 140 किलो और छह फुट छह इंच के रकहीम कार्नवाल थी लेकिन वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने उन्हें इस मैच में पदार्पण का मौका नहीं दिया। उनकी जगह शामारह ब्रूक्स को अंतिम एकादश में मौका दिया गया। ब्रूक्स को विंडीज की कैप दिग्गज बल्लेबाज विव रिचर्ड्स ने दी।

संजय बांगर की जगह विक्रम राठौर होंगे बल्लेबाजी कोच

मुंबई, प्रेट्र: संजय बांगर की जगह पूर्व सलामी बल्लेबाज विक्रम राठौर टीम इंडिया के नए बल्लेबाजी कोच होंगे, जबकि भरत अरुण और आर श्रीधर उम्मीद के मुताबिक क्रमशः गेंदबाजी कोच और फील्डिंग कोच बने रहेंगे।

एमएसके प्रसाद की अगुआई वाली सीनियर राष्ट्रीय चयन समिति ने सपोर्ट स्टाफ के इन तीनों पदों के लिए तीन-तीन नामों की सिफारिश की थी और तीनों वर्गों में शीर्ष पर रहने वाले को हितों के टकराव की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनके पदों पर नियुक्त कर दिया जाएगा।

50 साल के राठौर ने 1996 में भारत के लिए छह टेस्ट मैच और सात वनडे मैच खेले थे, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। लेकिन, पंजाब की ओर से घरेलू क्रिकेट में वह काफी सफल रहे। राठौर कुछ साल पहले (2016) तक संदीप पाटिल की अगुआई वाली सीनियर राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य थे।

राठौर ने पहले एनसीए बल्लेबाजी सलाहकार और अंडर-19 बल्लेबाजी कोच के पदों के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनके आवेदन को रोक दिया गया था, क्योंकि उनके रिश्तेदार आशीष कपूर अंडर-19 चयन समिति के चेयरमैन हैं।

बीसीसीआइ के सीईओ राहुल जौहरी ने कहा, 'विक्रम राठौर के पास पर्याप्त अनुभव है और हमें (कोच के रूप में) उनके कौशल पर विश्वास है। यदि उनके साथ कोई हितों का टकराव है तो हम उन्हें उसे घोषित करने को कहेंगे।'

चयन समिति की सिफारिशों के अनुसार, मौजूदा बल्लेबाजी कोच संजय बांगर दूसरे और इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज मार्क रामप्रकाश तीसरे स्थान पर रहे। जौहरी ने कहा, 'टीम प्रबंध का अपना नजरिया था, लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए हमें लगा कि सपोर्ट स्टाफ में कुछ नए चेहरों की जरूरत है।'

मुंबई इंडियंस के पूर्व फिजियो नितिन पटेल को फिर से टीम इंडिया का फिजियो बनाया गया है। वह 2011 में भी सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे। इंग्लैंड के ल्यूक वुडहाउस को स्ट्रेंथ एवं कंडिशनिंग (ट्रेनर) कोच नियुक्त किया गया है।

मौजूदा प्रशासनिक मैनेजर सुनील सुब्रहमण्यम को अपना पद गंवाना पड़ा। उन्हें वेस्टइंडीज दौरे के दौरान भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करना महंगा पड़ा। सुब्रहमण्यम की जगह गिरीश डोंगरी को यह पद सौंपा गया है।

शीर्ष तीन में भी नहीं आ सके महान फील्डर जोंटी रोड्स

नई दिल्ली, जेएनएन: आर श्रीधर की भारतीय टीम के फील्डिंग कोच के रूप में फिर से नियुक्ति हुई है। उनका इस पद पर फिर से चुना जाना तय माना जा रहा था, लेकिन यह भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स से कड़ी टक्कर मिलेगी। हालांकि, श्रीधर के फिर से फील्डिंग कोच बनने से ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह रही कि अपने दौर के बेहतरीन फील्डर रहे रोड्स इस पद के लिए शीर्ष तीन दावेदारों में भी अपनी जगह नहीं बना सके। रोड्स आइपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस फील्डिंग कोच रह चुके हैं। उन्होंने फील्डिंग कोच के लिए मंगलवार को एमएसके प्रसाद की अगुआई वाली सीनियर चयन समिति के सामने स्काइप के जरिये फील्डिंग कोच के पद के लिए साक्षात्कार दिया था, लेकिन वह इस दौड़ में काफी पीछे रह गए। उनके पीछे रहने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। श्रीधर बाजी मारने में सफल रहे, जबकि दूसरे स्थान पर अभय शर्मा और तीसरे स्थान पर टी दिलीप रहे।

सपोर्ट स्टाफ

- अरुण गेंदबाजी और श्रीधर फील्डिंग कोच बने रहेंगे
- हितों के टकराव की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद होगी नियुक्ति

दूसरे टेस्ट में श्रीलंका के दो विकेट गिरे

कोलंबो, रायटर : न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के बारिश से प्रभावित पहले दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने दो विकेट पर 85 रन बनाए थे, जिसमें लाहिरु थिरिमाने और कुशल मेंडिस के विकेट शामिल थे। कप्तान दिमुथ करुणारत्ने 49 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि एंजेलो मैथ्यूज को अभी खाता खोलना है। बारिश और खराब रोशनी की वजह से पूरे दिन में सिर्फ 36.3 ओवर का खेल ही हो सका।

मेजबान श्रीलंका ने गॉल में खेला गया पहला टेस्ट छह विकेट से जीता था। यहां सुबह देर से खेल शुरू होने के बाद करुणारत्ने ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उसके बाद दर्शनीय शुरुआत की। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज प्रभावित करने में नाकाम रहे और कीवी टीम को पहली सफलता बायें हाथ के स्पिनर विलियम समरविले ने थिरिमाने को दो रन पर आउट कर दिलाई। गॉल में दूसरी पारी में 122 रन की मैच विजयी पारी खेलने वाले करुणारत्ने और मेंडिस ने दूसरे विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी कर मेहमान टीम की मुश्किलें बढ़ाईं। इस साझेदारी को तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर कोलिन डि ग्रैंडहोम ने मेंडिस को 32 रन पर चलता कर तोड़ा। दोनों टीमों ने पहले टेस्ट की टीम में एक-एक बदलाव किया।

सधी शुरुआत

- पहले दिन 36.3 ओवर का ही खेल हो सका संभव
- श्रीलंका का स्कोर 85/2, करुणारत्ने 49 पर डटे

विकेट लेने के बाद खुश डि ग्रैंडहोम ● एएफपी

प्रणीत क्वार्टर फाइनल में

विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप

बासेल (स्विट्जरलैंड), प्रेट्र : भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणय यहां जारी विश्व चैंपियनशिप के अपने तीसरे दौर के मुकाबले में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी जापान के केंटो मोमोटा से हारकर चैंपियनशिप से बाहर हो गए। वहीं, अन्य भारतीय खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने विश्व के आठवें नंबर के खिलाड़ी इंडोनेशिया के एंटोनी सिनीसुका गिटिंग को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। 16वें वरीय प्रणीत ने छठे वरीय गिटिंग को 21-19, 21-13 से हरा दिया। प्रणीत ने 42 मिनट में यह मुकाबला जीता।

शीर्ष वरीय मोमोटा ने एक कड़े मुकाबले में प्रणय को 21-19, 21-12 से पराजित किया। नंबर वन मोमोटा ने 56 मिनट में यह मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में मोमोटा का सामना 14वीं वरीय मलेशिया के ली जी जिया से होगा, जिनके खिलाफ मोमोटा का 2-0 (जीत-हार) का रिकॉर्ड है। प्रणय ने पहले गेम में मोमोटा को कड़ी टक्कर दी और तीन बार स्कोर को बराबरी पर ला दिया। भारतीय खिलाड़ी एक समय 4-7 से पीछे थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने 12-12, 14-14 और 19-19 की बराबरी हासिल कर ली। अंतिम समय में प्रणय अंक बटोरने में विफल रहे और उन्हें पहले गेम में 19-21 से नजदीकी हार का सामना करना पड़ा। दूसरे गेम में प्रणय एक समय 5-11 से पीछे थे। इसके बाद वह लगातार पीछे होते चले गए। मोमोटा 17-10 से आगे हो चुके थे और फिर उन्होंने 21-12 से गेम और मैच जीतकर प्रणय के खिलाफ 5-0 (जीत-हार) का करियर रिकॉर्ड बनाया।

विकेट लेने के बाद खुश इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा ऑर्चर ● एएफपी

ऑस्ट्रेलिया को मिले शुरुआती झटके

लीड्स, एएफपी : इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और स्टुअर्ट ब्रॉड ने गुरुवार को बारिश से प्रभावित एशेज के तीसरे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटके दिए।

आर्चर ने मार्कस हैरिस (08) को चलता किया तो वहीं, ब्रॉड ने उस्मान ख्वाजा (08) को पवेलियन भेजकर मेहमान टीम की राह मुश्किल कर दी। खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया ने 25 ओवर में दो विकेट पर 93 रन बनाए। डेविड वार्नर 36 और मार्नस लाबुशाने 31 रन बनाकर क्रीज पर खड़े हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के सबसे उपयोगी खिलाड़ी स्टीव स्मिथ चोट के कारण इस मैच में नहीं खेलने उतरे। वह सीरीज के दूसरे मैच में आर्चर की गेंद पर चोटिल हो गए थे। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीता और तेज गेंदबाजों के मददगार हालात को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

एशेज के दौरान वार्नर को चीटर बताने वाली टी-शर्ट पहने दिखा एक अंग्रेज दर्शक ● रायटर

बारिश के कारण पहले सत्र में सिर्फ चार ओवर का खेल हो पाया और इसमें भी आर्चर ने इस सीरीज में पहली बार खेल रहे हैरिस को विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। लंच तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट पर 12 रन था। दूसरे सत्र में मेजबान टीम के अनुभवी गेंदबाज ब्रॉड की गेंद ख्वाजा के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बेयरस्टो के दस्तानों में समां गई। मैदानी अंपायर ने ख्वाजा को नॉटआउट दिया लेकिन कप्तान जो रूट ने डीआरएस लिया और तीसरे अंपायर ने इस फैसले को बदल दिया।

भारत-पाक का डेविस कप मुकाबला स्थगित

नई दिल्ली, प्रेट्र: अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आइटीएफ) ने गुरुवार को सुरक्षा समीक्षा के बाद पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले भारत के डेविस कप मुकाबले को नवंबर तक स्थगित कर दिया। यह मुकाबला इस्लामाबाद में 14-15 सितंबर को होना था। आइटीएफ ने कहा कि वह असाधारण परिस्थितियों में मुकाबले को स्थगित कर रहा है। आइटीएफ ने कहा, 'विशेषज्ञ सुरक्षा सलाहकारों द्वारा पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति की गहन सुरक्षा समीक्षा के बाद डेविस कप समिति ने भारत और पाकिस्तान के बीच इस्लामाबाद में 14-15 सितंबर को होने वाले डेविस कप एशिया/ओसियाना ग्रुप एक मुकाबले को स्थगित करने का फैसला किया है। यह असाधारण परिस्थिति है और आइटीएफ की पहली प्राथमिकता खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों की सुरक्षा है।'

खेल रत्न मिलना एक यात्रा पूरी होने जैसा : दीपा मलिक

दीपा मलिक भारत की ऐसी पैरा एथलीट हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर कई पदक जीतकर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया। उन्हें अब देश के सर्वोच्चतम खेल अवार्ड खेल रत्न से नवाजा जाएगा। लगभग दो दशक पहले बिस्तर से उठकर खेल मैदान पर पहुंचीं और देश को पैरा कॉमनवेल्थ से लेकर एशियन खेल, विश्व चैंपियनशिप और रियो पैरालंपिक में पदक दिलाए। उनके इस सफर को लेकर अनिल भारद्वाज ने दीपा मलिक से विशेष बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंश-

साक्षात्कार

पंजाब के मुख्यमंत्री ने की बलबीर सिंह सीनियर के लिए भारत रत्न की मांग

चंडीगढ़, प्रेट्र: पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिग्गज हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग की। अमरिंदर ने पत्र में 95 वर्षीय बलबीर को अपने दौर का लाजवाब खिलाड़ी बताया। उन्होंने लिखा, 'मैं आपका ध्यान इस विषय की ओर इंगित कराना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि आजादी के बाद भारत के सबसे सम्मानजनक और असाधारण खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर को भारत रत्न से नवाजा जाए। बलबीर सिंह सीनियर हॉकी के महान खिलाड़ी हैं और ओलंपिक 1948, 1952 और 1956 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं। वह 1956 ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान भी थे। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें 1957 में पद्मश्री से नवाजा गया। मैं अनुरोध करता हूं कि भारत रत्न के लिए बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर गौर किया जाए।' बलबीर को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम खिलाड़ियों में चुना था। ओलंपिक हॉकी फाइनल में सर्वाधिक गोल का उनका रिकॉर्ड आज तक कायम है। उन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में नीदरलैंड्स के खिलाफ फाइनल में भारत की 6-1 से जीत में पांच गोल दागे थे। वह विश्व कप 1975 विजेता भारतीय टीम के मैनेजर भी थे।

● अर्जुन व पद्मश्री अवार्ड के बाद आपको खेल रत्न से नवाजा जा रहा है। तीन बड़े सम्मान पाकर कैसा लग रहा है?

-बहुत लंबा सफर रहा और बहुत खुश हूं। आज एक यात्रा पूरी होने जैसा अहसास हो रहा है। वर्ष 1999 से संघर्ष शुरू हुआ था और आज 49 वर्ष की आयु में खेल रत्न का सम्मान मिल रहा है।

● आपका आधा शरीर लकवा ग्रस्त हुआ और उसके बाद आप खेलों में आईं। आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति तो रही होगी, लेकिन किनसे प्रेरित होकर यह सफर तय किया?

-बात वर्ष 2000 के आस पास की है। उन दिनों मैं महाराष्ट्र के अहमदनगर में रहती थी और वहां पर छोटा सा रेस्तरां चलाती थी। वहां पर सभी को पता था कि मैं दिव्यांग हूं। एक दिन विलास डोने नाम के एक व्यक्ति रेस्तरां में आए और उन्होंने मुझे खेलों में आने के लिए प्रेरित किया। वह स्वयं पैरा पावर लिफ्टर थे। उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया और प्रेरित किया, जिसके बाद मैं मैदान पर उतरी। राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र के लिए पदक जीता, तो वर्ष 2009 में महाराष्ट्र सरकार ने शिव छत्रपति अवार्ड से सम्मानित किया। यह मेरा पहला अवार्ड था जिसे लेकर बहुत खुश हुई। इस अवार्ड ने मुझे बहुत कुछ पाने की भूख जगा दी।

● आपके जीवन सुख और दुख से भरा रहा लेकिन किस दिन को अपने लिए सबसे बड़ा दिन मानती हैं?

-सही कहा आपने, जीवन में दुख आए तो सुख भी बहुत आए और मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन उस दिन आया, जब मैंने रियो पैरालंपिक 2016 में पदक जीता। यह दिन मेरे व परिवार के लिए बड़ा दिन था।

● इस क्षेत्र में कठिनाइयां तो बहुत आई होंगी?

-उन दिनों भारत में दिव्यांग होना अपने आपमें एक कठिनाई थी। भारत में दिव्यांग खिलाड़ी के लिए आज कुछ सुविधाएं मिल रही हैं। मोदी सरकार के ध्यान देने के बाद सुविधाएं बढ़ी हैं। एक समय था जब दिव्यांग खिलाड़ी को कोई नहीं पूछता था। दिव्यांग खिलाड़ी सुविधा के अभाव में दो-तीन साल तक एक खेल स्पर्धा का प्रशिक्षण लेता और बाद में सूचना मिलती कि यह खेल स्पर्धा एशियन या ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है। फिर खिलाड़ी दूसरे खेल स्पर्धा में तैयारी करता इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग खेल स्पर्धा में पदक जीते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई रही कि मैं अपने बच्चों की उम्र के एथलीटों के साथ प्रशिक्षण लेती थी। इस दौरान बच्चों का बहुत सहयोग मिला।

● अक्सर किसी को दूसरों के लिए काम करते, बहुत कम देखा जाता है। आप स्वयं खेलीं भी और दिव्यांगों को जागरूक करने का अभियान भी चलाया। यह प्रेरणा कहां से मिली ?

-आपको पता है, मेरे पिता सेना में अधिकारी रहे हैं और मेरे पति भी सेना में ही हैं। आर्मी परिवार में यही सिखाया जाता है कि स्वयं के साथ दूसरों के लिए काम करो। मैंने लक्ष्य बनाया था कि खेलने और घर संभालने के साथ देश में दिव्यांग बच्चों, खासकर लड़कियों को प्रेरित करूंगी ताकि वह घर से निकलें और स्वयं ऊंचाइयों को छू लें। मुझे खुशी है कि आज खेलों में सुविधा और खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है।

अशोक गहलोत के बेटे की 'क्रिकेट पारी' लड़खड़ाई

संवाद सूत्र, जोधपुर: राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) के माध्यम से खेल की राजनीति करने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की मंशा आसान नजर नहीं आ रही है। राजस्थान हाई कोर्ट ने गुरुवार को जोधपुर जिला क्रिकेट संघ को भंग कर नए सिरे से चुनाव के लिए बनाई गई एडहॉक कमेटी के गठन पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कमेटी के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मनमानी नहीं चल सकती। हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्थगन आदेश दिया है और 12 सितंबर को सुनवाई तय की है।

सूत्रों के मुताबिक इसी संघ में वैभव को पदाधिकारी बनाने के लिए सहकारिता विभाग ने जोधपुर जिला क्रिकेट संघ को भंग कर एडहॉक कमेटी बनाई थी। गहलोत विरोधी खेमे का कहना है कि वैभव को आरसीए में लाने के लिए यह कदम उठाया गया था लेकिन हाई कोर्ट से स्थगन मिलने के बाद उनकी राह आसान होती नजर नहीं आ रही।

उधर, संघ को भंग किए जाने का फैसला होते ही जोधपुर जिला क्रिकेट संघ की ओर से एडहॉक कमेटी के गठन को चुनौती देते हुए एडवोकेट विकास बालिया के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका पेश की गई। इसमें कहा गया कि देर शाम साढ़े पांच बजे पदाधिकारियों को पोस्टल नोटिस मिला और बिना अधिसूचना जारी किए रात को ही आनन-फानन में जोधपुर जिला क्रिकेट संघ को भंग कर एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया गया। याचिका में बताया गया कि संघ के खिलाफ जिस शिकायत का हवाला दिया गया है, उसमें शिकायतकर्ता का नाम तक नहीं है।

एडहॉक कमेटी का संयोजक राजीव खन्ना को बनाया गया था। खन्ना जोधपुर के होने के साथ ही गहलोत परिवार के काफी निकट माने जाते हैं। खन्ना को कमेटी का संयोजक बनाने का मकसद वैभव को जोधपुर जिला क्रिकेट संघ में पदाधिकारी बनाकर क्रिकेट की राजनीति में लाना और फिर राजस्थान क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनाना है। गौरतलब है कि आरसीए के मौजूदा अध्यक्ष सीपी जोशी का कार्यकाल खत्म होने वाला है।

राजस्थान हाईकोर्ट की रोक के कारण वैभव गहलोत के आरसीए में जाने की राह हुई कठिन

फिट भारत अभियान के लिए सलाहकार समिति गठित

नई दिल्ली, जेएनएन : सरकारी अधिकारियों, भारतीय ओलंपिक संघ के सदस्यों, राष्ट्रीय खेल महासंघ, निजी संस्थाओं और फिटनेस प्रमोटरों की मौजूदगी वाली समिति का गठन किया गया है जो 'फिट भारत अभियान' पर सरकार को सलाह देगी। इस समिति की अगुआई खेल मंत्री किरन रिजिजू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को इस अभियान का अनावरण करेंगे।

मैं पॉल पोग्बा का समर्थन करता हूं और उनके साथ हूं। लोगों को उनके खिलाफ नस्लीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी।
– जुआन माटा, स्ट्राइकर, मैनचेस्टर युनाइटेड

जोकोविक यूएस ओपन के प्रमुख दावेदार

नोवाक के सिनसिनाटी मास्टर्स के सेमीफाइनल में हार से दूसरे खिलाड़ियों का रास्ता खुला

सोमवार से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट में फेडरर व नडाल भी जीत के दावेदारों में शामिल

न्यूयॉर्क, रायटर : विश्व के नंबर एक खिलाड़ी और शीर्ष वरीय नोवाक जोकोविक सोमवार से शुरू हो रहे साल के अंतिम ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट यूएस ओपन के जीतने के प्रमुख दावेदार हैं लेकिन गत विजेता जोकोविक पिछले सप्ताह सिनसिनाटी मास्टर्स के सेमीफाइनल में हार गए थे जिसके बाद उनके प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों की भी यह खिताब जीतने की उम्मीदें जाग गईं हैं। सिनसिनाटी को छोड़ दिया जाए तो इस साल जोकोविक ने तीन अलग-अलग टेनिस कोर्ट पर तीन खिताब जीते हैं जिसमें दो ग्रैंडस्लैम खिताब भी शामिल हैं। उन्होंने इस साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता। जोकोविक ने पिछले पांच ग्रैंडस्लैम में से चार जीत हैं। जोकोविक के अलावा पुरुष सिंगल्स खिताब के दौड़ में स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और स्पेन के राफेल नडाल भी शामिल हैं।

प्रशंसकों की पसंद सेरेना : यूएस ओपन के महिला सिंगल्स की खिताब की दावेदार घरेलू दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम्स हैं। यहां के प्रशंसक सेरेना को खिताब का दावेदार मानते हैं। 37 वर्षीय सेरेना के पास इस खिताब के साथ 24वां रिकॉर्ड ग्रैंडस्लैम की ट्रॉफी उठाने का मौका है। सेरेना के अलावा फ्रेंच ओपन की विजेता एश्ले बार्टी और विंबलडन विजेता सिमोना हालेप इस दौड़ में बनी हुई हैं। वहीं, गत विजेता जापानी खिलाड़ी नाओमी ओसाका उलटफेर करने में सबसे आगे रहती हैं।

रामोस ने किया इन्कार : कार्लोस रामोस ने यूएस ओपन में उन मैचों में अंपायरिंग करने से इन्कार कर दिया जिसमें विलियम्स बहनें खेल रही होंगी। पिछले साल यूएस ओपन के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेयर अंपायर रामोस थे और इस मैच में सेरेना विलियम्स ने उनके साथ बहुत बहस की थी। ओसाका ने इस मैच में सेरेना को शिकस्त दी थी। सेरेना ने रामोस पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ओसाका को एक गेम दिया। साथ ही सेरेना ने चेयर अंपायर को चोर भी कहा था।

अंकिता क्वालीफाइंग से बाहर : भारत की शीर्ष महिला सिंगल्स खिलाड़ी अंकिता रैना तीन सेट तक चले कड़े मुकाबले में हार के साथ यूएस ओपन की महिला सिंगल्स क्वालीफाइंग स्पर्धा से बाहर हो गईं। दुनिया की 194वें नंबर की भारतीय खिलाड़ी को चेक गणराज्य की डेनिसा अलर्तोवा के खिलाफ मुकाबले में दो घंटे और 17 मिनट में 7-6, 4-6, 2-6 से हार का सामना करना पड़ा। अंकिता ने पहला सेट टाई ब्रेक में जीता लेकिन इसके बाद वह लय बरकरार रखने में सफल रही जिससे अलर्तोवा ने दूसरे सेट में उनकी सर्विस तोड़कर मुकाबले को तीसरे और निर्णायक सेट में खींचा। तीसरे सेट में अंकिता ने एक बार फिर अपनी सर्विस गंवाई और उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी। क्वालीफायर में भारतीयों में अब सिर्फ सुमित नागल बचे हैं।

चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान टेनिस खिलाड़ी सोमदेव व पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर जोंटी रोड्स। प्रेट्र

राफेल नडाल ओपन में खेलेंगे इंग्लिश खिलाड़ी मरे

मालोरका (स्पेन) : ब्रिटेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे ने सिंगल्स में अपनी वापसी जारी रखते हुए सोमवार से यहां शुरू हो रहे राफेल नडाल ओपन में हिस्सा लेंगे। मरे ने इस साल अब तक दो एटीपी टूर इवेंट में हिस्सा लिया है और 2005 के बाद पहली बार सेकेंड टीयर चैलेंजर टूर में खेलेंगे। 32 वर्षीय खिलाड़ी के सितंबर अंत तक चीन में दो टूर्नामेंट में खेलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने संकेत दिए कि वह अन्य टूर्नामेंट में भी खेल सकते हैं। नडाल अपने इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि इसी समय यूएस ओपन भी होना है। मरे ने न्यूयॉर्क में होने वाले टूर्नामेंट के डबल्स से अपना नाम वापस ले लिया था, क्योंकि वह सिंगल्स में ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।

आइसीसी के वकील व कंपनी सचिव बने जोनाथन हॉल

दुबई, प्रेट्र : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने गुरुवार को जोनाथन हॉल को अपना वकील और कंपनी सचिव नियुक्त किया है। हॉल के पास फुटबॉल और रग्बी जैसे खेलों में 27 साल का कानूनी अनुभव है। आइसीसी ने कहा कि हॉल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर और ब्रिटेन में कई खेल संगठनों में वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका निभाई है, जिसमें यूएफा और लॉरेस भी शामिल हैं।

हॉल ने 11 साल तक द फुटबॉल एसोसिएशन (द एफए) के साथ काम किया। वह पहले संचालन निदेशक के रूप में नियामक एवं संचालन से जुड़े सभी मुद्दों को देखते थे और फिर फुटबॉल सेवा प्रभाग के निदेशक के रूप में काम किया। द एफए से जुड़ने से पहले हॉल रग्बी फुटबॉल यूनियन (आरएफयू) के वकील और कंपनी सचिव भी रहे। इससे पहले वह आइएमजी के लिए कानूनी मामलों के उपाध्यक्ष रहे थे और क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी, टेनिस और गोल्फ के व्यावसायिक कानूनी मामले देखा करते थे।

आइसीसी के सीईओ मनु साहनी ने कहा, 'मुझे विस्तृत वैश्विक खोज के बाद जोनाथन जैसी क्षमता के वकील का आइसीसी में स्वागत करने की खुशी है जो हमारी कानूनी इकाई के प्रमुख होंगे। जोनाथन के पास खेलों की एक विस्तृत श्रेणी का व्यापक अनुभव है जो वैश्विक क्रिकेट समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।' हॉल सितंबर के मध्य में अपना पद संभालेंगे और यहां आइसीसी के मुख्यालय में कार्यभार संभालेंगे।

43 लाख रुपये में टोक्यो ओलंपिक का मिलेगा टिकट

खेलों का महाकुंभ

- उद्घाटन व समापन समारोह और नौ दिनों तक ट्रैक एवं फील्ड गेम्स देख सकेंगे
- बैठने के लिए लग्जरी सीट और भोजन की भी सुविधा उपलब्ध होगी

टोक्यो, एपी : क्या आपको अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक का टिकट पाने में परेशानी हो रही है? यदि आपके पास 60000 डॉलर (करीब 43 लाख रुपये) अतिरिक्त हैं तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है।

टोक्यो ओलंपिक के आयोजकों ने दर्शकों के लिए एक उच्च एवं आतिथ्य पैकेज (हाई एंड हॉस्पिटैलिट पैकेज) की व्यवस्था की है, जिसकी कीमत 60000 डॉलर है। इस पैकेज में दर्शक को उद्घाटन और समापन समारोह देखने का मौका मिलेगा। साथ ही नौ दिनों तक ट्रैक एवं फील्ड गेम्स भी देख सकते हैं। यहां आपको बैठने के लिए लग्जरी सीट मिलेगी और भोजन की भी सुविधा उपलब्ध होगी। हालांकि, आयोजकों ने एक छोटा पैकेज भी उपलब्ध कराया है जिसकी कीमत 1500 डॉलर (करीब एक लाख रुपये) है।

2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए टिकटों की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है। अगले साल जुलाई से शुरू होने वाले खेल के इस महाकुंभ को देखने दूर-दूर के देशों से लोग आएंगे। ऐसे में जापान के टोक्यो शहर के होटलों के रेट भी बढ़ गए हैं। खासतौर से जो दर्शक अमेरिका या यूरोप से आ रहे हैं उनकी जेब काफी ढीली होने वाली है। लगातार पिछले सात ओलंपिक देख रहे लास एंजेल्स के एक स्पोर्ट्स एजेंट ब्रेंट फेल्डमैन ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मैं इस बार ओलंपिक देखने जा पाऊंगा। मध्यम परिवार के लिए इस बार ओलंपिक देखना इतिहास में सबसे महंगा साबित होने वाला है।' महंगे टिकट को लेकर आयोजकों का कहना है, आतिथ्य पैकेज उन धनी लोगों के लिए है जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ आकर ओलंपिक का मजा ले सकते हैं। इस पैकेज की भारी कीमत की वजह इनमें मिलने वाली सुविधाएं हैं। यहां आपको स्पेशल शैंपेन, शेक और बियर वगैरह मिलेगी। यही नहीं, भोजन बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय शेफ को बुलाया गया है। इसके अलावा दर्शकों को निजी सेवा भी मुहैया कराई जाएगी, ताकि उन्हें जब भी कोई जरूरत हो तो बता सकें। यही नहीं, आतिथ्य पैकेज में दर्शक को सेलेब्रिटी से भी मिलने का मौका मिलेगा।

हालांकि एक रिपोर्ट से पता चला है कि भारतीय प्रशंसक भी इसमें अपनी रुचि दिखा रहे हैं। हालांकि भारतीय खिलाड़ियों का ओलंपिक में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है लेकिन देश के लोग अपने खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए ज्यादा तादाद में टोक्यो जा सकते हैं। एक प्रशंसक ने कहा कि हमारे खिलाड़ी जैसा भी प्रदर्शन करे लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम विदेश में जाकर उनका समर्थन करते हैं। सभी क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम का समर्थन करते हैं तो ओलंपिक में भी हमें करना चाहिए।

शुभमन के खेल पर है द्रविड़ और युवी का प्रभाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : शुभमन गिल के स्ट्रोक्स भले ही विराट कोहली की तरह हों, लेकिन क्रिकेट के प्रति शुभमन गिल का रवैया राहुल द्रविड़ से प्रभावित है, जिन्होंने इस युवा खिलाड़ी को हर हालत में अपने स्वाभाविक खेल पर डटे रहने की सलाह दी है। वहीं, उन्होंने दबाव का सामना करना युवराज सिंह से सीखा है।

दो सप्ताह बाद 20 साल के होने जा रहे गिल सिर्फ दो वनडे खेलने के बावजूद चर्चा में बने हुए हैं। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम में उनका चयन नहीं होने पर हैरानी जताई थी। इस महीने की शुरुआत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बने गिल ने कहा, 'राहुल सर भारतीय अंडर-19 टीम और फिर भारत-ए के समय से मेरे कोच हैं। उनसे सबसे अच्छी सलाह जो मुझे मिली उसे मैं हमेशा अपने दिमाग में रखता हूं। वह कहते थे कि हालात कुछ भी हों, मुझे अपना स्वाभाविक खेल नहीं बदलना है। मैं वेस्टइंडीज-ए के खिलाफ दोहरे शतक को लाल गेंद की क्रिकेट से अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी कहूंगा।'

जब उनसे पूछा गया कि यदि स्वाभाविक खेल दिखाने पर भी अनुकूल नतीजे नहीं मिले तो, गिल ने कहा, 'उन्होंने (द्रविड़ ने) मुझसे कहा कि यदि तकनीकी रूप से मुझे मजबूत बनना है तो अपने स्वाभाविक खेल के भीतर ही सारे बदलाव होने चाहिए।' उन्होंने कहा, 'मैं स्पिनरों के खिलाफ आक्रामक खेलता हूं। बचपन से ही मैंने स्पिनरों को खूब खेला है। स्पिनरों की मददगार विकेट पर खेलते हुए मैंने यह स्ट्रोक खेलने में महारत हासिल की।'

मेसी ने मुझे बेहतर खिलाड़ी बनाया : रोनाल्डो

फुटबॉल डायरी

लिस्बन, एएफपी : पुर्तगाल के सुपरस्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्वीकार किया कि अर्जेंटीना के लियोन मेसी से लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता ने उन्हें बेहतर खिलाड़ी बनाया और वह अर्जेंटीना के इस सुपरस्टार फुटबॉलर से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। पुर्तगाल के इस फुटबॉलर ने यह भी स्वीकार किया कि वह और मेसी साथ में घूमते फिरते नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'मैं उनकी उपलब्धियों का मुरीद हूं। वह पहले ही कह चुके हैं कि मेरे स्पेन छोड़ने से वह निराश हैं, क्योंकि इस प्रतिद्वंद्विता में उन्हें भी मजा आता था।' उन्होंने कहा, 'यह अच्छी प्रतिद्वंद्विता है, लेकिन बेमिसाल नहीं। माइकल जॉर्डन के भी बास्केटबॉल में प्रतिद्वंद्वी रहे। एर्टन और एलेन प्रोस्ट फॉर्मूला वन में। यह सभी स्वस्थ प्रतिद्वंद्विताएं थी। मेसी ने मुझे और मैंने उन्हें बेहतर खिलाड़ी बनाया। हमारे बेहतरीन पेशेवर संबंध रहे हैं। हमने कभी साथ में डिनर नहीं किया, लेकिन भविष्य में कर सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है।'

अभ्यास सत्र में लौटे मेसी : रविवार को रीयल बेटिस के खिलाफ होने वाले ला लीगा के मैच से पहले बार्सिलोना की टीम को उस समय राहत मिली जब मेसी अभ्यास सत्र में हिस्सा लेने के लिए मैदान पर पहुंच गए। मेसी पिंडली में चोट के कारण कुछ समय से मैदान से दूर थे। मेसी ने मैड्रिड में बुधवार की सुबह अकेले अभ्यास किया फिर वह दोपहर को टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ जुड़ गए। मेसी को पांच अगस्त को पिंडली में चोट लगी थी जिसके बाद वह क्लब के प्री-सत्र के मुकाबले से बाहर हो गए थे।

मेसी के अलावा टीम को अपने अन्य स्ट्राइकरों की चोटों से भी जूझना पड़ रहा है। लुइस सुआरेज को बिलबाओ के खिलाफ मैच में पिंडली में चोट लगी थी और अब वह भी लगभग एक महीने तक मैदान से दूर रहेंगे। वहीं, ओस्माने डेंबेले भी मांसपेशियों में खिंचाव के चलते परेशान हैं और उन्हें ठीक होने में लगभग पांच सप्ताह लग जाएंगे। एंटीनो ग्रीजमैन को इस स्पेनिश क्लब पे 120 मिलियन डॉलर (862 करोड़ रुपये) में एटलेटिको मैड्रिड से खरीदा था और वह ही एकमात्र पूरी तरह से फिट हैं। बेटिस के खिलाफ मैच में उनके ऊपर गोल करने की अधिक जिम्मेदारी रहेगी।

लियोन मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फाइल फोटो, एएफपी

पीएसजी ने नेमार के लिए बार्सिलोना का प्रस्ताव ठुकराया : रिपोर्ट

पेरिस : पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) ने नेमार के लिए बार्सिलोना द्वारा किए गए दूसरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रिपोर्ट के अनुसार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन करने वाले इटली के क्लब जुवेंटस ने भी अब नेमार को अपनी टीम में लाने के प्रयास शुरू कर दिए। पीएसजी ने बार्सिलोना के पहले प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया था। बार्सिलोना ने ब्राजील के स्ट्राइकर को लोन पर अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश की थी। इस प्रस्ताव के तहत नेमार के लिए लोन फीस का भुगतान, खिलाड़ी का वेतन और अगले सत्र उसे खरीदने का क्लॉज भी शामिल होता। इसके बाद बार्सिलोना ने एक और लोन का प्रस्ताव दिया जिसके तहत स्पेनिश क्लब अगले दो साल तक नेमार के वेतन का भुगतान करती।

विविध

रात को चिकन खाने के बाद तीन लोगों की मौत

जासं, तरनतारन : गांव माड़ी नौबाद में बीती रात बिहार निवासी तीन लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि रात को खाने में जहरीली वस्तु मिलने के कारण उनकी मौत हुई होगी। जानकारी के अनुसार बिहार के गांव मानपुर सकरी, बेतियां जिला पश्चिमी चंपारण निवासी राहुल (14) पुत्र राम देव, उसका भाई साहिल अपने दो अन्य साथियों कोमल पुत्र जराईव चौधरी व स्वपंस कुमार के साथ किराए पर रह रहे थे। चारों घरों की छतों की डेकोरेशन (पीओपी)का काम करते थे। ढाई साल से वे चारों गांव माड़ी नौबाद निवासी डॉ. सुखचैन सिंह के घर में किराये पर रह रहे थे।

युवक साहिल ने बताया कि बुधवार की रात को आठ बजे काम निपटाने के बाद वह पट्टी चला गया जबकि उसके तीनों साथी घर चले गए। रात को तीनों चिकन के साथ खाना खाकर सो गए। सुबह उसे कोमल का फोन आया कि उसकी तबीयत खराब है, जबकि राहुल व स्वपंस कुमार की मौत हो चुकी है। उसके बाद वह कोमल को लेकर निजी अस्पताल में गया लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। डीएसपी मान ने बताया कि संदिग्ध हालत में हुई तीन मौतों की प्रथम जांच में यह सामने आ रहा है कि खाने में बनाए गए चिकन में जहरीली वस्तु मिलने के कारण ऐसा हुआ हो सकता है।

470 वर्ष पुरानी परंपरा को तोड़ने का गुर्जर महापंचायत में लिया गया निर्णय

संवाद सहयोगी, लोनी (गाजियाबाद)

- गुर्जर समाज के लोगों ने कसाना और नागर गोत्र के युवक और युवतियों का विवाह कराए जाने का लिया निर्णय

लोनी क्षेत्र के गुर्जर समाज के लोगों ने महापंचायत कर कसाना और नागर गोत्र के युवक और युवतियों का विवाह कराए जाने का निर्णय लिया। इस मौके पर रिस्तल और मथुरापुर गांव के परिवारों ने अपने बच्चों का विवाह करने का फैसला लिया। बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य और गुर्जर समाज के लोग मौजूद रहे।

रिस्तल गांव निवासी विजय सिंह ने बताया कि गुर्जर समाज में करीब 470 वर्षों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक कसाना और नागर गोत्र के लोगों का आपस में मामा-फूफी का रिश्ता माना जाता था। इसके चलते इस गोत्र के युवक और युवतियों की आपस में शादी नहीं हो सकती थी। उन्होंने बताया कि बुधवार को जनपद बागपत स्थित गढ़ी कलंजरी गांव में रिस्तल गांव के कसाना गोत्र के ग्रामीणों और मथुरापुर गांव के नागर गोत्र के लोगों द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया।

महापंचायत में क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पंचायत में मौजूद लोगों ने आपसी सहमति से सराहनीय और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए करीब 470 वर्षों से चली आ रही परंपरा को समाप्त कर दिया। उन्होंने बताया कि महापंचायत में एकत्र लोगों ने दोनों गोत्र के युवक और युवतियों की शादी कराए जाने पर सहमति जताई।

इस मौके पर मथुरापुर गांव निवासी अशोक प्रधान ने अपनी भतीजी का रिश्ता रिस्तल गांव निवासी लायकराम प्रधान के पोते से करने की बात कहते हुए सगाई का शगुन भेंट किया। पंचायत में मौजूद लोगों ने दोनों परिवार के फैसले का एक सराहनीय कदम बताया। इस मौके पर प्रधान काशीराम, लीलू प्रमुख, बाबा भागमल, होतेराम प्रधान, शिवकुमार प्रधान, करतार सिंह, श्यामि, राजन, बबली प्रधान आदि मौजूद रहे।

दो साल पहले हुई महापंचायत में टूटी थी 11 सौ वर्ष पुरानी परंपरा : रिस्तल गांव निवासी विजय सिंह ने बताया कि करीब दो वर्ष पूर्व महापंचायत में 11 सौ वर्ष पुरानी चली आ रही परंपरा तोड़कर कसाना और बैंसला गोत्र में शादी करने का फैसला लिया था। घिटौरा निवासी करतार सिंह ने अपनी भतीजी की शादी रिस्तल निवासी विजय सिंह के पुत्र से की थी। इसके बाद से अब तक दोनों गोत्रों में कई युवक और युवतियों की शादी हो चुकी है।

पुरानी परंपराओं की ऐसे मिलती है जानकारी

रिस्तल गांव निवासी विजय सिंह के मुताबिक समाज की पुरानी परंपराओं और रीतियों की जानकारी समाज के कुछ लोगों के पास मौजूद अभिलेखों में दर्ज है। क्षेत्र के गांव और समाज की छोटी और बड़ी जानकारी इन लोगों के पास मौजूद होती है। इन लोगों को भाट के नाम से जाना जाता है। इनका कार्य समाज के हर गांव, परिवारों और व्यक्ति की जानकारी रखना होता है। उन्होंने दावा किया कि इनके पास क्षेत्र में गांव के बसने और उससे पूर्व की जानकारी होती है। जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

ग्रेनो में खुलेगा राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय

जासं, ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा में एक और राष्ट्रीय स्तर का संस्थान स्थापित होने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार शहर में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। प्राधिकरण बोर्ड ने विश्वविद्यालय के लिए सौ एकड़ के भूखंड आवंटन पर मुहर लगा दी है। भूखंड पर प्राधिकरण दस फीसद की छूट भी देगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर टेकजोन में आइटी के लिए विप्रो कंपनी को सौ एकड़ का भूखंड आवंटित किया था। लीज डीड की शर्त पूरी न करने पर प्राधिकरण ने भूखंड आवंटन निरस्त कर दिया था।

गृह मंत्रालय ने ग्रेनो में राष्ट्रीय पुलिस विवि स्थापित करने के लिए प्राधिकरण से सौ एकड़ जमीन मांगी थी। राष्ट्रीय स्तर के संस्थान को शहर में स्थापित करने का मौका प्राधिकरण हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। इसलिए प्राधिकरण बोर्ड ने विप्रो के निरस्त भूखंड को विश्वविद्यालय के लिए आवंटित करने के साथ प्रीमियम धनराशि पर दस फीसद छूट भी देने का फैसला किया है। गुरुवार को प्रदेश के मुख्य सचिव एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन डा. अनूप चंद पांडे की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति की मुहर लगा दी। विश्वविद्यालय के लिए भूखंड आवंटन से प्राधिकरण को 458 करोड़ रुपये मिलेंगे।

पवित्र छड़ी मुबारक पहुंची मचैल माता के दरबार

जागरण संवाददाता, किश्तवाड़

- विधिवत रूप से की गई छड़ी की पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं ने मचैल चंडी मां के दर्शन भी किए

मचैल माता की पवित्र छड़ी गुरुवार को पाडर स्थित माता के दरबार पहुंच गई। छड़ी यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। 18 अगस्त को जम्मू से चलकर किश्तवाड़ होते हुए मचैल पहुंचने पर लोगों ने पवित्र छड़ी का भव्य स्वागत किया। इसके बाद विधिवत रूप से छड़ी की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर लोगों ने परंपरा के मुताबिक कुड नृत्य भी किया। श्रद्धालुओं ने मचैल चंडी माता के दर्शन किए। छड़ी यात्रा में शामिल भक्तों ने मंदिर में स्थापित पवित्र छड़ी के त्रिशूल को माथा टेका। पिछले साल 22 अगस्त को छड़ी के पहुंचने पर संस्था के दो गुटों में विवाद हो गया था। इसके बाद संस्था के संस्थापक और यात्रा को शुरू करने वाले ठाकुर कुलबीर सिंह ने पवित्र छड़ी का त्रिशूल मंदिर से वापस नहीं लाया। बाद में त्रिशूल को स्थायी तौर पर मंदिर में ही स्थापित कर दिया गया।

इस बार छड़ी यात्रा के लिए जम्मू में रहने वाले मूल रूप से डोडा निवासी राजू जैन ने नया त्रिशूल बनवाकर उसके साथ छड़ी यात्रा को जम्मू से रवाना किया। सर्वशक्ति सेवा संस्था के प्रधान नेकराम मन्हास ने बताया कि इस बार छड़ी यात्रा को धूमधाम से निकालने का फैसला किया गया था। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित ज्वाला जी माता मंदिर से माता की दिव्य जोत विशेष रूप से लाई गई। छड़ी का त्रिशूल जम्मू से चलाया गया, लेकिन जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 समाप्त होने के बाद प्रशासन ने यात्रा को धूमधाम से संचालित करने की अनुमति नहीं दी। इसी कारण छड़ी यात्रा साधारण तरीके से थोड़े श्रद्धालुओं के साथ मंदिर पहुंची। इसके बाद में कुछ श्रद्धालु मचैल पहुंचे, जिनके लिए संस्था की ओर से लंगरों को दोबारा खुलवाया गया। श्रद्धालुओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

यात्रा का आखिरी दल हुआ रवाना

जासं, हल्द्वानी : कैलास मानसरोवर यात्रा 2019 का आखिरी 18वां दल गुरुवार को अल्मोड़ा रवाना हो गया। दल में आठ महिलाएं और 25 पुरुष यात्री हैं। दिल्ली से काठगोदाम पर्यटक आवास गृह पहुंचे यात्रियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। यात्रा के लाइजनिंग ऑफिसर कमल किशोर महाजन ने बताया कि बरसात के कारण दल को दिल्ली से दो दिन देरी से रवाना किया गया। यह दल 22 दिन बाद यात्रा पूरी कर लौटेगा।

चार दिन से बाधित चल रहा कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग गुरुवार को सुचारु हो गया। तीन दिन से आधार शिविर धारचूला में रुका 17वां दल रवाना हुआ और देर शाम बूंदी पहुंचा। 14 वें दल के यात्री देर शाम आधार शिविर धारचूला पहुंचे। 15वें और 16वें दल के यात्री तिब्बत में यात्रा कर रहे हैं।

बोगस बिल से लगाई 10 .80 करोड़ रुपये की चपत

जागरण संवाददाता, पटियाला

- आबकारी एवं कराधान विभाग ने खनौरी के गणपति मोटर स्टोर के मालिक को अदालत में पेश कर जेल भेजा

वाट्सएप के जरिए बोगस स्लिप कटती रही। कागजों में गाड़ियां दिल्ली से आती रहीं और सरकार को चूना लगता रहा। आबकारी एवं कराधान विभाग ने बोगस बिलों के सहारे सरकारी खजाने को 10.80 करोड़ रुपये की चपत लगाने के मामले का पर्दाफाश किया है। खनौरी स्थित फर्म गणपति मोटर स्टोर का मालिक सुभाष चंद्र बोगस बिलों के सहारे आयरन स्क्रैप का कारोबार कर रहा था। विभाग के अधिकारियों ने सुभाष चंद्र को जीएसटी एक्ट के तहत बुधवार रात को गिरफ्तार किया। उसे वीरवार को मूनक में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर संगरूर जेल में भेज दिया है। विभाग ने फर्म का 2017 से अब तक का डाटा एकत्रित किया था। इस मामले में कुछ और डीलरों की मिलीभगत होने की आशंका है। विभाग की ओर से मामले की पड़ताल जारी है।

आबकारी एवं कराधान विभाग की एडिशनल कमिश्नर नवदीप कौर भिंडर ने बताया कि फर्म के मालिक द्वारा हरियाणा व अन्य जगहों से पुराने ट्रक खरीदकर उनका स्क्रैप खनौरी में निकालकर मंडी गोबिंदगढ़ की पांच फर्मों को सप्लाई किया जाता था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली से माल की जगह सिर्फ बोगस बिल ही यहां आ रहे थे। उन्होंने बताया कि फर्म के मालिक द्वारा बोगस बिलों के सहारे दिल्ली से 60 करोड़ रुपये की आयरन स्क्रैप की खरीदारी दस्तावेजों में दिखाई गई है। वहीं 10.80 करोड़ रुपये के फर्जी टैक्स क्रेडिट दिखाए गए। दूसरी ओर पंजाब के विभिन्न डीलरों को भी फर्जी क्रेडिट जारी कर कर दिए। इस मामले में हरियाणा के टोल प्लाजा कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। विभाग ने इसकी पुष्टि भी कर दी है।

उत्तराखंड में वनों की सुरक्षा को कर्मियों के पास नहीं हैं उपकरण

जागरण संवाददाता, नैनीताल

70 फीसद वन क्षेत्र वाले उत्तराखंड में वनों को बचाने के लिए महकमे के पास उपकरणों की कमी होने के साथ ही एक तिहाई फील्ड कर्मचारियों का अभाव है। प्रदेश के वन 95 हजार करोड़ की पर्यावरणीय सेवा प्रदान कर रहे हैं। गंगा-यमुना का कैचमेंट भी उत्तराखंड में ही है, लेकिन वनों का प्रबंधन व सुरक्षा की हालत बेहद खस्ता है। फील्ड स्टाफ की कमी की वजह से एक फॉरेस्ट गार्ड सैकड़ों वर्ग किमी वनों की सुरक्षा में तैनात हैं। इस वजह से कर्मचारी श्रम कानूनों के अनुसार नियमित आठ घंटे के बजाय 24 घंटे महज लाठी के सहारे ड्यूटी दे रहे हैं। हाई कोर्ट ने वन विभाग की इन तमाम दुश्वारियों के मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

- हाई कोर्ट में याचिका दायर, केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव संदीप तिवारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वन विभाग के पास वनों को बचाने के लिए जरूरी उपकरण जैसे आग बुझाने के उपकरण, बंदूक, कर्मचारियों की फायर वर्दी, सेटेलाइट मोबाइल आदि का अभाव है। हर साल दावानल का दायरा बढ़ रहा है। कर्मचारियों के पास अत्याधुनिक संचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। जंगल जानवरों का अवैध शिकार किया जा रहा है। अवैध तरीके से वन एवं खनिज संपदा का दोहन किया जा रहा है। वन कर्मचारी पैदल गश्त करने को मजबूर हैं। वन चौकियों या चेक पोस्ट में धर्मकांटा व सीसीटीवी नहीं हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र या बुग्यालों में गश्त के लिए जरूरी उपकरण वन कर्मचारियों पास नहीं हैं। दुर्लभ वन्यजीवों के अंगों की तस्करी हो रही है। याचिका में पुलिस आधुनिकीकरण की तर्ज पर वन विभाग को बजट मुहैया कराने, रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने, उपकरण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र व राज्य सरकार को निर्देशित करने की गुहार लगाई गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने गुरुवार को मामले को सुनने के बाद केंद्र व राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

मौसम विशेष

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क और गर्म रहेगा। पूर्वी राजस्थान और दिल्ली में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा संभव है। जम्मू कश्मीर में मौसम शुष्क और आरामदायक रहेगा। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा जारी रहेगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/26/व	अहमदाबाद	35/25/व
कोलकाता	31/27/सा	बड़ौदा	33/25/आंबा
चेन्नई	33/25/आंबा	नागपुर	30/22/व
हैदराबाद	32/24/व	इन्दौर	28/22/सा
बंगलूरू	28/20/सा	रांची	34/25/व
त्रिवेन्द्रम	30/24/व	पटना	38/29/आंबा
गुवाहाटी	34/28/व	जमशेदपुर	35/27/व
गंगटोक	19/10/व	पुणे	27/22/व

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 23 अगस्त 2019
आजकल
16
www.jagran.com

चांद की कक्षा से भेजी पृथ्वी की पहली तस्वीर

1966 में आज ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा चांद की कक्षा में भेजे गए पहले रोबोटिक मानवरहित अंतरिक्ष यान लूनर ऑर्बिटर-1 ने वहां से ली गई पृथ्वी की पहली तस्वीर भेजी। इस यान को उसी वर्ष 10 अगस्त को रवाना किया गया था।

पहली बार जहाज से तट पर भेजा गया संदेश

1899 में आज ही लाइटशिप नंबर 70 नामक जहाज से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित क्लिफ हाउस स्टेशन पर संदेश भेजा गया। यह पहली बार था जब मार्कोनी के आविष्कार टेलीग्राफ का इस्तेमाल इंग्लैंड के बाहर किया गया।

गांधी जी को चंपारण लाने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे राजकुमार शुक्ल

आजादी की लड़ाई में चंपारण किसान आंदोलन का बड़ा योगदान है। इस आंदोलन की जमीन तैयार करने वाले राजकुमार शुक्ल का जन्म 1875 में आज ही चंपारण में हुआ। इस क्षेत्र में लंबे समय से किसान मजबूरन नील की खेती कर रहे थे। 1916 के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल लखनऊ पहुंचे और गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। उनके जिद पर अड़े रहने के बाद 15 अप्रैल, 1917 को गांधी जी चंपारण आए। किसानों और वकीलों के सहयोग से चंपारण आंदोलन शुरू हुआ जिसके बाद नील की खेती भी बंद हुई और किसानों का शोषण भी।

प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने दुनिया के सर्वाधिक दस कमाई करने वाले अभिनेताओं की जारी की सूची

सर्वाधिक कमाई में चौथे पायदान पर अक्षय कुमार

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार कमाई के मामले में हॉलीवुड के कई अभिनेताओं को पीछे छोड़ चुके हैं। सर्वाधिक कमाई वाले अभिनेताओं की फोर्ब्स की ताजा सूची में अक्षय कुमार चौथे पायदान पर हैं। जून 2018 से जून 2019 के बीच उनकी कुल आय 6.5 करोड़ डॉलर (करीब 467 करोड़ रुपये) है। सूची में 8.94 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ हॉलीवुड अभिनेता ड्वेन रॉक जानसन शीर्ष पर हैं। पेश है एक नजर:

करोड़ डॉलर
- 8.94 ड्वेन जॉनसन (47 साल)
- 7.64 क्रिस हेम्सवर्थ (36)
- 6.60 रॉबर्ट डाउनी जू. (54)
- 6.50 अक्षय कुमार (51)

खिलाड़ी कुमार की हाल की करीब सभी फिल्मों ने सौ करोड़ से ज्यादा की कमाई की। 2018 से 2019 के बीच इनकी पैडमैन, गोल्ड, 2.0, केसरी, और मिशन मंगल फिल्में रिलीज हुई। हालिया रिलीज मिशन मंगल 121.23 करोड़ कमाई के साथ अक्षय की लगातार दसवीं हिट फिल्म रही। 1987 में महेश भट्ट की फिल्म आज में छोटा सा किरदार निभाने वाले अक्षय की बतौर अभिनेता पहली फिल्म सौगंध आई। जिसमें उनके एक्शन सीन को काफी पसंद किया गया। उसके बाद खिलाड़ी टाइटल वाली फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का एक्शन किंग स्थापित किया। साल 2000 में उन्होंने अभिनय में विविधता का समावेश करते हुए कॉमेडी किरदारों को निभाना शुरू किया। हेराफेरी, भागमभाग, सिंह इज किंग और हाउसफुल प्रमुख फिल्में रहीं।

प्रमुख फिल्में	कुल कमाई
केसरी	100.00
गोल्ड	102.10
टायलेट एक प्रेमकथा	132.07
जॉली एलएलबी2	117.00
रुस्तम	127.49
हाउसफुल 3	109.14
एयरलिफ्ट	128.10

(कुल कमाई करोड़ रुपये में)

सूची में अन्य अभिनेता जिनका नाम प्रतिष्ठित पत्रिका फोब्स की सूची में शामिल है

5 जैकी चैन — 5.80 कुल कमाई

8 क्रिस इवांस — 4.35 कुल कमाई

6 ब्रैडले कूपर — 5.71 कुल कमाई

9 पॉल रुड — 4.10 कुल कमाई

7 एडम सैंडलर — 5.70 कुल कमाई

10 विल स्मिथ — 3.52 कुल कमाई

(सभी अभिनेताओं की कुल कमाई करोड़ डॉलर में)

इधर-उधर की

प्रेमिका का गुस्सा कार पर उतारा

फ्लोरिडा, एजेंसी : गुस्से में आदमी आपे से बाहर हो जाता है, उसे पता नहीं होता कि वह क्या कर रहा है। जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यहां के 20 वर्षीय हंटर मिल्स के साथ भी गुस्से ने कुछ ऐसा ही गुल खिलाया। दरअसल इन महाशय ने अपनी प्रेमिका को बातचीत के लिए अपने ऑफिस बुलाया। जल्दी पहुंचने के क्रम में प्रेमिका ने किसी की सफेद रंग की 2010 कैडिलैक कार ले ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बातचीत के क्रम में हंटर को प्रेमिका का एक जबाव पसंद नहीं आया और उसे गुस्सा आ गया। उसने कार की छत पर भारी मात्रा में धूल रख दी। कार के दरवाजे खुले हुए थे लिहाजा धूल कार के अंदर भी चली गई। मौके की नजाकत समझते हुए प्रेमिका ने नौ दो ग्यारह होने में ही भलाई समझी। इस क्रम में कार को एक हजार डॉलर से ज्यादा कीमत का नुकसान पहुंचा। पुलिस ने कार की तस्वीरों को फेसबुक पर पोस्ट करते हुए सारा वाकया बयान किया। सोशल मीडिया पर तस्वीरों के साथ यह कहानी वायरल हो रही है।

रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा रोबोट

बड़ी बात ▶ आइएसएस पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करना सीखेगा फेडोर

धरती की परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह पर पहली बार रूस ने भेजा है रोबोट

मॉस्को, एएफपी : रूस ने गुरुवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आइएसएस) के लिए मानवरहित रॉकेट लांच किया। यह रॉकेट एक आदमकद रोबोट को लेकर अपने साथ ले जा रहा है। फेडोर नामक यह रोबोट दस दिनों तक आइएसएस पर रहेगा और अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करना सीखेगा। रूस ने धरती की परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह आइएसएस पर पहली बार रोबोट भेजा है।

फेडोर को कजाखस्तान के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से सोयूज एमएस-14 अंतरिक्ष यान से स्थानीय समयानुसार सुबह छह बजकर 38 मिनट पर रवाना किया गया। सोयूज शनिवार को आइएसएस पर पहुंचेगा और सात सितंबर तक वहां रहेगा। सोयूज आमतौर पर अंतरिक्षयात्रियों को लेकर आइएसएस पर जाता है, लेकिन इस बार आपातकालीन बचाव प्रणाली की जांच के लिए इसे मानवरहित रवाना किया गया है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख दमित्री रोगाजिन ने इस महीने की शुरुआत में रोबोट की तस्वीरें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिखाई थीं। तब उन्होंने कहा था कि यह आइएसएस पर अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता करेगा और उनके काम में हाथ बंटाएगा।

फेडोर को कजाखस्तान के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से सोयूज एमएस-14 नामक यान के जरिये रवाना किया गया। रायटर

पायलट सीट पर रोबोट : सोयूज की पायलट सीट पर फेडोर को बैठाया गया है। उसके हाथ में रूस का एक छोटा झंडा भी है। इस रोबोट की लंबाई पांच फीट 11 इंच है और इसका वजन 160 किलोग्राम है।

फेडोर का ट्विटर अकाउंट भी : फेडोर का अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट भी है। इन पर बताया गया है कि वह पानी की बोतल खोलने जैसे नए हुनर सीख रहा है।

नए कौशल का होगा परीक्षण : स्पेस स्टेशन पर फेडोर रोबोट निम्न गुरुत्वाकर्षण में नए कौशल का परीक्षण करेगा। यह रोबोट इंसानी गतिविधियों की नकल भी करता है।

पहले भी अंतरिक्ष में भेजे गए रोबोट : अंतरिक्ष में जाने वाला फेडोर पहला रोबोट नहीं है। इससे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2011 में रोबोनॉट 2 को अंतरिक्ष में भेजा था। 2013 में जापान ने किरोबो नामक एक छोटा रोबोट आइएसएस पर भेजा था। इसे जापान के पहले अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेकर गए थे।

कमर दर्द दूर करने में सहायक हो सकता है एक्यूप्रेशर

वाशिंगटन डीसी, एएनआइ : कमर दर्द से निपटने के लिए अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक्यूप्रेशर तकनीक को प्रभावी बताया है। उनका मानना है कि घर पर ही एक्यूप्रेशर के जरिये कमर दर्द से राहत संभव है। अमेरिकी शोधकर्ता सुजैन मर्फी ने कहा, 'एक्यूप्रेशर काफी हद तक एक्यूपंक्चर जैसा ही है। इसमें सूई के स्थान पर अंगुली, अंगूठे या किसी उपकरण की मदद से शरीर में खास बिंदुओं पर दबाव बनाया जाता है।'

मर्फी ने बताया कि कैंसर के कारण होने वाले दर्द और गठिया के मामले में एक्यूप्रेशर को लाभकारी सिद्ध हो चुका है। हालांकि कमर दर्द पर इसके प्रभाव को लेकर ज्यादा अध्ययन नहीं हुए हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि एक्यूप्रेशर की मदद से कमर में दर्द उठने और थकान की परेशानी निपटा जा सकता है। मर्फी ने कहा, 'तेज दर्द की हालत में बेहतर इलाज जरूरी होता है। इलाज के तौर पर ज्यादातर दवाएं दी जाती हैं। शोध के नतीजों ने बिना दवा के इस परेशानी के हल की उम्मीद पैदा की है।'

मर्फी ने कहा कि कई बार इस तरह के दर्द से निपटने के लिए लोग दर्द निवारक गोलियों का सहारा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर दर्द कम करने वाली दवाओं का शरीर में विपरीत असर देखने को मिलता है। बुहत ज्यादा मात्रा में दर्द निवारक गोलियां लेने से कई बार किडनी तक खराब हो जाती है। ऐसे में यदि हमारे में अच्छे और किफायती विकल्प मौजूद हों तो हमें उन्हें जरूर अपनाना चाहिए। इससे दर्द तो दूर होगा ही, साथ ही आपके पैसों की भी बचत होगी।

घातक नहीं है पानी में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक : यूएन

कहा- पुराने अध्ययनों का डाटा काफी कमजोर है, हमें माइक्रोप्लास्टिक के पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभावों की गहन पड़ताल करने की जरूरत है

जेनेवा, एपी : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का कहना है कि पीने के पानी में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक यानी प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों का स्तर घातक नहीं लगता है, लेकिन कई अध्ययनों के परिणाम चौंकाने वाले भी होते हैं, इसलिए माइक्रोप्लास्टिक के पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की गहन पड़ताल करने की जरूरत है।

माइक्रोप्लास्टिक को परिभाषित करने का कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि माइक्रोप्लास्टिक का निर्माण तब होता है जब मानव निर्मित सामग्री (प्लास्टिक) को लगभग पांच मिलीमीटर से भी छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की स्वास्थ्य एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्लास्टिक के सूक्ष्म कण पर्यावरण में सर्वव्यापी हैं और पीने योग्य पानी में भी ये सूक्ष्म कण घुले रहते हैं। साथ ही नलों और बोतल के पानी में भी इन कणों की मौजूदगी देखी गई है।

डब्ल्यूएचओ में पानी, साफ-सफाई और स्वच्छता के समन्वयक ब्रूस गोर्डन ने कहा कि हम प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों पर अध्ययन कर रहे हैं, यह इसलिए नहीं कि इससे मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा 'मुझे लगता है कि यदि आप बोतल बंद पानी या नल का पानी पीते हैं तो इससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई शोधकर्ताओं ने बोतलबंद पानी में सूक्ष्म कणों की मौजूदगी को खतरनाक बताया गया है पर उनके अध्ययनों के डाटा काफी कमजोर मालूम पड़ते हैं। अभी इस पर और गहन अध्ययन की जरूरत है।' हालांकि गोर्डन ने लोगों से अपील की कि यदि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है तो इसके लिए मिलकर काम करने की जरूरत है।

डब्ल्यूएचओ की यह रिपोर्ट माइक्रोप्लास्टिक के संभावित मानव स्वास्थ्य जोखिमों की जांच करने वाली पहली समीक्षा है। इसमें कहा गया है कि दशकों से लोग इसके नुकसान का अनुमान लगाए बिना ही माइक्रोप्लास्टिकऔर अन्य कणों का सेवन कर रहे हैं।

अनदेखी पहुंचा सकती है नुकसान : ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया में केमिस्ट्री के वरिष्ठ लेक्चरर एंड्रयू मेयस का मानना है कि पानी में माइक्रोप्लास्टिक के कण स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय नहीं है। मेयस ने कहा कि इसका मतलब यह कतई नहीं है कि माइक्रोप्लास्टिक लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इससे पर्यावरण को भारी क्षति पहुंच सकती है। इसके लिए समय रहते उचित और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। मेयस ने कहा कि हम जानते हैं कि इस प्रकार की सामग्री से छोटे जीवों को काफी नुकसान पहुंचता है। इसकी अनदेखी करने पर हो सकता है यह और ज्यादा हानि पहुंचा दे।

शोध अनुसंधान

नौ घंटे से ज्यादा बैठे रहने से असमय मौत का खतरा

दिन में साढ़े नौ घंटे या इससे ज्यादा समय बैठकर बिताने वालों में असमय मौत का खतरा बढ़ जाता है। वहीं शारीरिक रूप से सक्रिय रहने वालों में यह खतरा कम रहता है। हालिया शोध में यह बात सामने आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, 18 से 64 साल की उम्र वालों को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट हल्का व्यायाम या 75 मिनट का कठोर व्यायाम अवश्य करना चाहिए। हालांकि इस बात का कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है कि कब और किस तरह का व्यायाम सेहत के लिए जरूरी है। अलग-अलग अध्ययनों से जुटाए गए 35 हजार से ज्यादा लोगों के आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि असमय मौत के खतरे को कम करने के लिए रोजाना करीब पांच घंटे की हल्की शारीरिक गतिविधियां जरूरी हैं। - प्रेट्र

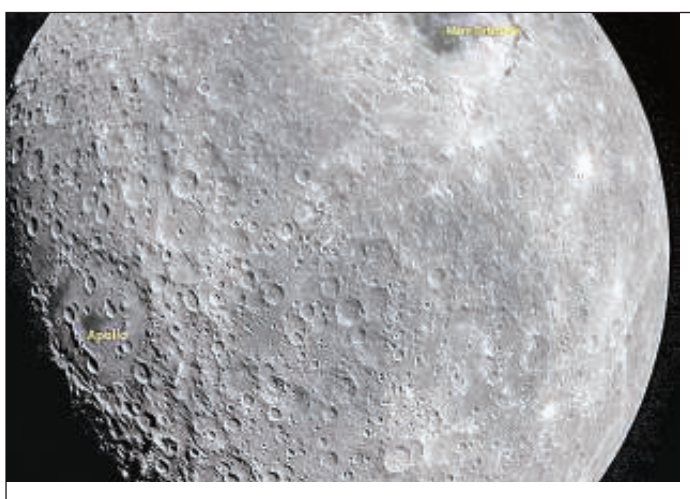

चांद का पहला दीदार...

भारत के चंद्रयान-2 ने चांद की पहली तस्वीर भेजी है। यान ने बुधवार को चांद की सतह से करीब 2,650 किलोमीटर की ऊंचाई से यह तस्वीर खींची थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गुरुवार को इसे जारी किया। इससे पहले इसरो ने चार अगस्त को चंद्रयान-2 द्वारा खींची गई धरती की तस्वीरें जारी की थीं। उल्लेखनीय है कि 22 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान-2 को लांच किया गया था। इसरो के चेयरमैन के सिवन ने कहा कि लैंडर-रोवर को चांद की सतह पर छह-सात सितंबर की दरम्यानी रात 1.40 से 1.55 बजे के बीच लैंड कराया जाएगा। सौजन्य से - इसरो

मिट रहा है टाइटैनिक

क्या कनाडा के न्यूफाउंडलैंड तट से करीब 596 किलोमीटर दूर उत्तर अटलांटिक महासागर में डूबे विश्व प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज का वजूद आगामी कुछ वर्षों में मिट जाएगा ? करीब 15 सालों में पहली बार टाइटैनिक के बेहद यादगार हिस्सों के नवीनतम फुटेज से ज्ञात हुआ है कि यह तेजी से नष्ट हो रहा है, बल्कि जहाज के कैप्टन के बाथटब समेत कई हिस्से पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। पनडुब्बी के जरिए गोता लगाकर जहाज के मलबे का सर्वे, फुटेज और फोटो कैप्चर किया है। इसी से पता चला है कि इसका वजूद तेजी से नष्ट हो रहा है। एपी

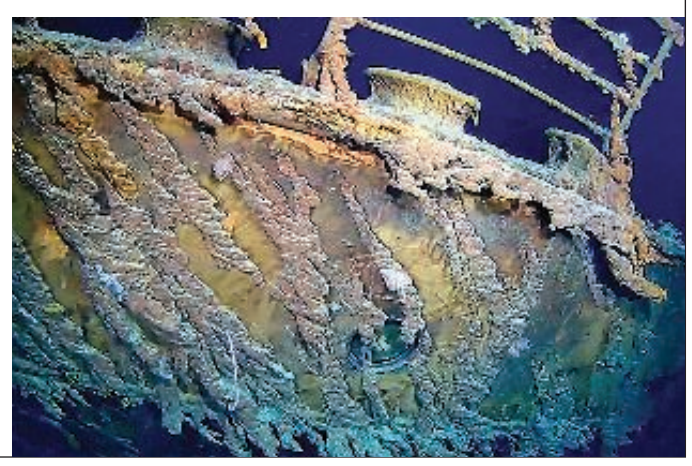

स्क्रीन शॉट

कश्मीर में शूटिंग करना चाहती हैं विद्या बालन

आजकल फिल्मों में विश्वसनीयता लाने के खूब प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए अक्सर जहां की कहानी होती है, उसी शहर में फिल्मों की शूटिंग करने का चलन अब जोरों पर है। हार्टलैंड की कहानियां उन्हीं से जुड़े शहरों में शूट की जा रही हैं। बात की जाए अगर धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की, तो उस पर कई फिल्में बन चुकी हैं, मगर कश्मीर में शूटिंग संभव न हो पाने की स्थिति में अक्सर फिल्मकार कश्मीर मुद्दों पर बनी फिल्मों की शूटिंग कश्मीर जैसी दिखने वाली अन्य जगहों पर, मसलन हिमाचल प्रदेश या विदेश में करा लेते रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों रिलीज हुई कुछ फिल्में वहां की वादियों में फिल्माई गई हैं। अब संविधान के अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद फिल्ममेकर्स के साथ-साथ कलाकारों की भी वहां जाकर काम करने की उम्मीद बढ़ी है। विद्या बालन इससे बहुत उत्साहित हैं। वह कश्मीर जाकर फिल्मों की शूटिंग करने के लिए उत्सुक हैं। कश्मीर का जिक्र होते ही वह वहां से जुड़ी यादें ताजा करते हुए कहती हैं कि मैं अपने जीवन में अब तक केवल एक बार कश्मीर गई हूं। बदली परिस्थितियों में अब अगर मुझे वहां जाकर काम करने का मौका मिलता है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई और नहीं होगी। हालांकि विद्या यह भी कहती हैं कि फिल्म की शूटिंग लोकेशन का चयन निर्देशकों और उस फिल्म के मेकर्स के हाथ में ही होता है, कलाकारों का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। यह बहुत अच्छी बात है कि अब वहां शूटिंग करने की संभावनाएं बन गई हैं।

सुपरहीरो वेब सीरीज में दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा

बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का अगला प्रोजेक्ट एक वेब-सीरीज है। वह नेटफ्लिक्स की सुपरहीरो फिल्म 'वी कैन बी हीरोज' में मुख्य भूमिका में होंगी। हालांकि यह अभी तय नहीं हुआ है कि फिल्म में प्रियंका सुपरहीरो का किरदार निभाएंगी या कोई और। यह फिल्म बच्चों के लिए है और इसके निर्देशक व निर्माता रॉबर्ट रॉड्रीगेज हैं। रॉबर्ट इससे पहले 'स्पाई किड्स' नाम की फ्रेंचाइज का निर्माण कर चुके हैं। यह फिल्म बच्चों के एक समूह की कहानी है, जो एलियंस द्वारा सुपरहीरोज के अपहरण के बाद दुनिया की रक्षा करते हैं। गौरतलब है कि प्रियंका की फिल्म 'द स्काई इज पिंक' रिलीज होने वाली है। हॉलीवुड में भी धाक जमा चुकीं प्रियंका द्वारा निर्मित मराठी फिल्म 'पानी' को पर्यावरण संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला चुका है।

आदिवासियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं राहुल ढोलकिया

शाह रुख खान के साथ 'रईस' फिल्म बनाने के बाद राहुल ढोलकिया स्वतंत्रता सेनानी तुकाराम पर फिल्म बनाने की तैयारी में हैं। यह काल्पनिक कहानी होगी, हालांकि उसमें सत्य घटनाक्रम होंगे। उसमें शाह रुख खान के काम करने की खबरें भी सुर्खियां बनी थीं। राहुल का कहना है कि 'तुकाराम' की स्क्रिप्ट और डायलॉग तैयार है। वह महंगी फिल्म है। उसकी तैयारी में समय लग रहा है। उसकी स्टारकास्ट फाइनल नहीं हुई है। प्री प्रोडक्शन में वक्त लगेगा। इसलिए उससे पहले वह एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं।

उसने पांच शादियां कर रखी हैं। उनसे 21 बच्चे हैं। सभी परिवार की तरह एकसाथ रहते हैं और खुश रहते हैं। खास बात यह है कि उसने अपनी जमीन को स्कूल के लिए दान दे दिया है। वहां पर आदिवासियों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जबकि वह खुद छोटी-सी जगह में सपरिवार रहता है। फिलहाल, वह इस डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं।

ऐश्वर्या-अभिषेक की शादी की यादें हुईं ताजा

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी को बारह साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आज भी इन दोनों की शादी को देश की सबसे चर्चित शादियों में गिना जाता है। इनकी शादी के परिधान डिजाइन करने वाली डिजाइनर जोड़ी अबू जानी और संदीप खोसला ने अपनी कंपनी के 33 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर अपने बेहतरीन कामों की तस्वीरें साझा की। इसके तहत उन्होंने ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की शादी की तस्वीरें भी साझा की हैं। एक तस्वीर में अमिताभ बच्चन, जया, श्वेता और श्वेता की बेटी नव्या शादी की तैयारियों में मशगूल नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में अमिताभ बच्चन और जया डांस कर रहे हैं। जबकि अभिषेक और ऐश्वर्या एक-दूसरे का हाथ थामे उन्हें देखकर खुश हो रहे हैं।

रहें सतर्क

आपकी हर बात पर लगे रहते हैं डिजिटल असिस्टेंट के कान, यह वह बातें भी सुन सकता है, जो आप नहीं चाहते सुनाना

धीरे-धीरे बोल, कहीं 'एलेक्सा' सुन ना ले

न्यूयॉर्क टाइम्स से

वाशिंगटन : टेक्नोलॉजी की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) से जो क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, उनसे कोई अछूता नहीं है। चिकित्सा, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में डंका बजाने के बाद एआइ ने अब लोगों के घरों में भी प्रवेश कर लिया है। इसका सबसे सामान्य उदाहरण हैं आपके डिजिटल असिस्टेंट एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और सिरी। एलेक्सा को अमेजन ने तैयार किया है। गूगल असिस्टेंट गूगल का प्रोडक्ट है और सिरी को एपल ने विकसित किया है।

ये असिस्टेंट आपके कहने पर टीवी का चैनल बदल देते हैं, आपका मनपसंद गाना चला देते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी को फोन भी मिला देते हैं। काफी हद तक इन्होंने आपकी जिंदगी को आसान बना दिया है। कई लोगों के लिए तो ये असिस्टेंट किसी दोस्त जैसे होते हैं। इन असिस्टेंट को इस्तेमाल करते हुए एक बात हम सब जानते हैं कि इन्हें आपकी आवाज सुनाई देती है और समझ भी आती है। इसी आधार पर ये आपके निर्देश का पालन करते हैं।

सुन सकते हैं गोपनीय बातें : अब एक बड़ा सवाल यह है कि जब आप इन्हें कोई कमांड नहीं दे रहे होते हैं, उस वक्त ये असिस्टेंट क्या करते हैं? ये पूरी तरह डिजिटल सिस्टम हैं, इसलिए जाहिर है कि इन्हें नींद नहीं आती। इनका ध्यान भी कभी नहीं भटकता। इन खूबियों का सीधा सा अर्थ है कि ये असिस्टेंट उस वक्त भी आपकी बातें सुनते हैं, जब आप इन्हें कमांड नहीं दे रहे होते। इन्हें आपकी वह बात भी सुनाई देती है, जो आप अपने किसी अंतरंग साथी से कर रहे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बिजनेस डील की कोई गोपनीय बात भी इन्होंने सुनी हो।

गलत इस्तेमाल का खतरा : खतरा केवल इनके सुनने भर से नहीं है, खतरा यह है कि इनकी सुनी बातों का कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले। कई खबरों में दावा किया गया है कि अपने डिजिटल असिस्टेंट को ज्यादा से ज्यादा सक्षम बनाने के लिए अमेजन, गूगल और एपल लोगों की रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करती हैं। इन कंपनियों में सैकड़ों लोग बैठकर आपकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं और उसके आधार पर सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। इस दौरान उन्हें वह भी सुनाई दे सकता है, जो आपने नहीं सोचा होगा।

सामने आए हैं कई मामले : अमेरिका में अमेजन को एलेक्सा द्वारा बिना जानकारी के बच्चों की आवाज रिकॉर्ड करने के मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ा था। वहीं एक हत्या के मामले में एलेक्सा की रिकॉर्डिंग को बतौर सुबूत जमा कराया गया था। एक मामला ऐसा भी सामने आया था जब डिजिटल असिस्टेंट ने पति-पत्नी की बातें रिकॉर्ड करके उनके एक दोस्त को भेज दी थीं।

बचने के लिए कुछ जरूरी कदम : कंपनियों ने डिजिटल असिस्टेंट पर यूजर्स को नियंत्रण के लिए कुछ विकल्प दिए हैं। अमेजन ने यूजर्स को यह विकल्प दिया है कि वे अपनी रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल एलेक्सा के सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं या नहीं। इसी तरह पुरानी रिकॉर्डिंग को डिलीट करने का भी विकल्प है। गूगल ने भी गूगल असिस्टेंट को डिसेबल करने, डाटा शेयरिंग को नियंत्रित करने और रिकॉर्डिंग को डिलीट करने का विकल्प दिया है। इसी तरह एपल के मामले में आइफोन की सेटिंग में जाकर सीधे सिरी को डिसेबल किया जा सकता है। ऐसा करने से सभी रिकॉर्डिंग भी डिलीट हो जाती हैं।